



सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

क्विक प्रिंट्स, नारायणा फेज-1, नई दिल्ली-110 028 द्वारा टाईप सेट।

मुद्रक : विबा प्रेस (प्रा.) लि. नई दिल्ली-110 020

विषय - सूची

उपलब्धियां

1.	एक नजर	1
2.	प्रशासन	3
3.	सूचना क्षेत्र	11
4.	प्रसारण क्षेत्र	42
5.	फिल्म क्षेत्र	76
6.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	138
7.	योजना एवं गैर-योजना कार्यक्रम	139
8.	नई पहल	151

परिशिष्ट

1.	मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	154
2.	वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के लिए मीडिया अनुसार बजट	156

वर्ष की उपलब्धियां

- बाल फिल्म समिति, भारत (सी एफ एस आई) ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग के 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह 14 से 20 नवंबर 2005 तक हैदराबाद में आयोजित किया। 10 थियेटर्स में 35 से अधिक देशों की 170 फिल्में दिखाई गईं।
 - सी एफ एस आई की फिल्मों 23 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शामिल हुईं।
 - उद्घाटन समारोह के दौरान सी एफ एस आई के 50 वर्ष पूरे करने की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया।
 - 36वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2005 गोवा में राज्य सरकार के सहयोग से 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2005 तक आयोजित किया गया। देवानंद उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे।
 - 21 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। श्री अदूर गोपालकृष्णन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
 - दिसंबर, 2005 तक भारतीय फिल्मों ने 22 देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया।
 - गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ने 3 जनवरी 2006 को भारत संदर्भ ग्रंथ-2006 का 50वां संस्करण सफलतापूर्वक प्रकाशित किया।
 - सरकार ने 91 शहरों में एफ एम रेडियो स्टेशनों के लिए 337 भारतीय कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित कीं जिनमें 280 निविदाएं पूरी हुईं। सरकार को इससे 1157.35 करोड़ रुपये एकमुश्त प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त हुए जिसमें मौजूदा प्राइवेट एफ एम चैनलों से प्राप्त माइग्रेशन शुल्क भी शामिल है।
 - केबल टीवी नेटवर्क (रेग्युलेशन) एक्ट, 1995 तथा सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 अंतर्गत फिल्म प्रमाणन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन कोड की समीक्षा के लिए समिति बना दी गई है।
 - टी वी चैनलों पर प्रसारित 'कंटेंट' से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निपटारा करने के लिए ब्राडकास्टिंग कंटेंट रेग्युलेटरी अथारिटी गठित कर दी गई है।
 - मीडिया के बदलते परिदृश्य में अपलिकिंग दिशा निर्देशों को अद्यतन करने के लिए अपलिकिंग दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई और नए दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
 - अप्रैल से नवंबर 2005 के दौरान डीएवीपी ने 15,502 प्रेस विज्ञापन जारी किए। बाहरी प्रचार के हिस्से के रूप में इस अवधि के दौरान 19,896 डिस्पले हुए। निदेशालय ने मुद्रित प्रचार सामग्री की 97,08,100 प्रतियां तैयार कीं। अप्रैल 1 दिसंबर 2005 की अवधि के दौरान डीएवीपी ने 3,305 ऑडियो स्पॉट प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम तथा 467 वीडियो फिल्मों/स्पॉट भी तैयार किए। डीएवीपी की प्रदर्शनी इकाई ने 2,032 दिनों की 453 प्रदर्शनियां आयोजित कीं।
 - डीएवीपी के 'रेट स्ट्रक्चर' की एक रेट स्ट्रक्चर कमेटी विस्तारपूर्वक समीक्षा करती है। नए रेट एक जनवरी, 2006 से लागू कर दिए गए हैं।
 - भारतीय जनसंचार संस्थान (आई आई एम सी) ने अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन "अपना रेडियो एफ एम 96.9 मेगाहर्टज" शुरू किया है।
 - अप्रैल से अक्टूबर 2005 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने एड्स से लेकर भारत निर्माण थीम के प्रति जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत 23,407 फिल्म शो, 1,173 गीत एवं नाटक शो, 4,578 विशेष कार्यक्रम, 32,826 मौखिक संचार कार्यक्रम और 19,000 से अधिक फोटो प्रदर्शनियों के अलावा 3,5445 जनविचार गोष्ठियां आयोजित कीं।
 - अप्रैल से दिसंबर, 2005 की अवधि के दौरान प्रकाशन विभाग ने 85 पुस्तकें प्रकाशित कीं।
 - अप्रैल से दिसंबर 2005 के दौरान फिल्म प्रभाग ने 1,341 फिल्मों का डिजिटलीकरण किया।
 - पत्र सूचना कार्यालय ने अप्रैल से नवंबर 2005 के दौरान प्रिंट मीडिया के लिए 77613 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। ब्यूरो ने प्रेस के लिए 11,469 फोटो, विभिन्न मुद्दों पर 568 फीचर भी जारी किए तथा 1,289 प्रेस सम्मेलन भी आयोजित किए।
 - भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक ने अप्रैल से दिसंबर 2005 के दौरान 14,549 आवेदनों की पड़ताल शीर्षकों के लिए की और 7724 शीर्षकों की स्वीकृति प्रदान की। इसी अवधि के दौरान प्रेस पंजीयक द्वारा 9,516 शीर्षकों को मुक्त किया गया।
 - फोटो प्रभाग ने अप्रैल से दिसंबर 2005 के दौरान 2,12,545 फोटो तथा इमेजों का डिजिटलीकरण किया।
 - गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा 32,000 से अधिक कार्यक्रम/शो भारत निर्माण तथा अन्य सामाजिक मुद्दों पर आयोजित किए।
-

1

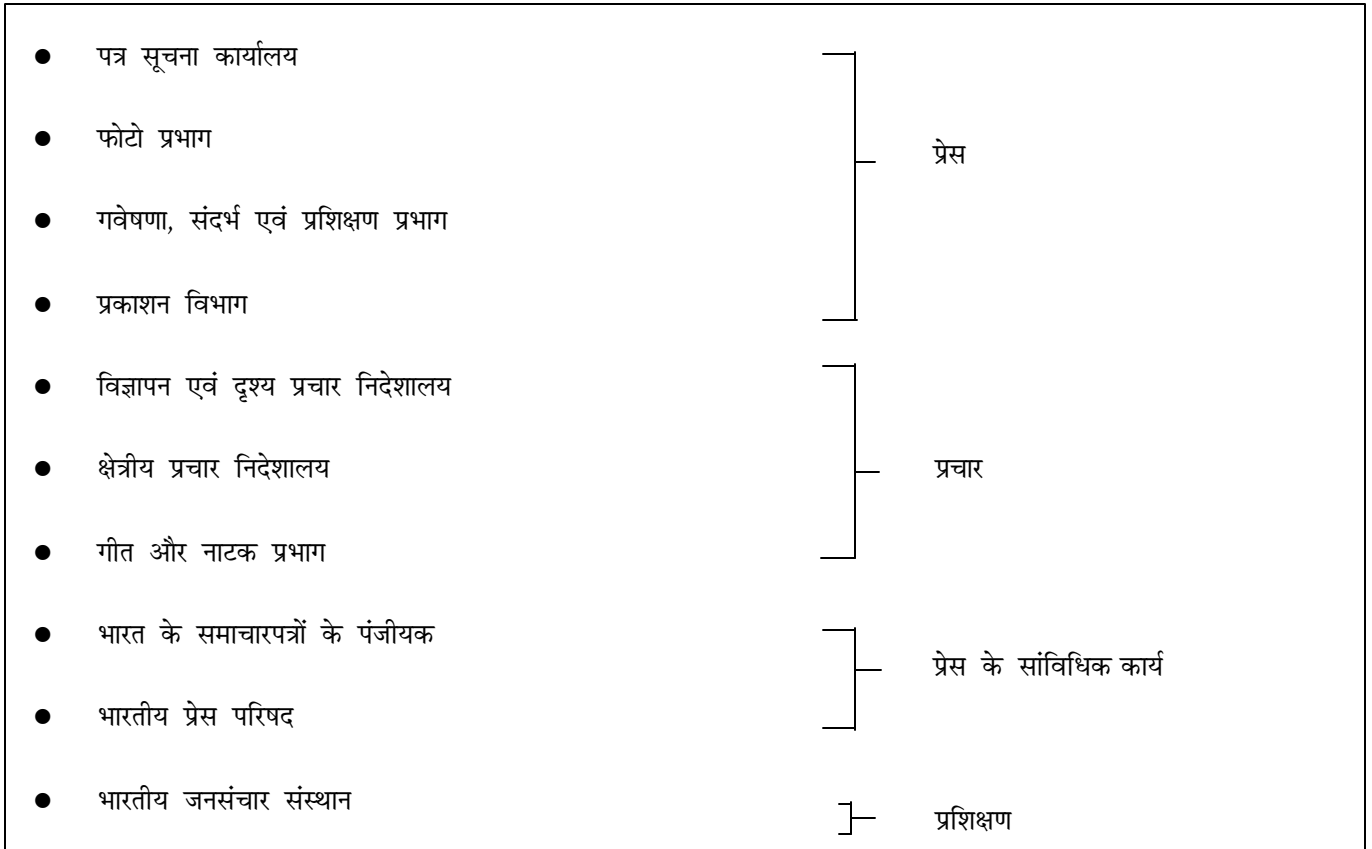
एक नजर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय जनसंचार माध्यमों जिसमें रेडियो-टेलीविजन, फिल्म, समाचारपत्र प्रकाशन, विज्ञापन और नृत्य तथा नाटक के पारंपरिक तरीकों के द्वारा लोगों को आसानी से सूचना हासिल करने में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। मंत्रालय विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की मनोरंजन तथा बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों के अलावा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों पर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करता है।

मंत्रालय चार विंग में विभाजित है : सूचना खंड, प्रसारण खंड, फिल्म खंड तथा एकीकृत वित्त खंड।

सूचना विंग, संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन) के तहत भारत सरकार के नीतिगत मामले, प्रकाशन तथा पत्र और प्रचार आवश्यकताओं को देख जाता है। इस खंड की मीडिया इकाई इस प्रकार है :

प्रसारण खंड संयुक्त सचिव (प्रसारण) की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामलों को देखता है। इस क्षेत्र के प्रसारण सेवा, केबल टेलीविजन संचालन, प्राइवेट टेलीविजन चैनल, एफ



एम चैनल इत्यादि के लिए नीतियां और नियमों को बना कर उन्हें लागू करती है।

इस खंड के अंतर्गत निम्नलिखित संगठन आते हैं :

- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके अंतर्गत निम्न संस्थान हैं :
- आकाशवाणी
- दूरदर्शन

- ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
- फिल्म क्षेत्र से संबंधित मामलों को **फिल्म विंग** संयुक्त सचिव (फिल्म) की देखरेख में देखता है। फिल्म उद्योग से संबंधित विकास और प्रचार गतिविधियां जिसमें प्रशिक्षण, सार्थक सिनेमा का प्रचार, फिल्म समारोहों का आयोजन और निर्यात नियंत्रण आदि शामिल हैं। इसके अलावा आंतरिक तथा बाहरी प्रचार के लिए आवश्यक वृत्तचित्रों का निर्माण और वितरण इसी विंग की जिम्मेदारी है। इसकी निम्नलिखित मीडिया इकाई हैं :

● फिल्म प्रभाग	-	वृत्तचित्र निर्माण
● केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	-	प्रमाणन
● भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	-	संरक्षण
● राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	-	फिल्म वित्त
● भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	}	प्रशिक्षण
● सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता		
● फिल्म समारोह निदेशालय	-	अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन
● बाल फिल्म सोसाइटी, भारत	-	बाल फिल्मों को प्रोत्साहन

एकीकृत वित्त खंड मंत्रालय के वित्तीय मामलों की देखरेख करती है जिसमें बजट निर्माण और योजना समन्वयन शामिल है। मंत्रालय की विकास आवश्यकताओं के लिए 10वीं पंचवर्षीय

योजना (2002-2007) के अंतर्गत कुल व्यय 5130.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

2

प्रशासन

कामकाज के आबंटन के नियमानुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मुद्रित मीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्मों से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।

मंत्रालय को उसके कार्यों में सहायता और सहयोग देने के लिए 13 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, छः स्वायत्त संगठन और दो सार्वजनिक उपक्रम हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य

- विदेशों में रह रहे भारतीयों सहित आम जनता के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के जरिए समाचार सेवाएं प्रदान करना।
- रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण का विकास।
- फिल्मों का आयात एवं निर्यात।
- फिल्म उद्योग की उन्नति और विकास।
- फिल्म समारोहों का आयोजन और इस उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार।
- भारत सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करने और इनके बारे में जन प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए प्रेस संबंध बनाना।
- समाचार-पत्रों के संदर्भ में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का कार्यान्वयन।
- भारत से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रकाशनों के जरिए देश-विदेश में जानकारी का प्रसार।
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता के लिए शोध, संदर्भ तथा प्रशिक्षण।
- मंत्रालय से जुड़े संस्थानों को महत्वपूर्ण योगदान करने वाले उत्कृष्ट कलाकारों, संगीतकारों, वाद्य संगीतकारों, नाटककारों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्रसारण और समाचार सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय संगठन

संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

1. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय
2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
3. पत्र सूचना कार्यालय
4. प्रकाशन विभाग
5. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
6. फिल्म समारोह निदेशालय
7. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग
8. फिल्म प्रभाग
9. फोटो प्रभाग
10. गीत और नाटक प्रभाग
11. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
12. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार
13. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र
13. मुख्य लेखा नियंत्रक

स्वायत्त संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे
3. भारतीय जन-संचार संस्थान
4. बाल फिल्म समिति, भारत
5. भारतीय प्रेस परिषद
6. सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
7. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
8. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

मुख्य सचिवालय

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है जिसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त सचिव, एक वित्तीय सलाहकार और अतिरिक्त सचिव, तीन संयुक्त सचिव और एक मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं। मंत्रालय के विभिन्न खंडों में निदेशक/उपसचिव स्तर के अधिकारियों के 11, अवर सचिव स्तर के 15, राजपत्रित अधिकारियों के 41 और 284 अराजपत्रित पद हैं।

लोक शिकायत

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर

रहा है। संयुक्त सचिव (पी एंड ए) को आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रमुख नामित किया गया है।

सूचना सुविधा केंद्र

प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 4 जुलाई, 1997 से मंत्रालय में सूचना सुविधा केंद्र शुरू कर किया गया है।

मूल घोषणापत्र

मंत्रालय ने अपना मूल घोषणापत्र तैयार किया जो मंत्रालय के वेबसाइट (<http://www.mib.nic.in>) पर उपलब्ध है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में स्वीकृत स्टाफ

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या
	सचिव	1
	अतिरिक्त सचिव	1
	ए एस और एफ ए	1
	संयुक्त सचिव	3
	निदेशक/उप निदेशक	11
	निदेशक (ओ एल)	1
	वरिष्ठ पी पी एस	1
	अपर सचिव	20
	वरिष्ठ विश्लेषक	1
	पी पी एस	2
	राजपत्रित पद (कुल 46)	
	अनुभाग अधिकारी	34
	पी एस	8
	सहा. निदेशक (ओ एल)	1
	अनुसंधान अधिकारी	1
	ए.ओ. (पार्ल.)	1
	कनिष्ठ विश्लेषक	1
	अराजपत्रित पद (कुल 284)	
	सहायक	59
	स्टेनो 'सी'	21
	स्टेनो 'डी'	18
	यू डी सी	37
	एल डी सी	42
	स्टार कार चालक	8
	रिकार्ड कीपर	5
	वरिष्ठ जी ओ	1
	डिस्पेच राइडर	1
	ग्रेड 'सी' केंटीन कर्मचारी	8
	एक्स कैडर पोस्ट	9
	ग्रेड 'डी'	75

अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

जहां तक सेवाओं में आरक्षण का सवाल है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय हैं। सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.जा. को आरक्षण देने तथा अन्य लाभ प्रदान करने के बारे में नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा हिदायतों पर सख्ती से अमल करने के लिए सभी मीडिया इकाइयों को अनिवार्य रूप से निर्देश दिए जाते हैं।

मंत्रालय सरकार द्वारा जारी आदेशों/हिदायतों/दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मंत्रालय अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित समूचे मंत्रालय में विभिन्न पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत और उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच अंतर को कम से कम करने के लिए सभी कदम उठा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में पदों के आधार पर रोस्टर भी बनाए जाते हैं।

पहली जनवरी 2005 को संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित समूचे मंत्रालय में कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत इस प्रकार है :

	वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'	वर्ग 'ग'	वर्ग 'घ'	कुल
अनुसूचित जाति	11.67%	15.21%	18.35%	27.19%	19.16%
अनुसूचित जनजाति	4.81%	5.44%	7.46%	12.08%	7.85%
अन्य पिछड़ी जाति	3.43%	3.52%	6.42%	7.11%	5.76%

मंत्रालय आरक्षण नीति को लागू करने और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. को नियमानुसार देय विभिन्न लाभ दिलाने संबंधी काम की निगरानी के लिए मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव स्तर के संपर्क अधिकारी की देखरेख में एक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

राजभाषा हिंदी का उपयोग

हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने की सरकार की सोची-समझी हुई नीति है। भारत सरकार की राजभाषा भाषा नीति के तहत मंत्रालय हिंदी के प्रयोग पर बल दे रहा है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुख्य सचिवालय तथा मंत्रालय से संबद्ध और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने के कार्य पर नजर रखती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की भाषा नीति को लागू करने की स्थिति की समीक्षा की गई और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में कई सुझाव रखे गए। इस बारे में नोडल विभाग के तौर पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर सभी मीडिया इकाइयों में वितरित कर उनसे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास करने का आग्रह किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा बैठकों में निर्धारित लक्ष्यों के बारे में मीडिया इकाइयों के साथ विचार-विमर्श किया गया और उन्हें पूरा करने के सभी संभव प्रयास किए गए।

14-28 सितंबर 2005 तक सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 'हिंदी पखवाड़ा' आयोजित किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, कविता, टिप्पण एवं आलेखन, भाषण, अनुवाद, हिन्दी आशुलिपि, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 186 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें 75 अधिकारियों/कर्मचारियों (हिन्दी भाषी और गैर-हिन्दी भाषी दोनों) को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसी तरह मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें विजेताओं को प्रमाण-पत्र व नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय मंत्री महोदय ने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की अपील जारी की। इसमें अलावा इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री और कैबिनेट सचिव द्वारा की गई अपील को मंत्रालय में वितरित किया गया।

मंत्रालय के सचिवालय को राजभाषा संबंधी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक निदेशक (ओ एल), एक सहायक निदेशक (ओ एल तथा चार अनुवादक हैं जो भारत सरकार की

राजभाषा नीति की व्याख्या सहित उसके क्रियान्वयन तथा निगरानी और अनुवाद का काम देखने के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है और उसे मंत्रालय का हिंदी अनुभाग देखता है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेजों/पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करने तथा हिंदी में लिखे और हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देने संबंधी निर्देशों पर पक्के तौर पर अमल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न अनुभागों/मीडिया इकाइयों से मिली त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई और राजभाषा नीति का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 24 अक्टूबर, 2005 से 26 अक्टूबर, 2005 तक एक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 83 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

मंत्रालय और उसके नियंत्रण में आने वाले अधीनस्था संबंधित कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग में प्रगति की समीक्षा तथा इसे बढ़ावा देने के तौर तरीके सुझाने के लिए मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक हिंदी सलाहकार परिषद काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में पिछली बैठक 20 जनवरी 2005 को आयोजित की गई।

आलोच्य वर्ष के दौरान मंत्रालय ने अपनी गृह पत्रिका 'सूचना भारती' का तीसरा अंक निकाला। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत हिंदी में टिप्पण और प्रारूपण के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2004-05 में 8 स्टाफ कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

राजभाषा संबंधी संसद की द्वितीय उप-समिति ने वर्ष के दौरान (31 दिसंबर, 2005 तक) मंत्रालय के अधीन 8 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इन निरीक्षण बैठकों में एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। समिति के सुझावों पर गौर किया गया और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। मंत्रालय के अधीन दस कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और राजभाषा नीति पर बेहतर तरीके से अमल के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए।

मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय आकाशवाणी महानिदेशालय के कार्यालयों ने देश के विभिन्न भागों में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए। इन सम्मेलनों के आयोजन से राजभाषा नीति क्रियान्वयन में जोरदार सुधार देखा गया।

आंतरिक कार्य अध्ययन एकक

आंतरिक कार्य अध्ययन एकक (आई डबल्यू एस यू) ने संगठन की प्रशासनिक और वित्तीय कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास जारी रखे और न केवल खर्च में किफायत के लिए बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से अधिक कुशल बनाने के भी उपाय सुझाए।

व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) की सिफारिशों पर मंत्रालयों के संबद्ध कार्यालयों में कार्य अध्ययन के संदर्भ में नियमावली जारी करने का कार्य अब वित्त मंत्रालय की स्टाफ जांच इकाई के पास है। इस इकाई ने विविध संगठनात्मक तथा व्यवस्थित गतिविधियों जैसे नियंत्रण तथा देरी के विभिन्न पहलुओं की मानीटरिंग, मामलों को दायर करने तथा रफा-दफा करने के चरणों की समीक्षा, मामलों को निपटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से संबंधित कदम उठाए। इसके अलावा रिकार्ड प्रबंधन गतिविधि पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान अभिलेखन गतिविधियों संबंधी मासिक प्रयासों के साथ-साथ अभिलेख प्रबंधन के कार्य के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए जिसमें 33,932 फाइलों को अभिलेखबद्ध किया गया, 15,559 फाइलों की समीक्षा की गई और 8,672 फाइलों को रद्दी करार दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोजमर्रा के कामकाज को निपटाने में कार्यालय प्रक्रिया संबंधी मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है, अनुभागों/डेस्क का संगठन और प्रविधि (ओ एंड एम) द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत इस मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में संगठन और प्रविधि (ओ एंड एम) निरीक्षण करना भी इस यूनिट का कार्य है। इसी के तहत इस इकाई द्वारा फोटो प्रभाग मुख्यालय का ओ एंड एम निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार इस इकाई द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के चंडीगढ़ और लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। आर एन आई के चेन्नई तथा एस एंड डी डी के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक इस इकाई की ऐसे ही दो या तीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण की योजना है।

कैबिनेट सचिवालय द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप इस इकाई ने प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में सचिवों की समिति के समक्ष सचिव (सू एंड प्र) द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन की तैयारी के मामले में समन्वय का काम किया। इसी प्रक्रिया की कड़ी में मंत्रालय तथा मीडिया यूनिटों में वर्तमान प्रारूप की समीक्षा के लिए 10-11-2005

को संयुक्त सचिव (पी एंड ए) की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल के गठित होने के छः महीनों के भीतर सुझाव देने की आशा है।

आंतरिक कार्य अध्ययन एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और जनता के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न पुरस्कार योजनाओं को लागू करने और जवाबदेह बनाने में मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

लेखांकन संगठन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख के अलावा प्रधान लेखांकन अधिकारी भी हैं। सचिव को इस कार्य में अतिरिक्त सचिव और वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक से सहायता प्राप्त होती है।

मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन का प्रमुख होता है। इस कार्य में उनकी मदद के लिए एक लेखा नियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक, एक सहायक लेखा नियंत्रक तथा 14 वेतन और लेखा अधिकारी होते हैं। वेतन और लेखा कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित है।

लेखांकन संगठन मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं :

- विनियोगों के ऊपर नियंत्रण
- प्राप्तियों और खर्च को समय पर हिसाब में लेना
- महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को भेजने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के खातों का संकलन और समन्वयन।
- प्राप्ति बजट बनाना
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना
- पेंशन, भविष्य निधि और अन्य दावों का शीघ्रता से निपटान
- मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा
- संबंधित अधिकारियों को लेखांकन संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना
- फिल्म समारोह निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग तथा गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के लिए आंतरिक वित्त सलाहकार के कार्य।

कंप्यूटरीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लेखा संगठन द्वारा ई-गवर्नेंस की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

सी पी एफ (कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड मैनेजमेंट) लागू करना

यह सॉफ्टवेयर वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के एन आई सी प्रकोष्ठ ने विकसित किया है तथा इसका उपयोग प्री-चेक, संकलन और लेखा एकीकरण के लिए होता है।

लेखा कम्प्यूटरीकरण (कांपेक्ट)

यह सॉफ्टवेयर वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के एन आई सी प्रकोष्ठ ने विकसित किया है जिसका उपयोग प्री चेक, संकलन और लेखा एकीकरण के लिए होता है।

वेबसाइट पर मासिक खर्च

मई, 2005 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट : <http://mib.nic.in> पर मंत्रालय के व्यय का विवरण उपलब्ध है।

ई सी एस के जरिये वेतन भुगतान

जुलाई, 2005 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सी सी ए कार्यालय के स्टाफ के वेतन का भुगतान ई सी एस से किया जा रहा है। अन्य डी डी ओ को भी चेक/नकद भुगतान के स्थान पर ई सी एस के जरिए वेतन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा से अनियमित खर्च को रोकने और प्रशासन की वित्तीय स्थिति ठीक रखने के दिशा-निर्देश देने में सहायता मिलती है।

सुविधा और किफायत की दृष्टि से चार जोनल आंतरिक लेखा परीक्षा दल उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पश्चिमी जोन और पूर्वी जोन बनाए गए हैं जो क्रमशः नई दिल्ली, चैन्नई और कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक जोनल आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यालय का प्रमुख लेखा अधिकारी होता है। मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा उत्तरी जोन की लेखा परीक्षा करती है और बाकी तीन क्षेत्रीय शाखाओं के लेखा परीक्षा कार्य का समन्वय करती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों से कुछ ऐसी प्रमुख अनियमितताओं को रोकने में मदद मिली है जिनमें बड़ी रकम शामिल थी। ये इस प्रकार हैं -

1. सरकारी लेनदारी की वसूली न होना	137633.09 लाख रुपये
2. अधिक भुगतान	4.23 लाख रुपये
3. बेकार पड़ी मशीनरी/फालतू भंडार	4.84 लाख रुपये
4. नुकसान/बरबाद खर्च	17.72 लाख रुपये
5. अनियमित खर्च	31.60 लाख रुपये
6. अग्रिम का समायोजन न होना	1271.91 लाख रुपये
7. अनियमित खरीद	8.59 लाख रुपये
8. सरकारी धन का फंसना	14.24 लाख रुपये
9. महंगी भंडार सामग्री को हिसाब में न लेना	2.64 लाख रुपये
10. अन्य विशिष्ट वस्तुएं	10.87 लाख रुपये
कुल	138999.73 लाख रुपये

सतर्कता

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सचिव की देख रेख में कार्य करता है। इनकी सहायता के लिए इनके अधीन मुख्य सतर्कता अधिकारी (मुख्य सचिव स्तर पर) निदेशक/ उपसचिव (सतर्कता) तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्वीकृति से प्रसार भारती के लिए अलग से एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की सतर्कता गतिविधियों पर नजर रखता है। मंत्रालय से संबद्ध/अधीन अन्य कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा पंजीकृत समितियों की सतर्कता गतिविधियों का समन्वय मंत्रायय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है।

भ्रष्टाचार की संभावनाओं को सीमित करने के उद्देश्य से कार्य प्रणाली को सरल बनाने के प्रयास किए गए। संदेहास्पद निष्ठा वाले अधिकारियों की पहचान कर उन पर कड़ी नजर रखी गई। संवेदनशील यहीं पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को बदलते रहने का प्रयास किए गए। कार्य प्रणाली और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित आकस्मिक निरीक्षण किए गए। अप्रैल, 2005 से दिसंबर 2005 के दौरान 58 नियमित तथा 64 आकस्मिक निरीक्षण किए गए तथा 97 ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन पर निगरानी रखने की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों पर निगरानी रखे जाने लायक 34 क्षेत्रों का चयन किया गया। इस दौरान मंत्रालय और मीडिया इकाइयों में संदेहास्पद निष्ठा वाले राजपत्रित अधिकारियों की सूची तैयार करने और समीक्षा का कार्य मीडिया

इकाइयों और सी बी आई के परामर्श से किया गया। सूची में शामिल अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अग्रप्रेषित शिकायतों को निपटाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को जन संपर्क अधिकारी मनोनीत किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर लगातार नजर रखी जाती है और समय-समय पर संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

अप्रैल, 2005 से दिसंबर, 2005 के दौरान मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में विभिन्न स्रोतों से 238 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। छानबीन के बाद 65 मामलों में आरंभिक जांच के आदेश दिए गए। इस वर्ष के दौरान 35 मामलों में आरंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं। नियमित विभागीय कार्यवाही के तहत 40 मामलों में बड़ी दंडात्मक कार्यवाही और 9 मामलों में हल्की दंडात्मक कार्यवाही हुई। 21 मामलों में कड़ा दंड दिया गया जबकि 26 मामलों में हल्के दंड दिए गए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और 7 के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की गई।

सभी मीडिया इकाइयों से अनुशासनात्मक कार्यवाही के बकाया मामलों की मासिक रिपोर्ट तथा कार्यवाही की मंजूरी के लिए लंबित मामलों की पाक्षिक रिपोर्ट प्राप्त होती है। इन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित किया जाता है। लंबित मामलों की पूरी जानकारी समय-समय पर मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजी गई। इसके अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी समय-समय पर मंत्रालय के अधिकारियों की बैठकें बुलाते हैं, जिसमें मीडिया इकाइयों और मंत्रालय में लंबित अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की जाती है।

लिंग-समानता के मुद्दे

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा महिलाओं संबंधी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगाह रखने के लिए मंत्रालय में एक महिला प्रकोष्ठ बनाया गया है। हाल में इस प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है और निदेशक (प्रशासन) इसकी अध्यक्ष बनाई गई है तथा तीन वरिष्ठ महिला अधिकारियों को सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। यह प्रकोष्ठ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में शिकायत समिति का भी कार्य करेगा। इस फैसले से संबंधित

प्रावधान को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण), नियमावली, 1964 में नियम 3 सी के रूप में शामिल किया जा चुका है।

मंत्रालय भारतीय सूचना सेवा के काडर नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इस सेवा के अधिकारी सरकार तथा मीडिया के बीच संपर्क-सेतु का काम करते हैं। वे लोक सेवा प्रसारण संगठनों में समाचारों के प्रसारण संबंधित कार्य करते हैं। वे एक ऐसा माध्यम हैं जो व्यक्तिगत संपर्क सेतु बनकर जनता तक संदेश पहुंचाते हैं। इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर उनके समुचित प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय सूचना सेवा के वर्ग 'क' के 328 अधिकारियों में से 68 महिला अधिकारी हैं।

सी एंड ए.जी. लेखा निरीक्षण

आंतरिक नियंत्रण सिस्टम/आंतरिक लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली:

मंत्रालय कार्यालय प्रणाली, सरकारी नियमों, आदेशों और दिशा-निर्देशों, जो कि समय-समय पर केंद्रीय सचिवालय मैनुअल में वर्णित हैं, को लागू करता है। इन नियंत्रणों के लागू करने में बरती गई ढील से तंत्र में कमी आती है। इनमें से विभिन्न प्रबंधन और प्रशासनिक नीतियों/मामलों की कमी के कई मामले हैं जिनकी समीक्षा नहीं होती। आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षा में गिनाई गई कमियों के मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करना 10 लाख रुपये से अधिक का अनुपादन पाने वाली संस्थाओं को निष्पादन की समीक्षा नहीं हो पाती।

(2005 की रिपोर्ट सं. 2 का अनुच्छेद नं. 11)
(ट्रांजेक्शन आडिट टिप्पणी)

स्रोत पर कर कटौती की असफलता के चलते अतिरिक्त खर्च:

दूरदर्शन के मामले में बैलेंस आयकर को डिस्चार्ज करने में असफल रहने के चलते आयकर विभाग द्वारा 4.43 करोड़ रुपये का जुर्माना

(2005 की रिपोर्ट की संख्या 4 का अनुच्छेद 12.1)
(स्वायत्त संगठन)

रोका जा सकने वाला ब्याज भुगतान :

भारत में क्रिकेट बोर्ड को अधिकार शुल्क की किरतें जमा करने में देरी के चलते 1.42 करोड़ का ब्याज भुगतान

(2005 की रिपोर्ट का अनुच्छेद सं. 12.2)
(स्वायत्त संगठन)

रोके जा सकने वाले खर्च

रामपुर में आकाशवाणी को बंद रिसेविंग केंद्र की इमारत का निस्तारण न करने की स्थिति में 26.51 लाख रुपये का खर्चा

(2005 की रिपोर्ट का अनुच्छेद 12.3)
(स्वायत्त संगठन)

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्रसार भारती द्वारा खर्चीले आइटम की अनियमित सप्लाई बिना किसी एग्रीमेंट के, लिहाजा 22.68 की कम लेनदारी।

(2005 की रिपोर्ट का अनुच्छेद 12.4)
(स्वायत्त संगठन)

3

सूचना क्षेत्र

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

वर्ष 1945 में स्थापित गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयों के लिए सूचना-प्रदाता एकक के रूप में कार्य करता है। यह मीडिया इकाइयों को अपने अभियानों में सहायता लेने के लिए सूचना बैंक के रूप में कार्य करता है। यह जनमाध्यमों (मास मीडिया) में चल रहे रुझानों का अध्ययन करने के साथ ही जनसंचार पर संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा भी उपलब्ध कराता है। प्रभाग भारतीय जनसंचार संस्थान (आई आई एम सी) के सहयोग से भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य भी देखता है।

प्रभाग की एक नियमित सेवा 'डायरी आफ इवेंट्स' है जो प्रत्येक पखवाड़े प्रकाशित होती है। यह दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया - ए रेफरेंस एनुअल तथा मास मीडिया इन इंडिया भी निकालता है जो देश में जनसंचार पर एक व्यापक प्रकाशन है। इंडिया हिन्दी में भारत - एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के नाम से प्रकाशित किया जाता है। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी द्वारा 03 जनवरी 2006 को वार्षिक संदर्भ ग्रंथ - इंडिया/भारत - 2006 के 50वें संस्मरण का विमोचन किया गया।

प्रभाग विभिन्न अवसरों पर सामयिक विषयों पर आधारीक प्रपत्र भी जारी करता है। प्रभाग प्रत्येक माह वांछित जांच के बाद विशेष पत्रिकाओं पर एक रिपोर्ट भी तैयार करता है।

संदर्भ पुस्तकालय

प्रभाग का अपना विशाल पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों पर प्रलेखों का वृहत संग्रह, चुनी हुई पत्रिकाओं के सजिल्द खंडों के साथ विभिन्न मंत्रालयों, समितियों तथा आयोगों के प्रतिवेदन संकलित हैं। इसके भंडार में जनसंचार, पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन तथा

श्रव्य दृश्य माध्यमों पर विशिष्ट पुस्तकें, सभी प्रमुख एनसाइक्लोपीडिया श्रृंखलाएं, वार्षिकी पुस्तकें (ईयर बुक्स) तथा समकालीन लेख शामिल हैं।

इस पुस्तकालय की सुविधा भारतीय एवं विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के सभी प्रत्यापित संवाददाताओं एवं सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध है। वर्तमान निम्न वर्ष में दिसम्बर 2005 तक पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर 116 नयी पुस्तकें शामिल की गईं जिसमें से 57 पुस्तकें हिन्दी में हैं, पुस्तकालय के सदस्य पाठकों की कुल संख्या 1056 है।

जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र

प्रभाग के एक अंग के रूप में अपनी सामयिक पत्रिका सेवा के माध्यम से जनमाध्यमों में हो रही गतिविधियों तथा रुझानों के बारे में सूचनाओं को एकत्र करने, उनका अर्थ निकालने तथा उनके वितरण हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के मद्देनजर जनसंचार पर राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र (एन डी सी एम सी) का सृजन किया गया था। यह केन्द्र प्रमुख समाचारों, लेखों तथा जनसंचार पर उपलब्ध अन्य सूचना सामग्री का प्रलेखन करता है। केन्द्र का वर्तमान कार्य देश भर में जनसंचार के विकास हेतु सूचनाओं का एकत्रीकरण और प्रलेखन करने साथ ही उनका वितरण करना है।

एकत्र की गई सूचनाओं को एक स्थान पर रख कर उनका वितरण (प्रसार) विभिन्न सेवाओं के माध्यम से किया जाता है। इनमें चुनिंदा लेखों हेतु की गई टिप्पणी तालिका के लिए **करेंट अवेयरनेस सर्विस**, लेखों की विषय टिप्पणी तालिका हेतु - **बिब्लोग्राफी सर्विस**, फिल्म उद्योग की विभिन्न गतिविधियों के निचोड़ हेतु - **बुलेटिन ऑन फिल्मस**, प्रख्यात मीडिया व्यक्तियों की जीवनियों पर रेफरेंस इनफार्मेशन सर्विस **हू इज हू इन मास मीडिया**; जन संचार

कर्मियों को दिए गए पुरस्कारों के विवरण हेतु, आनर्स कन्फर्ड ऑन मास कम्युनिकेटर्स तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया पहलुओं पर मीडिया अपडेट शामिल हैं। केन्द्र द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर 2005 तक) ऐसी 38 सेवाएं प्रदान की गईं।

एन डी सी एम सी एक संदर्भ पुस्तक “मास मीडिया इन इंडिया” का संकलन और संपादन भी करता है। इस वार्षिक ग्रंथ में जन माध्यमों के विभिन्न पक्षों पर लेख, केन्द्र, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मीडिया संगठनों की स्थिति पर सूचना दी जाती है। इसमें प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में भी सामान्य सूचनाएं भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण

भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है दसवीं योजना अवधि में आर आर टी डी को आई आई एस अधिकारियों के प्रशिक्षण पक्ष की भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने के चौथे वर्ष में प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

- (क) आई आई एम सी, नई दिल्ली में 20 से 24 जून 2005 तक एडीटिंग ऑफ बुक्स/जर्नल्स पर लघु अवधि रिफ्रेशर पाठ्यक्रम (ख) आई आई एम सी, नई दिल्ली में 25 से 29 जुलाई, 2005 तक पी आई बी अधिकारियों के लिए लघु अवधि रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, (ग) पी आई बी अधिकारियों हेतु आई आई एम सी नई दिल्ली 22 से 26 अगस्त 2005 तक लघु अवधि रिफ्रेशर पाठ्यक्रम (घ) नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट शिमला में आई आई एस ग्रुप - ए) अधिकारियों के लिए 05 से 09 सितम्बर 2005 तक वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा सुग्राहीकरण (फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड आडिट सेन्सीटाइजेशन) (च) आई आई एम - लखनऊ में 17 से 21 अक्टूबर 2005 तक टीम बिल्डिंग पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम (मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम) (छ) आई आई एम सी, नई दिल्ली में थामसन फाउंडेशन, यूके के प्रशिक्षकों द्वारा 17 से 28 अक्टूबर 2005 तक संपादन, लेखन एवं साक्षात्कार (एडीटिंग, राइटिंग एंड इन्टरव्यूज) पर पाठ्यक्रम, (ज) आई आई एम, लखनऊ में प्रबंधकीय प्रभावशीलता (मैनेपरियल इफेक्टिवनेस) पर 21 से 25 नवम्बर 2005 तक प्रबंधन विकास कार्यक्रम (मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम)

सतर्कता

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) इस प्रभाग के सतर्कता अधिकारी हैं। वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान देकर उचित कार्यवाही की गई।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन करके उन्हें आकर्षक एवं किफायती मूल्यों पर पाठकों को उपलब्ध कराता है। अंग्रेजी और हिन्दी के साथ ही सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। पुस्तकों की विषयवस्तु का कला, इतिहास, संस्कृति, लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों की जीवनियां, देश एवं निवासी, वनस्पति एवं प्राणी जगत, बाल साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा गांधी साहित्य से लेकर भारत - एक संदर्भ ग्रंथ जैसे संदर्भ ग्रंथ, प्रेस इन इंडिया तथा मास मीडिया इन इंडिया (भारत में प्रेस तथा भारत में जनसंचार के माध्यम) तक है। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति के चुने हुए भाषणों का भी प्रकाशन किया जाता है।

विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है तथा यह अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों - नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवनन्तपुरम स्थित बिक्री केन्द्रों एवं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद तथा बंगलौर स्थित योजना कार्यालयों, के माध्यम से कार्य करता है। रोजगार समाचार (एम्प्लायमेंट न्यूज) एवं पत्रिकाओं के कार्यालय आर.के. पुरम, नई दिल्ली में स्थित हैं। हाल में ही विभाग का मुख्यालय पटियाला हाउस नई दिल्ली से स्थानांतरित होकर सूचना भवन, सी जी ओ कांप्लेक्स, नई दिल्ली में पहुंच गया है।

पुस्तकें

विभाग द्वारा प्रति वर्ष 120-150 पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं तथा अब तक 7600 विषयों (शीर्षकों) पर पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। अप्रैल-दिसम्बर 2005 की अवधि में अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 85 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। इस अवधि में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं - अंग्रेजी में - इंडियन रेलवे, ग्लोरियस 150 ईयर्स, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, भारतीय विज्ञान मंजूषा, कॉमन बर्ड्स ऑफ इंडिया,

कन्साइस ऑफ दी रेस : इंडियाज ऑफ बीट सिनेमा तथा हिन्दी में - कथा सम्राट प्रेमचन्द, कल्पना चावला, लाल बहादुर शास्त्री, दिल्ली की खोज, आर्यभट्ट, एवं क्षेत्रीय भाषाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल, गीत रामायण, जवाहरलाल नेहरू - ए पिक्टोरियल बायोग्राफी एवं मदर टेरेसा।

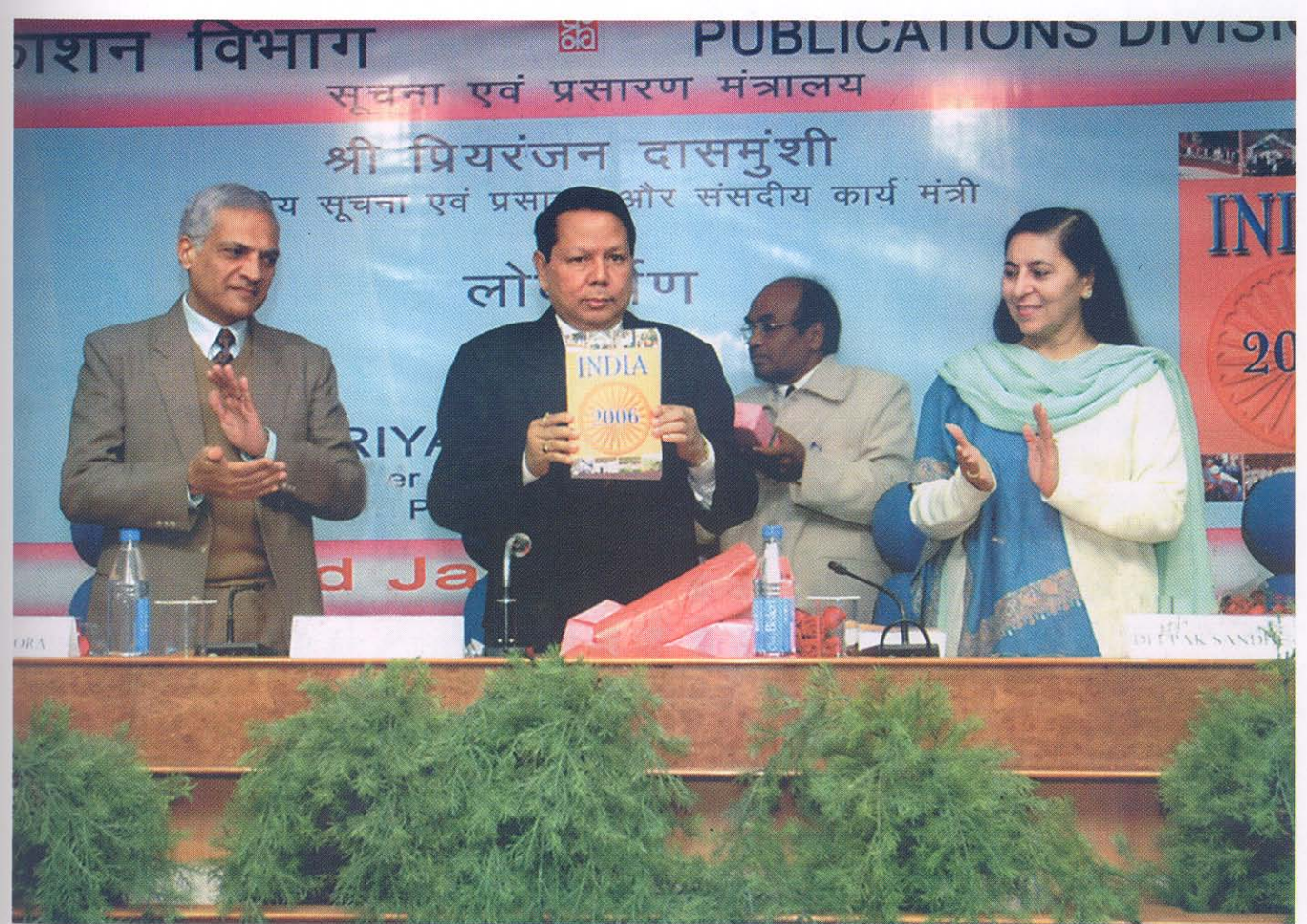
पत्रिकाएं

विभाग द्वारा 18 मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिसमें बच्चों के लिए पत्रिका 'बाल भारती', हिन्दी और उर्दू में 'आजकल', हिन्दी एवं अंग्रेजी में 'कुरुक्षेत्र' एवं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी,

उड़िया, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ में 'योजना' शामिल है।

बाल भारती

हिन्दी में बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका बाल भारती का 1948 से नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। इसका प्रमुख लक्ष्य लघु कथाओं, कविताओं, चित्र कथाओं एवं सूचनाप्रद लेखों के माध्यम से बाल पाठकों का मनोरंजन करने के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। वर्ष के दौरान बाल भारती द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें



सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित भारत-2006 (इंडिया-2006) पुस्तक का लोकार्पण किया, 3 जनवरी 2006, नई दिल्ली

दिल्ली राज्य के स्कूलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विजयी बालकों को दिसंबर 2005 में नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में पुरस्कृत किया गया।

आजकल

प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका 'आजकल' हिन्दी और उर्दू में निकलती है। विभाग द्वारा आजकल के ऐसे कई विशेषांक निकाले गए जिनमें भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के विविध स्वरूपों की झांकी दिखती है।

योजना

प्रकाशन विभाग की प्रमुख पत्रिका योजना है जिसमें वर्तमान सामाजिक आर्थिक मुद्दों को समहित किया जाता है। तेरह भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के नागरिकों विशेषकर अर्ध-शहरी/छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों में विभिन्न विकास योजनाओं तथा सामयिक आर्थिक विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष के दौरान प्रकाशित विभिन्न अंकों में रोजगार गारंटी, आधारभूत ढांचा, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार तथा ई-गवर्नेंस, शिक्षा और मनोरंजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया।

बजट एवं पूर्वोत्तर पर दो विशेष अंक निकाले गए। जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से पत्रिका में एक स्तंभ - **जे एंड के विंडो** शुरू किया गया है जिनसे इस राज्य में व्यापार के अवसरों और राज्य में आर्थिक गतिविधियों की संभावनाओं के बारे में जानकारी बढ़ाई जा सके। एक अन्य नया स्तंभ - "बेस्ट प्रैक्टिसेस" (सर्वश्रेष्ठ तरीके) भी प्रारंभ किया गया है जिसमें गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा की गई पहल, प्राप्त सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी दी जाती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के सहयोग से पत्रिका ने एक नई शृंखला "शोधयात्रा" प्रारंभ की। इस स्तंभ का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी बेहतरी के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी को प्रचारित करना है।

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र का प्रकाशन विभाग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से किया जाता है। ग्रामीण विकास को समर्पित यह पत्रिका ग्रामीण कार्यक्रमों, नीतियों तथा विकास प्रयासों के कार्यान्वयन की स्थिति

पर विचारों के आदान प्रदान हेतु मंच का कार्य करती है। इस पत्रिका के लिए लब्धप्रतिष्ठ लेखकों से लेख प्राप्त होते रहे हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम का मुख्य विषय "ग्रामीण आवास निर्माण तथा आधारभूत ढांचा" था।

एम्प्लायमेंट न्यूज (रोजगार समाचार)

विभाग द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में रोजगार समाचार/एम्प्लायमेंट न्यूज का प्रकाशन भी किया जाता है जिसमें सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों, विभागों, लोक उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, बैंकों तथा विश्वविद्यालयों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है। इस साप्ताहिक पत्रिका की लगभग सात लाख प्रतियां प्रकाशित होती हैं। देश भर में इसका 300 बिक्री एजेंटों तथा 4000 प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं का नेटवर्क है।

वर्ष 2005-06 की पहली छमाही में प्राप्त राजस्व 23.31 करोड़ रु. से अधिक रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से काफी अधिक है। वर्ष 2003-04 में प्राप्त कुल राजस्व 33.76 करोड़ रु. था जो वर्ष 2004-05 में बढ़कर 39.24 करोड़ रु. हो गया। प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या भी वर्ष 2003-04 के 43.7 से बढ़ कर 2005-05 में 46.62 हो गई तथा वर्तमान वर्ष में यह और अधिक बढ़कर 48.04 हो गई है। लागत मूल्य में हुई वृद्धि के बावजूद एम्प्लायमेंट न्यूज द्वारा अर्जित सकल राजस्व जो वर्ष 2003-04 में 12.51 करोड़ रु. था, वर्ष 2004-05 में 15.6 करोड़ रु. हो गया तथा इस वर्ष इसके 18 करोड़ रु. को पार कर जाने की आशा है।

एम्प्लायमेंट न्यूज की वेबसाइट भी www.employmentnews.gov.in के डोमेन नाम से क्रियाशील कर दी गई है। इस वेबसाइट में वर्तमान अंक के अतिरिक्त पिछले अंकों में रिक्त स्थानों के बारे में दी गई जानकारी के अलावा प्रकाशित लेखों तथा अन्य उपयोगी जानकारी भी मिलती है। जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने के एक कदम के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुस्तकालयों, शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में रोजगार समाचार की प्रतियां निशुल्क भेजी जाती हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार

जनसंचार पर हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए

शुरू किए गए 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार' अब बाल साहित्य तथा महिलाओं की समस्याओं एवं राष्ट्रीय एकता पर मौलिक लेखन के लिए भी दिए जाते हैं।

आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण

प्रकाशन विभाग के आधुनिकीकरण/कंप्यूटरीकरण की योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 2005-06 की अवधि में योजना मद में विभाग ने आधुनिकतम आई मैक कंप्यूटर की खरीद की। विभाग में नेटवर्किंग तथा वेबसाइट प्रबंधन के लिए दो और कम्प्यूटर खरीदे जा रहे हैं। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.publicationdivision.nic.in> है। विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं के विवरण, पुस्तक उद्योग की प्रमुख घटनाओं तथा आगामी पुस्तक प्रदर्शनियों/पुस्तक मेलों के बारे में जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विभाग के दो ई-मेल पते : publicationsdivision@hub.nic.in तथा publicationdivision@sb.nic.in हैं जिनका क्रय आर्डर देने तथा जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

नई योजनाएं/परियोजनाएं

विभिन्न विषयों जैसे भारत के ऐतिहासिक स्मारक, भारतीय शास्त्रीय संगीत इत्यादि पर बहुमाध्यमी इंटरएक्टिव सीडी तैयार करने की परियोजना गत वर्ष प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने चार ऐसी सीडी तैयार करने का लक्ष्य रखा है जिनसे शोधार्थियों, पर्यटकों तथा जनसामान्य को भारतीय सांस्कृतिक विरासत की जानकारी मिल सकेगी।

आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला

दसवीं योजनावधि के दौरान विभाग ने 'आधुनिक भारत के निर्माता' शृंखला के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशन हेतु 60 विभूतियों की जीवनियों के अनुवाद के प्रकाशन की परियोजना प्रारंभ की है।

नई पहल

विभाग ने वाराणसी तथा शिमला में लेखकों का सम्मेलन आयोजित

किया। जिसमें प्रकाशन तथा बिक्री के अवसरों के क्षेत्रों का पता चला। बच्चों की हिन्दी पत्रिका बाल भारती द्वारा एक कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। साथ ही आजकल ने अपने प्रकाशन के 60 वर्ष पूरे किए।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय केन्द्र सरकार की मल्टी मीडिया (बहु प्रचार माध्यम) विज्ञापन एजेंसी है। केन्द्र सरकार को सभी मंत्रालयों/विभागों और करीब 200 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और स्वायत्तशासी संस्थाओं की नीतियों और कार्यक्रमों को विभिन्न माध्यमों से प्रचारित करने वाली यह एक निर्दिष्ट सिंगल-विंडो एजेंसी है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करती है और विकास गतिविधियों में भागीदारी के लिए उन्हें अनुप्रेरित करती है। डी.ए.वी.पी. की संचार के विविध माध्यमों से जनता तक पहुंच है। इनमें समाचार-पत्र विज्ञापन, मुद्रित प्रचार सामग्री, दृश्य-श्रव्य प्रचार कार्यक्रम, बाहरी प्रचार सामग्री और प्रदर्शनियां शामिल हैं। डी.ए.वी.पी. के विज्ञापन और प्रचार के मुख्य विषय हैं, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य और सांप्रदायिक सद्भाव, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एड्स जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिशु उत्थान, नए आर्थिक उपाय, लघु बचत, साक्षरता उपभोक्ता मामले, रोजगार, आयकर, रक्षा, पर्यावरण, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और हस्तशिल्प।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के मुख्यालय में अनेक अनुभाग हैं। इनमें, प्रशासन, बजट और लेखा, अभियान, विज्ञापन बाहरी प्रचार, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर, मास मेलिंग, दृश्य-श्रव्य प्रकोष्ठ, डी.टी.पी. सुविधायुक्त डिजाइन स्टूडियो आदि शामिल हैं। इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः बंगलौर और गुवाहाटी में हैं। कोलकाता और चेन्नई में दो क्षेत्रीय वितरण केन्द्र हैं जो क्रमशः उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में मुद्रित प्रचार सामग्री के वितरण का कामकाज देखते हैं। देश भर में डी.ए.वी.पी. की 35 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां हैं। क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां सरकार और जनता के बीच प्रमुख संचार संपर्क के रूप में कार्य करती हैं।

इन क्षेत्रीय इकाइयों के अधिकारी केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सामाजिक और

विकासात्मक विषयों पर देश ने दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रदर्शनीयतां लगाते हैं।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को ध्यान में रख कर डी.ए.वी.पी. की ओर से मल्टी मीडिया (बहु प्रचार-माध्यम) अभियान शुरू किया गया। ग्रामीण स्वच्छता और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), एन आर.ई.जी.ए. और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित ग्रामीण रोजगार के बारे में सजावटी विज्ञापन जारी किए गए। जल संभरण प्रबन्धन (हरियाली), ग्राम विकास संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण सर्वोदय योजना की नियमावली, ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास योजना) के बारे में इस अवधि के दौरान पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं। आकाशवाणी से हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में ‘अब मंजिल दूर नहीं’ और ‘नई आशाएं नई दिशाएं’ शीर्षक से दो प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए गए। लोक जीवन पर आधारित एक प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम “गीत गूंजे गांव गांव” भी तैयार किया गया है।

गोवा में आयोजित 36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान डी.ए.वी.पी. ने प्रचार कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आई.एफ.एफ.आई. ब्रोशर्स, भारतीय पेनोरमा पर एक पुस्तिका और पोस्टर्स भी डी.ए.वी.पी. ने जारी किए। फिल्म समारोह के दौरान की घटनाओं और निर्धारित कार्यक्रमों के बारे में फेस्टिवल न्यूज (अंग्रेजी) और समारोह समाचार (हिन्दी) शीर्षक के प्रतिदिन बुलेटिन प्रकाशित किए गए। इन बुलेटिनों में फिल्म समीक्षा के साथ-साथ लोगों के विचार भी प्रकाशित किए गए। डी.ए.वी.पी. की ओर से समारोह के दौरान “मेनी फैसट्स - वन फेसिनेशन” शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। दहेज, बालिका भ्रूण हत्या, बाल-विवाह और घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता सम्बन्धी सन्देशों के प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों में, अनेक विज्ञापन जारी किए गए। इन संदेशों को और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाहय प्रचार अभियान चलाया गया। पोषाहार तथा सभी के लिए शिक्षा जैसे बाल कल्याण कार्यक्रमों पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए। पूरक आहार के बारे में संदेशयुक्त बाहय प्रचार फार्मेट में विज्ञापन प्रदर्शित किए गए। शिशु स्तनपान और शिशु और बाल आहार विधि के बारे में पुस्तिकाएं,

फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण तथा पोषाहार के बारे में गणक के साथ-साथ पुष्ट आहार पर पोस्टर भी डी.ए.वी.पी. की ओर से तैयार किए जा रहे हैं।

इन सबके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़-शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह के साथ-साथ शिक्षक दिवस पर विज्ञापन और पोस्टर जारी और वितरित किए गए। विश्व खाद्य दिवस, आयोडिन अभाव दिवस, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, शिक्षक दिवस और स्तनपान सप्ताह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर सन्देशों के प्रचार किए गए।

डी.ए.वी.पी. की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एक बहु प्रचार माध्यम अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से डी.ए.वी.पी. ने इस मिशन के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन के अलावा एक व्यापक दृश्य-श्रव्य प्रचार की योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और हैदराबाद के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान इस विषय पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं।

पल्स पोलियो टीकाकरण, एच आई वी/एड्स, तंबाकू निषेध बालिका शिशु सुरक्षा, स्तनपान, मलेरिया और फाइलेरिया बचाव तथा नेत्रदान आदि के बारे में प्रचार के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ विज्ञापन जारी किए गए। एच आई वी/एड्स जागरूकता और रक्तदान के बारे में समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी कर तथा पुस्तिकाएं और पोस्टर्स प्रकाशित कर उनके वितरण के माध्यम से बहु प्रचार माध्यम अभियान चलाया गया। स्वेच्छा से रक्तदान और एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता के लिए बसों के पीछे पैनल और जगह-जगह बड़े हार्डिंग्स लगाकर बाहय प्रचार किया गया। एच आई वी/एड्स जागरूकता पर डी.ए.वी.पी. की ओर से देश भर में 334 प्रदर्शनियां लगाई गईं। परिवार नियोजन उपाय सुरक्षित, प्रसव, टीकाकरण, नशाबन्दी और आरोग्य मेला जैसे विषयों के प्रचार के लिए हार्डिंग्स बसों के पीछे पैनल कियोस्क का इस्तेमाल किया गया।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए डी.ए.वी.पी. ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी मीडिया अभियान की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी मीडिया अभियान शुरू किया। देश भर में नियमित

रूप से रंगीन विज्ञापन जारी किए गए। नई उपभोक्ता जागरूकता पर टी.वी. स्पॉट निजी टी.वी. चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं।

डीएवीपी ने एन सी एम पी के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केन्द्रित अभियान के लिए विभिन्न फार्मेटों का प्रयोग करते हुए प्रचार कार्य चलाया। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन सी एम पी) पर एक पुस्तिका अंग्रेजी, हिन्दी तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में निकाली गई जिसका व्यापक रूप से वितरण किया गया जिससे लोगों में एन सी एम पी के विभिन्न आलेखों तथा प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इसके अतिरिक्त यूपीए सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर एक पुस्तिका “ए केयरिंग गर्वनमेंट” प्रकाशित की गई। ‘भारत निर्माण –ग्रामीण भारत के लिए एक नई पहल’ पर एक पुस्तिका और पोस्टर प्रकाशित किए गये तथा जागरूकता पैदा करने के लिए वितरित किए गये। ग्रामीण भारत के लिए सरकार के विजन/रोड मैप को प्रचारित करने के लिए बाहरी फारमेटों का प्रयोग किया गया। एन सी एम पी के विभिन्न पहलुओं पर अनेक विज्ञापन जारी किए गये। इनमें सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, कर का अनुपालन, खाद्य एवं पौष्टिकता, सुरक्षा एवं विकास के मुद्दे शामिल हैं। कृषि विस्तार तथा बाल कल्याण पर भी कार्यक्रम निर्मित और प्रसारित किए गये। मूल क्षेत्रों में उपलब्धियों को दर्शाते हुए यूपीए सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर विज्ञापनों की एक शृंखला जारी की गई। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और धर्मनिरपेक्षता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को जोड़ते हुए स्वतन्त्रता संग्राम, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू पर प्रदर्शनियां लगाईं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए टीकाकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा कन्या बालिका आदि पर केन्द्रित प्रदर्शनियां लगाईं गईं। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एच आई वी/एड्स पर देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। बाहरी माध्यमों के जरिए राष्ट्रीय एकता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान निषेध का भी प्रचार किया गया। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी प्रदर्शनियां लगाईं गईं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यू.पी.ए.) सरकार की पहली वर्षगांठ डी.ए.वी.पी. की ओर से प्रचार का एक और प्रमुख अवसर था। डी.ए.वी.पी. ने बेहतरीन डिजाइन के लागत-प्रभावी कुल 12 विज्ञापन तैयार कर देश भर के समाचार पत्रों को जारी किए। इस अवसर पर डी.ए.वी.पी. ने सरकार के वायदों और उपलब्धियों को दर्शाते हुए एक पुस्तिका प्रकाशित की। यू.पी.ए. सरकार के एक वर्ष पूरे होने

पर “ए केयरिंग गर्वनमेंट” शीर्षक से पुस्तिका प्रकाशित की। इनके अतिरिक्त यू.पी.ए. सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रमुख क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों के उल्लेख के साथ कई विज्ञापन जारी किए गए।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों की ओर से कर-अनुपालन, सेवा-कर, लघु-बचत, सहायता केन्द्रों की स्थापना, आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख, जैसे विषयों पर लगातार प्रचार अभियान चलाया गया और अनेक निवेशों के साथ बहुत से डिस्प्ले विज्ञापन जारी किए गए। इन मुद्दों पर डी.ए.वी.पी. द्वारा दीर्घविधि के दृश्य-श्रव्य अभियान भी चलाए गए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2005 के दौरान डी.ए.वी.पी. ने परिवार कल्याण मंडप में “स्वस्थ ग्राम – स्वस्थ भारत” से प्रदर्शनी लगाई गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विषय पर एक नई प्रदर्शनी तैयार कर इसे रंगीन ट्रांसलिट्स, टच स्क्रीन, लेजर डिस्प्ले, चलते-फिरते माडलों और डायोरोमास के माध्यम से दर्शाया गया। प्रदर्शनी के दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतिकरण ने इसे और जीवन्त स्वरूप प्रदान किया।

डी.ए.वी.पी. ने अल्पसंख्यकों, विकलांगों और बेसहारा बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रचारित करने का अभियान चलाया। डॉ. अम्बेडकर जयन्ती और मद्य परिनिर्वाण दिवस, मादक द्रव्यों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सद्भावना दिवस आदि अवसरों पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को सुर्खियां प्रदान करते हुए समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन जारी किए गए। “संवरती जाएं जीवन की राहें” विषय पर हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम तैयार कर आकाशवाणी की प्राइमरी और एफ.एम. चैनलों पर प्रसारित किया गया। यह कार्यक्रम समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए समर्पित था।

एग-मार्क एग्री-क्लीनिक, एग्री-बिजनेस, खरीफ-उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को नुस्खे, और राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की ओर किसानों के लिए सब्सिडी आदि के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन जारी किए गए। डी.ए.वी.पी. ने “सुनामी एक चुनौती” शीर्षक से प्रदर्शनी

लगाने और पुस्तिकाएं प्रकाशित करने के अलावा सुनामी के बारे में विज्ञापन भी जारी किए। दंडी मार्च के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी विज्ञापन जारी हुए और निदेशालय के प्रदर्शनी खण्ड ने इस समारोह को मनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई प्रदर्शनियां आयोजित की।

डीएवीपी ने सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन जारी करके तथा निजी टीवी चैनलों पर टीवी स्पॉट्स प्रसारित करके और साथ में मंत्रालय के लिए सड़क सुरक्षा पर एक कलेन्डर जारी करके मल्टीमीडिया अभियान चलाया। डीएवीपी ने 'डोनीयर' मंत्रालय के लिए पूर्वोत्तर में विकासात्मक मुद्दों पर विज्ञापन भी जारी किए। इसके अतिरिक्त इनके लिए दीवार तथा टेबल कलेन्डर मुद्रित किए। नियमित विज्ञापन जारी करने के साथ डीएवीपी ने रक्षा मंत्रालय के लिए काफी संख्या में कलेन्डर, ब्रॉशर, पोस्टर तथा प्लानर भी मुद्रित किए।

विज्ञापन

चालू वित्त वर्ष के दौरान (नवंबर 2005 तक) देश भर में विभिन्न समाचार पत्रों को कुल 15,502 विज्ञापन जारी किए गए। इनमें से 902 सजावटी (डिस्प्ले) विज्ञापन और शेष वर्गीकृत विज्ञापन थे। इनमें से कुछ विज्ञापन, 'पल्स पोलियो दिवस', 'सड़क परिवहन सप्ताह', 'विश्व स्वास्थ्य दिवस', 'इंदिरा गांधी जयंती', 'राजीव गांधी जयंती', 'सरदार पटेल जयंती', 'डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती', 'उपभोक्ता जागरूकता अभियान', 'आयकर', 'विश्व एड्स दिवस', 'नेत्रदान', 'रक्तदान', 'बाल दिवस', 'विकलांग व्यक्तियों', 'विश्व पर्यावरण दिवस', 'आतंकवाद विरोधी दिवस', 'स्वाधीनता दिवस', 'आयोडीन अभाव दिवस', 'विश्व खाद्य दिवस', 'दहेज विरोध', 'मानवाधिकार दिवस', 'राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस' आदि के बारे में थे।

दृश्य-श्रव्य प्रचार : डी.ए.वी.पी. का दृश्य-श्रव्य प्रकोष्ठ सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रयोजित रेडियो और वीडियो कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है। इसके अन्तर्गत जिंगल्स, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम तैयार कर आकाशवाणी दूरदर्शन, निजी टी.वी चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का प्रदर्शन क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों द्वारा भी किया जाता है। विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर अनेक साप्ताहिक प्रायोजित रेडियो

कार्यक्रम डी.ए.वी.पी. द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से इनका प्रसारण हो रहा है जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कल्याण योजना पर आधारित कार्यक्रम "संवरती जाएं जीवन की राहें", स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम "खुशियों भरा आंगन" ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम - 'गीत गूंजे गांव-गांव', 'नई आशाएं - नई दिशाएं', और 'अब मंजिल दूर नहीं', राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के एड्स जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम 'जीवन है अनमोल', 'लेट अस टॉक' पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए कार्यक्रम 'ये गुलिस्तां हमारा' और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के महिला और बाल विकास कार्यक्रम के बारे में 'आकाश हमारा है', जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम 15 से 30 मिनट की अवधि के हैं और ये हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में रोचक नाटकों के रूप में तैयार किए गए हैं। डी.ए.वी.पी. ने पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की ओर से 'खेल-खेल में बदलो दुनिया' शीर्षक से आधे घंटे की अवधि का साप्ताहिक वीडियो कार्यक्रम बनाया है जिसका दूरदर्शन से प्रत्येक रविवार को प्रसारण होता है और बुधवार को यह दोबारा दिखाया जाता है। इसके अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आर्थिक गणना, कृषि मंत्रालय के खरीफ अभियान पर आडियो/वीडियो स्पॉट/फिल्में बनाई गईं। सेतु समुद्रम जहाज चैनल परियोजना, आयकर विभाग के लिए रिटर्न दाखिल करने के बारे में आडियो/वीडियो स्पॉट के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, स्वेच्छिक रक्तदान और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के एड्स जागरूकता कार्यक्रम के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार अभियान चलाए गए।

इनके अलावा आयुश विभाग के लिए आरोग्य मेला, खाद्य और पोषाहार बोर्ड के पोषाहार शिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की बागवानी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के बारे में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार अभियान चलाए गए।

मुद्रित प्रचार अनुभाग

मुद्रित प्रचार अनुभाग, मुद्रण संबंधी कार्यों की योजना/ निर्माण और

देखरेख का काम देखता है। इसके तहत, बहुरंगी पोस्टर्स, फोल्डर्स, ब्रोशर्स, कलेण्डर, डायरी, बुकलेट स्टिकर्स, दीवार पर लटकाने वाली सामग्री टेबल कलेण्डरों और अन्य प्रचार सामग्री का मुद्रण कराया जाता है। हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा डीएवीपी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित प्रचार सामग्री तैयार कराता है। चालू वित्त वर्ष में तैयार कराई गई मुद्रित प्रचार सामग्री में 'यू.पी.ए. सरकार के एक वर्ष', 'भारत निर्माण', एक जिम्मेदार सरकार, पर बुकलेट प्रकाशित हुई। सुनामी, पंचायती राज, सुरक्षित प्रसव, केन्द्रीय बजट-2005, डी ए वी पी कलैण्डर 2006, सड़क परिवहन कलैण्डर 2006 का प्रकाशन हुआ। प्रधानमंत्री भाषण-शृंखला के तहत, प्रगति के पथ पर अर्थव्यवस्था विज्ञान को नए प्रोत्साहन की जरूरत, ग्रामीण भारत के लिए नए कदम, पूर्वोत्तर 2020 (फोल्डर) शीर्षक से बुकलेट और फोल्डर्स प्रकाशित किए गए।

वेक्टर जनित रोगों, रक्तदान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारत निर्माण, शिक्षक दिवस आदि पर पोस्टर्स छापे गए। मुद्रित प्रचार अनुभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान (नवंबर 2005) तक मुद्रण के 106 कार्य हाथ में लिए जिसमें 383 आइटमों की कुल 97,08,100 प्रतियां प्रकाशित हुईं।

बाहरी प्रचार

बाहरी प्रचार अनुभाग, संदेशों के प्रचार के लिए होर्डिंग्स, बस पैनल, कियोस्क दीवारों पर चित्रांकन, बैनर्स, एनिमेशन डिस्प्ले, सजावटी रेलिंग्स, सिनेमा स्लाइड्स, मैट्रो डिस्प्ले बोर्ड आदि बाह्य प्रचार प्रसार का इस्तेमाल करता है। इस अनुभाग ने 2005-06 के दौरान (नवंबर 2005) कुल 19896 डिस्प्ले किए।

राष्ट्रीय एकता, भारत निर्माण, एच आई वी/एड्स, आपदा प्रबन्धन, रक्तदान, पर्यावरण बचाओ, हालमार्क प्रतीक, भारतीय मानव संस्थान प्रतीक, बच्चों और महिलाओं के लिए संदेश, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण इ.पी.एफ., तंबाकू निषेध, आरोग्य मेला, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रचार अभियान चलाए गए। इसके अतिरिक्त सिमकॉन, फिल्म समारोहों जैसे घटनाक्रमों का प्रचार किया गया।

प्रदर्शनियां

प्रदर्शनी प्रभाग ने वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान 2032 प्रदर्शनी दिवसों में कुल 453 प्रदर्शनियां आयोजित की। राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी, जवाहर लाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डा. बी.आर. अम्बेडकर, राजीव गांधी, रबीन्द्रनाथ टैगोर, के कामकाज के जीवन वृत्त पर फोटो प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम, ऐतिहासिक घटना दांडी मार्च की 75वीं वर्षगांठ पर समारोह, जम्मू-कश्मीर-समय के साथ परिवर्तन, सुनामी-चुनौती, स्वस्थ ग्राम स्वस्थ भारत, पुनरुत्थानशील भारत, आतंकवाद का घृणित चेहरा और भारतीय महिलाएं, के बारे में भी प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त डी ए वी पी की क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयों ने चर्चित मेलों और समारोहों में भी प्रदर्शनियां लगाईं जिनमें, केरल का तिशूरपुरम उत्सव, मेरठ का नौचंदी मेला, पुरी रथ-उत्सव, चन्दौसी मेला, आई.टी.पी.ओ. में आरोग्य मेला, मैसूर का दशहरा समारोह राजा गार्डन्स का पूर्ण स्वास्थ्य मेला शामिल है।

मास मेलिंग

डी.ए.वी.पी. का मास मेलिंग अनुभाग देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों तक मुद्रित संदेश सामग्री भेजने का काम करता है। यह अनुभाग अपनी तरह की सबसे बड़ी संस्था है जिसकी पहुंच ब्लाक स्तर तक है। मास मेलिंग अनुभाग के पास 564 श्रेणियों के 16 लाख 50 हजार संगठनों के पते संरक्षित हैं। अप्रैल से नवंबर 2005 के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाशित सामग्री की 94 लाख प्रतियां इन पतों पर भेजी गईं। इसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यू.पी.ए. सरकार के एक वर्ष और प्रधानमंत्री के भाषण-शृंखला के तहत प्रकाशित पुस्तिकाओं का वितरण किया गया।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर एन आई)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर एन आई) द्वारा विभिन्न प्रकार के सांविधिक तथा गैर सांविधिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के शीर्षकों का सत्यापन और स्वीकृति, पंजीकरण तथा उनके प्रसार दावों की जांच की जाती है। अपने गैर-सांविधानिक कार्यों के अंतर्गत आर एन आई पंजीकृत प्रकाशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज के आयात हेतु पात्रता प्रमाण पत्र तथा प्रिंटिंग मशीनों के आयात हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करता है। यह प्रतिवर्ष "प्रेस इन इंडिया" भी

प्रकाशित करता है जिसमें देश में समाचार पत्रों की स्थिति का विवरण दिया जाता है।

शीर्षक संस्थापन और पंजीकरण

अप्रैल से दिसम्बर 2005 की अवधि में आर एन आई द्वारा शीर्षकों के सत्यापन हेतु 14,549 आवेदनों के दावों की जांच की ओर 7724 शीर्षकों को स्वीकृति दी गई। इसी अवधि में 2284 समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र (1623 नये + 661 संशोधित) जारी किए गए तथा 435 समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रसार दावों का मूल्यांकन किया गया।

शीर्षकों को मुक्त किया जाना (डी-ब्लॉकिंग)

ऐसे शीर्षक जिन्हें आर एन आई द्वारा वर्ष 2002 से सत्यापित

कर दिया गया था किंतु जिनका प्रकाशकों द्वारा कतिपय औपचारिकताएं पूरी नहीं किए जाने के कारण पंजीकरण नहीं किया जा सका, को मुक्त करने की कार्रवाई की गई। तदनुसार अप्रैल से दिसम्बर 2005 की अवधि में 9596 शीर्षकों को मुक्त किया गया।

अखबारी कागज (न्यूज प्रिंट)

अखबारी कागज को पहली मई 1995 से ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है तथा सभी प्रकार के अखबारी कागज (ग्लेण्ड तथा स्टैंडर्ड न्यूज प्रिंट) का आयात किसी भी वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आर एन आई की निर्धारित पात्रता शर्तों के अंतर्गत किया जा सकता है। अप्रैल से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान आर एन आई द्वारा पंजीकृत समाचार पत्रों /पत्रिकाओं को न्यूज प्रिंट में आयात हेतु 689 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए।



भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट प्रेस इन इंडिया 2004-05, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री एस.के. अरोड़ा को भेंट की गई, 29 दिसम्बर, 2005, नई दिल्ली

प्रिंटिंग मशीनरी

प्रिंटिंग मशीनरी और इससे सम्बद्ध उपकरणों के आयात हेतु आर एन आई प्राधिकृत अनुमोदनकर्ता है। अप्रैल से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान छह समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की प्रिंटिंग मशीनरी और इससे संबद्ध उपकरणों के आयात हेतु अनुशंसा की गई।

राजभाषा

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 14 से 28 सितम्बर, 2005 के दौरान किया गया तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अवधि में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजभाषा को समर्पित अर्द्ध-वार्षिक पत्रिका पंजीयन भारती का सातवां संस्करण अक्टूबर 2005 में प्रकाशित किया गया। राजभाषा पर गठित संसदीय समिति द्वारा जुलाई 2005 में आर एन आई कार्यालय का निरीक्षण किया गया।

कम्प्यूटरीकरण

शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया को आर एन आई में पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। स्वीकृत शीर्षकों को प्रति सप्ताह आर एन आई की वेबसाइट में डाल दिया जाता। वेबसाइट का पता <http://rni.nic.in> है। इस सुविधा को शुरू कर दिए जाने से अब कोई भी आवेदनकर्ता वर्तमान शीर्षकों तथा उसके/उसकी पसंद के शीर्षकों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये आंकड़े राज्य/भाषा वार उपलब्ध हैं।

आधुनिकीकरण योजना

आर एन आई के आधुनिकीकरण के योजना कार्यक्रम के दो प्रमुख घटकों -- आर एन आई का कम्प्यूटरीकरण और आर एन आई मुख्यालय का जीर्णोद्धार को 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए 19.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पूर्वोत्तर पहल

आर एन आई ने पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों का सहयोग लेकर अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई है। पी आई बी (पत्र सूचना कार्यालय) के क्षेत्रीय कार्यालयों को यह अधिकार दिया

गया है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रकाशकों को शीर्षक सत्यापन पंजीकरण, पंजीकरण विवरणों में परिवर्तन जैसे कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी दे सकते हैं। उन्हें इस उद्देश्य हेतु प्रकाशकों से आवेदन प्राप्त करने और उन्हें स्वीकृति के लिए आर एन आई मुख्यालय, नई दिल्ली भेज सकने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है।

आर एन आई हेतु योजना कार्यक्रम के आबंटन :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	योजना का नाम	बजट	संशोधित
		अनुमान 2005-06	अनुमान 2005-06
1	2	3	4
1.	फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण	19.70	19.70

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की स्थापना 1953 में हुई। उस समय इसे पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन कहा जाता था। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता था। दिसम्बर 1959 में इसका नाम बदला गया और इसे क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डी एफ पी) के नाम से पुनर्गठित करते हुए इसका दायरा बढ़ाया गया।

संगठन

निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके 22 प्रादेशिक कार्यालय तथा 246 क्षेत्रीय प्रसार इकाइयां कार्यरत हैं। समाज के निचले स्तर पर प्रचार संगठन के रूप में यह निदेशालय सभी स्तरों के लोगों को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। प्रचार अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों और अन्य आवश्यक साधनों से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें समूह वार्ताएं, जनसभाएं, सेमिनार, संगोष्ठियां और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। संदेश पहुंचाने के लिए फिल्मों और जीवन्त मनोरंजन माध्यमों का भी इस्तेमाल

किया जाता है। निदेशालय सरकार और लोगों के बीच दो तरफा माध्यम के रूप में काम करता है। निदेशालय के काम का एक महत्वपूर्ण भाग फीडबैक प्राप्त करना होता है। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों तथा ग्राम स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बारे में सफलता की कहानियां और जन प्रतिक्रियाएं एकत्र करती हैं, जिन्हें समेकित फीडबैक रिपोर्ट के रूप में सरकार और कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजा जाता है, ताकि सुधार के उपाय और अन्य समुचित कार्यवाहियां की जा सकें।

योजना गतिविधियां

योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान निदेशालय के लिए 11.00 करोड़ के अनुदान की मंजूरी दी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना के अंतर्गत क्षेत्रानुसार ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्षेत्र	10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 का परिव्यय प्रावधान	2005-2006 का परिव्यय प्रावधान
	11.00 करोड़	2.26 करोड़

योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की उपलब्धियां

निदेशालय के योजना कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचार गतिविधियों के लिए आधुनिक साफ्टवेयर की व्यवस्था करना और घिसे-पिटे व पुराने प्रचार ढांचे को बदलना।

योजना के अंतर्गत दो कार्यक्रम हैं : (1) **राजस्व** : फिल्म/कैसेटों की खरीद और (2) **पूँजीगत**: आधुनिकीकरण और पूँजीगत माल का उन्नयन/फिल्म प्रभाग और एन एफ डी सी से 17 फिल्म वी एच एस कैसेट/सी डी की खरीद का आर्डर दे दिया गया है जिन्हें देश भर में फैली 246 इकाइयों द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत 2.28 लाख रुपयों का व्यय गत वर्ष की शेष राशि से किया गया है। “आधुनिकीकरण और पूँजीगत माल का उन्नयन” के तहत पुराने वाहनों को बदलने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। 15 कम्प्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। पांच क्षेत्रीय कार्यालयों को कर्मचारियों/अधिकारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 2.50 लाख रुपये दिए गए। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है और शेष चार वित्तीय वर्ष के शेष भाग में आयोजित

किए जायेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डाटा प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेयर और वायरलेस पब्लिक एड्रेस सिस्टम खरीदे जाने के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है।

उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम

निदेशालय ने वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारित 226 लाख रुपये के कुल वार्षिक परिव्यय में से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 60 लाख रुपये की राशि रखी गई है। फिल्म/कैसेटों की खरीद योजना के लिए निर्धारित 50 लाख रुपये के कुल राजस्व में से 10 लाख रुपये और आधुनिकीकरण तथा पूँजीगत सामान के उन्नयन की योजना के लिए निर्धारित कुल एक करोड़ 96 लाख रुपये में से 50 लाख पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रखे गए हैं।

कार्यक्रम गतिविधियां

वर्ष 2005-2006 के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों का वार्षिक निष्पादन अप्रैल-अक्टूबर 2005 की अवधि के दौरान निदेशालय की कार्यक्रम गतिविधियों और नवंबर 2005-मार्च 2006 की अवधि में प्रत्याशित निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से अनेक विशेष प्रचार अभियान चलाये। सभी क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के नियमित प्रचार अभियानों के भाग के रूप में प्रजनन, बाल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का प्रचार किया गया। इनमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, आर टी आई/एस टी आई, रोग प्रतिरोधी टीकाकरण, प्रसव-पूर्व निदानात्मक तकनीक (पी एन डी टी/अधिनियम, लिंग संबंधी मुद्दे, एन आई डी डी सी पी, एड्स की जानकारी और बाल विवाह जैसे विषय शामिल थे।)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर निदेशालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देश भर में प्रचार करने के मूल विषय के रूप में लिया। नई दिल्ली में आयोजित एक दो दिवसीय कार्यशाला में मंत्रालय ने जन साधारण के लाभ के लिए मिशन के अनेक पहलुओं की चर्चा की और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाने के लिए अनुदान प्रदान किया। 15 सितम्बर 2005 से आरंभ ये प्रचार अभियान समूचे देश में पूरी गति से जाती है। अभियान अवधि

क्र.स.	कार्यक्रम	वास्तविक उपलब्धियां (31.10.2005 तक)	प्रत्याशित उपलब्धियां (0.11.2005 से (31.03.2006 तक)
1	फिल्म शो	23,407	20,063
2	गीत और नाटक	1,173	1,005
3	विशेष कार्यक्रम (भाषण/निबंध/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता/ग्रामीण खेल/चित्रकारी प्रतियोगिता/रैली/बेबी शो आदि सहित)	4,578	3,927
4	मौखिक वार्ताएं (समूह वार्तालाप, सेमिनार और संगोष्ठियों सहित)	32,826	28,136
5	फोटो प्रदर्शनियां	19,614	16,812
6	जन प्रतिक्रिया बैठकें।	3,545	3,038

के दौरान निदेशालय ने “राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं सामाजिक क्षेत्र” पर पांच दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जिनमें क्षेत्र संचारक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य सामाजिक क्षेत्र मसलों का प्रचार करने वाले विषय पर गहन रूप से जानकारी प्रदान करना था।

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण प्रचार अभियान

निदेशालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के देश से पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रचार किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल के संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी क्षेत्रीय इकाइयों ने 1-14 मई 2005 तक दो सप्ताह चलने वाले एक विशेष अभियान आरंभ किया जिससे जनसाधारण को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और लोग अपने 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 15 मई 2005 को आयोजित राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन आयोजन में ले जाकर उनको पोलियो की खुराक दिलवा सकें। इसी प्रकार उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो 7 अगस्त, 25 सितम्बर, 20 नवम्बर तथा 27 नवम्बर

2005 को आयोजित किए जाते हैं उनके लिए भी विशेष प्रचार अभियान चलाए गए।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

आयोडीन अल्पता से उत्पन्न होने वाले रोगों और लोगों को केवल आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए प्रेरित करने वाला राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की प्रचार सहायता से चलाया जा रहा है। यह विशेष अभियान नवम्बर 2005 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आरंभ हुआ और मार्च 2006 तक जारी रहेगा। इस अभियान में फिल्म प्रदर्शन, मौखिक वार्ताएं, फोटो प्रदर्शनियां, सूचना शिक्षा सामग्री का वितरण और विशेष वार्ता कार्यक्रमों को शामिल किया गया। कार्यक्रमों का आयोजन राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के आयोडीन अल्पता विकार सेल, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों और समेकित बाल विकास कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और अन्य संबद्ध एजन्सियों के सहयोग से किया गया।

एड्स जागरूकता

समाज में (एड्स का बढ़ता हुआ संकट निदेशालय के लिए चिंता

का विषय बना हुआ है। इस दुर्दान्त रोग के फैलाव और बढ़ती को रोकने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रचार कार्यक्रम जारी रखा है और लोगों को एड्स के मरीजों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता आ रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एक ऐसा वरीयता क्षेत्र है जिसमें निदेशालय दूर दराज में रहने वाले लोगों को जानकारी प्रदान करने का भरसक प्रयास कर रहा है। क्षेत्रीय इकाइयों ने अपने नियमित क्षेत्र कार्यक्रमों के जरिये लोगों को अनेक मसलों जैसे जन्म नियंत्रण, आहार, गर्भधारण के समय सावधानी, नवजात की देखभाल, प्रसव, विवाह की आयु आदि पर लोगों को जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया। महिला एवं बाल विकास विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा चंडीगढ़ में अप्रैल-मई के दौरान एक माह तक चलने वाला विशेष प्रचार अभियान चलाया गया जो 11 मई 2005 को समाप्त हुआ।

मलेरिया उन्मूलन

जून 2005 माह मलेरिया-उन्मूलन माह के रूप में मनाया गया। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने फिल्म प्रदर्शनों, पोस्टर प्रदर्शनियों और मौखिक वार्ताओं के जरिए मलेरिया उन्मूलन के लिए निवारक उपायों और सावधानियां लेने पर बल दिया।

ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। निदेशालय ने अक्टूबर 2005 से समूचे देश में एक अभियान चलाया जिसका उद्देश्य लोगों को आतिशबाजियों के कम प्रयोग और संगीत उपकरणों की ध्वनि कम रखकर ध्वनि प्रदूषण को घटाना था। यह अभियान वर्ष के अंत तक चला। अभियान के दौरान लोगों को ध्वनि प्रदूषण के कानूनों के बारे में अवगत कराया गया।

विश्व तम्बाकू रहित दिवस

31 मई 2005 को आयोजित विश्व तम्बाकू रहित दिवस पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिन्होंने धूम्रपान और तम्बाकू चबाने के कुप्रभावों को दर्शाया। अभियान का मुख्य केन्द्र सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाना और निष्क्रिय धूम्रपान के हानिकारक

प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करना था।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

सरकार द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्वीकार किये जाने को देखते हुए निदेशालय की सभी क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों का प्रचार किया। प्रचार कार्यक्रमों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सभी छह बुनियादी सिद्धान्तों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इनमें सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, सात-आठ प्रतिशत विकास दर का आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना, रोजगार मुहैया करवाना, किसानों और मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देना, महिलाओं का सम्पूर्ण सशक्तिकरण, समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करना शामिल था। तृण मूल स्तर की संस्था होने के नाते क्षेत्रीय प्रचार अभियानों का केन्द्र निर्धन लोगों के लिए कार्यक्रम व योजनाएं रही। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र व जम्मू एवं कश्मीर में संचार माध्यमों की पहुंच पर बल देना भी सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों का मुख्य केन्द्र रहा।

दांडी यात्रा की प्लेटिनम जयंती समारोह के भाग के रूप में निदेशालय ने अनेक प्रचार कार्यक्रम चलाये जिनसे 1930 के इस ऐतिहासिक दिवस के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके और युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के बलिदान के बारे में बताया जा सके। यह अभियान अप्रैल 2006 तक जारी रहेगा।

केरोसिन का सार्वजनिक वितरण

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से निदेशालय ने विभिन्न राज्यों के लगभग 500 चिन्हित खंडों में केरोसिन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रचार अभियान चलाया।

गैर परंपरागत उर्जा स्रोत

गैर परंपरागत उर्जा स्रोत मंत्रालय ने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी कार्यक्रम गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मंत्रालय को क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के कार्यालयों का उनके सभी प्रकार के उपकरणों के प्रदर्शन केन्द्रों के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया।

विकलांगों के लिए विशेष अभियान

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से निदेशालय

ने विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए विशेष जानकारी अभियान आयोजित किया। इनमें उनके विकास के लिये लागू अनेक कार्यक्रमों और सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई। यह अभियान जुलाई में आरंभ हुआ और दिसम्बर 2005 तक चला। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए क्षे.प्र.नि. ने उनके लिए विभिन्न योजनाएं एवं सुविधाओं से संबंधित कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रचार किया। निदेशालय ने वृद्ध जनों की देखभाल, उनकी सुरक्षा और कल्याण को वरीयता क्षेत्र मानकर प्रचार किया जिससे उनके अनुकूल विचारधारा विकसित हो सके।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा कार्यक्रम

निदेशालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से समाज के निर्धन, कमजोर और असहाय वर्गों के लिए कानूनी साक्षरता व निशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमों पर जानकारी अभियान आयोजित किये। राज्यों के कानूनी सेवा प्राधिकरण की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने 9 नवम्बर, 2005 को राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता दिवस के रूप में मनाया और शेष माह में गहन जानकारी प्रदान करने के कार्यक्रम आयोजित किये। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग्य व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करना और निहित स्वार्थी व्यक्तियों से गलत राय न लेने से आगाह करवाना था।

इसके अलावा राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव, सर्व शिक्षा अभियान, अस्पृश्यता और पर्यावरण संरक्षण क्षे०प्र०नि० के नियमित प्रचार कार्यक्रमों के भाग बने रहे।

पाक्षिक समाचार डाइजेस्ट

प्रचार गतिविधियों के अलावा सरकार को उसके कार्यक्रमों और नीतियों पर जनसाधारण की राय से अवगत कराना भी क्षे.प्र.नि की एक महत्वपूर्ण सेवा है जो वह सरकार को प्रदान कर रहा है। नियमित मासिक फीडबैक के अलावा हाल ही में आरंभ की गई 'पाक्षिक समाचार डाइजेस्ट' लोगों और समाज की बुनियादी परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो नीति निर्माताओं और प्रशासकों को राष्ट्रीय महत्व के अनेक मसलों पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने और क्रियान्वयन पर उपयोगी जानकारी प्रदान करती है।

सूचना प्रदायक केन्द्र

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने और एकदम दूर-दराज के ग्रामीण वासी को सरकार के बारे में सूचना हासिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां सूचना प्रदायक केन्द्रों के तौर पर भी कार्य करने लगी हैं। सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी मनोनीत कर दिया गया है जिससे वे निदेशालय की ओर से आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

मल्टीमीडिया अभियान

राष्ट्रीय महत्व के मसलों को व्यापक पैमाने पर अन्य मीडिया इकाइयों के साथ मल्टी मीडिया अभियानों के द्वारा प्रचारित करना निदेशालय का एक अन्य प्रमुख कार्य है। ऐसे कार्यक्रम के पीछे अवधारणा यह है कि सभी सरकारी मीडिया इकाइयों के एक मंच पर आकर किसी विषय पर गहन अभियान लक्षित जन समुदाय पर दीर्घगामी प्रभाव डालता है। निदेशालय ने नवम्बर 2005 के दौरान मल्टी मीडिया अभियान पर एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय वर्कशाप आयोजित की जिनमें अन्य मीडिया संगठनों के प्रमुखों और उनके कुछ क्षेत्रीय प्रमुखों ने भाग लिया जिससे देश के विभिन्न भागों में मल्टी मीडिया अभियानों को आयोजित करने के लिए योजना तैयार की जा सकें। इस वर्ष प्रत्येक क्षेत्र से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर ऐसे दो कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा है।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/दिवसों/सप्ताहों और विषयों को मनाना

क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों द्वारा क्षेत्रीय प्रमुखों के मार्गदर्शन में निम्नलिखित उपयुक्त प्रचार कार्यक्रम आयोजित किये गए : 1-7 अप्रैल तक नेत्रहीनता निवारण सप्ताह, 7 अप्रैल 2005 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल 2005 को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 मई 2005 को राष्ट्रीय श्रम दिवस, 8 मई 2005 को विश्व रेडक्रास दिवस, 11 मई 2005 को टेक्नालोजी दिवस, 21 मई 2005 को आतंकवाद विरोध दिवस, 31 मई 2005 को विश्व तम्बाकू रहित दिवस, 5 जून 2005 को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई, 2005 को विश्व जनसंख्या दिवस, 1 से 7 अगस्त 2005 तक विश्व स्तनपान सप्ताह, 15 अगस्त 2005 को स्वतंत्रता दिवस और 19 अगस्त से 5 सितंबर 2005 तक सद्भावना दिवस और साम्प्रदायिक

सदभाव पखवाड़ा, 1 से 7 सितम्बर 2005 तक राष्ट्रीय आहार सप्ताह, 5 सितम्बर 2005 को शिक्षक दिवस, 8 सितम्बर 2005 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 से 28 सितम्बर 2005 तक हिन्दी पखवाड़ा, 27 सितम्बर 2005 को विश्व पर्यटन दिवस, 1 अक्टूबर 2005 को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 से 8 अक्टूबर 2005 तक महात्मा गांधी जन्म दिवस और अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह, 11 से 25 अक्टूबर 2005 तक परिवार कल्याण पखवाड़ा, 21 अक्टूबर 2005 को विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस, 9 से 14 नवम्बर तक अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह, 14 नवम्बर 2005 को बाल दिवस, 19 से 25 नवम्बर 2005 को कौमी एकता सप्ताह, 19 नवम्बर 2005 को राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 नवम्बर 2005 को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, 20 नवम्बर 2005 को बाल अधिकार दिवस, 21 नवम्बर 2005 को भाषा सद्भाव दिवस, 22 नवम्बर 2005 को कमजोर वर्ग दिवस, 23 नवम्बर 2005 को सांस्कृतिक एकता दिवस, 24 नवम्बर 2005 को महिला दिवस, 25 नवम्बर 2005 को संरक्षण दिवस, 1 दिसम्बर 2005 को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसम्बर 2005 को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 8 दिसम्बर 2005 को बालिका दिवस, 10 दिसम्बर 2005 को मानवाधिकार दिवस, 14 दिसम्बर 2005 को राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण दिवस।

जनवरी से मार्च 2006 के महीनों के दौरान निदेशालय 5 से 11 जनवरी 2006 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह, 12 जनवरी 2006 को राष्ट्रीय युवा दिवस, 26 जनवरी 2006 को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी 2006 को कुष्ठ-निवारण दिवस, 1 फरवरी से 14 फरवरी 2006, तेल संरक्षण पखवाड़ा, 28 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 1 से 7 मार्च 2006 तक अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह, 8 मार्च 2006 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च 2006 को उपभोक्ता अधिकार दिवस आयोजित करेगा।

मेले और उत्सव

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित अनेक मेलों और उत्सवों में भाग लिया। कुछ महत्वपूर्ण मेले और उत्सव इस प्रकार हैं :

1. आंध्र प्रदेश में आयोजित गोदावरी नदी का कुम्भ मेला।
2. आंध्र प्रदेश में कृष्णा पुष्काम (कृष्णा नदी का कुम्भ मेला)।
3. पुरी में आयोजित लोक मेला।

4. परफेक्ट हेल्थ मेला, शिवाजी प्लेस, राजा गार्डन नई दिल्ली (21-30 अक्टूबर 2005)।
5. श्रावण मास महोत्सव मेला, खुर्जा, उत्तर प्रदेश।
6. हेल्थ मेला रायबरेली (31 मार्च 2005-3 अप्रैल 2005)।
7. पुरी, बारीपदा तथा कोरापुट में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव।
8. दिल्ली हाट और दिल्ली पर्यटन एवं यातायात विकास निगम लि. के साथ दिल्ली हाट में तिरंगा उत्सव।
9. भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला-नई दिल्ली।
10. भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2005-गोवा।

वर्ष के दौरान निदेशालय की सतर्कता गतिविधियां

निदेशालय रोजमर्रा के कार्यकलापों में अनुशासनहीनता और अनियमितताओं को रोकने के लिए सतर्कता गतिविधियों पर सर्वाधिक ध्यान देता है। निदेशालय स्तर पर सतर्कता कार्यवाहियों के लिए महानिदेशक समर्थ अधिकारी है और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र निदेशक। कार्यप्रणाली को मुस्तैद बनाने के लिए समय समय पर निवारक, निगरानी और गुप्तचरी की जाती है। वर्ष के दौरान अनियमितताओं पर नौ शिकायतों की जांच की गई और आरंभिक जांच पड़ताल आयोजित की गई। पांच में पी ई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पूर्व की तरह क्षेत्रनि मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों ने नवम्बर 2005 माह के दौरान सतर्कता दिवस मनाया। इस सप्ताह के दौरान देश के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भ्रष्टाचार और मुक्त समाज की आवश्यकता पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में हिन्दी का प्रयोग

क्षे०प्र०नि० ने राजभाषा विभाग द्वारा जैसा राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा (संघ के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग) नियम 1976 में संघ के राजकीय कार्यों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अनुदेश जारी किए हैं और उन्हें लागू करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए गए।

हिन्दी दिवस/पखवाड़ा मनाया

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से और कर्मचारियों में राजभाषा नीति के बारे में जानकारी बढ़ाने तथा हिन्दी के सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए अनेक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के मद्देनजर 14-28 सितम्बर 2005 को 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया। पखवाड़े के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी टंकण, हिन्दी वक्तृता, हिंदी अंताक्षरी आदि क्षेत्रनि मुख्यालय में आयोजित किए गए। क्षेत्रनि के क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस पखवाड़े के दौरान 73 फिल्म प्रदर्शन, 95 मौखिक वार्ताएं, 15 निबन्ध प्रतियोगिताएं, 9 संगोष्ठी, 3 जनसभाएं, 10 सुलेखन प्रतियोगिताएं, 3 पठन प्रतियोगिताएं, 12 वक्तृताएं, 4 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, 2 परिचर्चाएं, 1 परिसंवाद, 1 टंकण प्रतियोगिता, 1 नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, 3 कवि सम्मेलन, 1 हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता और 11 अन्य विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

गीत और नाटक प्रभाग

गीत और नाटक प्रभाग का गठन सन् 1954 में आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में हुआ था। वर्ष 1956 में इसे स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दिया गया क्योंकि यह लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क का बेहतर माध्यम था। यह देश का ऐसा सबसे बड़ा संगठन था जो विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क के जरिए कला का निष्पादन करता है। गीत और नाटक प्रभाग कला के विभिन्न रूपों ड्रामा, बैले, ओपेरा, नृत्य-नाटक, लोक और पारंपरिक शैली के गीतों और कठपुतली के माध्यम से प्रदर्शनी करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग राष्ट्रीय हित के अनेक विषयों जैसे-सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि विषयों पर थियेटर के शो भी आयोजित करता है। यह विभाग ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

संगठनात्मक स्वरूप

इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त इसके निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालय हैं :

1. **बारह क्षेत्रीय कार्यालय** : बंगलौर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, रायपुर और रांची में स्थित है।
2. **सात सीमावर्ती केंद्र** : इम्फाल, जम्मू, शिमला, नैनीताल,

दरभंगा, जोधपुर और गुवाहाटी में हैं।

3. **छह नाटक मंडली** : भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर।
4. सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई की नौ मंडलियां (टूप) दिल्ली और चेन्नई में हैं।
5. इलाहाबाद, बंगलौर और दिल्ली में तीन ध्वनि व श्रव्य इकाईयाँ।
6. रांची में जनजातीय पायलट योजना।

वर्ष 2005-2006 वित्त वर्ष में (दिसंबर 2005 तक) गीत और नाटक प्रभाग ने लगभग 515 विभागीय स्टाफ आर्टिस्टों (कलाकारों), करीब 700 पंजीकृत मंडलियों और लगभग 800 सूचीबद्ध कलाकारों की मदद से 32,000 कार्यक्रम आयोजित किए।

सन् 2005 में जनवरी से मार्च तक की अवधि में इस इकाई में क्षेत्रीय इकाइयों के जरिए 7100 कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें एड्स से बचाव के लिए विशेष अभियान आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम शामिल थे।

समर यात्रा शीर्षक से ध्वनि और प्रकाश के 21 प्रदर्शन पुणे, सूरत और राजकोट में दिखाए गए। गणतंत्र दिवस समारोहों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती राष्ट्रीय युवक दिवस, दांडी मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस और होली पर्व का व्यापक प्रसार किया गया। सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई ने दिल्ली में एक विशेष समारोह का आयोजन किया इसमें श्रीमती सोनिया गांधी मुख्य अतिथि थीं। कार्यक्रम में अधिकतर केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए।

सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई

यह प्रभाग दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले सैन्य बलों की मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। सशस्त्र सेना मनोरंजन इकाई सभी राज्यों के लोकनृत्यों को उनके वास्तविक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। इस इकाई ने विभिन्न राज्यों के लोकनृत्यों के प्रस्तुतिकरण में रंगों और वस्त्रों का बेहतर संयोजन किया है जिससे देश के सांस्कृतिक समन्वय की झलक मिलती है। दिसम्बर 2005 तक इस इकाई ने लेह, लद्दाख, जुमतेंग, थोयास, परतापुर,

(PARATAPUR) मोकोकचुंग, लुंग तलाई, आलोन समधु (पंग) पोर्टब्लेयर और अन्य द्वीपों में 167 कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

जनजातीय प्रचार-प्रसार

वर्ष 1980 में रांची जनजातीय केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विकास प्रक्रिया में जनजातीय कलाकारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की मंडलियों ने 688 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों के जरिए वर्ष 2005-2006 में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई विकास योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई।

सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रचार-प्रसार मंडलियां (टूप)

ये मंडलियां सूदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी मुहैया कराती हैं। इसके अलावा यह सीमा पार से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को दूर करने का काम भी करती है। यह विभागीय (टूप) मंडलियां इम्फाल, गुवाहाटी, दरभंगा, नैनीताल, शिमला, जम्मू और जोधपुर में काम कर रही हैं। ये कार्यक्रम एस एस बी, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल करके आयोजित किए जाते हैं। इन मंडलियों ने 669 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

विभागीय नाट्य मंडलियां

इस वित्तीय वर्ष में अब तक पुणे, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर और दिल्ली में 290 नाटक-शो प्रस्तुत किए गए। ये नाटक परिवार कल्याण एड्स, नशाखोरी से बचाव, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और पर्यावरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर आधारित थे। ये नाटक मंडलियां स्थानीय मेला और पर्व-त्यौहारों के अवसर पर ऐसी जगह नाटकों का मंचन करती हैं जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हों ताकि जनमानस तक वास्तविक संदेश पहुंच सके।

कार्यप्रणाली योजना

पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी संवेदनशील व सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियां व प्रभाव का मूल्यांकन तथा गीत व नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण।

वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रभाग के लिए अनुमोदित (स्वीकृत) योजना :

1. पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील व सीमावर्ती क्षेत्रों में

सूचना, संचार व तकनीक से संबद्ध 4000 कार्यक्रमों का आयोजन।

2. पहचान किए गए 56 क्षेत्रों में गतिविधियों का संचालन।
3. बारह प्रादेशिक केंद्रों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार।
4. जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशिष्ट गतिविधियां (कार्यक्रम)।
5. राष्ट्रीय/सामाजिक विषयों पर नाटकों का मंचन।
6. गीत व नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण।

पर्वतीय/जनजातीय, रेगिस्तानी/संवेदनशील व सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियां (कार्यक्रमों का आयोजन)।

यह प्रभाग जनजातीय, पर्वतीय और रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों के समस्त ऐसे कार्यक्रमों का मंचन करता है जिससे उनमें जागरूकता उत्पन्न हो। अलग-थलग पड़े रेगिस्तानी व पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोग यह जान सकें कि उनके कल्याण के लिए किस तरह की विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों में इस देशका वासी होने की भावना जाग्रत करना और विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए क्षेत्रीय जनसमुदाय में से ही प्रदर्शन मंडली तैयार की जाती है वहीं की भाषा, मुहावरों से शैली के अनुरूप कार्यक्रमों का निष्पादन होता है। इस योजना के तहत दिसंबर 2005 तक 4323 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पहचान किए गए 56 क्षेत्रों में गतिविधियां

वर्ष 2005-2006 में इस प्रभाग ने संपूर्ण भारत में पहचान किए गए 56 क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, आतंकवाद विरोधी व देशभक्ति के भावों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम प्रदर्शित किए। दिसंबर 2005 तक 558 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रसार

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रसार की योजना के तहत इस प्रभाग को वर्ष 2005-2006 की अवधि में 9400 कार्यक्रमों का मंचन करना है। दिसंबर 2005 तक 4262 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका था। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों की जानकारी मुहैया कराई गई थी।

जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रम

योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2005-06

के दौरान गीत और नाटक प्रभाग को पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर व अन्य पहचान किए गए क्षेत्रों में 30,000 कार्यक्रमों का मंचन करना है।

राष्ट्रीय हित के विषयों पर नाटकों का प्रस्तुतिकरण

आम जनता को राष्ट्रीय हित के मुद्दों के प्रति जागरूक करने व युवा वर्ग को देश की समृद्ध सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत की जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रभाग की ध्वनि व प्रकाश इकाई देश के विभिन्न भागों में ध्वनि व प्रकाश शो आयोजित करती है। प्रभाग ने सूरत और पटियाला में **समर यात्रा**, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में **कविता में कृष्णा** व रायबरेली में **'शतरूपा'** शीर्षक से कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बंगलौर इकाई ने चिकमगलूर में **कर्नाटक वैभव** कर्नाटक में हम्पी के **विजय वैभव** तथा मालापुरम में **स्वातंत्रियम थाने जीवितम** Swatantriyam Thanne Jeevitham प्रस्तुत किए। दिसंबर 2005 तक प्रभाग ने 49 कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण

प्रभाग ने दिसंबर 2005 तक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर लगभग 1000 कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। प्रभाग की क्षेत्रीय इकाइयों ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में विश्व जनसंख्या दिवस सहित अन्य स्वास्थ्य मेलों में विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया। नई दिल्ली में आयोजित किए गए परफेक्ट स्वास्थ्य मेले में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस वर्ष नवंबर में प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर आयोजित प्रचार कार्यक्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। प्लस पोलियो टीकाकरण पर 4563, कन्या भ्रूण और बालिकाओं पर 116, कुष्ठ निवारक पर 141 और आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग पर दिसंबर 2005 तक 315 कार्यक्रमों का मंचन किया गया।

एड्स पर रोक व बचाव पर विशेष अभियान

सभी क्षेत्रीय इकाइयों ने एड्स से बचाव पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों से पहले महिलाओं और बालकों की देखभाल, बालिकाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों, एच.आई.वी. और एड्स पर जानकारी उपलब्ध कराई गई। बंगलौर इकाई ने कर्नाटक राज्य एड्स निवारण समिति के साथ मिलकर 409 कार्यक्रमों का आयोजन किया। देश भर में चुने हुए क्षेत्रों में 1607 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मेले व पर्व

गीत व नाटक प्रभाग ने विशिष्ट दिनों के अलावा क्षेत्रीय मेलों और

त्यौहारों में भी भाग लिया। इसके जरिए जनहित व राष्ट्रहित से जुड़े विषयों की जानकारी उपलब्ध कराई गई।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कल्याण कार्यक्रम

तमिलनाडु में यूनीसेफ के सहयोग से गीत और नाटक प्रभाग ने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल के बारे में विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया। नागपट्टनम, कुडलूर और कन्याकुमारी जिलों में 300 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

अन्य प्रमुख गतिविधियां

विभाग ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में देश भर में प्रचार किया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए गए। वर्ष के दौरान प्रभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवाद निरोधक कार्यक्रम चलाए। दांडी मार्च, अंबेडकर जयंती, पुरी रथ यात्रा महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, स्वाधीनता दिवस, सद्भावना दिवस, गांधी जयंती पर जम्मू-कश्मीर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया। कौमी एकता सप्ताह, बाल-दिवस, सभी प्रमुख गतिविधियों और क्षेत्रीय मेलों, त्यौहारों और वर्षगांठ समारोहों का व्यापक प्रसार किया गया। श्रावणी तीज मेले के उपलक्ष्य में जम्मू-कश्मीर के डोडा और राजौरी जिलों में 38 कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, राज्य सभा दांडी-मार्च की हीरक जयंती, बाल विवाह अभियान पर संवाददाता सम्मेलन, बाबू जगजीवन राम की जयंती, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राज्य सचिवों की अखिल भारतीय बैठक, महिलाओं की सत्ता में भागीदारी पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा दिल्ली में फूलवालों की सैर और 52वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (प.सू.का.) सरकार की नीतियों कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों को उपलब्ध कराने वाली नोडल एजेंसी है। प्रचार माध्यमों और सरकार के बीच माध्यम की भूमिका निभाने के अलावा ब्यूरो पत्र-पत्रिकाओं में व्यक्त जनता की राय से सरकार को अवगत कराती है। ब्यूरो के 8 क्षेत्रीय कार्यालय और 35 शाखा कार्यालय हैं। ब्यूरो प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, संवाददाता सम्मेलन, फोटोग्राफ, साक्षात्कार, ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस, प्रेस यात्राओं आदि के जरिए सूचना का प्रसार करता है। अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में जारी सूचना सामग्री

लगभग 2400 समाचारपत्रों और संगठनों तक पहुंचाई जाती है। नई दिल्ली स्थित ब्यूरो के मुख्यालय में विभागीय प्रचार अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबद्ध किया गया है। इनका कार्य प्रेस रिलीज और प्रेस सम्मेलनों आदि के द्वारा संबंधित मंत्रालय या विभाग को सूचना प्रसारण में सहायता प्रदान करना और प्रचार कार्यों से संबंधित सभी मामलों में सलाह देना है। विभागीय प्रचार अधिकारी सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में व्यक्त जानकारी फीड बैक के रूप में अपने मंत्रालयों और विभागों को उपलब्ध कराते हैं। विशेष सेवाओं के रूप में, ब्यूरो का फीड बैक सेल राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के समाचार सम्पादकीयों के आधार पर डेली डाइजेस्ट तथा विशेष सेवा की फीचर यूनिट संदर्भ सामग्री, अद्यतन सामग्री, विशेष लेख और

रेखाचित्र (ग्राफिक्स) उपलब्ध कराता है। इन्हें राष्ट्रीय नेटवर्क पर परिचालित किया जाता है और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों को भेजा जाता है ताकि अनुवाद के बाद इन्हें स्थानीय प्रेस को जारी किया जा सके।

जहां तक ई-क्लिपिंग परियोजना का सम्बन्ध है, दिसम्बर 2005 तक सम्पदा प्रबंध कार्यक्रम 'क्यूमुलस' के तहत 2,45,100 प्रेस कतरनों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

ब्यूरो की फीचर इकाई संदर्भ सामग्री, अद्यतन सामग्री, सूचना सामग्री (इन्फो नॉगेट), विशेष लेख और रेखाचित्र (ग्राफिक्स) उपलब्ध कराती है। इन्हें राष्ट्रीय नेटवर्क और इंटरनेट पर परिचालित किया जाता है तथा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय को अनुवाद कर स्थानीय प्रेस को जारी करने के लिए भेजा जाता है।

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आर्थिक संपादकों का सम्मेलन
ECONOMIC EDITORS' CONFERENCE

16-18 नवम्बर, 2005

8 November, 2005



पत्र सूचना कार्यालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए
केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, 16 नवम्बर, 2005

पत्र सूचना कार्यालय ने वर्ष भर विभिन्न सरकारी समारोहों के फोटो कवरेज की व्यवस्था की और दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को फोटोग्राफ उपलब्ध कराए। अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2005 के दौरान ब्यूरो की फोटो प्रचार इकाई ने 1094 कार्यक्रम कवर किए और 1265 फोटोग्राफ जारी किए। फोटो इकाई ने इस वर्ष फोटो प्रभाग के सहयोग से फोटो लायब्रेरी (अभिलेखागर) के डिजिटलीकरण का कार्य शुरू किया है। लायब्रेरी में कैप्शनयुक्त लगभग 8 लाख फोटोग्राफ हैं। अभी तक लगभग एक लाख फोटो डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं। इस अवधि के दौरान ब्यूरो ने 77613 प्रेस रिलीज और 4568 विशेष लेख जारी किए तथा 1289 प्रेस सम्मेलन आयोजित किए। ब्यूरो ने हाल ही में गोवा में आयोजित भारत के 36वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का शानदार प्रचार किया। ब्यूरो ने हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मीडिया की व्यवस्था भी की।

पत्र सूचना कार्यालय अपने मुख्यालय से मीडिया के प्रतिनिधियों को प्रत्यापन सुविधा प्रदान करता है, इसमें विदेशी मीडिया भी शामिल है। इससे मीडिया को सरकारी स्रोतों से सूचना मिलने में आसानी होती है। विदेशी पत्रकारों को अस्थायी प्रत्यापन प्रदान करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था शुरू की गई है। मुख्यालय में 1146 संवाददाताओं और 309 कैमरामैनों को प्रत्यापन प्रदान किया गया है। इसके अलावा 171 तकनीशियनों और 65 सम्पादकों तथा मीडिया समालोचकों को भी प्रत्यापन दिया गया है। स्थायी प्रत्यापन के अलावा, ब्यूरो थोड़े समय के लिए भारत आने वाले विदेशी पत्रकारों को हर वर्ष 500 अस्थायी प्रत्यापन भी प्रदान करता है। पत्र सूचना कार्यालय ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2005 के दौरान गोवा में सर्वसुविधायुक्त मीडिया केन्द्र स्थापित किया था। इस समारोह के कवरेज के लिए मीडिया को प्रत्यापन के फार्म ऑन-लाइन उपलब्ध कराए गए। समारोह में शामिल फिल्मों के स्टिल फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप्स पहली बार ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड की गईं और इन्हें सीडी के रूप में मीडिया के प्रत्यापन प्राप्त लोगों में वितरित किया गया। 25 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित मध्य एशियाई देशों के तेल मंत्रियों के गोलमेज सम्मेलन के लिए एक मीडिया केन्द्र स्थापित किया गया। इस सम्मेलन में नौ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ब्यूरो की फीचर इकाई हर वर्ष लगभग 250 विशेष लेख तैयार करती है इसमें फोटोयुक्त विशेष लेख और संदर्भ सामग्री भी शामिल है। सारे देश में ब्यूरो के विशेष लेखों के पाठकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन पाठकों में सभी भाषाओं के लोग शामिल हैं। ये विशेष लेख ब्यूरो की वेबसाइट www.pib.nic.in पर उपलब्ध है।

पत्र सूचना कार्यालय के होम पेज www.pib.nic.in पर प्रचार सामग्री हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध कराई गई है। ब्यूरो की वेबसाइट की दिनोंदिन बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ तथा ई-मेल के जरिए रिलीजों की मांग भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पत्र सूचना कार्यालय की ई-मेला सेवा के ग्राहकों की संख्या अब लगभग 8000 हो गई है, ये लोग अपनी पसंद की रिलीजें ई-मेल के द्वारा प्राप्त करते हैं। ब्यूरो की वेबसाइट (<http://pib.nic.in>) को फिर से डिजाइन किया है ताकि यह डायनामिक मोड पर काम कर सके। पहली दिसम्बर 2003 से सभी नई सामग्री डायनामिकली सर्चबल मोड पर डाल दी गई है। ब्यूरो का इंटरनेट पोर्टल इंटर पी आई बी, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान और निगरानी का एक सक्षम उपकरण है। सभी क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों को (<http://pib.nic.in>) साइट पर यूजर एकाउन्ट दिए गए हैं।

26 दिसम्बर 2004 को सुनामी आपदा के बाद से राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए व्यापक प्रचार व्यवस्था ब्यूरो की प्रमुख उपलब्धि रही। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में दो मीडिया केन्द्र खोले गए। इनमें से एक तमिलनाडु के नागपट्टिनम में था, जिसने 31.12.04 से काम करना शुरू कर दिया और दूसरा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में था, जिसने 09-01-05 से काम करना शुरू कर दिया। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के दौरे के समय कई प्रतिनिधि मण्डलों ने उनसे मुलाकात की। इन मुलाकातों की कई प्रेस रिलीजें और फोटो कवरेज जारी की गईं। प्रधानमंत्री कोलकाता में भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक में भी शामिल हुए थे। ब्यूरो ने इस अवसर की भी व्यापक कवरेज की व्यवस्था की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन समारोह के व्यापक प्रचार के लिए मीडिया प्रबंध का कार्य ब्यूरो द्वारा सफलतापूर्वक निभाया गया। अभिभाषण का पूरा मूलपाठ, मुख्य अंश और उल्लेखनीय वाक्य मीडिया को जारी किए गए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन पहली बार पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर सीधा वेबकास्ट किया गया।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर ब्यूरो ने सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और पहल पर “टेकिंग इंडिया अहेड” नामक संकलन प्रकाशित किया और इसे पूरे देश में मीडिया को जारी किया। ब्यूरो ने “ए केयरिंग गवर्नमेंट-वन ईयर ऑफ द यू पी ए गवर्नमेंट” शीर्षक से एक पुस्तिका

प्रकाशित की और इसे मीडिया के लोगों में वितरित किया।

16-18 दिसम्बर 2005 तक नई दिल्ली में आर्थिक सम्पादकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 300 स्थानीय तथा बाहर के 85 वित्तीय/आर्थिक सम्पादकों ने भाग लिया। सम्मेलन में वित्त, सूचना और प्रसारण, वस्त्र, नौवहन, सड़क परिवहन व राजमार्ग, वाणिज्य तथा उद्योग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, नागर विमानन, कम्पनी कार्य, इस्पात, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालयों के मंत्रियों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भाग लिया। सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए विषयों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रव्यापी प्रचार किया गया। इस अवसर पर सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में वित्तीय लेखकों और सम्पादकों से फीडबैक भी प्राप्त किया गया।

ब्यूरो ने 9 तथा 10 नवम्बर 2005 को पहली बार गुवाहाटी में सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर सम्पादकों का सम्मेलन-2005 आयोजित किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र सम्मेलन का केन्द्र बिन्दु था। 16 राज्यों के 60 से ज्यादा पत्रकारों 5 मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। गुवाहाटी और शिलांग के आसमास केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर पत्रकारों के दौरे भी आयोजित किए गए।

ब्यूरो के मुम्बई कोलकाता, चण्डीगढ़, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी, रायपुर और पोर्ट ब्लेयर स्थित क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रमों में उल्लिखित विकासात्मक कार्यक्रमों विशेषकर कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा महिला तथा बाल विकास, एड्स जागरूकता, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव और बालिकाओं पर कार्यक्रमों के लिए कई मल्टी मीडिया अभियान चलाए।

पत्र सूचना कार्यालय, चेन्नई ने मदुरै में 14 से 19 नवम्बर, 2005 तक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर मल्टी मीडिया अभियान का आयोजन किया। वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने इस अभियान का उद्घाटन किया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कम्पनियों के 25 प्रतिनिधि संगठनों, केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के विभागों, गैर सरकारी संगठनों, महिला स्व-सहायता समूहों ने अभियान में भाग लिया। अभियान में कृषि ऋण, स्व-रोजगार के लिए ऋण और शिक्षा ऋण, स्वरोजगार तथा कौशल विकास की सुविधा जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई और स्वरोजगार के उपलब्ध अवसरों पर विशेष जोर दिया गया। इन कार्यों के लिए लगभग 440 लोगों को 5 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया।

ब्यूरो ने प्रधानमंत्री की हुरियत नेताओं से बातचीत, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक, पुलिस अधीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन, भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वर्ण जयन्ती समारोह को संबोधन के लिए मल्टी-मीडिया कवरेज की व्यवस्था की।

ब्यूरो ने नई दिल्ली में 19 तथा 20 मई को आयोजित जिलाधीशों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री के संबोधन के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया प्रचार की व्यवस्था की। बैठक में इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि जिला स्तर पर प्रशासन को उत्तरदायी तथा सक्षम बनाने के लिए डिलीवरी प्रणाली में किस प्रकार सुधार किया जाए। कृषि विज्ञान केन्द्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन और समाचार के साथ बातचीत के लिए उल्फा द्वारा नामित पीपुल्स कन्सल्टेटिव ग्रुप के साथ बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन के व्यापक मल्टी-मीडिया कवरेज की व्यवस्था की।

पश्चिम आस्ट्रेलिया के प्रीमियर डा० ज्याफ गैलय, रोमानिया के आर्थिक तथा वाणिज्य मंत्री, बर्सिलोना के मेयर लारेंस जान ब्रिंकहार्स्ट, नीदरलैंड के उपप्रधानमंत्री तथा आर्थिक मामलों के मंत्री फ्रांस के रोहन आल्प्स रीजन के प्रेसीडेन्ट ज्या जैक क्वैरें की भारत यात्रा के दौरान सरकार द्वारा लिए गए व्यापार संबंधी फैसलों के लिए ब्यूरो ने मल्टी मीडिया प्रचार की व्यवस्था की।

ब्यूरो ने ज्यूरिख में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) देशों के मंत्रियों की बैठक में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल की शिरकत, दिसम्बर, 2005 में डब्ल्यूटीओ की हांगकांग बैठक और जिनेवा में जी-33 देशों की बैठक के लिए मल्टी-मीडिया प्रचार की व्यवस्था की। जिनेवा बैठक में कई सदस्य देशों ने डब्ल्यूटीओ में जी-33 को सक्षम दल बनाने में भारत का भूमिका की सराहना की थी।

मंत्रिमंडल/मंत्रिमण्डल समिति की बैठकों में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष प्रेस सम्मेलन आयोजित किए गए और इसके बारे में प्रेस रिलीजें ब्यूरो की वेबसाइट पर डाली गईं। भारत और पाकिस्तान द्वारा कैदियों की रिहाई पर कई संवाददाताओं के साथ आमने-सामने की बातचीत की व्यवस्था भी की गई। प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा पर संसद के दोनों सदनों में हुई बहस के दौरान उनके द्वारा दिए गए जवाब, नानावती आयोग की रिपोर्ट पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में बहस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, संसद में महिलाओं के आरक्षण के बारे में तीन बैठकों और ज्ञान आयोग की दो बैठकों के लिए व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई।

आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की नौवीं बैठक पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक, गुजरात, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य, मणिपुर में आर्थिक नाकेबन्दों को समाप्त करने के प्रयास, 1984 के दंगों पर नानावती आयोग की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर भारत और पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश, भारत और म्यांमार के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता, पुलिस अधीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन, जम्मू-कश्मीर में बंदियों की रिहाई और हुरियत प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद सुरक्षा बलों द्वारा मानव अधिकारों की समीक्षा और अनुपालन, पाकिस्तानी असैन्य कैदियों की रिहाई, प्रवासी भारतीयों को भारत की नागरिकता स्कीम की संभावनाएं तथा आपदा प्रबंधन एवं साम्प्रदायिक सद्भाव विधेयक बनाने और पेश करने, इन सभी के लिए ब्यूरो ने प्रचार की व्यवस्था की।

प्रधानमंत्री द्वारा श्रीनगर में श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस को झंडी दिखाकर रवाना करना एक बड़ी मीडिया घटना थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों के 400 से ज्यादा पत्रकार शामिल हुए। ब्यूरो ने राज्य सरकार, विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार प्रभाग और सुरक्षा बलों के सहयोग से श्रीनगर इस्लामाबाद, और नियंत्रण रेखा पर कमान सेतु, इन तीन महत्वपूर्ण स्थलों पर सीधे कवरेज तथा मीडिया प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी, ले. कर्नल वी.के. बत्रा, सेवा पदक, की मीडिया के साथ परस्पर चर्चा व्यवस्था की जनरल आफिसर कमांडिंग ले. जनरल निर्भय सिंह ने सराहना की।

ब्यूरो ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के मीडिया कवरेज के लिए विशेष इंतजाम किए। इन यात्राओं में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए उनकी न्यूयार्क यात्रा, फ्रांस यात्रा, काबुल यात्रा, ब्रिटेन यात्रा ढाका में सार्क शिखर बैठक, मास्को यात्रा, कुआलालंपुर में आसियान शिखर बैठक शामिल हैं। 11-17 सितम्बर 2005 के दौरान प्रधानमंत्री की फ्रांस तथा अमरीका यात्रा जाने माने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बहु-प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार को व्यापक कवरेज दिया गया। पेरिस में राष्ट्रपति जेक्स शिराक के साथ मुलाकात के बाद उनका विदाई वक्तव्य और भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्य, न्यूयार्क में संयुक्त वक्तव्य तथा ग्लेनईगल्स में जी-8 शिखर बैठक में शामिल होने के लिए उनकी ब्रिटेन यात्रा का व्यापक प्रचार किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री के संबोधन का वेब पर सीधे प्रसारण किया गया और उनके अभिभाषण को तत्काल पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर रखा गया।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के दो-दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन और समापन समारोह में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के वक्तव्य, महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का दौरा, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण व्यवधान की वजह से इधर-उधर फंसे रेल तथा वायुयान यात्रियों को राहत और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और बाढ़ प्रभावित महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में बीमा दावों के तुरंत निपटाने, राज्य के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के दौरे और राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान की अपील को प्रचारित किया गया, जम्मू-कश्मीर में भूकम्प आने पर सरकार द्वारा राहत और बचाव अभियान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री द्वारा नारायण मेघाजी लोखण्डे पर स्मारक डाक टिकट जारी करने, विश्व संचार दिवस-2005 पर स्मारक सिक्कों के दो सेट जारी करने और गृहमंत्री द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण के शुभारंभ के व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच गृह सचिव स्तर की बातचीत के लिए भी व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई। ब्यूरो ने 8 अप्रैल, 2005 को विदेश व्यापार नीति 2004-09 के वार्षिक अनुपूरक की घोषणा को व्यापक रूप से प्रचारित किया। इस अनुपूरक में व्यापार संबंधी नए कदमों का खुलासा किया गया है और निर्यात पर जोर दिया गया है। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष आर्थिक जोन विधेयक को पारित किए जाने, 2 अरब अमरीकी डालर के सीधे विदेशी निवेश की संभावना, रोजगार के अवसरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि अप्रैल, 2005 के दौरान निर्यात के 6.5 अरब अमरीकी डालर के आंकड़े को पार कर जाने, पेरिस में डब्ल्यूटीओ के लघु मंत्रिस्तरीय बैठक में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की शिरकत, सिडनी में भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद का उद्घाटन, सिंगापुर और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सी.ई.सी.ए.) पर हस्ताक्षर, मंत्री द्वारा व्यापार बोर्ड की बैठक के उद्घाटन की जानकारी दी गई है। एस पी एस विनियमों के बारे में पूछताछ से निपटने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा स्वच्छता तथा पादप-स्वच्छता (एस पी एस) उपायों पर तीन पूछताछ बिन्दुओं को अंतिम रूप दिए जाने का व्यापक रूप से प्रचार किया गया और इन्हें समाचार पत्र-पत्रिकाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रमुखता से प्रचारित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए।

पंचायतों को कार्यों, कोष और कार्यकर्ताओं से अधिकार संपन्न बनाने के लिए उठाए गए कदमों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया। स्थानीय संसाधनों की बिक्री और मूल्य संवर्धन के लिए ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की अवधारणा की ओर मीडिया का ध्यान आकर्षित

प्रचार कार्य की प्रमुख बातें

बहुप्रचार माध्यमों से प्रचार (मल्टीमीडिया पब्लिसिटी)

- सं.प्र.ग. सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का संकलन।
- दिसम्बर 2005 में हांगकांग में आयोजित **डबल्यू टी ओ** सम्मेलन।
- ज्यूरिख में डबल्यू टी ओ मंत्रियों की बैठक।
- साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर मल्टीमीडिया अभियान।
- बिहार में विधानसभा चुनाव।
- उद्योग तथा आर्थिक सहयोग पर भारत-जर्मनी संयुक्त आयोग की बैठक।
- हरियत नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत।
- भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2005।
- पेट्रोलियम मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के समय 20 संवाददाताओं का एक दल पाकिस्तान भेजा गया।

व्यापक मीडिया कवरेज निम्नांकित को प्रदान किया गया

- सं.प्र.ग. सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष के समापन पर सरकार द्वारा लागू नीतियां, कार्यक्रम और पहल।
- प्रधानमंत्री द्वारा श्रीनगर से श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस को झण्डी दिखाकर रवाना करना।
- मूल्यवर्धित कर (वैट), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ब्याज दर का कार्यन्वयन और ऋण वितरण।
- विश्व संचार दिवस-2005 के अवसर पर नारायण मेघाजी लोखण्डे पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष आर्थिक जोन विधेयक को पारित करना।
- सिंगापुर और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सी ई सी ए) पर हस्ताक्षर।
- कई सेवाओं को सेवाकर से छूट, सेवा कर आधार का विस्तार और कर भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाना।
- सं.प्र.ग. सरकार के तहत अंतरराज्यीय परिषद की पहली बैठक।
- महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का दौरा।
- ग्लेनईगल्स में जी-8 की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा।
- डालियां, चीन में विश्व व्यापार संगठन का लघु-मंत्रिस्तरीय सम्मेलन।
- दिल्ली-कालका खण्ड पर परीक्षण के तौर पर ई-टिकटिंग की शुरुआत।
- आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर भारत और पाकिस्तान के बीच गृहसचिव स्तर की वार्ता।
- प्रधानमंत्री की फ्रांस और अमरीका यात्रा।
- भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक और भारत-ब्रिटेन शिखर बैठक के समापन पर भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस सम्मेलन।
- राष्ट्रमण्डल देशों के वित्तमंत्रियों के सम्मेलन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक की बैठकों में वित्तमंत्री के अभिभाषण।
- जम्मू-कश्मीर में भूकम्प से हुई तबाही के समय सरकार द्वारा राहत तथा बचाव कार्यों के लिए उठाए गए कदम।
- राजीव गांधी अक्षम ऊर्जा दिवस।
- हाइड्रो-कार्बन ऊर्जा पर पेट्रोलियम मंत्री को रूपरेखा की प्रस्तुति।

विशेष प्रचार अभियान

- सार्क मीडिया विकास कोष के गठन पर विशेषज्ञ दल की बैठक।
- आर्थिक सम्पादकों का सम्मेलन-2005।
- सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर सम्पादकों का सम्मेलन-2005।
- भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आई एफ एफ आई-2005)।
- हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस।
- एशियाई तेल मंत्रियों, पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक और प्रमुख उपभोक्ताओं का गोलमेज सम्मेलन।
- उत्तर तथा मध्य एशिया के तेल उत्पादक देशों और एशिया के प्रमुख उपभोक्ता देशों के साथ गोलमेज सम्मेलन।

पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा कार्यालय	कार्यालय एवं सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	शिविर कार्यालय	कुल
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र चंडीगढ़	1. जम्मू 2. शिमला 3. देहरादून	1. श्रीनगर 2. जालंधर			6
2. मध्य क्षेत्र भोपाल	1. जयपुर 2. इंदौर 3. कोटा 4. जोधपुर 5. रायपुर				6
3. पूर्व-मध्य क्षेत्र लखनऊ	1. वाराणसी 2. कानपुर 3. पटना 4. रांची				5
4. पूर्व-क्षेत्र कोलकाता	1. कटक 2. अगरतला 3. भुवनेश्वर	1. गंगटोक			5
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी	1. शिलांग	1. कोहिमा 2. इंपाल	आइजोल		5
6. दक्षिण-मध्य क्षेत्र हैदराबाद	1. विजयवाड़ा 2. बंगलौर				3
7. दक्षिण क्षेत्र चेन्नई	1. मदुरै 2. कोचीन 3. तिरुवनन्तपुरम 4. कोझीकोड				5
8. पश्चिमी क्षेत्र मुम्बई	1. नागपुर 2. पुणे 3. पणजी 4. राजकोट 5. नांदेड़ 6. अहमदाबाद				7
कुल : क्षेत्रीय कार्यालय = 8	शाखा कार्यालय = 28	5	2		43

किया गया। ये केन्द्र भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और पंचायतों की भागीदारी से स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में पंचायती राज्यमंत्री के दौरों के समय उनके साथ कई प्रेस पार्टियां आयोजित की गईं। पंचायती राज्यमंत्री का इन राज्यों में दौरा पंचायती राज संस्थानों, कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रबंध प्रणाली की समीक्षा और ग्राम पंचायतों के सदस्यों से परिचर्या से संबंधित था। पंचायती राज्यमंत्री के इन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया गया। गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों पर समीक्षा बैठक के लिए पंचायती राज्यमंत्री की बंगलौर यात्रा के प्रचार की व्यवस्था की गई।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दृश्य सहायता उपलब्ध कराने वाली मिडिया इकाई है। यह प्रभाग भारत सरकार की ओर से आंतरिक (देश में) तथा बाह्य (विदेशों) में प्रचार हेतु श्वेत-श्याम तथा रंगीन चित्र और दृश्य प्रलेख उपलब्ध कराने का दायित्व संभालता है।

प्रभाग का मुख्य कार्य चित्रों के माध्यम से देश में हुए विकास तथा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों को चित्रों के माध्यम से एक स्थान पर संग्रह करना एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों जिनमें राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के प्रचार माध्यम एककों के साथ ही विदेश मंत्रालय के बाह्य (विदेश) प्रचार विभाग के माध्यम से विदेश स्थित भारतीय मिशनों को महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र (स्टिल) उपलब्ध कराना है।

यह प्रभाग गैर-प्रचार संगठनों तथा जन सामान्य को भी अपनी मूल्य नीति के अन्तर्गत भुगतान आधार पर श्वेत-श्याम तथा रंगीन चित्र उपलब्ध कराता है।

10वीं योजना कार्यक्रम

प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से रखते हुए प्रभाग ने दसवीं योजना अवधि के दौरान अपनी योजना को पुनः बनाया है जिसके अंतर्गत प्रभाग की प्रयोगशालाओं तथा इसके संग्रहालय में उपलब्ध चित्रों को डिजिटल करने पर जोर दिया गया है। योजना अवधि के तीसरे वर्ष में प्रभाग ने अपने पास उपलब्ध सभी चित्रों

कुछ आंकड़े

(अप्रैल 2005 से नवम्बर 2005)

1.	मुख्यालय द्वारा कवर किए गए कार्यक्रम	969
2.	समाचारपत्रों को जारी किए गए समाचार फोटोग्राफ	898
3.	पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी फोटोग्राफ	11469
4.	जारी प्रेस रिलीजें	77613
5.	जारी विशेष लेख	4568
6.	आयोजित किए गए प्रेस सम्मेलनों की संख्या	1289

का अभिलेखीकरण, वर्गीकरण (कैटलाग बनाना) तथा डिजिटलीकरण करने के साथ ही चरणबद्धक्रम में अपनी प्रयोगशालाओं को डिजिटल बना दिया है और समाचार फोटो प्रणाली (न्यूज फोटो नेटवर्क) को अद्यतन कर दिया है। समाचार कवरेज क्षेत्रों से चित्रों के तुरंत संप्रेषण के लिए प्रभाग ने डिजिटल कैमरे तथा डाटा कार्ड सुविधा युक्त लैप टॉप खरीद लिए हैं। इससे अब प्रभाग प्रेस को जारी करने के लिए डिजिटल चित्रों का शीघ्र संप्रेषण कर सकता है। चित्रों का कैटलॉग बनाने और उनका डिजिटलीकरण करने के एक भाग के रूप में प्रभाग ने 2.12545 चित्रों को क्यूमुलस प्रणाली में बदल दिया है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

प्रभाग ने प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक अमरीका यात्रा, अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को प्रधानमंत्री के संबोधन एवं अमरीकी राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री का भाषण तथा उनके द्वारा विभिन्न देशों की यात्रा की व्यापक फोटो कवरेज की।

प्रभाग ने गोआ में हुए 36वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हेतु व्यापक फोटो कवरेज उपलब्ध कराया। प्रेस प्रचार के लिए पी आई बी को बड़ी संख्या में फोटोग्राफ्स जारी किए गए। पत्रकारों में वितरित करने के लिए लगभग 10,000 (दस हजार) चित्र मुहैया कराए गए। प्रभाग ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के दौरों की फोटो कवरेज की जो विवेचनाधीन अवधि में भारत यात्रा पर आए।

प्रभाग ने नेहरू स्मारक निधि, गांधी स्मारक न्यास (ट्रस्ट) तथा संजीव गांधी संस्थान (फाउंडेशन) को अपनी मूल्य नीति के अन्तर्गत 21001 चित्रों वाले एल्बम भेजे हैं जिससे कि वहां पुस्तकालयों में आने वाले शोधकर्ता लाभान्वित हो सकें।

प्रभाग ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस यात्रा, उधमपुर जम्मू-श्रीनगर रेल मार्ग, दिल्ली प्राणी उद्यान में तथा दिल्ली में मेट्रो रेल जैसे विषयों पर अनूठे फीचर कवरेज किए हैं।

अप्रैल से दिसम्बर 2005 की अवधि में प्रभाग ने प्रेस को 985 चित्रों के माध्यम से लगभग 35985 चित्र जारी किए।

प्रभाग ने “धर्म निरपेक्ष भारत” विषय पर 17वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

प्रभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर एक व्यापक फोटो प्रलेखन कार्य किया।

विषय : फोटो प्रभाग के संबंध में ‘योजना निष्पादन 2005-06’ अध्याय हेतु सामग्री

योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आंबटन इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2005-06	संशोधित अनुमान 2005-06
1	2	3	4
1.	फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण	110.00	110.00

भारतीय जनसंचार संस्थान

पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसे संचार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र के ‘उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है। संस्थान की स्थापना 17 अगस्त 1965 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य देश के संपूर्ण विकास की रणनीति के तहत संचार के साधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए एक रास्ता अख्तियार करना था। बाद में आई आई एम सी को 22 जनवरी 1966 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (21) 1960 के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया। भारत सरकार इसे आवर्ती एवं गैर-आवर्ती खर्च के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। आई आई एम सी प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो एवं टेलीविजन सहित विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों को शिक्षित-प्रशिक्षित करने के साथ-साथ संगोष्ठियों, प्रशिक्षणों और कार्यशाला आदि के संचालन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सहयोग भी प्रदान करता है। यहां संचार उद्योग, सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए

संयुक्त शोध परियोजनाओं और अल्पावधि पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है।

वर्तमान गतिविधियां

वर्ष 2005-06 के दौरान आई आई एम सी ने लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये हैं-

1. भारतीय सूचना सेवा (समूह-ए) के अधिकारियों के लिए ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम।
2. नई दिल्ली और ढेनकानाल (उड़ीसा) में अंग्रेजी पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

3. हिन्दी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
4. विज्ञापन एवं जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
5. रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
6. उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और
7. डेवलपमेंट जर्नलिज्म में डिप्लोमा कोर्स।

इसके अलावा, संस्थान द्वारा मध्यम श्रेणी एवं वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों एवं विभिन्न मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के लिए अल्पवधि शैक्षणिक कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। संस्थान

भारतीय जन
संचार संस्थान



Indian Institute of
Mass Communication



सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान की बैठक को संबोधित करते हुए, 26 अप्रैल, 2005

के विषय वस्तु को बेहतर बनाने एवं मौजूदा पाठ्यक्रमों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए संकाय और इस क्षेत्र के माहिर खिलाडियों, खासकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन, जन संपर्क, प्रसारण एवं प्रिंटिंग के विशेषज्ञों के बीच व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। संबद्ध उद्योग के आवश्यक तथ्यों पर आधारित ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किये जाते हैं जो अत्यधिक व्यावहारिक इनपुट एवं ज्ञान प्रदान कर सकें।

संगोष्ठी एवं सम्मेलन

भारत और अन्य विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में संचार व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियां और सम्मेलन भी आयोजित किये जाते रहे हैं।

परामर्श

आई आई एम पी केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आग्रह पर परामर्श सेवा भी प्रदान करता है और संचार के क्षेत्र में विकास से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रम संचालित करने में मदद भी करता है।

शैक्षणिक सत्र

नई दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों सहित आठ केंद्रों पर 20 मई 2005 को आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर कुल 40 विद्यार्थियों को राजधानी दिल्ली में हिन्दी पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए और 43 को अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए चुना गया जबकि ढेनकानाल में 39 विद्यार्थियों ने नामांकन लिए। विज्ञापन एवं जन संपर्क पाठ्यक्रम में 50 विद्यार्थियों, रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता पाठ्यक्रम में 35 और ढेनकानाल में उड़िया पत्रकारिता में 15 विद्यार्थियों ने नामांकन लिये। इन विद्यार्थियों में 13 अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, जिन्होंने विज्ञापन एवं जन संपर्क, रेडियो एवं टी वी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया। सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक अगस्त 2005 को शुरू हुए।

विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

विकासशील देशों में पत्रकारिता कौशल में सुधार के गुट निरपेक्ष

आंदोलन (नैम) के प्रयासों को जारी रखते हुए तथा तीसरी दुनिया का स्वरूप विकसित करने के लिए संस्थान विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। प्रत्येक वर्ष ऐसे दो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जिनकी अवधि चार-चार महीने होती है। इस शृंखला का 45वां पाठ्यक्रम पहली अगस्त 2005 से शुरू हुआ।

संकाय एवं शोध कर्मचारी

भारतीय जनसंचार संस्थान के संकाय एवं शोध कार्यों से संबंधित अधिकारियों में शिक्षाविद, शोधकर्ता और मीडिया से जुड़े लोग शामिल होते हैं। जिन्होंने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान दिया है, इनके अलावा प्रमुख समाचारपत्रों और अन्य मीडिया संगठनों ने विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया है। प्रशिक्षुओं और विद्यार्थियों को संबंधित उद्योग के बारे में विशिष्ट जानकारी देने के लिए पेशागत महत्वपूर्ण लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है।

संचार आधार व्यापक बनाना

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब सुदूर इलाकों में जनसंचार और संचार शिक्षा का आधार विकसित करने के मद्देनजर ढेंकानाल (उड़ीसा), दीमापुर (नगालैंड), कोट्टयम (केरल) और झाबुआ (मध्य प्रदेश) में भी आई आई एम पी के केंद्र स्थापित किए गये।

आई आई एम सी का ढेंकानाल केंद्र अगस्त 1993 से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और बड़ी संख्या में पूर्वी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। इस शाखा में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और यह प्रतिवर्ष अंग्रेजी तथा उड़िया भाषाओं में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है।।

नगालैंड विश्वविद्यालय के साथ सहयोग

पूर्वोत्तर में विकास की पहल और “शिक्षा के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सहयोग” योजना के अंतर्गत आई आई एम सी ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स चलाने के लिए नगालैंड विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। इस तरह का पहा पाठ्यक्रम 14 विद्यार्थियों के साथ 20 जनवरी 2005 से शुरू हो गया है। अन्य बेहतरीन संस्थानों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावना तलाशी जा रही है।

2005-06 की महत्वपूर्ण घटनाएं

आई आई एम सी ने अपना रेडियो स्टेशन भी शुरू किया है जिसका नाम है-अपना रेडियो एफएम 96.9 मेगाहर्ट्ज। इसका उद्घाटन नौ सितंबर 2005 को किया गया, जो विद्यार्थियों को सार्वजनिक सेवा प्रसारण के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराता है।

वार्षिक योजना 2006-07

आई आई एम सी ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छह योजनाएं क्रियान्वयन के लिए तैयार की थीं जिनमें से दो का विलय कर दिया

गया है। अब इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार योजनाएं क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं।

1. आई आई एम सी, नई दिल्ली की इमारत एवं आवासीय योजना।
2. इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता के लिए आवश्यक सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार।
3. क्षेत्रीय शिक्षण केंद्रों के साथ साठगांठ।
4. शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन।

वित्तीय व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	सकल योग	योजना		गैर-योजना		
		राजस्व प्राप्ति/व्यय	कुल अनुदान योग	सकल प्राप्ति	राजस्व अनुदान/व्यय	कुल
2004-05						
एसबीजी	395.00	—	395.00	490.30	120.00	370.30
आरई	110.00	—	110.00	—	—	345.00
व्यय	99.70	—	99.70	509.91	161.50	348.41
2005-06						
एसबीजी	240.80	—	240.80	521.00	160.00	361.00
आरई (प्रस्तावित)	103.50	—	103.50	537.30	161.00	376.30
बीई (प्रस्तावित)	183.50	—	183.50	570.46	170.00	400.46
2006-07						

अल्पावधि कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित किये :

क्रम सं.	अल्पावधि पाठ्यक्रम/ कार्यशाला/संगोष्ठी	प्रतिभागी	आयोजन स्थल नई दिल्ली
1.	वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए नौ से 20 मई 2005 तक मीडिया काम्युनिकेशन कोर्स	15	नई दिल्ली
2.	20-24 जून 2005 तक आईआईएस अधिकारियों, पुस्तक/पत्रिका संपादन	10	नई दिल्ली
3.	हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए 27 जून से पहली जुलाई 2005 तक पत्र-व्यवहार कौशल कार्यशाला	10	नई दिल्ली
4.	सेना, नौसेना एवं वायुसेना के मध्य स्तरीय अधिकारियों के लिए 18-19 जुलाई 2005 मीडिया काम्युनिकेशन पाठ्यक्रम	30	नई दिल्ली
5.	25-29 जुलाई 2005 तक पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स	09	नई दिल्ली
6.	22-26 अगस्त 2005 तक पीआईबी अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स	10	नई दिल्ली
7.	वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए 03-28 अक्टूबर तक मीडिया कॉम्युनिकेशन कोर्स	21	नई दिल्ली
8.	17-28 अक्टूबर 2005 तक आईआईएस 14 के अधिकारियों के लिए थॉमसन फाउंडेशन के माध्यम से संपादन, लेखन एवं साक्षात्कारों पार कार्यशाला	14	नई दिल्ली

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद (पी सी आई) भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अधीन गठित एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका कार्य प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखना और देश के समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर के संरक्षण तथा इनमें सुधार करना है। परिषद् का एक अध्यक्ष और 28 सदस्य हैं। इनमें से 20 प्रेस

के विभिन्न क्षेत्रों से है, 5 संसद सदस्य हैं और 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिषद को केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के जरिए कोष उपलब्ध कराया जाता है। परिषद एक सांविधिक निकाय है, इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार परिषद की वार्षिक रिपोर्ट अलग से संसद में पेश की जाती है।

4

प्रसारण क्षेत्र (भारतीय प्रसारण निगम)

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 2005-2006 की वार्षिक रिपोर्ट

प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य इस प्रकार हैं :

1. श्री एम.वी. कामथ	अध्यक्ष
2. श्री के.एस. सरमा	कार्यकारी सदस्य
3. श्री डी.पी.एस. लाम्बा	सदस्य कार्मिक
4. श्री प्रदीप सिंह, अतिरिक्त सचिव	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि
5. श्रीमती चित्रा मुद्गल	अंशकालिक सदस्य
6. श्री एम.एल. मेहता	अंशकालिक सदस्य
7. श्री आर.एन. बिसारिया	अंशकालिक सदस्य
8. श्री बृजेश्वर सिंह महानिदेशक, आकाशवाणी	पदेन सदस्य
9. श्री नवीन कुमार महानिदेशक, दूरदर्शन	पदेन सदस्य

एक अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2006 तक प्रसार भारती बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित की गईं और संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के पर्वतीय केन्द्रों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को गर्म कपड़ों की सुविधा
- दूरदर्शन की वार्षिक पुरस्कार योजना में संशोधन
- फुटबल टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिये ए आई एफ एफ के साथ समझौता
- कार्यक्रम हासिल करने के लिये दिशा-निर्देशों में संशोधन
- भारतीय गौरव ग्रंथों पर आधारित कार्यक्रम

- स्करोलर्स टेलीकास्ट के लिये रेट कार्ड
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में केबल हेड एंड्स
- प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये दिशा निर्देशों में संशोधन
- दसवीं योजना के अंतर्गत आकाशवाणी में 26 चैनल वेबकास्टिंग/पॉडकास्टिंग
- विपणन विभाग द्वारा वाणिज्यिक समय की बिक्री
- दूरदर्शन चैनलों पर स्वचित्त कमीशन कार्यक्रमों के दिशा निर्देशों में संशोधन के लिए विचारण प्रक्रिया और मंजूरी
- डी डी की डीटीएच सेवा

दूरदर्शन

2005-06 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम

संगठन

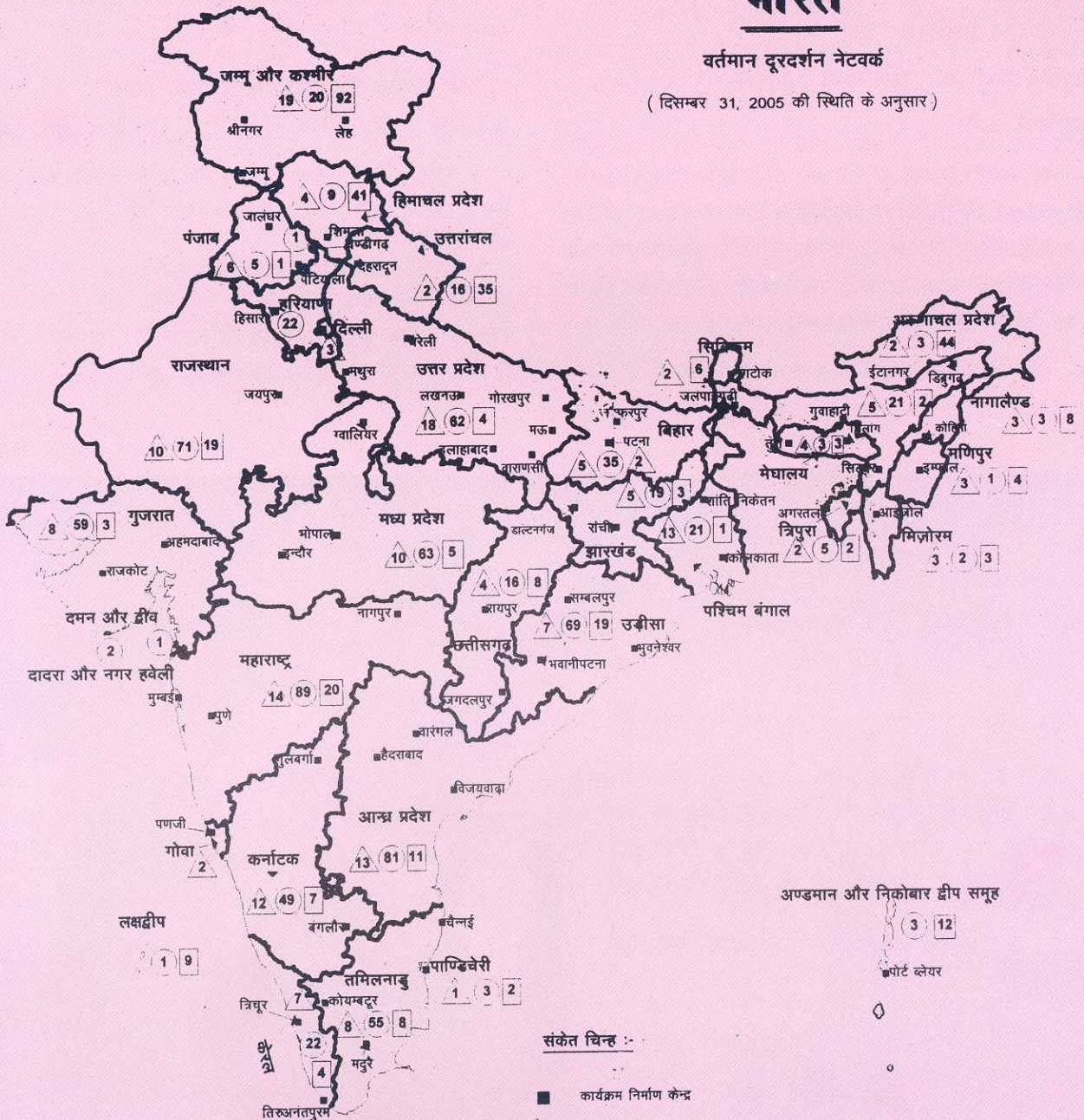
सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन विश्व में सबसे बड़े भूभाग को कवर करने वाला संस्थान है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को शैक्षिक एवं विकास संबंधी आधे घंटे के कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिये प्रयोग के आधार पर की गई थी। दिल्ली में 1982 में आयोजित नौवें एशियाई खेलों के साथ देश में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई। यह देश में प्रसारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद दूरदर्शन का तेजी से विकास किया गया और 1984 में देश में लगभग प्रतिदिन एक ट्रांसमीटर स्थापित किया गया। इस समय दूरदर्शन 26 चैनलों का संचालन करता है। इनमें 5 अखिल भारतीय चैनल, 11 क्षेत्रीय भाषा के सेटलाइट चैनल, 8 हिन्दी क्षेत्र के चैनल, दो संसदीय चैनल - डी डी लोकसभा और डी डी राज्यसभा और एक अंतरराष्ट्रीय चैनल शामिल हैं।

दूरदर्शन का एक महानिदेशक होता है, कार्यक्रम प्रभाग में उन्हें सहायता देने के लिये उप निदेशक होते हैं। इंजीनियरिंग प्रभाग का

भारत

वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क

(दिसम्बर 31, 2005 की स्थिति के अनुसार)



संकेत चिन्ह :-

- कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
- △ उच्च शक्ति प्रेषित्र
- अल्प शक्ति प्रेषित्र
- अति अल्प शक्ति प्रेषित्र/द्रांसपोजर

प्रमुख इंजीनियर इन चीफ होता है, प्रशासन एवं वित्त प्रभाग का एक अतिरिक्त महानिदेशक होता है, और समाचार प्रभाग के लिये एक अलग अतिरिक्त महानिदेशक होता है।

इंजीनियरिंग प्रभाग की उपलब्धियां 2005-06

नये स्टूडियो केन्द्र

वारंगल, मदुरै और कोयंबटूर में तीन नये स्टूडियो बनाए गये। इसके साथ ही देश भर में दूरदर्शन के स्टूडियो की संख्या 64 हो गई है। इसके अलावा रायपुर में एक अतिरिक्त स्टूडियो की स्थापना की गई। रांची में एक अन्य स्टूडियो बन रहा है और इसका काम 2005-06 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

गोरखपुर और देहरादून में स्थायी केन्द्र बनाने की दिशा में भी काम

चल रहा है। लेह, चंडीगढ़ और पणजी के दूरदर्शन केन्द्रों में अतिरिक्त स्टूडियो बनाने की योजना को भी 2005-06 के दौरान मंजूरी दी गई।

स्टूडियो परिसर “दूरदर्शन भवन दूसरा चरण”

दिल्ली में दूरदर्शन के एक शानदार स्टूडियो की शुरुआत की गई। 81.6 करोड़ रुपये की लागत से बने इस परिसर का उद्घाटन सूचना प्रसारण और संस्कृति मंत्री जयपाल रेड्डी ने 23 अगस्त 2005 को किया।

दो बेसमेंट के साथ कुल 39678 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली ग्यारह मंजिला इमारत कई सुविधाओं से संपन्न है। स्टूडियो पूरी तरह डिजीटलयुक्त है और इसमें निम्नलिखित सुविधाएं हैं :



केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी ने नई दिल्ली में दूरदर्शन भवन की नई इमारत 'टावर-बी' का उद्घाटन किया, 23 अगस्त, 2005

- (क) इसमें 593 वर्ग मीटर, 425 वर्ग मीटर, और 234 वर्ग मीटर के तीन स्टूडियो हैं। प्रत्येक स्टूडियो की ऊंचाई 14.1 मीटर है।
- (ख) एक स्टूडियो 133 वर्ग मीटर बड़ा और दो स्टूडियो 50-50 वर्ग मीटर के हैं। इन तीनों स्टूडियो की ऊंचाई नौ मीटर है।
- (ग) इसमें 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला समाचार कक्ष है।
- (घ) इसमें 25 एन एल ई संपादन कक्ष, 25 ए/बी रोल संपादन कक्ष, 19 कम्प्यूटर ग्राफिक्स और 6 प्रीव्यू कक्ष शामिल हैं।
- (ङ) मास्टर स्विचिंग और फीड कक्ष
- (च) 2651 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले दफ्तर में 217 कमरे हैं।

भूभागीय कवरेज

1. 2005-06 के दौरान इन आठ ट्रांसमीटरों को शुरू किया गया :
- (i) एल पी टी : पुंगानूर और कोल्हापुर (आंध्र प्रदेश), फतेहाबाद और कैथल (हरियाणा), खाजूवाला (राजस्थान), सिंघनूर और मधोल (कर्नाटक)
- (ii) वी एल पी टी : देवभोग (छत्तीसगढ़)

इसके अलावा दूरदर्शन ने राजकोट (गुजरात) और अम्बाजोगई (महाराष्ट्र) में भी एच पी टी न्यूज चैनल की शुरुआत की। एच पी टी परियोजनाओं पर वडौदरा (डी डी एक और समाचार), बीकानेर, छतरपुर, राधनपुर, धर्मपुरी, तिरुनेलवेली, धर्मशाला, सागर, सहरसा, हिसार (डी डी एक और समाचार), भटिंडा (डी डी न्यूज) और कार्सियांग (डी डी न्यूज) में भी काम चल रहा है। देश में डी डी न्यूज के नेटवर्क का ब्यौरा चार्ट में दिया गया है।

दूरदर्शन की (फ्री टु एअर) डी टी एच सेवा

दूरदर्शन की फ्री-टु-एअर डी टी एच सेवा ("डी डी डायरेक्ट प्लस") में फिलहाल 33 चैनल उपलब्ध हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 50 करने की दिशा में काम चल रहा है।

डी टी एच भू-केंद्र अभी उसी इमारत में है। डी टी एच सुविधा से संपन्न एक नयी इमारत दिल्ली के टोडापुर में बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिये योजना तैयार कर ली गई है और उसे स्थानीय संकायों की मंजूरी के लिये भेजा गया है।

डिजीटलीकरण

2005-06 के दौरान दूरदर्शन ने श्रीनगर और जयपुर में 2 डिजीटल भू केन्द्र शुरू किये। इसके साथ ही दूरदर्शन के 26 केन्द्रों का डिजीटलीकरण हो चुका है।

अहमदाबाद, जयपुर, पटना और गुवाहाटी स्थित चार प्रमुख केन्द्रों के डिजीटलीकरण का काम प्रगति पर है और इन केन्द्रों का 2005-06 के दौरान पूरी तरह डिजीटलीकरण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बरेली, रांची, विजयवाड़ा, मुजफ्फरपुर, पुणे और गुवाहाटी में छह छोटे केन्द्रों के आंशिक (50 प्रतिशत) डिजीटलीकरण के लिये काम चल रहा है। इस काम के 2005-06 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

एच पी टी को बदलना

वर्तमान वर्ष के दौरान नागपुर, इंदौर और वाराणसी में तीन पुराने एच पी टी को बदलकर नये एच पी टी लगाये गए। श्रीनगर, कार्सियांग, भटिंडा, कोच्चि और कोडईकनाल में भी पुराने एच पी टी बदलने का काम चल रहा है। इसके साथ ही श्रीनगर में डी डी न्यूज एच पी टी और कश्मीर चैनल एच पी टी को भी उन्नत किया जा रहा है। ये सभी काम 2005-06 के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है।

एल पी टी का ऑटोमेशन

1984 में लगाए गये 100 वाट वाले 27 पुराने एल पी टी की जगह इस साल नये ऑटो मोड ट्रांसमीटर लगाये गये। इनके अलावा 16 पुराने एल पी टी की जगह ऑटो मोड एल पी टी लगाने का काम चल रहा है। इसे 2005-06 में पूरा लिया जाएगा।

प्रोडक्शन सुविधाओं का आधुनिकीकरण

विभिन्न केन्द्रों पर पुराने उपकरणों जैसे कैमरा, वीसीआर, इंजीनियरिंग यूनिटों, उपकरणों और लाइटों को बदला गया है। विभिन्न केन्द्रों को अतिरिक्त उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आउटडोर कवरेज सुविधा में भी सुधार किया गया है। पांच वी-सेट टर्मिनलों का आर्डर दिया गया है और नौ डी एस एन जी यूनिट और दो ओ बी वैन हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

न्यूज ऑटोमेशन (स्वचालन)

डी डी भवन टावर वी में समन्वित समाचार स्वचालन व्यवस्था की सुविधा दी जा रही है। यह व्यवस्था समन्वित वातावरण में न्यूज

चैनल में चौबीसों घंटे उत्पादन, प्लेआउट और स्टोरेज की स्वचालन सुविधा उपलब्ध कराती है। इसमें वीडियो सर्वर, नॉन नियर एडिटिंग स्यूट्स, केरेक्टर जनरेटर, घोषणा पत्रों और अनेक प्रसारण उपकरणों को बिना जोड़े एक साथ विविध गतिविधियां जैसे कि कहानी की रिकार्डिंग, स्क्रिप्ट और वीडियो सम्पादन, ग्राफिकों की तैयारी अभिलेखागार से कार्यक्रम प्राप्त करना, स्टोरेज और समाचार चलाना आदि कार्य किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त व्यवस्था में पत्रकारों के लिए 75 कार्य स्टेशन होंगे और प्ले आउट के लिए एक समर्पित ट्रान्समिशन सर्वर और आठ क्राफ्ट एडीटिंग सिस्टम होंगे। न्यूज रूम के लिए डिजिटल आटोमेडेड प्रणाली सप्लाइ और उसे लगाने का आर्डर दिया जा चुका है और आशा है कि यह सिस्टम 2005-06 की समाप्ति के पहले लगा दिया जाएगा।

अन्य घटनाक्रम

- प्राइवेट पार्टियों के वाणिज्यिक विज्ञापनों की भुगतान के आधार पर स्कॉलिंग का 12 एच पी टी तक विस्तार किया गया यथा आगरा, आसनसोल, अमृतसर, औरंगाबाद, कोच्चि, जमशेदपुर, जलगांव, कानपुर, कसौली, कोडइकनाल, मसूरी और विशाखापटनम।
- नेशनल और स्पोर्ट्स चैनलों पर एस एम एस आधारित अन्योन्यक्रिया की सुविधा दी गई।
- डी डी अभिलेखागार ने 5 डी वी डी, 4 डी सी डी और 2 ए सी डी शुरू किए।
- अब तीन चरणों में नैरोकास्ट लागू किया जा रहा है - राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय (माइक्रो) स्तर और दिल्ली 18 क्षेत्रीय केन्द्रों और 36 नैरोकास्ट समूहों के 180 ट्रान्समीटरों से टेलीकास्ट किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

2005-06 के दौरान दूरदर्शन ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की निम्न घटनाओं का सीधा प्रसारण किया :

- स्वतंत्रता दिवस समारोह
- गणतंत्र दिवस समारोह
- केन्द्रीय बजट-रेल/आम
- महात्मा गांधी की जयंती/शहीदी दिवस

- अति विशिष्ट मेहमानों की यात्रा/राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
- भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
- भारत और श्रीलंका और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला।
- भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट श्रृंखला
- राष्ट्रमंडल खेलों में क्वीन्स बार्टन रिले
- दिल्ली हाफ मैराथन
- त्यागराज समारोह
- गुरु गोविन्द सिंह का जन्मदिन
- जन्माष्टमी
- बिहार विधानसभा चुनाव
- लोकसभा/राज्य सभा में प्रश्नकाल

कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किये गये :

स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन, विजय दिवस (1971 युद्ध) और नौसेना दिवस के मौके पर वृत्तचित्र

5 सितंबर को प्रधानमंत्री की यात्रा की कवरेज और न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से सीधा प्रसारण। यूरोपीय यूनियन-भारत शिखर सम्मेलन और आसियान शिखर बैठक की कवरेज।

नयी पहल

500 एच पी टी/एल पी टी से विज्ञापनों की स्कॉलिंग

डी डी डायरेक्ट प्लस के टी वी चैनलों की संख्या बढ़ाकर 50 करना

डी डी राष्ट्रीय चैनल

डी डी-1 (राष्ट्रीय चैनल)

दूरदर्शन का डीडी-1 चैनल विश्व में सबसे बड़े भूभाग पर प्रसारित होता है। इस समय 90.7 प्रतिशत आबादी इसका प्रसारण देख सकती है। दूरदर्शन मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक बदलाव, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, लोगों में जागरूकता पैदा करने, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन, महिला कल्याण, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने और शिक्षा के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा

है। डीडी-1 चैनल ने खेलों, कलाकारों और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देने में योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रमों और धारावाहिकों का भी प्रसारण होता है। इसके अलावा दूरदर्शन के विभिन्न केंद्र कार्यक्रम बनाकर उनका प्रसारण करते हैं।

2005-06 के दौरान निम्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रसारण किया गया :

- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, गणतंत्र दिवस परेड, एन सी सी रैली, बीटिंग रिट्रीट आदि
- कुछ विधानमंडलों के चुनाव
- खेल घटनाएं
- त्यौहार, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस
- संसद सत्र
- केन्द्रीय बजट, रेल बजट और लोगों की प्रतिक्रिया
- संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण
- प्रवासी भारतीय दिवस

इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े विकास कार्यक्रमों, पल्स पोलियो अभियान, कैंसर रोधी, कुष्ठ रोग, तपेदिक, डेंगू और स्वास्थ्य संबंधी अन्य बीमारियों पर विशेष कार्यक्रमों को भी कवरेज दी गई। प्राइमरी शिक्षा, एड्स, आई आर डी ए, उपभोक्ता शिक्षा, सड़क सुरक्षा, समाज के कमजोर तबके को मुफ्त कानूनी सहायता के लिये विशेष अभियान चलाया गया।

इसके अलावा विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रीय केंद्रों ने विकास संबंधी प्रसारण, क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों और क्षेत्रीय भाषा के मनोरंजन कार्यक्रम के लिये भी इस चैनल का उपयोग किया।

राष्ट्रीय चैनल सेवा के कार्यक्रम टेरेस्ट्रियल मोड और सेटेलाइट मोड पर सुबह साढ़े पांच बजे से आधी रात तक और उसके बाद सेटेलाइट मोड में अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे तक प्रसारित होते हैं।

क्षेत्रीय भाषा की उपग्रह सेवा और क्षेत्रीय नेटवर्क

ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं की सेटेलाइट सेवाएं निम्न हैं :

डीडी-मलयालम	डीडी-सप्तगिरी (तेलुगु)
डीडी-बांग्ला	डीडी-चंदना (कन्नड़)

डीडी-उड़िया	डीडी-सहयाद्रि (मराठी)
डीडी-गुजराती	डीडी-कशीर (कश्मीरी)
डीडी-पंजाबी	डीडी-पूर्वोत्तर
डीडी-पोधीगई (तमिल)	

क्षेत्रीय भाषा की उपग्रह सेवा और क्षेत्रीय नेटवर्क अपनी भाषा में जनता के साथ संपर्क करने के लिये विकास से जुड़ी खबरों, धारावाहिकों, वृत्तचित्रों, समाचारों और सामयिक कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर प्रसारण करते हैं। अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में सामान्य सूचना से जुड़े कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों और फिल्मी कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है।

क्षेत्रीय नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। प्रतिदिन दिन में तीन बजे से रात आठ बजे तक इन राज्यों की राजधानियों के केंद्रों से इस सेवा के लिये तैयार कार्यक्रमों को राज्य के सभी जमीनी ट्रांसमीटरों से रिले किया जाता है।

डीडी न्यूज चैनल

दूरदर्शन के 24 घंटे के न्यूज चैनल डीडी-न्यूज की भूभागीय कवरेज 22 प्रतिशत हो गई और देश की 45.9 प्रतिशत आबादी इसके प्रसार क्षेत्र में आ गई।

वर्ष 2005 के दौरान डी डी न्यूज ने राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, नेताओं और जनता के बीच स्टूडियो में सीधे संवाद वाला एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम “चर्चा में” शुरू किया है। उसका “सभी के लिये शिक्षा” कार्यक्रम सी बी ए-यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिये चुना गया जिसमें राष्ट्रपति ने भी हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन, विजय दिवस और नौसेना दिवस के मौके पर वृत्तचित्र बनाए गये। कुछ नए साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किये गए जिनमें *मेरे देश की धरती* (ग्रामीण पत्रिका) और *एहसास* (साम्प्रदायिक सौहार्द) शामिल हैं। इस साल हमारी रक्षा क्षमता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी कार्यक्रम शुरू किये गये जैसे युद्ध और शांति और रक्षा निगरानी। अन्य नये कार्यक्रमों में ‘आमने-सामने’ और ‘जायजा’ शामिल हैं।

डी डी न्यूज प्रोडक्शन अपने चैनलों के प्रसार के लिये व्यावसायिक और प्रोत्साहन देने वाली पैकेजिंग तैयार करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बांबे स्टॉक एक्सचेंज और एन सी डी ई एक्स, एम सी एक्स जैसे प्रमुख उत्पाद एक्सचेंजों से सूचना हासिल कर स्टॉक

और उत्पादों के बारे में सूचनाओं को एक ऑटोमेटिक डिलीवरी मोड के जरिये दिन भर प्रसारित करता है। सितम्बर 2005 में प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र यात्रा की व्यापक कवरेज की गई और न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूरोपीय यूनियन-भारत शिखर बैठक और आसियान शिखर बैठक का सीधा प्रसारण किया गया। ग्राफिक का इस्तेमाल करते हुए केन्द्रीय बजट 2005 और विधानसभा चुनावों का कवरेज किया गया।

डी डी स्पोर्ट्स

(1) 18 मार्च 1999 को शुरू किया गया डी डी स्पोर्ट्स चैनल देश का एकमात्र फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल है।

स्पोर्ट्स चैनल में इस साल जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया वे इस प्रकार हैं :

1. भारत-श्रीलंका एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला
2. भारत-दक्षिण अफ्रीका एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला
3. भारत-इंग्लैंड महिला क्रिकेट टेस्ट मैच और एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला
4. भारत-पाकिस्तान के वरिष्ठ खिलाड़ियों का क्रिकेट मैच
5. 20:20 क्रिकेट त्रिकोणीय शृंखला
6. डेविस कप-भारत और चीन के बीच मैच
डेविस कप-भारत और उजबेकिस्तान के बीच मैच
7. दिल्ली हाफ मैराथन
8. पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन - 2005
9. सुब्रतो कप फुटबाल टूर्नामेंट
10. डूरंड फुटबाल टूर्नामेंट-2005

गैर ओलंपिक और पारंपरिक खेलों के प्रसारण के लिये एक नकदी निर्गमन प्रणाली शुरू की गई। कमेंटरी को दी जाने वाली राशि का भुगतान करने के साथ सीधे प्रसारण के लिये डी एस एन जी और ओ बी वैन पर आने वाले खर्च के लिये मुख्यतः नकदी निर्गमन राशि वसूल की गई। दूरदर्शन ने विभिन्न खेल महासंघों और संघों द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का कवरेज भी जारी रखा।

खेलों को बढ़ावा देने के लिये नकदी निर्गमन प्रणाली का इन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया :

1. सशस्त्र और अर्द्धसैनिक बलों
2. विकलांगों के खेलों
3. शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों
4. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल
5. हर तरह की स्पर्धाओं में महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिये
6. जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और लक्षद्वीप जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में हुई घटनाएं।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूद घटनाओं की कवरेज जो मैसर्स/आई ई सी इन स्पोर्ट्स (इन्टरनेशनल इवेंट्स एंड कम्युनिकेशन ए.वी.) से हुए समझौते के अन्तर्गत 2005-06 और 2006-07 के लिए प्राप्त की गई थी, चैनल पर टेलीकास्ट की जाती रही।

डीडी भारती

डीडी-भारती चैनल 26 जनवरी 2002 को शुरू किया गया। यह स्वास्थ्य, बच्चों, संगीत, नृत्य और विरासत पर कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है।

साहसिक कार्यों, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, ललित कला/पेन्टिंग, दस्तकारी और डिजाइन, कार्टून, प्रतिभा-खोज आदि कार्यक्रमों के अलावा, इसने युवाओं के साथ एक घंटे का जीवन्त (लाइव) शो 'मेरी बात' टेलीकास्ट करना जारी रखा है। इसके अलावा, एक जीवन्त कार्यक्रम 'विजन आफ इंडिया' जिसमें राष्ट्रपति ने देश भर के हजारों बच्चों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया, टेलीकास्ट किया गया।

एक चार घंटे का स्वस्थ जीवनशैली पर जोर देने वाला और इस बात पर ध्यान केन्द्रित करने वाला कार्यक्रम कि रोग के उपचार से उसकी रोकथाम बेहतर है, चिकित्सा के परम्परागत और आधुनिक-दोनों तरीकों के साथ टेलीकास्ट किया जा रहा है।

इस खंड में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के चोटी के कलाकारों के शास्त्रीय नृत्य/संगीत के कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाते हैं। रंगमंच, साहित्य, पेंटिंग, मूर्तिकला और स्थापत्य के कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं।

यह चैनल आई जी एन सी ए, सी ई सी, इग्नू पी एस बीटी, एनसीईआरटी और साहित्य अकादमी जैसे संगठनों के सहयोग से भी कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है। यह चैनल आकाशवाणी के संगीत सम्मलेन की व्यापक कवरेज करता है। दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों के योगदान को नियमित रूप से लाइव/रिकार्डेड टेलीकास्ट किया गया।

डीडी इंडिया

डीडी इंडिया 14 मार्च 1995 को शुरू किया गया। इस चैनल के कार्यक्रम इस तरह प्रस्तुत किए जाते हैं कि विश्व को विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों को भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृश्यावली की झांकी देखने को मिले। यह चैनल हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मलयालम और तेलुगु समाचार बुलेटिन, सामयिक घटनाओं पर विशेष रूपक और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर परिचर्चा टेलीकास्ट करता रहा है। यह चैनल फीचर फिल्मों के अलावा अनेक मनोरंजन कार्यक्रम, सीरियल, रंगमंच, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी टेलीकास्ट करता है।

क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और मराठी के कार्यक्रम इस चैनल के आवश्यक संघटक हैं। इस चैनल में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं नियमित रूप से दिखाई जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह और बजट पेश करने जैसी राष्ट्रीय घटनाओं का सीधा प्रसारण किया जाता है।

डीडी-समाचार, डीडी-पंजाबी और डीडी-बांग्ला के साथ इस चैनल को अमरीका में वितरित करने के लिए वितरण भागीदार चुनने की प्रक्रिया और कनाडा में डीडी-इंडिया के लिए भागीदार चुनने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया गया है। डीडी-इंडिया सहित डीडी चैनल के वितरण के लिए अन्य देशों में भागीदारों की खोज के लिए विश्व भर में टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा

डीडी कमर्शियल सर्विस दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के लिए सामान और सेवाओं के विज्ञापनों की बुकिंग करता है। हिन्दी और अंग्रेजी विज्ञापन डीडी नेशनल और डीडी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट किए जाते हैं, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापन क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर टेलीकास्ट किए जाते हैं। विज्ञापनों की बुकिंग प्रत्यायित और पंजीकृत एजेंसियों के जरिए की जाती है। अग्रिम भुगतान

मिलने पर बिना एजेंसी कमीशन के सीधे भी बुकिंग की जाती है।

वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर 2006 तक) दूरदर्शन ने 600 करोड़ रु. की वाणिज्यिक आय अर्जित की।

विकास संचार मंडल

विकास संचार मंडल की स्थापना मार्च 2001 में सरकारी विभागों/संगठनों की संचार संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई थी। यहां कार्यक्रम तैयार करने, सृजनात्मकता को विकसित करने, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मीडिया नियोजन और कार्यान्वयन सहित सभी कार्य किए जाते हैं। इसने सरकारी विभागों/संगठनों की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मीडिया अभियान चलाए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल्याणी अभियान का लगातार चौथे वर्ष विस्तार किया गया। कल्याणी II के साथ भी ऐसा ही हुआ।

पेट्रोलियम मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना पर एक टेली ब्रिज अभियान, जिसका शीर्षक था “जन कैरोसीन परियोजना”, अक्टूबर 2005 में देश के 21 राज्यों से प्रतिक्रियाएं और उत्तर प्राप्त करके सफलतापूर्वक पूरी की गई।

केन्द्रीय कमीशनिंग यूनिट

केन्द्रीय कमीशनिंग यूनिट ने भारतीय गौरव ग्रंथ श्रृंखला के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने के लिए 15 भाषाओं में उत्कृष्ट गौरव ग्रंथ चुनने की प्रक्रिया पूरी की।

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर एक टेली फिल्म भी बनाई जा रही है।

केन्द्रीय कमीशनिंग यूनिट ने पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टिंग ट्रस्ट के सहयोग से बाजार-प्रिय कार्यक्रम तैयार करना जारी रखा।

वर्ष के दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित एक रूपक कार्यक्रम “प्रगतिशील भारत” 90 उपाख्यानों में कमीशन और राष्ट्रीय नेटवर्क में टेलीकास्ट किया गया।

दूरदर्शन अभिलेखागार

दूरदर्शन के केन्द्रीय अभिलेखागार में लगभग 70,000 घंटे के कार्यक्रम एनालोग वीडियो टेप में हैं। अब क्योंकि यह टेक्नालाजी

हटाई जा रही है, दूरदर्शन ने अपने सभी कार्यक्रमों को डिजीटल रूप में सुरक्षित करने की विस्तृत योजना तैयार की है। उसने अब तक 1400 घण्टे के कार्यक्रम को डिजीटल रूप में सुरक्षित कर लिया है। भावी कार्यक्रम में शामिल हैं :

- डिजीटल माइग्रेसन।
- ब्रॉडबैंड अभिसरण को सुसाध्य बनाना।
- कार्यक्रमों का वाणिज्यिक दोहन।
- डीवीडी/सीडी/वीसीडी का मुद्रण ताकि उन्हें ग्राहक अधिक आसानी से देख और सुन सकें।
- भारतीय संस्कृति के साधकों और युवाओं में रुचि जगाई जा सके।
- प्रवासी भारतीयों को यह सांस्कृतिक निधि उपलब्ध कराना।
- भारत और विदेशों की सांस्कृतिक संस्थाओं को हमारे महान कलाकारों का प्रदर्शन उपलब्ध कराना।

डीडी अभिलेखागार ने अब तक बाजार में 51 शीर्षक जारी किए हैं।

डीडी एमटीएनएल ब्राडबैंड परियोजना के लिए 600 शीर्षकों की पहचान की जा चुकी है। इनमें केवल सांस्कृतिक, यात्रा, व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्थानों, स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर, जीवन शैली, हस्तशिल्प विषय हैं।

श्रोता अनुसंधान

दूरदर्शन की श्रोता अनुसंधान शाखा (स्कंध) जिसे श्रोता अनुसंधान यूनिट कहा जाता है 1976 से प्रसारण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन में लगी है। इस यूनिट का कार्य व्यावसायिक अनुसंधानकर्ता संभाले हैं और इसकी देश भर में 19 क्षेत्रीय यूनिटें हैं। क्षेत्रीय यूनिटें दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बद्ध हैं और प्रशासनिक दृष्टि से अपने-अपने केन्द्रों से नियंत्रित होती हैं लेकिन तकनीकी दृष्टि से ये निदेशालय में निदेशक, श्रोता अनुसंधान से नियंत्रित होती हैं।

श्रोता अनुसंधान यूनिट ने 2005-06 के दौरान 12 स्थानों पर नेरोकास्ट कृषि कार्यक्रमों पर मूल्यांकन अध्ययन किया। इसने शहरी और ग्रामीण इलाकों में दूरदर्शन चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अपने 'डार्ट' अध्ययन भी जारी रखे।

नेरोकास्ट कृषि कार्यक्रमों पर नियमित प्रतिपुष्टि (फीडबैक) अध्ययन। जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान टीवी के प्रभाव पर एक अध्ययन इन दिनों किया जा रहा है।

आकाशवाणी

आकाशवाणी अपने विभिन्न केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सूचित एवं शिक्षित करता है और साथ ही उनका मनोरंजन भी करता है। आकाशवाणी सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी अपने विविध सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं पर आधारित कार्यक्रमों के जरिए समूचे देश की जनता तक पहुंचाता है। यह देश के सभी हिस्सों के लोगों तक ताजा घटनाक्रमों की भी जानकारी पहुंचाता है। आकाशवाणी की एक व्यावसायिक सेवा 'विविध भारती' भी है जिसमें विज्ञापनों के प्रसारण के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। खाड़ी देशों के श्रोताओं के लिए आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हैं।

(क) आकाशवाणी के नेटवर्क का विकास तथा दायरा - आजादी के बाद आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में शामिल हो चुका है। आजादी के समय भारत में छह रेडियो स्टेशन और 18 ट्रांसमीटर थे और देश की 11 प्रतिशत आबादी और 2.5 प्रतिशत क्षेत्र इनके प्रसारण के दायरे में आता था। आज इस नेटवर्क में 222 स्टेशन और 337 ट्रांसमीटर शामिल हैं और देश की 99.13 प्रतिशत जनसंख्या और 91.42 प्रतिशत क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक देश में रेडियो प्रसारण 99.49 प्रतिशत जनता तक पहुंच सकेंगे और 92.92 प्रतिशत क्षेत्र इसके दायरे में आएगा। देश के दूरस्थ क्षेत्र जिनमें मुख्यतः उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल शामिल हैं और जहां तक अभी रेडियो की पहुंच नहीं है। ऐसी जगहों पर 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटरों के साथ कम शक्ति के ट्रांसमीटर रिले केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एफ एम सेवा में उच्च क्वालिटी के कार्यक्रम देने के लिए बड़े बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है।

ख. दसवीं योजना के विशेष महत्व वाले क्षेत्र

दसवीं योजना में आकाशवाणी जिन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दे रही है वह इस प्रकार हैं :

- मीडियम वेव प्रसारण सेवा को वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जाएगा। मीडियम वेव सेवा का विस्तार केवल सामरिक दृष्टि

संलग्नक
1/2/2006

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्राइमरी चैनल (डी डी 1) ट्रांसमीटर					न्यूज चैनल ट्रांसमीटर				क्षेत्रीय चैनल ट्रांसमीटर				
		स्टूडियो	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपी	कुल	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	कुल	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	3	9	75	0	1	85	4	6	0	10	0	0	10	10
2	अरुणांचल प्रदेश	1	1	3	40	1	45	1	0	0	1	0	0	0	0
3	असम	4	3	20	1	1	25	2	1	0	3	0	0	0	0
4	बिहार	2	3	33	2	0	38	2	2	0	4	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	2	3	16	8	0	27	1	0	0	1	0	0	0	0
6	गोवा	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
7	गुजरात	2	6	54	0	0	60	4	3	0	7	0	0	3	3
8	हरियाणा	1	0	14	0	0	14	0	8	0	8	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	2	8	39	2	51	2	1	0	3	0	0	0	0
10	जम्मू-कश्मीर	3	10	8	72	1	91	5	3	0	8	4	9	17	30
11	झारखंड	2	3	17	2	0	22	2	2	1	5	0	0	0	0
12	कर्नाटक	2	8	47	0	0	55	4	2	0	6	0	0	7	7
13	केरल	2	4	20	0	0	24	3	2	0	5	0	0	4	4
14	मध्य प्रदेश	3	6	63	5	0	74	4	0	0	4	0	0	0	0
16	महाराष्ट्र	3	8	79	0		87	5	10	0	15	0	0	20	20
17	मणिपुर	1	2	1	4	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0
15	मेघालय	2	2	3	2	1	8	2	0	0	2	0	0	0	0
18	मिजोरम	1	2	1	2	1	6	1	1	0	2	0	0	0	0
19	नागालैंड	1	2	2	6	2	12	1	1	0	2	0	0	0	0
20	उड़ीसा	3	5	62		1	68	2	7	2	11	0	0	16	16
21	पंजाब	2	4	5	0	1	10	2	0	0	2	0	0	0	0
22	राजस्थान	1	6	67	17	2	92	4	4	0	8	0	0	0	0
23	सिक्किम	1	1	0	6	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	3	4	46	0	1	51	2	9	0	11	1	0	7	8
25	त्रिपुरा	1	1	5	1	1	8	1	1	0	2	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	7	11	51	3	0	65	7	11	1	19	0	0	0	0
27	उत्तरांचल	1	1	15	33	2	51	1	1	0	2	0	0	0	0
28	वेस्ट बंगाल	3	8	19	0	0	27	3	2	0	5	1	0	1	2
29	अंडमान, निकोबार द्वीप	1	0	2	11	0	13	0	1	0	1	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादर, नगर हवेली	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन द्वीव	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	8	8
35	पांडिचेरी	1	1	2	1	0	4	0	1	0	1	0	0	1	1
कुल		64	118	743	255	18	1134	69	79	5	153	6	9	94	109

नोट : इन ट्रांसमीटरों के साथ, चार महानगरों में चार डिजिटल ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं :
ट्रांसमीटरों की कुल संख्या 1400

से महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाकों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में किया जाएगा।

- एफ.एम. रेडियो प्रसारण का विस्तार कर 50 प्रतिशत जनसंख्या को इसके दायरे में लाया जाएगा।
- कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के करीब 50 प्रतिशत का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा ताकि विभिन्न माध्यमों में इस्तेमाल की जा सकने वाली कन्वर्जेंस सक्षम सामग्री उपलब्ध रहे। इससे श्रोताओं से परस्पर संवाद वाली रेडियो प्रणाली में भी मदद मिलेगी।
- आकाशवाणी सेवाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना।
- रेडियो लोक सेवा प्रसारण की अपनी भूमिका कारगर तरीके से निभा सके इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक टिकाऊ साग्री तैयार करना।

साल का संक्षिप्त लेखा-जोखा

इंजीनियरिंग

1. एफ एम ट्रांसमीटरों के साथ नए रेडियो स्टेशन मांडला, राजगढ़ और सरायपल्ली में शुरू किए गए।
2. मीडियम वेव ट्रांसमीटर का एक नया स्टेशन हिम्मतनगर में स्थापित किया गया है।
3. पोर्टब्लेयर, इम्फाल, अगरतला, शिमला, रोहतक, गोरखपुर, उदयपुर, गुलबर्गा, मदुरै और औरंगाबाद में वर्तमान स्टेशनों पर एफ एम ट्रांसमीटर शुरू किए गए हैं।
4. कोलकाता में एक नया अपलिंक स्टेशन स्थापित किया गया है और बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम और भोपाल - इन पांच शहरों में वर्तमान में चालू एनालॉग को डिजिटल प्रणाली में अपग्रेड किया जा रहा है।
5. जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में आकाशवाणी की सेवाओं के विस्तार एवं सुधार के लिए विशेष पैकेज लागू किए जा रहे हैं।

शिलांग, शिमला और कुडप्पा में चालू 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को नए उच्च तकनीक के ट्रांसमीटरों में बदल दिया गया है और दिल्ली एवं रायपुर में भी चालू ट्रांसमीटरों को बदला जा रहा है।

नया प्रसारण भवन, दिल्ली

समाचार सेवाओं के लिए पूरी तरह से डिजीटलीकृत स्टूडियो नए प्रसारण भवन में उपलब्ध है। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण तथा संस्कृति मंत्री ने 23 अगस्त 2005 को औपचारिक रूप से नए प्रसारण भवन का उद्घाटन किया। तब से प्रसारण भवन से आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवाओं और घरेलू प्रसारण सेवाओं का नियमित प्रसारण शुरू हो चुका है।

आकाशवाणी की 'फोन पर समाचार' सेवा

विश्व के किसी भी हिस्से में श्रोता अब किसी भी समय आकाशवाणी के मुख्य समाचार हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में एक निर्दिष्ट नम्बर को डायल करके सुन सकते हैं। यह सेवा अब पांच शहरों दिल्ली, मुम्बई, पटना, चेन्नई और हैदराबाद में चालू है। इस सेवा का 11 और स्टेशनों तक विस्तार किया जा रहा है।

इसके अलावा वर्ष 2005-06 के निर्धारित लक्ष्यों संबंधी परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक 1 में दी गई है।

कार्यक्रम

आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार

वर्ष 2005 में आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2004 का वितरण समारोह 5 सितंबर 2005 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। गांधी दर्शन तथा लोकसेवा प्रसारण पुरस्कार 2005 की घोषणा की जा चुकी है।

संगीत

वर्ष 2005 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन समारोह देश भर में 12 और 13 नवम्बर, 2005 को 22 स्टेशनों पर आयोजित हुए जिसमें हिंदुस्तानी तथा शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने हिस्सा लिया। समारोह में साथी कलाकारों सहित कुल 126 कलाकारों ने हिस्सा लिया।

सुप्रसिद्ध कलाकार जैसे पण्डित देबू चौधरी, पण्डित उल्हास काशलकर, पण्डित अजय चक्रवर्ती, प. भजन सोपोरी, प. कार्तिक कुमार, काला रामनाथ, पं. विद्याधर व्यास, पं. छन्नुलाल मिश्र, पं. मणिप्रसाद, पं. एल.के. पण्डित, प. यशवंत भुवा जोशी, प. अमिया राजन बनर्जी, विदुषी जया बिस्वास, नेदुनुरी कृष्णामूर्ति, एम.एस. गोपालकृष्णन, डा. पशपंचाम सीताराम, आर. वेदावल्ली, राजेश्वरी, अरुणा साईराम, चन्द्रशेखर ने समारोह में हिस्सा लिया। इन सभी

संगीत सम्मेलन समारोहों का प्रसारण 17 दिसंबर, 2005 से 29 जनवरी 2006 तक किया गया। जिसमें बारी-बारी से हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत का प्रसारण किया गया।

आकाशवाणी ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के साथ ही क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत समारोह का भी आयोजन किया। यह समारोह फरवरी 2006 में वसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया गया। कुछ चुने हुए स्थानों पर आयोजित इस समारोह में जाने-माने कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस समारोह का उद्देश्य हमारे देश की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति और उसमें बढ़ावा देना था।

मार्च 2005 के दौरान आकाशवाणी ने दिल्ली में ट्रिनिटी (TRINITY) संगीत समारोह आयोजित किया। इसमें छह जाने-माने कर्नाटक संगीत के उभरते कलाकारों - टी.एन. कृष्णन, गायत्री गिरीश, ई. गायत्री, संगीता शिवकुमार, कदरी गोपालनाथ, डी. शेषाचारी और डी राघवाचारी ने अपनी प्रस्तुति दी। संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध तथा उभरते कलाकारों में से डी.वी. मुरलीकृष्ण, डी. श्रीनिवास, आर.के. श्रीकांतन, लालगुडी श्रीमती ब्रह्मानंदन, डा. के ओमनाकुट्टी और नित्यश्री महादेवन की रिकार्डिंग प्रसारित की गई।

नई प्रतिभाओं की खोज के लिए आकाशवाणी अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता आयोजित करता है। आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता आकाशवाणी का एक नियमित कार्यक्रम है जो युवाओं तक पहुंचने और नई प्रतिभाओं को ढूंढने का सशक्त जरिया है। वर्ष 2005 के हिन्दुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की फाइनल प्रतियोगिता क्रमशः दिल्ली और चेन्नई में अक्टूबर में हुई। प्रतियोगिता के जरिए हिंदुस्तानी/कर्नाटक संगीत श्रेणी में कई नई प्रतिभाएं शामिल हुईं।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के शौकीन लोगों की मांग पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और रविवार रात्रि कार्यक्रमों की अवधि 60 मिनट से बढ़ाकर पहले की तरह 90 मिनट कर दी गई है।

फार्म एण्ड होम

आकाशवाणी की फार्म एण्ड होम इकाई समन्वित कार्यक्रम का प्रसारण करती है इसमें ग्रामीण विकास योजनाएं और कृषि से संबंधित कुछ खास किस्म के कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में कृषि से संबंधित विशेष कार्यक्रम पर वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं, जैसे पशुपालन, मछली-पालन और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप,

सूखी और बंजर भूमि में खेती। इसके अलावा दूसरे खंड में रोजगार योजनाओं ऋण और प्रशिक्षण सुविधाएं, सफाई, स्वास्थ्य-स्वच्छता और पोषण आदि से संबंधित वार्तालाप शामिल हैं।

आकाशवाणी ने कृषि प्रसारण से संबंधित अपने क्रियाकलापों में वृद्धि की है। इसके अंतर्गत उसने कृषि मंत्रालय के सहयोग से 15 फरवरी, 2004 से किसान वाणी नाम से अपना एक विशेष कृषि चैनल शुरू किया है। स्थानीय किसानों को दैनिक बाजार दरों, मौसम की जानकारी और उनके आस-पास के क्षेत्रों में निचले स्तर पर होने वाली गतिविधियों के बारे में सूचनाएं देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिलहाल आकाशवाणी के एफ.एम. स्टेशनों से इस कार्यक्रम का प्रसारण और रिले किया जाता है।

पर्यावरण

केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली पर्यावरण और वन विकास योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित रूप से किया जाता है। आकाशवाणी ने पर्यावरण, वन, वन्य-जीव और पारिस्थितिकी से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बहुभाषी प्रसारण का जरिया अपनाया है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण प्रमुख भाषाओं, स्थानीय बोलियों तथा विभिन्न छोटे-छोटे समुदायों द्वारा बोले जाने वाली आम बोल-चाल की भाषा में किया जाता है।

वन्य-जीवन और वनों के संरक्षण के महत्व को देखते हुए आकाशवाणी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है अतः इससे संबंधित गतिविधियों तथा सामाजिक अनुष्ठानों पर विशेष बल दिया जा रहा है। वन-विद्या, वन्य-जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के क्षेत्र में सरकार द्वारा की जाने वाली पहल की सफलताओं को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसके लिए आकाशवाणी अपने विभिन्न विशेष श्रोता कार्यक्रमों में वन्य जीवन और पशुओं से संबंधित देखभाल के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ विशेष कार्यक्रम निर्मित और प्रसारित किए जाते हैं। कुछ स्टेशनों द्वारा रोजाना 'वसुंधरा कार्यक्रम' प्रसारित किया जाता है। ग्रामीण/महिला ग्रामीण महिलाएं एवं युवा स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे अपने विशेष श्रोता के कार्यक्रम में हमने श्रोताओं की टोलियों को पंजीकृत किया है। लोगों में जनजागृति पैदा करने के लिए इन श्रोताओं से मदद ली जाती है।

आकाशवाणी के सभी केंद्र पर्यावरण और वन प्रबंधन से संबंधित कानूनी विषयों का व्यापक प्रचार एवं प्रसार करते हैं। इस संबंध में सभी केंद्रों से हर महीने सूचनाएं एकत्रित करके इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।

परिवार कल्याण

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा देश की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में किया जाता है।

आकाशवाणी के केंद्र हर महीने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित 15 हजार से अधिक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिसकी अवधि लगभग 25 हजार मिनट की होती है। ये कार्यक्रम सामान्य एवं विशेष श्रोता कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किए जाते हैं जैसे ग्रामीण, महिलाएं/बाल एवं आम श्रोता कार्यक्रम आदि। इन कार्यक्रमों का प्रसारण विभिन्न रूपों में होता है जैसे वार्ता, विचार-विमर्श, फीचर, जिंगल्स, स्पॉट, कहानियां, नाटक, सफलता की कहानियां, फोन से संपर्क कार्यक्रम आदि। इसके अलावा आकाशवाणी के शेष केंद्र जिसमें स्थानीय केंद्र भी शामिल हैं अपनी-अपनी विषय-वस्तु पर नियमित रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इस विषय-वस्तु में विवाह की आयु में वृद्धि, पहला बच्चा देरी से, दो बच्चों के जन्म की अवधि में अंतर, गर्भपात के तरीके, मां की देखभाल, शिशुओं की देखभाल, महिलाओं का सशक्तिकरण, पति-पत्नी के बीच बेहतर समझ/पिता के दायित्व, बेटा पाने की अदम्य इच्छा को निरूत्साहित करना, चिकित्सा, गर्भपात, संस्थागत कानूनी प्रावधानों को प्रोत्साहन, यौन रोगों की रोकथाम, जन्म से पूर्व बच्चे के लिंग का निर्धारण (दुरुपयोग की रोकथाम एवं नियमन) कानून-1994, एड्स, नशीले पदार्थों का सेवन, ड्रग्स, स्तनपान, बच्चे का अधिकार, बाल मजदूरी, बालिका, विकलांगता, टी.बी., कुष्ठरोग और जननीय बाल स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।

रक्तदान और नेत्रदान जैसे कार्यक्रमों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन, तम्बाकू सेवन, वेश्यावृत्ति, कुष्ठ निवारण और एड्स आदि बुराईयों से दूर रहने के लिए भी समुचित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आकाशवाणी का हर केंद्र सप्ताह में एक दिन 15 मिनट की अवधि का स्वास्थ्य मंच (हेल्थ फोरम) कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसमें श्रोताओं को सामान्य बीमारियों और रोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित किया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो आकाशवाणी के साथ बराबर संपर्क में रहता है और उसे वह संदर्भ सामग्री तथा अपनी विशेष सलाह उपलब्ध कराता है। परिवार कल्याण पर बेहतर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए हर साल आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (नेशनल रूरल हेल्थ मिशन)

आकाशवाणी के चुने हुए 18 केंद्रों से इस साल 15 सितम्बर 2005 से 15 मिनट के साप्ताहिक कार्यक्रम निर्मित और प्रसारित किए गए। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित केंद्रों से प्रसारित हुए - बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नगालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर)।

बाल कार्यक्रम

आकाशवाणी तीन वर्गों के बच्चों के लिए अपने लगभग सभी केंद्रों से कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ये कार्यक्रम 5 से 7 वर्ष और 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रसारित किए जाते हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए अलग से विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है।

बालिकाओं के जन्म को महत्व और प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम विचार-विमर्श, वार्ता, कहानियां, जिंगल्स, स्पॉट आदि के रूप में हमेशा नियमित अवधि पर प्रसारित होते रहते हैं। इसके जरिए पूरे साल लोगों में यह जन-जागृति पैदा की जाती है कि लड़के के बजाए लड़की के जन्म को महत्व दें।

कुछ कार्यक्रम साप्ताहिक रूप से प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों को नाटकों, कहानियों, फीचर, समूहगान, साक्षात्कार और प्राचीन ग्रंथों से ली गई कथा-कहानियों के रूप में प्रसारित किया जाता है।

ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम

आकाशवाणी के जिन केंद्रों में 'फार्म एण्ड होम' ईकाईयां हैं, वहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सप्ताह में एक बार बच्चों को भी भाग लेने का मौका दिया जाता है, चाहे उनकी शैक्षणिक और साक्षरता की योग्यता कुछ भी क्यों न हो। इसमें किशोरवय के बच्चे के लिए भी कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। किशोरों के लिए सभी कार्यक्रमों में सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित संदेशों को विशेष रूप से स्थान दिया जाता है।

नन्हें-मुन्नों के लिए कार्यक्रम (5-7 वर्ष)

यह कार्यक्रम सप्ताह में एक बार प्रसारित होता है तथा कम अवधि का होता है। इन कार्यक्रमों में नाटक, फीचर, समूहगान, साक्षात्कार,

यात्रा संस्मरण, प्राचीन ग्रंथों की कहानियां तथा विभिन्न प्रदेशों की कथाओं से संबंधित सामग्री होती है। ऐसे कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समूहगान, कहानियों और नाटकों आदि में नन्हें-मुन्नों के अधिकारों से संबंधित चीजों को विशेष महत्व दिया जाता है तथा बच्चों से साक्षात्कार भी प्रसारित किए जाते हैं। इनमें मुक्त जीवन एवं स्वस्थ विकास और स्वच्छ वातावरण का आनंद लेना तथा परिवार कल्याण के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में भाग लेना आदि गतिविधियों के बारे में बच्चों और बड़ों के बीच वार्तालाप प्रसारित किए जाते हैं।

महिला कार्यक्रम

आकाशवाणी के केंद्रों से ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए ऐसे समय पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो संबंधित वर्गों की महिलाओं के लिए सुविधाजनक हो। महिला श्रोताओं के लिए प्रसारित होने वाले इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है - महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं पोषण, वैज्ञानिक रूप से घर का रख-रखाव, महिला उद्यमी, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और महिलाओं से संबंधित मुद्दे आदि। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सामाजिक चेतना पैदा करना भी है जिसे कानूनी शिक्षा के जरिए प्रचारित-प्रसारित किया जाता है।

महिलाओं के प्रति देश की सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास करता रहता है। इसके लिए ग्रामीण महिला श्रोताओं के साथ विशेष रूप से संपर्क कायम करने के लिए विभिन्न पारंपरिक लोक कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ पूरे वर्ष भर के लिए मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान घर और घर से बाहर महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित माहौल बनाने तथा महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण पैदा करने के लिए शुरू किए गए हैं। महिलाओं के प्रति सामाजिक रुख और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विशेष कार्यक्रम तथा आम श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुखों के समय-समय पर यह दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं कि वे महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार करें जिनमें महिलाओं के सशक्तीकरण तथा उनकी समस्याओं से संबंधित सामाजिक मुद्दे शामिल हों।

आकाशवाणी ने इस वर्ष के दौरान कुछ चुनी हुई विषयवस्तु पर कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जिनमें महिलाओं का आर्थिक अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और महिलाओं पर होने वाले अधिकार तथा उनकी कठिन परिस्थितियों से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

एड्स/एच.आई.वी. कार्यक्रम

आकाशवाणी ने देश भर में फैले अपने विभिन्न केंद्रों के जरिए, विभिन्न भाषाओं और बोलियों में एच.आई.वी./एड्स के बारे में लगातार कार्यक्रम प्रसारित किए।

इस समय आकाशवाणी से एड्स पर **जीवन है अनमोल** शीर्षक से एक शृंखला प्रसारित की जा रही है। यह आकाशवाणी के 76 प्राइमरी चैनलों पर प्रसारित हो रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम 31 मार्च, 2005 तक प्रसारित होगा।

स्वास्थ्य युवा, बाल कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, ग्रामीण महिलायें, औद्योगिक मजदूर और ग्रामीण कार्यक्रमों में प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में **जिओ और जीने दो** (लिव एण्ड लेट लिव) के नारे और विषयवस्तु पर व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श हुआ है। एड्स पर हर साल सबसे अधिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिनमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि समुचित ज्ञान और जानकारी के बल पर एड्स की रोकथाम की जा सकती है।

विज्ञापन

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में नियमित रूप से प्रचार-प्रसार किया जाता है जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है : 1. रोजगार के अवसर, 2. कृषि उत्पादन में वृद्धि, 3. शिक्षा, 4. स्वास्थ्य, 5. महिला और बच्चे 6. खाद्य और पोषण, 7. पंचायती राज, 8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 9. सामाजिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों का कल्याण 10. उद्योग, 11. बुनियादी ढांचे का विकास, 12. जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्यों का विकास। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं, जैसे रोजगार गारण्टी योजना, जन किरासिन परियोजना आदि के बारे में जो प्रचार-प्रसार किया गया वह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सूचना के अधिकार का कानून 2005 अमल में आने के बाद इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया। आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुखों को यह हिदायत दी गई कि इस कार्यक्रम के प्रमुख बिन्दुओं को विशेष रूप से प्रचारित-प्रसारित करें। दहेज विरोधी साक्षरता के

बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार किया गया है।

पटाखों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगाये जाने वाले प्रतिबंध को लागू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में जो निर्णय दिया, आकाशवाणी के सभी केंद्रों ने उसे प्रसारित किया।

विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सालाना कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी प्रचार किया गया। इसमें विदेश मंत्रालय ने फरवरी 2005 में संभावित यात्रियों से आवेदन आमंत्रित किया था।

आकाशवाणी के सभी केंद्रों ने विश्व पर्यटन दिवस से संबंधित समारोहों को प्रसारित किया। इस संबंध में आयोजित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए कवरेज की सुविधा प्रदान की गई।

उपभोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करके राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विशेष रूप से प्रचार-प्रसार किया गया।

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की कई अन्य योजनाओं और नीतियों को जनहित में तथा उस समय प्रसारित किया गया जब उन्हें प्रसारित करने के लिए अनुरोध किया गया।

व्याख्यान कार्यक्रम

इस वर्ष नई दिल्ली में 25 अक्टूबर 2005 को अंग्रेजी में **सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान** का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया ने **इंडिया 2020: दी नेक्सट ट्रायस्ट वीद डेस्टनी** विषय पर अपना व्याख्यान दिया। इसकी रिकार्डिंग 31 अक्टूबर 2005 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर प्रसारित की गई।

सर्व भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन 1956 से किया जा रहा है इसमें संस्कृत सहित 22 भारतीय भाषाओं में कविताएं शामिल की जाती हैं। इन कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और सृजनात्मकता की आवाज बड़े ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त होती हैं। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम आम तौर पर जनवरी के महीने में आयोजित होता है और इसका प्रसारण हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय हुक-अप पर किया जाता है। आकाशवाणी के लगभग सभी केंद्रों द्वारा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। पिछले वर्ष सर्व भाषा कवि सम्मेलन गणतंत्र दिवस 2006 से पूर्व किया गया।

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा रोजाना 81 भाषाओं/बोलियों (देशी और विदेशी) में 360 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। इनके जरिए देश भर में और विदेशों में लोगों को सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाती है।

समाचार बुलेटिन

आकाशवाणी का देशीय, क्षेत्रीय और विदेश समाचार सेवा प्रभाग, दिल्ली से तथा देश भर में फैली 44 अन्य क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के जरिए, 44 घंटे से अधिक की अवधि का समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। दिल्ली से देशीय सेवा (होम सर्विस) में 75 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। समाचार सेवा प्रभाग की क्षेत्रीय समाचार इकाइयां अपनी क्षेत्रीय सेवा में रोजाना 66 भाषाओं/बोलियों में 24 घंटे से अधिक की अवधि के 225 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करती हैं। इसमें एफ.एम. रेडियो रेनबो चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले न्यूज हेडलाइन बुलेटिन तथा एफ.एम. गोल्ड चैनल द्वारा खास तौर पर प्रसारित कुछ बुलेटिन भी शामिल हैं। आकाशवाणी की विदेश सेवा द्वारा 26 भाषाओं (भारतीय और विदेशी) में 65 समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं जो कुल लगभग 9 घंटे के होते हैं। इनके अलावा समाचार सेवा प्रभाग अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में समाचार आधारित अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

फोन पर समाचार

दिल्ली में आकाशवाणी की 'फोन पर समाचार' सेवा देश और विदेश में स्थित श्रोताओं के लिए फोन पर अंग्रेजी और हिंदी में ताजा समाचारों की जानकारी देता है। यह समाचार फोन पर विशेष नम्बर डायल करके सुने जा सकते हैं। फोन पर समाचार सेवा तमिल में उपलब्ध है जो चेन्नई स्थित क्षेत्रीय समाचार ईकाई द्वारा प्रसारित की जाती है। हैदराबाद से तेलुगु में, मुम्बई से मराठी और पटना से हिंदी में भी यह सेवा उपलब्ध है। इस सेवा को रायपुर, लखनऊ, बंगलौर, शिमला, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इफाल, जयपुर और तिरुवनंतपुरम से भी शुरू किया जा रहा है।

इंटरनेट पर आकाशवाणी के समाचार

आकाशवाणी के समाचार इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। इसकी अधिकृत वेबसाइट है : www.newsonair.com बड़ी संख्या में श्रोता इस सेवा का लाभ उठाते हैं।

इस वर्ष जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वह यह था कि समाचार बुलेटिनों को वेबसाइट पर सुनने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वेबसाइट पर हर घंटे 5 मिनट की अवधि के बुलेटिन उपलब्ध कराये जाते हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं तथा इन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। प्रमुख समाचार बुलेटिन 08:15 बजे, 14:00 बजे और 21:00 बजे प्रसारित किए जाते हैं। नेट पर केवल मुख्य समाचार उपलब्ध कराए जाते हैं।

समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट पर आकाशवाणी के संवाददाताओं की डिसपैच की आडियो, प्रमुख समाचारों के आलेख के साथ उपलब्ध होती है।

समसामयिक मामलों पर विशेष कार्यक्रम 'स्पॉटलाइट' भी वेबसाइट पर सुनी जा सकती है।

दूसरी जो बड़ी पहल थी, वह थी वेबसाइट पर देवनागरी में हिंदी समाचार बुलेटिन का अभिलेख उपलब्ध कराना। वेबसाइट पर हिंदी समाचारों की हेडलाइन भी उपलब्ध होती है और हर घंटे अपडेट की जाती है।

भारत-श्रीलंका और भारत-दक्षिण अफ्रिका के बीच खेली गयी एक-दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का स्कोर भी वेबसाइट पर दिया गया। हर पांच से दस मिनट के अंतर पर इस स्कोर को अपडेट किया जाता था।

इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अब जल्द ही क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट पर सुन सकेंगे।

इस कार्य के लिए आवश्यक आधारभूत कार्यवाही पूरी कर ली गयी है। आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के बुलेटिन डी टी एच के जरिये डाउनलॉक किये जाएंगे और उन्हें उन प्रवासी भारतीयों के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय खबरें सुनने के इच्छुक हैं।

समाचारों पर आधारित कार्यक्रम

समाचार सेवा प्रभाग द्वारा दिल्ली और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से समाचार आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं। दिल्ली से शुक्रवार को रात साढ़े 9 बजे अंग्रेजी में 'करेंट अफेयर्स' कार्यक्रम प्रसारित होता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम बुधवार को रात साढ़े 9 बजे हिंदी में 'चर्चा का विषय है' प्रसारित होता है। दिल्ली से रोजाना 'सामयकी' और 'स्पॉटलाइट' भी प्रसारित होता है। दिल्ली से एफ एम गोल्ड पर रोजाना सुबह और शाम को हिंदी और

अंग्रेजी में तीस-तीस मिनट की अवधि के कार्यक्रम विशेष रूप से प्रसारित किये जाते हैं। इसमें सुबह हिंदी में 'समाचार सवेरा' और अंग्रेजी में 'ब्रेकफास्ट न्यूज' तथा शाम को 'समाचार संध्या' हिंदी में प्रसारित होता है। एफ एम गोल्ड से **मार्केट मंत्र** और (व्यापार पत्रिका), और **स्पोर्ट्स स्कैन** नाम से विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाले मार्केट मंत्र कार्यक्रम में जनता की भागीदारी भी शामिल की गयी है। इसमें स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ जनता द्वारा आर्थिक विषयों पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देते हैं। एफ एम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले अन्य समाचार आधारित कार्यक्रमों में 'करस्पॉण्डेंट कार्नेर', 'वाद संवाद', 'कंट्रीवाइड' और 'सुर्खियों से परे' शामिल है।

संसद समाचार

संसद-सत्र के दौरान चलनेवाली संसद की कार्यवाही की कवरेज की जाती है। इसमें रोजाना प्रसारित होनेवाली समीक्षा, अंग्रेजी में 'टुडे इन पार्लियामेंट' और हिंदी में 'संसद समीक्षा' के दो भाग होते हैं, एक लोकसभा की कार्यवाही का और दूसरा राज्य सभा की कार्यवाही। हर सप्ताह अंग्रेजी में प्रसारित होने वाली समीक्षा 'दिस वीक इन पार्लियामेंट' और हिंदी में 'इस सप्ताह संसद में' दोनों सदनों में पूरे सप्ताह चलने वाली कार्यवाही की मुख्य झलकियों की समीक्षा की जाती है। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां भी, राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही की रोजाना और साप्ताहिक समीक्षा प्रसारित करती हैं।

भाषाई इकाइयों का स्थानांतरण

समाचार सेवा प्रभाग के मुख्यालय से तीन भाषा इकाइयों को क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में स्थानांतरित किया गया है। तेलुगु इकाई 1 अप्रैल 2005 से हैदराबाद ले जायी गयी है। इसके बाद कन्नड़ इकाई को बंगलौर और धारवाड़ तथा सिंधी इकाई अहमदाबाद स्थानांतरित की गयी है। भाषाई समाचार बुलेटिन अब क्षेत्रीय समाचार इकाइयों को स्थानांतरित किये गए हैं क्योंकि दिल्ली के मुकाबले क्षेत्रीय केंद्रों में संबंधित भाषाओं की ज्यादा प्रतिभाएं उपलब्ध हैं। यह स्थानांतरण आकाशवाणी की उस योजना के अनुरूप है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय केंद्रों से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों का विस्तार किया जाना है तथा इसके लिए व्यावसायिक और विज्ञापन के पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है।

पहल

समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी के एफ एम ट्रांसमीटरों से समाचार और समाचारों पर आधारित कार्यक्रमों के प्रसारण के सुझाव पर काम

कर रहा है। दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार के बीच सामंजस्य बैठाने की कार्यवाही पर काम पूरा कर लिया गया है। इंटरनेट चैनल भी शुरू करने का सुझाव विचाराधीन है। समाचार सेवा प्रभाग द्वारा उद्घोषणा के स्वरूप में परिवर्तन, सिगनेचर ट्यून में परिवर्तन और विशेष श्रोता समूह को लक्ष्य करके नये कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है तथा इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है।

कवरेज

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने वर्ष 2005 के दौरान सभी प्रमुख घटनाओं पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। समाचार सेवा प्रभाग ने हिंदी में 'कहिये मंत्रीजी' और अंग्रेजी में 'टेल अस् मिनिस्टर' शीर्षक से विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण केंद्र में यू.पी.ए. सरकार के एक वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में किया गया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों से लिए गए साक्षात्कार पर आधारित था। जिन मंत्रियों से साक्षात्कार लिया गया उनमें निम्नलिखित शामिल थे : वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, योजना आयोग के अध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पंचायत राज मंत्री मणिशंकर अय्यर तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दयानिधि मारन।

सितंबर 2005 के दौरान समाचार सेवा प्रभाग ने अपने समाचार बुलेटिनों में जिन खबरों को प्रमुखता दी उनमें प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह की एक सप्ताह की फ्रांस, अमरीका यात्रा और विश्व के नेताओं से उनकी बातचीत तथा न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण अधिवेशन में उनका भाषण। प्रधानमंत्री की यात्रा की व्यापक कवरेज करने के लिए आकाशवाणी के संवाददाताओं की टीम को विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। इस यात्रा से संबंधित खबरों पर आधारित कार्यक्रमों के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में डा. मनमोहन सिंह के भाषण का 'लाईव' प्रसारण किया गया।

जम्मू और कश्मीर में बचाव और राहत कार्यों की कवरेज बड़े पैमाने पर की गयी। इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर खोले गये राहत केंद्रों की कवरेज के लिए आकाशवाणी के संवाददाताओं ने दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा की और वहां से समाचारों के डिस्पैच भेजे। इसके अतिरिक्त नैशनल और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय हुक-अप पर भी इस विषय से संबंधित समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित किये गए।

अन्य प्रमुख घटनाक्रम जो आकाशवाणी से प्रसारित किए गए :

- बिहार में हुए विधानसभा चुनाव।
- जम्मू और कश्मीर में आए भूकम्प से पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास हेतु बड़े पैमाने पर चलाए गए कार्यक्रम।
- जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर राहत शिविरों का खुलना।
- श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच ऐतिहासिक बस सेवा का प्रारंभ।
- भारत और पाकिस्तान के बीच मई तथा सितम्बर 2005 में हुई वार्ता।
- प्रधानमंत्री की फ्रांस तथा अमरीका की एक सप्ताह की यात्रा और न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन सत्र में उनका अभिभाषण।
- जकार्ता में अफ्रो-एशियाई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अधिवेशन में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का भाषण।
- यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की रूस की चार दिन की यात्रा।
- प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य जिसमें बुश ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति सम्पन्न देश के रूप में मान्यता दी और अन्य चीजों के अलावा तारापोर परमाणु प्लांट को ईंधन आपूर्ति जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई।
- प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधन, जिसमें उन्होंने सभी तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत और अमरीका के एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया।
- भारत और अमरीका ने सैन्य, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- गुप-8 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए डा. मनमोहन सिंह की स्काटलैंड यात्रा।
- प्रधानमंत्री की रूस यात्रा और मास्को में उनका विश्व नेताओं से विचार-विमर्श।

- डा. मनमोहन सिंह की रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और दोनों देशों ने असैनिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने की इच्छा जाहिर की।
- महत्वपूर्ण विदेशी व्यक्तियों जिनमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कोफी अन्नान, चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन जिआबाओ और जापान के प्रधानमंत्री श्री जूनिचिरो कोईजुमी शामिल हैं, की भारत यात्रा।
- राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की चार देशों - रूस, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और यूक्रेन की यात्रा।
- स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश।
- स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का राष्ट्र को संबोधन।
- राष्ट्रपति द्वारा जाने-माने 96 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा।
- डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा वर्ष 2004 के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करने और फिल्म निर्देशक अदूर गोपालकृष्णन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा।
- कैसर विशेषज्ञ डा. वी. शांता को जनसेवा हेतु प्रतिष्ठित मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाना।
- ढाका, बांग्लादेश में सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा भाग लेना।
- प्रधानमंत्री द्वारा यूपीए सरकार का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह में अपनी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाली 42 पृष्ठों की एक पुस्तिका का विमोचन और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा इसी समारोह में दिया गया वक्तव्य कि सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वायदों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
- प्रधानमंत्री द्वारा मद्रुरै में 2400 करोड़ रुपये की लागत की सेतुसमुद्रम चैनल परियोजना का शिलान्यास।
- पांच वर्षों में सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का शुभारम्भ।
- संरचनात्मक ढांचे पर कैबिनेट समिति द्वारा दस हजार करोड़ रुपये की एस पी वी परियोजना को मंजूरी।
- केंद्र द्वारा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र राज्य के लिए 700 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा।
- दिल्ली में एक के बाद एक हुए कई बम धमाकों में 60 से अधिक लोगों की मृत्यु।
- संसद के मानसूत्र सत्र की कवरेज।
- केंद्र द्वारा भारत निर्माण योजना के तहत ग्रामीण संरचनात्मक ढांचे के लिए एक लाख 74 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का अनुमोदन।
- संसद में रोजगार गारंटी विधेयक, महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा विधेयक और हिंदू दत्तक (संशोधन) विधेयक आदि जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित।
- केंद्र द्वारा दसवीं योजना का मध्यावधि आकलन अनुमोदित।
- कार्टोसेट-I (CARTOSAT) तथा हेमसेट (HAMSAT) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण।
- जर्मनी में आयोजित पुरुष शतरंज क्लासिक 2005 प्रतियोगिता में विश्वनाथन आनंद की जीत।
- गोवा ने चौथी बार संतोष ट्राफी फुटबाल चैम्पियनशिप जीती।
- दिल्ली हाफ मैराथन दौड़।
- महेश भूपति और उनकी स्लोवाकियाई पार्टनर डानिएला हंतुचोवा ने अमरीकी ओपन मिक्स्ट डब्ल्स खिताब जीता और सानिया मिर्जा अमरीकी ओपन सिंगल्स में चौथे दौर में पहुंची।
- भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट क्रिकेट श्रृंखलाएं जीतीं।
- श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला।

आगामी कवरेज

31 मार्च, 2006 से पहले जिन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद हैं, वे हैं :- संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी 2006 में हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, गणतंत्र दिवस समारोह, संसद का बजट सत्र जिसमें वर्ष 2006-07 के लिए रेल बजट और केन्द्रीय बजट शामिल है, पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, भारत और श्रीलंका तथा भारत और द. अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय तथा टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला आदि। नववर्ष की पूर्व संध्या पर वर्ष भर के कार्यक्रमों

के लेखाजोखा पर एक विशेष कार्यक्रम “वर्ष समापन समीक्षा” (ईयर एंड रिव्यू) प्रसारित किया गया जिसमें वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दी गई।

श्रोता अनुसंधान गतिविधियां 2005-06

श्रोता अनुसंधान एक लक्षित श्रोताओं, उनकी आवश्यकताओं, वरियताओं आदि का अध्ययन करके प्रभावशाली तथा श्रोताओं की पसंद के रेडियो कार्यक्रम तैयार करने के लिए शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों की लोकप्रियता जानने के लिए यह एकक देशव्यापी सर्वेक्षण कराता है जिससे मार्केटिंग डिवीजन को एयरटाइम बेचने में मदद मिलती है। साथ ही, हाल ही में महानिदेशालय की श्रोता अनुसंधान इकाई ने राज्य सरकार के विभागों और भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा आयोजित एक प्रभाव अध्ययन शुरू किया है।

वर्ष 2005-2006 में श्रोता अनुसंधान एकक ने निम्नलिखित अध्ययन किए :

1. देश भर में 63 स्थानों पर रेडियो कार्यक्रमों के श्रोताओं का अध्ययन।
2. आकाशवाणी के प्रस्तावित 24 घंटे के समाचार चैनल को शुरू करने के पहले बाजार सर्वेक्षण।
3. देश भर में 29 स्थानों पर आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा से प्रसारित रेडियो कार्यक्रमों का श्रोता सर्वेक्षण।
4. देश भर में 87 स्थानों से प्रसारित ‘कृषि वाणी चैनल’ के जरिए होने वाले कृषि विस्तार संबंधी प्रसारणों को जनसंचार मदद पर सर्वेक्षण जिसे कृषि एवं सहभागिता मंत्रालय ने प्रायोजित किया।
5. आकाशवाणी के एफ.एम. चैनलों पर चार मेट्रो शहरों में सर्वेक्षण।
6. सुनामी आपदा के समय रेडियो की भूमिका पर सर्वेक्षण।
7. पी सी आर ए द्वारा चलाए जा रहे अभियान “बूंद बूंद की बात” का व्यापक से अध्ययन।
8. क्रिकेट कमेंट्री फोन से सर्वेक्षण।
9. फ्रेंच और विम्बलडन ओपन टेनिस चैम्पियनशिप के रेडियो प्रसारण पर फोन से सर्वेक्षण।
10. आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर सर्वेक्षण।

श्रोताओं में वृद्धि			
(रेडियो सुनने वालों का प्रतिशत)			
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	कुल
1997-98	49	46	47
1998-99	56	44	50
2000-2001	52	49	51
2001-2002	53	48	51
2002-2003	58	48	53
2003-2004	55	53	54
2004-2005	56	55	56

विकास, गतिविधियां और नई पहल

1. जम्मू और कश्मीर में रेडियो कवरेज का विस्तार - जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो के दायरे के विस्तार की एक विशेष योजना लागू की जा रही है। श्रीनगर में चालू 200 किलोवाट के ट्रांसमीटर के स्थान पर 300 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया गया है और कटुआ में 6 किलोवाट के ट्रांसमीटर को बदलकर 10 किलोवाट का एफ एम ट्रांसमीटर लगा दिया गया है। नौशहरा, कुपवाड़ा, राजौरी, दिसकिट, खलसी, न्योमा, द्रास, तेसुरू और पादुम में रिले स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कारगिल में 200 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया गया है।

2. उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रेडियो कवरेज का विस्तार

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रेडियो के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। शिलांग, इम्फाल, अगरतला और आइजोल में स्टीरियो प्लेबैक सुविधा के साथ एफ.एम. चैनल शुरू किए जा चुके हैं और कोहिमा एवं इटानगर में एफ.एम. चैनल शुरू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

गुवाहाटी, इटानगर और शिलांग में चालू अपलिक सुविधाओं को डिजीटल अपलिक प्रणाली में अपग्रेड कर दिया गया है। त्रिपुरा में लोंगथेरी और धर्मनगर में नए रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

शिलांग में चालू 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की जगह उच्च तकनीक युक्त नया ट्रांसमीटर लगाया गया है। जोरहाट में वर्तमान 10 किलोवाट एफ एम ट्रांसमीटर की जगह नया ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

पूर्वोत्तर पैकेज - विशेष पैकेज के पहले चरण के लिए 24.80 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए और इसमें छह परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं हैं - इटानगर, गुवाहाटी तथा शिलांग में वर्तमान अनालॉग अपलिंक प्रणाली को डिजिटल प्रणाली में अपग्रेड करना और इटानगर, कोहिमा तथा पोर्ट ब्लेयर में 10 किलोवाट एफ एम ट्रांसमीटरों को अपग्रेड करना। कोहिमा को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कोहिमा में अभी एक किलोवाट का सेट अस्थाई रूप से उपलब्ध है और 10 किलोवाट का स्थायी सेट इस वित्त वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। विशेष पैकेज के चरण II के तहत 145.75 करोड़ रुपये दिए जाने हैं जिसके लिए सी सी ई ए का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

3. तकनीक : डिजिटल प्रसारण की ओर - प्रभावी इंजीनियरिंग आधारभूत ढांचे के निर्माण के बाद, आकाशवाणी अब आधुनिकीकरण और तकनीकी उच्चीकरण की तरफ बढ़ रहा है। आकाशवाणी ने निर्माण तथा प्रसारण दोनों क्षेत्रों में डिजिटलीकरण का एक बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। कई रेडियो स्टेशनों पर एनालॉग उपकरणों की जगह अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण लगाए गए हैं। आकाशवाणी के 141 केंद्रों पर कम्प्यूटर आधारित रिकार्डिंग, सम्पादन तथा प्लेबैक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

डिजिटल केप्टिव भू-केंद्र (अपलिंक) - दसवीं योजना में वर्तमान एनालॉग अपलिंक तथा डाउनलिंक सुविधाओं को डिजिटल प्रणालियों में बदला जा रहा है। रांची, रायपुर, जालंधर, अल्मोड़ा और कोलकाता में नए डिजिटल अपलिंक स्टेशन स्थापित किए गए हैं। साथ ही, गुवाहाटी, शिलांग, इटानगर, लखनऊ, श्रीनगर, पटना, जयपुर, कटक, शिमला, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर और भोपाल में वर्तमान अपलिंक प्रणालियों को डिजिटल प्रणालियों में अपग्रेड किया गया है। दिल्ली तथा मुंबई में भी वर्तमान में चालू अपलिंक प्रणालियों को अपग्रेड किया जा रहा है जो इस वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा।

डिजिटल डाउनलिंक

डाउनलिंक सुविधाएं कई चरणों में डिजिटलकृत की जाती हैं। 53 स्टेशनों पर डिजिटल डाउनलिंक उपलब्ध कराए जा चुके हैं जबकि चालू वित्त वर्ष में 115 और स्टेशनों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आकाशवाणी, लेह में नया स्टीरियो स्टूडियो

आकाशवाणी के लेह केंद्र पर एक नया स्टीरियो स्टूडियो बनाने की योजना है जहां संगीत, ड्रामा, वार्ता और ट्रांसमीशन स्टूडियो सहित

डबिंग तथा सम्पादन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने की कगार पर है।

एफ एम सेवाओं का विस्तार

एफ एम प्रसारणों की उच्च क्वालिटी की वजह से देश में यह प्रसारण काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने एफ एम स्टेशनों के नेटवर्क की विस्तार योजना हाथ में ली है। जिसके तहत चालू दसवीं योजना के अंत तक करीब 50 प्रतिशत जनसंख्या तक एफ. एम. नेटवर्क की पहुंच होगी।

5. नेटवर्क का कम्प्यूटरीकरण

आकाशवाणी की विभिन्न इकाइयों की क्षमता सुधारने और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कई साफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। वर्ष की गतिविधियां इस प्रकार रहीं :

- आकाशवाणी की ऑनलाइन सूचना प्रणाली के लिए साफ्टवेयर।
- रायल्टी की भुगतान प्रणाली के लिए साफ्टवेयर।
- स्टेशनों को प्राप्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करना।

मुख्यालय पर वेब आधारित ई-मेल सेवा शुरू की गई है। सभी स्टेशनों तथा निदेशालयों को कार्पोरेट पहचान के साथ ई-मेल खाता उपलब्ध कराया गया है। (XYZ@air.org.in)

दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित ऐसे 38 आकाशवाणी केंद्रों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जहां पहले कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं थे।

मुख्यालय पर लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) स्थापित और आधुनिकतम डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए। बी.एस.एन.एल. के सभी सर्किलों में फोन पर समाचार (न्यूज ऑन फोन) सेवा के लिए बी एस एन एल के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोई भी सब्सक्राइबर (subscriber) 125800/125900 डॉयल करने पर निकटतम रेडियो न्यूज ऑन फोन सर्वर से समाचार सुन सकता है।

आकाशवाणी 'रिसोसिस की' गतिविधियां

आकाशवाणी ने प्रसारण के क्षेत्र में सलाह और टर्नकी समाधान के लिए अपनी वाणिज्यिक शाखा "आकाशवाणी रिसोसिस" शुरू की है। इसकी वर्तमान गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है -

यह देश में 40 स्थानों पर इग्नू को उसके ज्ञानवाणी स्टेशनों के लिए एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु टर्नकी समाधान उपलब्ध करा

रहा है। भूमि, इमारत तथा टॉवर जैसी आधारभूत सुविधाएं ज्ञान वाणी स्टेशनों को किराए पर उपलब्ध कराई गई हैं।

16 ज्ञानवाणी चैनल पहले से चालू है। चालू वित्त वर्ष में 8 और स्टेशन आरम्भ होने की उम्मीद है। इस तरह इस वर्ष के अंत तक 24 ज्ञानवाणी स्टेशन चालू हो जाएंगे इसने अब तक कमीशन किए गए सभी ज्ञानवाणी स्टेशनों के कार्यान्वयन और रखरखाव का कार्य भी अपने हाथों में ले लिया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की चरण-1 योजना के तहत बी एस एन एल और निजी प्रसारणकर्ताओं को मूलभूत सुविधाएं जैसे भूमि, भवन तथा टॉवर किराए/ लाइसेंस फीस के आधार पर दिए गए हैं। इसके अलावा 91 शहरों में प्रस्तावित योजना के चरण II के तहत इन मूलभूत सुविधाओं को बांटने पर भी जोर दिया गया है। मोबाइल आपरेटरों को मूलभूत ढांचा भी किराये पर दे दिया गया है।

वर्ष 2005-2006 में नवंबर तक आकाशवाणी रिसॉसिस ने करीब 5 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)

आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरी कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं दिल्ली स्थित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) और भुवनेश्वर तथा शिलांग सहित क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरी की जाती हैं।

1. कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) दिल्ली

1948 में स्थापित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनकर उभरा है। संस्थान में एक सुसज्जित पुस्तकालय और उन्नत मल्टी मीडिया उपकरणों से लैस एक कम्प्यूटर केंद्र उपलब्ध है। संस्थान विभागीय उम्मीदवारों तथा समान सेवा प्रदान करने वाले विदेशी संगठनों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। विभिन्न फील्ड कार्यालयों में कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। यह संस्थान सीधे भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरी सहायकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, और अधीनस्थ इंजीनियरी काडरों में पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी करता है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

अप्रैल 2005 से अक्टूबर 2005 की अवधि में 65 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित/के आयोजन की योजना बनायी गयी। इनमें 1105 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। नवम्बर 2005 से मार्च 2006 की अवधि

में 41 और पाठ्यक्रमों के आयोजन की योजना है। इस अवधि में 600 कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त भू-केन्द्र के लिए 200 डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी ए और 10 कि.वा. एफएमबीई ट्रांसमीटर के बारे में संस्थान में 3 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों का आयोजन उपकरण निर्माता के सहयोग से किया गया।

एस टी आई (टी) और एस टी आई (पी) ने संयुक्त रूप से पीएसबीटी के प्रायोजन के अंतर्गत पत्रकारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

(2) क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) भुवनेश्वर

इस संस्थान की स्थापना जुलाई 2000 में भुवनेश्वर में न्यूनतम सुविधाओं के साथ की गयी थी। संस्थान टीवी/ध्वनि स्टूडियो से सुसज्जित है इसका मुख्य कार्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

अप्रैल 2005 से नवम्बर 2005 की अवधि में इस संस्थान ने 13 पाठ्यक्रम आयोजित/के आयोजन की योजना बनाई, जिनमें 133 इंजीनियरी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। दिसम्बर 2005 से मार्च 2006 की अवधि में 9 पाठ्यक्रमों के आयोजन की योजना है, जिनमें 120 कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

इंजीनियरी कालेज विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एसटीआई (टी) दिल्ली और आर एस टी आई (टी) भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिनमें कुल 251 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

आरएसटी (टी) भुवनेश्वर में प्रकाश सहायकों को कैमरामैन में परिवर्तित करने के बारे में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(3) क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) शिलांग

इस संस्थान की स्थापना 27 जून 2004 को न्यूनतम सुविधाओं के साथ शिलांग में की गयी थी। संस्थान में दो क्लासरूम, एक बहु-प्रयोजन स्टूडियो, एक प्रयोगशाला, एक छोटा होस्टल और स्टाफ क्वार्टर हैं। इसका मुख्य कार्य विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना है। यहां कम्प्यूटरीकृत हार्डडिस्क आधारित रिकार्डिंग, संपादन और प्लेबैक प्रणाली में पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

अप्रैल 2005 से नवम्बर 2005 की अवधि में इस संस्थान ने 5 पाठ्यक्रम आयोजित/आयोजन की योजना बनाई, जिनमें 152 इंजीनियरी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। दिसम्बर 2005 से मार्च 2006 की अवधि में 6 पाठ्यक्रमों के आयोजन की योजना है, जिनमें करीब 200 कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया गया है ताकि इस क्षेत्र के विकास में योगदान किया जा सके। इस पैकेज के अंतर्गत 31 मार्च 2006 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा 15 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पैकेज के अंतर्गत पहले पाठ्यक्रम का उद्घाटन 18 जुलाई 2005 को आकाशवाणी गंगटोक में किया गया था।

कार्यक्रम

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान एसटीआई(पी) दिल्ली और भुवनेश्वर अपने पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (कार्यक्रम)-अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुवनंतपुरम के साथ प्रसार भारती के उद्घोषकों, ट्रांसमिशन अधिशासियों, पुस्तकालयाध्यक्षों, कार्यक्रम अधिशासियों, कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तरीय प्रबन्धन और कार्यक्रम संवर्गों, को प्रशिक्षण देता है। ये संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यक्रम और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं।

प्रशिक्षण के लिए संभावना वाले क्षेत्रों में परिवर्तित तकनीकों का प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन, कार्पोरेट कार्य संस्कृति, डिजिटल प्रसारण, प्रस्तुतीकरण की आधुनिक तकनीकें, ध्वनि संस्कृति, प्रसारण प्रबन्धन, मौलिक कार्यक्रम, प्रोग्राम पैकेजिंग और प्रोत्साहन, वार्तालाप और भागीदारी पूर्ण कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम और रेडियो जॉकिंग शामिल हैं।

एसटीआई (पी) ने इग्नू, इंडियन एयरलाइन्स (ध्वनि संस्कृति), और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्मिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना भी प्रारम्भ किया है। इन संस्थानों ने दूरदर्शन के कार्यक्रम व्यवसायों के लिए भी प्रशिक्षण देना शुरू किया है।

उपलब्धियां

वर्ष 2004-2005 के दौरान एसटीआई (पी) दिल्ली और भुवनेश्वर ने अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और तिरुवनंतपुरम स्थित पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ 30 पाठ्यक्रमों का संचालन किया, इनमें 17 पाठ्यक्रम कार्यक्रम संबंधी थे और 13 प्रशासनिक पाठ्यक्रम थे। इन पाठ्यक्रमों के जरिए 404 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें आकाशवाणी के कार्यक्रम संबंधी 202 कार्मिकों और इतनी ही संख्या में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रशासनिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रसारण प्रबन्धन और शांति पत्रकारिता के बारे में एआईबीडी के सहयोग से दो अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों का आयोजन एसटीआई (पी), दिल्ली में सितंबर और अक्टूबर 2004 में किया गया। इन पाठ्यक्रमों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम तथा समाचार संबंधी 34 कार्मिकों ने हिस्सा लिया।

समन्वित पाठ्यक्रम

वर्ष 2004-2005 के दौरान कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) आकाशवाणी, दिल्ली ने कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) आकाशवाणी और दूरदर्शन, दिल्ली के समन्वय से हार्ड डिस्क आधारित रिकॉर्डिंग प्रणाली के बारे में आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारियों के लिए 7 पाठ्यक्रमों का संचालन किया। इनमें आकाशवाणी के 43 कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

बाहरी पाठ्यक्रम

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान एसटीआई (पी.) दिल्ली ने इंडियन एयरलाइन्स के लिए 10 कार्यशालाओं का आयोजन किया और 258 विमान परिचारिकाओं तथा केबिन कू को आरटीआई (पी), हैदराबाद में वाइस कल्चर यानी ध्वनि संस्कृति का प्रशिक्षण प्रदान किया। इस संस्थान ने जून और जुलाई 2004 में 3 कार्यशालाओं का आयोजन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए किया, जिसमें 30 परिचारिकाओं को वाइस कल्चर यानी ध्वनि संस्कृति का प्रशिक्षण प्रदान किया।

(ख) रेडियो प्रसारण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरपी) और श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएपीपी) के विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के

बारे में प्रसार भारती ने 'इग्नू' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार 'इग्नू' द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए ली जाने वाली फीस आधा हिस्सा प्रसार भारती को मिलता है।

(ग) आकाशवाणी के लिए नए चुने गए कम्पीयरों, उद्घोषकों और प्रस्तुतकर्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2003 से **वाणी** - यानी वाइस आर्टिकुलेशन एंड नर्चिंग इनिशिएटिव प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया। ये पाठ्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर भुगतान आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। मार्च 2005 तक आकाशवाणी के 46 केंद्रों पर करीब 70 पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया, जिनमें 1250 नए उद्घोषकों, कम्पीयरों और प्रजेंटर्स को प्रशिक्षित किया गया।

'**वाणी**' नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है, जो वाणी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के भागीदारों के लिए पूरक सामग्री के रूप में अत्यंत मददगार सिद्ध हुई है। मार्च 2005 तक वाणी की करीब 1500 प्रतियां बेची गईं, जिससे प्रसार भारती को राजस्व प्राप्त हुआ।

एसटीआई (पी) की गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए **लीडिंग द वे** नाम की एक पुस्तिका भी प्रकाशित की जा रही है। इसे विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संगठनों तथा एजेंसियों को भेजा जाता है। इसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करना है और इसके जरिए वाइस कल्चर यानी ध्वनि संस्कृति में प्रसार भारती की विशेषज्ञता का लाभ अन्य संगठनों को पहुंचाया जाता है।

अर्जित राजस्व

वर्ष 2004 के दौरान एसटीआई (पी) ने रुपए 74,65,610/- अर्जित किए और 2002 से 31 अगस्त 2005 तक उसने सभी स्रोतों से कुल रुपए 1,20,65,399- का राजस्व अर्जित किया।

भावी योजनाएं

एसटीआई (पी) अपनी विशेषज्ञता का लाभ उन विश्वविद्यालयों, प्राइवेट रेडियो और टीवी चैनलों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर्स, रेलवे, प्राइवेट एयरलाइन्स और अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों को प्रदान करने की संभावनाएं तलाश रहा है, जो वाइस कल्चर और प्रबंधन के बारे में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

जनवरी-मार्च 2006 के दौरान योजनाबद्ध कार्यक्रम

विभागीय पाठ्यक्रम

इस अवधि में सभी 7 प्रशिक्षण संस्थानों ने 15-20 पाठ्यक्रमों का आयोजन निर्धारित किया है, जिसमें 300 से 400 के बीच कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

बाहरी पाठ्यक्रम

जनवरी 2006 से मार्च 2006 तक इंडियन एयरलाइन्स के लिए 5-6 पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिनमें करीब 150 केबिन क्रू सदस्यों को वाइस कल्चर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2005 की पहली छमाई में ऐसे 3 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिनमें 80 केबिन क्रू सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

इग्नू के साथ हुए समझौते के अंतर्गत मार्च 2006 तक 2 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पीजीडीएपीपी और पीजीडीआरपी के करीब 350 विद्यार्थियों को देश भर में विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इस अवधि में आकाशवाणी के नए चुने गए कैजुअल उद्घोषकों और कम्पीयरों को प्रशिक्षण देने के लिए वाणी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।

अनुसंधान और विकास विभाग की वर्ष 2005-06 की गतिविधियां

आकाशवाणी और दूरदर्शन का अनुसंधान और विकास विभाग रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों में रत है। 2005-06 के दौरान शुरू की गयी महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार रहीं :

ध्वनि मूल्यांकन - विभिन्न प्रकार की ध्वनि संबंधी सामग्री के वाणिज्यिक आधार पर मूल्यांकन के अतिरिक्त नई दिल्ली स्थित कांफ्रेंस हॉल, प्रधानमंत्री कार्यालय और नये प्रसारण भवन का ध्वनि मूल्यांकन किया गया।

इन्टरएक्टिव रेडियो सेवा (आईआरएस)-आकाशवाणी की यूनिट प्रणाली (कोटा, भटिन्डा, रोळनक, शिलांग, गुवाहाटी, इंदौर, मैसूर) में आईआरएस सॉफ्टवेयर लगाया है और सम्बद्ध स्टेशन के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा विकसित न्यूज रूम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर समाचार प्रसारण के चार चरणों, - एजेंसियों से कम्प्यूटर पर समाचार आइटम संग्रह करना, संपादन, समाचार वाचन और उसके बाद अभिलेखन - को एकीकृत करता है। लखनऊ, शिलांग, जयपुर, गुवाहाटी और शिमला स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में सॉफ्टवेयर लगाया गया है। कुछ और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में यह प्रणाली लगाने का प्रस्ताव है।

ए एम ट्रांसमीटर के लिए टेलीमीटरी प्रणाली - डिजिटल मीडियम वेब ट्रांसमीटर को दूरवर्ती स्थान से नियंत्रित करने और उस पर निगरानी रखने के लिए टेलीमीटरी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली का हार्डवेयर तैयार कर लिया गया है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम जारी है।

एफएम ट्रांसमीटर के लिए टेलीमीटरी प्रणाली - आकाशवाणी के शिलांग केंद्र में लगाए जाने के लिए ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके विकास का कार्य लगभग पूरा हो गया है।

वाइस कास्ट यूनिटें - अनुसंधान और विकास विभाग ने 10 वाइस कास्ट यूनिटें विकसित की हैं। इनमें से 6 रेडियो कश्मीर, श्रीनगर भेजी गईं।

(iii) **डाटा रेडियो चैनल प्रणाली** - यह एक डाटा प्रसारण प्रणाली है, जिमसे एफ एम ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से सूचना प्रदाताओं को एफ एम रेडियो नेटवर्क कवरेज के अंतर्गत आने वाले किसी भी स्थान पर डाटा (पाठ, चित्र या वीडियो) संप्रेषित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। उपयुक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मॉड्यूल के साथ डी ए आर सी (डार्क) का बिलबोर्ड अनुप्रयोग विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अलग-अलग प्रकार के करीब 20 तरीकों से डार्क के जरिए पाठ संदेश और बिटमैप चित्र बिलबोर्ड पर डिस्प्ले करना शामिल है। एफएम गोल्ड (106.4 मेगा हर्ट्ज) से इसका ट्रांसमिशन पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है। एफएम ट्रांसमीटर से 60 किलोमीटर के दायरे में विभिन्न दिशाओं में एफ एम ट्रांसमीटर की रेंज के भीतर बिलबोर्ड पर सिग्नल का परीक्षण सफल रहा है। आईईटीई और केबल क्वेस्ट प्रदर्शनियों में अगस्त और सितंबर 2005 के दौरान

इस परियोजना का लाइव डिमान्स्ट्रेशन किया गया। 3 से 7 जनवरी 2006 के बीच हैदराबाद में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन सम्मेलन में इस सिस्टम के प्रजेंटेशन की मांग की गई है।

सम्प्रेषण (प्रोपेगेशन)

विभिन्न प्रकार के भवनों में डिजिटल प्रसारण के मामले में उच्च फ्रीक्वेंसियों (30 मेगा हर्ट्ज से नीचे) पर सम्प्रेषण क्षति का आकलन करने के लिए आयोजना मानदंडों की पड़ताल की गई। विभागीय आधार पर विकसित वर्टिकल पोलराइज्ड एफएम एंटीना के लिए फील्ड स्ट्रेन्थ सर्वेक्षण किया गया ताकि उसकी सैद्धांतिक विशेषताओं का पता लगाया जा सके।

डिजिटल रेडियो मॉड्यूल (डी आर एम)

डिजिटल रेडियो मॉड्यूल (डी आर एम) के बारे में प्रयोगात्मक अध्ययन नामक एक परियोजना शुरू की गई है। इस अध्ययन में कवरेज क्षेत्र, विशिष्ट कौशल, श्रव्य गुणवत्तावर्द्धन, आंकड़े, पाठ जैसी मूल्य संवर्द्धित सेवाओं को कवर किया जाएगा। एक मौजूदा शॉर्ट वेब ट्रांसमीटर में डी आर एम लागू करने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

उच्च शक्ति एफएम ट्रांसमीटिंग एंटीना

उच्च शक्ति एफएम ट्रांसमीटिंग एंटीना बड़े महंगे होते हैं और आमतौर पर भारत में उनका आयात किया जाता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए सिंगल बे सरकुरली पोलराइज्ड क्रॉस - बी एफएम ट्रांसमीटिंग एंटीना विकसित किया गया और सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल किया गया। इसके आधार पर एक सिक्स बे हाई पावर एफएम एंटीना तैयार किया गया है और उसके फील्ड ट्रायल किए जा रहे हैं।

ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (BECIL)

बी ई सी आई एल भारत सरकार द्वारा 1955 में स्थापित ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहली सलाहकार और निर्माण से लेकर चलाने की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी है। बी ई सी आई एल के पास आकाशवाणी और दूरदर्शन समेत विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी

आकाशवाणी

वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त वास्तविक लक्ष्य

कुल-63

क्र.सं.	स्थान	राज्य	परियोजना	टिप्पणी
1 से 25	25 स्थान	जम्मू-कश्मीर	100 वॉट एल.पी.टी. रिले स्टेशन	
26	दिल्ली	दिल्ली	सी.इ.एस. क्षमता वृद्धि	
27	मुम्बई	महाराष्ट्र	वही	
28	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	सी.इ.एस.	
29	दिल्ली	दिल्ली	डी.एस.एन.जी. मोबाइल सिस्टम	
30	मुम्बई	महाराष्ट्र	वही	
31	कोलकता	पश्चिम बंगाल	वही	
32	चेन्नई	तमिलनाडु	वही	
33	रायपुर	छत्तीसगढ़	100 कि.वा. मे.वा. (100 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
34	दिल्ली	दिल्ली	वही	ट्रांसमीटर
35	बारीपदा	उड़ीसा	5 कि.वा. एफ.एम. बदलना	ट्रांसमीटर
36	कोटा	राजस्थान	20 कि.वा. - मे.वा. (1 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
37	दिल्ली	दिल्ली	20 कि.वा. - एफ.एम. (10 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
38	दिल्ली	दिल्ली	20 कि.वा. - एफ.एम. (5 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
39	चेन्नई	तमिलनाडु	20 कि.वा. - एफ.एम. (10 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
40	चेन्नई	तमिलनाडु	20 कि.वा. - एफ.एम. (5 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
41	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	20 कि.वा. - एफ.एम. (5 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
42	मुम्बई	महाराष्ट्र	20 कि.वा. - एफ.एम. (5 किलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर

क्र.सं.	स्थान	राज्य	परियोजना	टिप्पणी
43	रायरंगपुर	उड़ीसा	1 कि.वा. - एफ एम को बदलना स्टूडियो और एस/क्यूकिलोवाट को बदलना)	ट्रांसमीटर
44	त्रिशूर	केरल	स्टूडियो का नवीनीकरण	
45	सिलचर	असम	वही	
46	बांसवाड़ा	राजस्थान	10 कि.वा.-एफ एम (6 कि.वा. को बदलना)	एफएम ट्रांसमीटर लगाने का आर्डर मिलने पर
47	अलवर	राजस्थान	वही	वही
48	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	वही	वही
49	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	वही	वही
50	सूरत	गुजरात	वही	वही
51	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	वही	वही
52	कोची	केरल	वही	वही
53	नागपुर	महाराष्ट्र	वही	वही
54	जोरहाट	असम	10 कि.वा.-एफ एम	10 कि.वा. को बदलना
55	चंडीगढ़	चंडीगढ़	10 कि.वा.-एफ एम	वही
56	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	10 कि.वा.-मे.वा. को बदलना (ट्रा. एवं स्टीरियो स्टूडियो	10 कि.वा.मे.वा. को बदलना
57	शोलापुर	महाराष्ट्र	10 कि.वा.-एफ.एम (1 कि.वा. मे.वा. को बदलना) ट्रा. एवं स्टीरियो स्टूडियो	ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर
58	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	वही	वही
59	जालंधर	पंजाब	वही	वही
60	पटना	बिहार	10 कि.वा.-एफ.एम ट्रांसमीटर एवं स्टीरियो स्टूडियो	
61	बीकानेर	राजस्थान	वही	वही
62	रांची	झारखंड	वही	वही
63	तिरुनेलवेली	चेन्नई	वही	वही

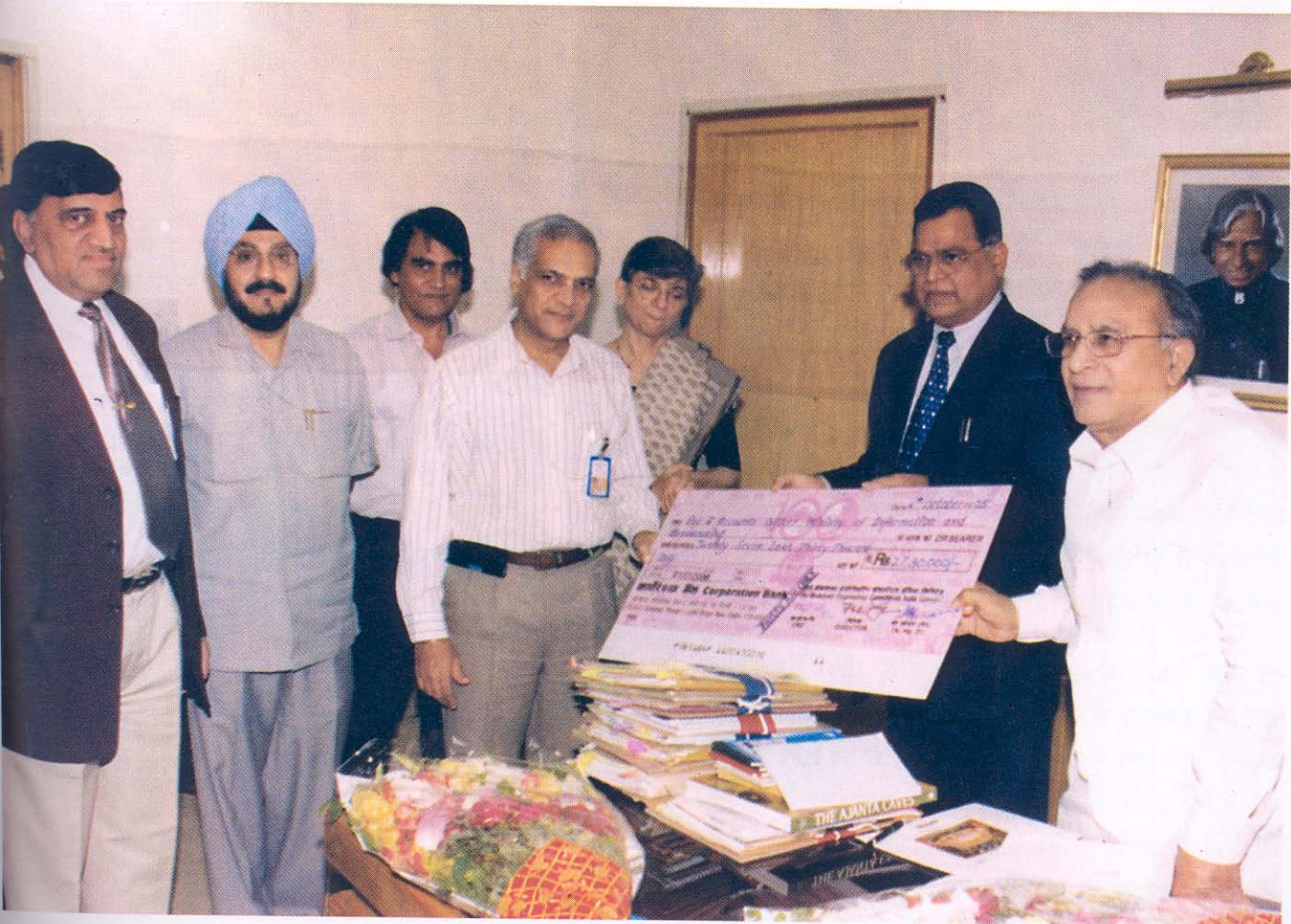
विशेषज्ञ हैं। बी ई सी आई एल आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने के साथ अपनी क्षमताओं का निरंतर सुधार करती रहती है।

1989 में खाड़ी युद्ध के बाद ब्राडकास्टिंग क्षेत्र का उद्भव होने के साथ अधिक से अधिक उपग्रह चैनलों ने भारत में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया। 1991-92 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि भारतीय कंपनियां भी उपग्रह के जरिये प्रसारण करने की आवश्यकता महसूस करने लगीं। इन कंपनियों को प्रसारण के क्षेत्र में सलाह लेने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। उस समय सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास ऐसी विशेषज्ञता हासिल थी। भारत सरकार ने ऐसी एक एजेंसी बनाने का निर्णय लिया और इस प्रकार बी ई सी आई एल की स्थापना की गई।

बी ई सी आई एल क्षेत्रीय और उपग्रह प्रसारण, सी ए टी वी नेटवर्क, डाटा प्रसारण और एकोस्टिक्स और आडियो वीडियो समेत स्टूडियो के विशिष्ट क्षेत्रों में निर्माण से लेकर चलाने समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर की सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराती है।

बी ई सी आई एल सभी प्रकार की प्रसारण प्रणाली को चलाने और उसके रख-रखाव का काम भी करती है।

प्रसारण प्रणालियों के प्रोजेक्ट को चलाने और रख-रखाव करने के अलावा बी ई सी आई एल सभी प्रकार के प्रसारण प्रोजेक्ट को विकसित करने और चलाने के लिए भारत और विदेश में इकाइयों को तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर और विशेषज्ञ भी आसानी से मुहैया कराती है।



केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड से चेक ग्रहण करते हुए,

6 अक्टूबर, 2005

बी ई सी आई एल समय पर हर प्रोजेक्ट को कारगर ढंग से और कम लागत से पूरा करने के लिए रख-रखाव करने के साथ एक पेशेवर और गुणवत्तापूरक दृष्टिकोण अपनाते हुए हर उपभोक्ता की सभी जरूरतों को पूरा करने का काम करती है।

अपने इन्हीं दृष्टिकोण के कारण कंपनी ग्राहकों को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने में कामयाब रही है। ऐसा करके उसने न केवल अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखा है अलबत्ता वह सरकार का एक लाभकारी उपक्रम बन गई है। बी ई सी आई एल ने इस वर्ष सरकार को 20 प्रतिशत लाभांश दिया है।

बी ई सी आई एल प्रबंधन और संगठन

इसके निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक (संचालन एवं विपणन) और सरकार द्वारा नामित चार से सात अंशकालिक निदेशक होते हैं। निदेशक मंडल से नीचे संयुक्त महाप्रबंधकों के दो नियमित पद, एक सह महाप्रबंधक (संचालन एवं विपणन) एक सह प्रबंधक (वित्त) और कनिष्ठ प्रबंधक का एक पद होता है। कंपनी तकनीकी कार्यों में मदद के लिए अनुबंध पर सलाहकार नियुक्त करती है। इसके अतिरिक्त बी ई सी आई एल के पास अपने तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समेत विभिन्न क्षेत्रों के काफी विशेषज्ञ हैं।

वित्तीय स्थिति

बी ई सी आई एल ने 24 मार्च 1995 में स्थापना के बाद से सार्वजनिक और निजी प्रसारकों और एजेंसियों के लिए भारत और विदेशों में काम करके उल्लेखनीय प्रगति की है। अस्तित्व में आने के समय से ही कंपनी सरकार को लाभांश दे रही हैं। पिछले पांच वर्षों की कंपनी की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :

31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में संचालन से आय में चार गुणा ज्यादा 207.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जमा कार्य समेत इस वर्ष के दौरान कुल आय पिछले वर्ष के 1,683.24 लाख रुपये से बढ़कर 3,773.22 लाख रुपये हो गई। वर्ष 2004-05 के वित्तीय वर्ष के दौरान बी ई सी आई एल को पिछले वर्ष के 173.19 लाख रुपये के मुकाबले 201.24 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 16.20 प्रतिशत का शुद्ध मुनाफा हुआ।

इस समय बी ई सी आई एल अफगानिस्तान में सूचना व्यवस्था की पुनः स्थापना और अफगानिस्तान के जलालाबाद और नंगरहार प्रांतों में टेलीविजन हार्डवेयर को पुनः स्थापित करने समेत विभिन्न परियोजनाओं के ठेकों को पूरा करने में जुटी है। इस परियोजना का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि यह अफगानिस्तान को भारत द्वारा दी जा रही सहायता का हिस्सा है। हाल में कंपनी ने अफगानिस्तान में टेलीविजन की कवरेज के लिए विदेश मंत्रालय के साथ एक और अनुबंध किया है। भारत सरकार ने 91 शहरों में निजी एफ एम चरण दो योजना के तहत लाइसेंस जारी करने की एक नीति घोषित की है। बी ई सी आई एल को सामान्य ट्रांसमिशन ढांचा उपलब्ध कराने के लिए समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सात शहरों में टावरों का निर्माण करेगी।

बी ई सी आई एल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ वित्त वर्ष 2005-06 के लिए समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने समझौते के ज्ञापन को सुसाध्य बनाया है। कम्पनी के वित्तीय और अन्य लक्ष्य दिए गए हैं।

पूरी की गई, पूरी की जा रही और साथ ही प्रक्षेप की जा रही परियोजनाओं की सूची नीचे दी जा रही तालिकाओं में है :

- i) परियोजनाओं की सूची-प्राप्त/निष्पादित अप्रैल 2004 से मार्च 2005-संलग्नक I
- ii) परियोजनाओं की प्राप्त सूची-अप्रैल 2005 से आज तक-संलग्नक II

4. व्यवसाय प्रचालन और गतिविधियां (वर्ष के दौरान)

i) अफगानिस्तान सूचना व्यवस्था का पुनर्स्थापन/पुनर्गठन

कम्पनी ने काबुल, अफगानिस्तान में सूचना व्यवस्था के पुनः स्थापना/पुनर्गठन के लिए विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में शामिल हैं एक मुद्रणालय की स्थापना, सेटलाइट अपलिंग और डाउनलिंग सुविधा। डाउनलिंग व्यवस्था की स्थापना का काम विशेष रूप से कठिन था क्योंकि इन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया जाना था। 100 के डब्ल्यू शार्ट वेव ट्रांसमीटर का काम पूरा होने के अन्तिम चरण में है, स्थानीय

लाख रुपये में						
क्रम सं.	देनदारी	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	शेयर पूंजी	36.50	136.50	136.50	136.50	136.50
2	शेयर आवेदन राशि	100.00	-	-	-	-
3	रिजर्व और अतिरिक्त	167.00	227.89	287.10	364.80	464.02
4	ऋण कोष	11.00	4.00	8.95	268.44	503.48
5	वर्तमान देनदारी और प्रावधान	403.60	757.54	1187.18	1022.81	1560.04
	कुल	718.10	1125.93	1619.73	1792.55	2644.04
	परिसम्पत्तियाँ					
6	स्थायी परिसम्पत्तियाँ	41.65	38.08	33.40	96.41	122.56
7	पूंजी कार्य में प्रगति	-	-	-	-	1.12
8	वर्तमान परिसम्पत्तियाँ ऋण और अग्रिम राशि	676.03	1087.53	1585.15	1688.33	2530.44
9	मिलानजुला खर्च	0.42	0.32	1.18	7.81	9.92
	कुल	718.10	1125.93	1619.73	1792.56	2664.05

लाख रुपये में

क्रम सं.	ब्यौरा	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	बिक्री	1339.23	818.76	770.33	808.77	2990.59
2	परामर्श और ठेके से आय	255.01	397.33	284.55	314.45	584.07
3	अन्य आय	29.83	20.61	54.52	55.55	47.99
4	जमा कार्य का मूल्य	255.81	128.74	645.71	504.87	150.67
	जमा कार्य सहित कुल खर्च	1889.88	1365.44	1755.11	1683.64	3773.32
5	कुल आय					
6	खर्च	1744.00	1220.14	1599.06	1510.45	3572.06
7	कर से पहले लाभ	145.87	145.30	156.05	173.19	201.24
8	आय कर	57.92	56.55	59.08	70.50	73.58
9	कर के बाद लाभ	87.95	88.19	90.00	108.61	130.14
10	लाभांश कर सहित लाभांश	20.11	27.30	30.80	30.86	30.86
11	अग्रिम प्राप्ति	67.84	60.89	59.20	77.75	99.28

अधिकारियों और अफगानिस्तान सरकार ने बी ई सी आई एल के काम की सराहना की है।

ii) अफगानिस्तान के जलालाबाद और नंगरहार प्रान्तों में टेलीविजन हार्डवेयर की पुनः स्थापना/आवर्धन

वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन के आधार पर विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के जलालाबाद और नंगरहार प्रान्तों में टेलीविजन हार्डवेयर के पुनःस्थापन/आवर्धन के विषय में एक और समझौता किया है। इस परियोजना का कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है।

iii) प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति

वर्ष के दौरान कम्पनी ने ग्लोबल बिडिंग टेंडर सिस्टम के जरिए आल इंडिया रेडियो से प्राप्त आर्डर के अनुसार विभिन्न प्रसारण उपकरण सप्लाई किए हैं। इस सप्लाई में शामिल है 100 के डब्ल्यू एम डब्ल्यू ट्रान्समीटर के लिए डमी लोड का विकास और एकीकरण। देश में पहली बार डमी लोड का एकीकरण किया गया। देश में उपकरणों का विकास आयातित उपकरणों के एक तिहाई मूल्यों पर किया गया। ये उपकरण आल इंडिया रेडियो के तीन केन्द्रों को सप्लाई किए गए। उपकरण संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। कम्पनी ने आल इंडिया रेडियो के 6 अपग्रेडेशन केप्टिव अर्थ का संस्थापन पूरा कर लिया है।

iv) सामुदायिक रेडियो स्टेशन

भारत सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की एक योजना शुरू की है। वर्ष के दौरान बी ई सी आई एल ने ए.जे. किदवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेन्टर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली; आई आई एम जयपुर; और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कमीशन किए। कम्पनी अन्य संस्थाओं में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए उनके साथ बातचीत कर रही है।

v) प्रचालन और रख-रखाव

कम्पनी ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 137 केबल हेड एन्ड स्थापित

किए हैं। वर्ष के दौरान इसने इन केन्द्रों का प्रचालन और रख-रखाव किया। कम्पनी आई जी एम ओ यू, नई दिल्ली, ए एन एन एस आई आर डी मैसूर, कंसोर्टियम आफ एजुकेशन कम्युनिकेशन और दूरदर्शन के न्यूज चैनल के लिए भी अर्थ स्टेशनों का रख-रखाव कर रही है।

समुद्रपार व्यवसाय

वर्ष के दौरान, बी ई सी आई एल ने समुद्र पार व्यवसाय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए। कम्पनी ने विदेशी कम्पनियों के साथ व्यवसाय में भागीदार बनने के लिए समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कम्पनी पहले ही भारत सरकार के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडियो एंड टेलीविजन अथारिटी को उपकरण सप्लाई कर रही है। कम्पनी ने अमरीका की कॉन्स्टीलेशन विजनेस इनका. के साथ काबुल में टर्न-की आधार पर टी वी चैनल स्थापित करने के लिए समझौता किया है। कम्पनी ने मै० थेल्स मल्टी मीडिया एंड ब्राडकास्ट से बंगलादेश को उपकरण सप्लाई करने का आर्डर प्राप्त किया है। आपकी कम्पनी ने बंगलादेश में एफ एम स्टेशनों की नेटवर्क प्लानिंग करने के लिए एक निजी कम्पनी को सलाह-सेवा प्रदान की है।

5 सतर्कता गतिविधियां

क. सतर्कता ढांचे का विवरण

ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक छोटा प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई। यह माल तैयार करने वाली यूनिट नहीं है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है इसका कार्य क्षेत्र केवल ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग और इन्फारमेशन टेक्नालॉजी के क्षेत्र में सलाह-सेवा, टर्न की, डिपाजट वर्क और सर्विस परियोजनाओं तक सीमित है। कम्पनी के नियमित कर्मचारियों में शामिल है केवल 13 कर्मचारी, और अधिकांश कर्मचारी ठेके के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। बी ई सी आई एल में कोई विशेष सतर्कता व्यवस्था नहीं है। तथापि, श्री हरकेश गुप्ता, निदेशक (प्रचालन और ब्रिकी) बी ई सी आई एल सतर्कता कार्य का निरीक्षण करते हैं।

ख. वर्ष के दौरान निरोधक सतर्कता गतिविधियां

निरोधक सतर्कता गतिविधियां निम्न तरीके से की जाती हैं :

- i) बी ई सी आई एल के आन्तरिक लेखा परीक्षकों (मैसर्स एम. जयरामन एंड कम्पनी, चाटर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा नियमित/आवधिक लेखा परीक्षा।
- ii) सी ए जी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के जरिए कानूनी लेखा परीक्षा।
- iii) सी ए जी की टीम के द्वारा पूरक लेखा परीक्षा।

ग. वर्ष के दौरान निगरानी और खोज की गतिविधियां

- i) निगरानी के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण विशेष रूप से कोई नहीं
- ii) निगरानी के लिए चुने गए व्यक्तियों की संख्या शून्य

घ. दंडात्मक कार्रवाई (जहां नियुक्त अधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई आर है डी (i) से (viii) के विरुद्ध संख्या का संकेत होना चाहिए।

- i) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों/संदर्भों की संख्या शून्य
- ii) मामलों की संख्या जिनमें प्रारम्भिक जांच की गई शून्य
- iii) मामलों की संख्या प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त की गई शून्य
- iv) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्रमुख दंड दिया गया शून्य
- v) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मामूली दंड दिया गया शून्य
- vi) निलम्बित किए गए व्यक्तियों की संख्या शून्य
- vii) व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई जैसे कि चेतावनी जारी करना की गई शून्य
- viii) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें संबद्ध नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत समय पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया शून्य

सामान्य

बी ई सी एल का बजट खुले बाजार में प्रतियोगी टेंडर प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त सलाह सेवा और टर्न-की कामों के लिए आय और खर्च के बारे में उसके अपने आन्तरिक अनुमान है।

बी ई सी आई एल को औरतों, पूर्वोत्तर (सिक्कीम सहित), रोजगार

पैदा करने, ग्रामीण संघटक, जनजातीय उप योजना, विशेष संघटक योजना, स्वैच्छिक क्षेत्र, सूचना और प्रचार, अल्पसंख्यक कल्याण आदि से संबंधित कोई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं सौंपी गई है। तथापि, दूरदर्शन के महानिदेशक ने उसे 712 लाख रुपये की अनुमानित लागत की पूर्वोत्तर क्षेत्र के 160 गांवों में केबल हेड एन्ड लगाने का काम सौंपा है।

संलग्नक-1

अप्रैल 2004 से प्राप्त परियोजनाओं की सूची-मार्च-2005

क्रम संख्या	नाम, स्थान और परियोजना का प्रकार	ठेका मूल्य लाख रुपये में (अनुमानित)
1.	अफगानिस्तान के जलालाबाद और नांगरहार प्रांत में टेलीविजन हार्डवेयर का जीर्णोद्धार/विस्तार	663.27
2.	आकाशवाणी को 200 किलोवाट मेगावाट के एक ट्रांसमीटर की आपूर्ति	591.86
3.	आकाशवाणी को ऑडियो विश्लेषक की आपूर्ति	311.30
4.	सी.एम.एस. आयानगर में टी वी मानिट्रिंग सुविधा में सुधार	260.00
5.	दूरदर्शन को 2x20 किलोवाट के स्लॉट टाइप यू एच एफ एंटीना प्रणाली और साधनों की आपूर्ति	54.02
6.	1-5/8'' फोम डायइलेक्ट्रिक आर एफ फीडर केबल 50 ओ एच एम एस की आपूर्ति	35.57
7.	कोलकाता में कैप्टिव अर्थ स्टेशन का अपग्रेडेशन	139.00
8.	टाइम्स टी वी की स्थापना के लिए परामर्श और तकनीकी लेखा सेवा	12.00
9.	इग्नू को कम्बाइनर/मल्टीप्लेक्स की आपूर्ति	43.63
10.	सिंगल डायपोल एफ एम एंटीना की आर एफ एस केबल और अन्य सामान के साथ आपूर्ति	2.86
11.	रूस के राष्ट्रपति का भारत यात्रा के दौरान ई बी यू को अपलिकिंग सेवा देना	10.26
12.	सेंटीनल ब्राडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को सेटलाइट टी वी स्थापित करने के लिए परामर्श देना	25.00
13.	यू टी वी स्थापित करने के लिए परामर्श	3.00
14.	जामिया मिलिया इस्लामिया में सामुदायिक रेडियो की स्थापना	6.97
15.	थेल्स मल्टीमीडिया और प्रसारण के लिए फीडर केबल की आपूर्ति	5.64
16.	समूह बिजनेस ग्रुप के लिए टी वी स्टूडियो की स्थापना	232.00
17.	आकाशवाणी से 5 किलोवाट के मोसफेट वी एच एफ टी एक्स प्रो की आपूर्ति	285.16
18.	फिल्म डिवीजन परिसर में चलती-फिरती प्रतिभाओं के संग्रहालय की स्थापना	10.00
19.	स्पेस टी वी के लिए भारत में डी टी एच के संचालन और स्थापना के लिए परामर्श	8.00
20.	चीफ इंजीनियर दक्षिणी जोन को आर एफ फीडर केबल की आपूर्ति	2.11
21.	एफ एम रेडियो बांग्लादेश के लिए परामर्श	3.48
कुल		2,705.13

संलग्नक-11

अप्रैल 2005 से अब तक प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	नाम, स्थान और परियोजना का प्रकार	ठेका मूल्य लाख रुपये में (अनुमानित)
1.	आकाशवाणी के लिए 2×100 किलोवाट ए एम मैगावाट के ट्रांसमीटर की आपूर्ति	539.00
2.	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना	25.00
3.	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लिए केप्टिव टी वी सुविधा की स्थापना के लिए परामर्श	2.00
4.	शेख नेटवर्क, जलालाबाद के लिए ट्रांसमीटर, एंटीना, टावर और केबल की आपूर्ति	69.48
5.	विदेश मंत्रालय के लिए अफगानिस्तान में टी वी कवरेज के विस्तार के लिए समझौता	1440.91
6.	एच टी मीडिया लिमिटेड के लिए एफ एम रेडियो परियोजना के लिए परामर्श	3.00
7.	राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए जनसंचार केन्द्र	21.74
8.	आकाशवाणी के लिए 100 एम स्टील टावर की आपूर्ति	266.26
9.	टाइम्स ग्लोबल ब्राडकास्टिंग के लिए डिश एंटीना की स्थापना	22.00
10.	मलयालम मनोरमा की एफ एम परियोजना के लिए परामर्श	7.50
11.	वर्ल्ड स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए सेवा, स्टूडियो डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन, परीक्षण और शुरुआत का प्रावधान	12.50
12.	इग्नू, नई दिल्ली के लिए रिजीड लाइन रिड्यूसर की आपूर्ति	1.99
13.	म्यूजिक ब्राडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए परामर्श और व्यावसायिक सेवा	4.00
14.	स्पेस टी वी के लिए परामर्श और व्यावसायिक सेवा	4.00
15.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए टी वी मॉनिटरिंग सुविधा की स्थापना	1,165.00
16.	राजस्थान पत्रिका के एफ एम रेडियो के लिए परामर्श	7.50
17.	आनंद बाजार पत्रिका के एफ एम रेडियो के लिए परामर्श	7.00
18.	ए पी एस एस डी सी के लिये एन एस सी साफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन	9.00
19.	नई दिल्ली में इग्नू की छह जगहों पर ज्ञानवाणी स्टूडियो का निर्माण	78.64
20.	जे बी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के एफ एम रेडियो के लिए परामर्श	4.00
कुल		3,691.11

5

फिल्म क्षेत्र

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग का इतिहास स्वतंत्रता उपरांत भारत के घटनापूर्ण वर्षों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है और पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनमानस को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए अनुप्रेरित करता रहा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग के उद्देश्यों में लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए शिक्षित करना और प्रेरित करना व देश की परंपरागत विरासत तथा छवि को देश-विदेश के सम्मुख प्रस्तुत करना है। इसके अलावा फिल्म प्रभाग देश में वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा देने का काम भी करता है जो राष्ट्रीय, सूचना, संचार और अखण्डता के लिए अति महत्वपूर्ण है।

यह प्रभाग मुंबई स्थित मुख्यालय से वृत्तचित्र, लघु फिल्मों, एनीमेशन फिल्मों और न्यूज मैगजीनें तैयार करता है, इसकी दिल्ली इकाई रक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर फिल्मों बनाती है। जबकि कोलकाता और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय निर्माण केंद्रों पर ग्रामीण दर्शकों के लिए लघु-कथा फिल्मों बनाई जाती हैं। फिल्म प्रभाग देश भर के 12000 सिनेमाघरों, देश भर में फैली क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों, दूरदर्शन, परिवार कल्याण मंत्रालय की क्षेत्रीय इकाइयों, शैक्षिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। राज्य सरकारों के वृत्तचित्र और न्यूज रीलों को भी प्रभाग प्रदर्शन के लिए जारी करता है। फिल्म प्रभाग वृत्तचित्रों और फीचर फिल्मों के प्रिंट, स्टॉक शाट, वीडियो कैसेट तथा वितरण अधिकार देश-विदेश में बेचता है। फिल्म-निर्माण के अलावा फिल्म प्रभाग निजी फिल्म निर्माताओं को अपने स्टूडियो, रिकार्डिंग थियेटर, संपादन कक्ष और अन्य सिनेमा उपकरण किराए पर देता है।

मार्च 1990 से मुंबई में वृत्तचित्रों, लघु फिल्मों और एनीमेशन फिल्मों का द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव आयोजित करवाने के कारण प्रभाग की दुनिया भर में वृत्तचित्र आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पहचान बन गई है, आठवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह मुंबई में 3-

9 फरवरी 2004 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नवां फिल्मोत्सव 3-9 फरवरी 2006 तक मुंबई के पी-एल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी प्रभादेवी में आयोजित किया जा रहा है।

फिल्म प्रभाग ने तिरुवनन्तपुरम, पुणे, पटना, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़, पांडिचेरी, हैदराबाद, चेन्नई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व बंगलौर में फिल्मोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वृत्तचित्र आंदोलन को प्रोत्साहन मिल सके। प्रभाग को कामकाज की दृष्टि से चार खंडों में बांटा गया है। ये हैं : (1) निर्माण, (2) वितरण, (3) अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्मोत्सव और (4) प्रशासन

निर्माण खंड

निर्माण खंड (1) वृत्तचित्र, (2) ग्रामीण दर्शकों के लिए लघु फीचर फिल्मों, (3) एनीमेशन फिल्मों और (4) वीडियो फिल्मों का निर्माण करता है। मुंबई में मुख्यालय के अलावा प्रभाग के तीन निर्माण-केंद्र बंगलौर, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं। वृत्तचित्रों में विषय वस्तु की दृष्टि से, कृषि से कला तक, उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक, खानपान से त्यौहारों तक, स्वास्थ्य सुविधाओं से आवास तक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से खेल-कूद तक, व्यापार और वाणिज्य से परिवहन तक, आदिवासी कल्याण से सामुदायिक विकास आदि शामिल होता है।

आम तौर पर प्रभाग की बनाई जाने वाली फिल्मों में देशभर के स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए 40 प्रतिशत सुरक्षित होता है, ताकि वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। अपने सामान्य फिल्म निर्माण कार्य के अलावा फिल्म प्रभाग सरकारी विभागों व मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को वृत्तचित्र निर्माण में सहायता देता है।

फिल्म प्रभाग का **न्यूजरील खंड** समस्त भारत के प्रमुख शहरों और कस्बों में फैले अपने नेटवर्क के जरिए, प्रमुख घटनाओं, अति

विशिष्ट व्यक्तियों के देश-विदेश भ्रमण तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि की कवरेज कराता है। इस कवरेज को पाक्षिक न्यूज मैगजीनों और अभिलेखन सामग्री के संकलन में भी प्रयुक्त किया जाता है।

प्रभाग की कार्टून फिल्म इकाई उच्च प्रौद्योगिकी युक्त हो गई है। सेल और क्लासिकल एनीमेशन की जगह कंप्यूटर एनीमेशन ने ले ली है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कला प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ प्रभाग की कार्टून फिल्म इकाई के उन्नत प्रौद्योगिकी वाले, यू.एस. एनीमेशन, 2 डी और 3 डी एनीमेशन का निर्माण, ओपर, कंसर्टो, हाइ एण्ड माया जैसे अत्याधुनिक साफ्टवेयर सहित किया जा सकता है। कमेंटरी अनुभाग अंग्रेजी और हिंदी में बनी फिल्मों और न्यूज मैगजीनों का 14 भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में रूपान्तरण तैयार करता है। प्रभाग की दिल्ली स्थित निर्माण इकाई, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रेरक फिल्मों तैयार करती है। बदलते समय के अनुसार इस इकाई को अब वीडियो फिल्म बनाने की सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है।

प्रभाग के कोलकाता और बंगलूर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों ने सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों जैसे परिवार कल्याण, सांप्रदायिक सद्भाव, दहेज, बंधुआ मजदूर, छूआछूत आदि पर सामाजिक और शैक्षिक वृत्तचित्रों का निर्माण किया है।

वितरण खंड

फिल्म प्रभाग के वितरण खंड में 1200 सिनेमाघरों के लिए एक के अनुपात में शाखा कार्यालय हैं। इस समय इसके दस शाखा कार्यालय, बंगलौर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, मदुरै, नागपुर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में हैं। वर्ष 2005-06 में 23 दिसंबर 2005 तक देश भर में हर सप्ताह 9857 सिनेमाघरों में कुल 5 से 6 करोड़ लोगों ने प्रभाग द्वारा जारी फिल्मों देखी। फिल्म प्रभाग क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों को फिल्मों के प्रिंट और वीडियो कैसेट उपलब्ध कराता है। इसके वृत्तचित्र दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर दिखाए जाते हैं। शिक्षा संस्थान, फिल्म सोसायटी और सामाजिक संस्थान भी प्रभाग के वितरण कार्यालयों की लाइब्रेरी से फिल्मों लेकर दिखाते हैं। प्रभाग ने 1 अप्रैल 2005 से 23 दिसंबर 2005 के बीच 28 वृत्त चित्र और 12 न्यूज मैगजीन के कुल 10,900 प्रिंट सिनेमाघरों के लिए जारी किए। इसके अलावा राज्य सरकारों के लिए 3 वृत्तचित्र और 4 न्यूज मैगजीन के कुल 431

प्रिंट जारी किए गए। दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण के लिए 119 फिल्मों भेजी गईं। मुंबई में 8 संस्थानों और अन्य संगठनों को प्रदर्शन के लिए 15 फिल्मों के प्रिंट उधार दिए गए।

प्रभाग की फिल्मों के वीडियो कैसेट रेलवे, सार्वजनिक संस्थानों, केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों, शिक्षा संस्थानों और निजी संगठनों को गैर-व्यवसायी प्रयोग के लिए बेचे जाते हैं। 1 अप्रैल 2005 से 30-12-2005 के बीच प्रभाग ने फिल्मों के तीन प्रिंट, 453 वी.एच.एस., 1205 वी.सी.डी. 241 डी.वी.डी. 6 बीटी कैसेट कुल 357,533 रुपये में गैर-व्यवसायी प्रयोग के लिए बेचे और 8416 रुपये में एक प्रिंट की बिक्री विदेश के लिए की गई। 6,16,310 रुपये के स्टॉक शाट्स भी बेचे गए। इस दौरान 77,291 रुपये की राशि रायल्टी के रूप में अर्जित की गई। इसी अवधि के दौरान 7613 वी एच एस कैसेट और 273 वी सी डी क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को 11,80,379 रुपये में बेचे गए। इसके अतिरिक्त 9 वी सी डी, प्रधानमंत्री कार्यालय, 9 वी सी डी विदेश मंत्रालय और 9 वी सी डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए। विदेश मंत्रालय का विदेश प्रचार विभाग फिल्म प्रभाग से चुनिंदा फिल्मों के प्रिंट लेकर विदेशों में स्थित दूतावासों को उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और कुछ निजी एजेंसियां भी प्रभाग की फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय वितरण की व्यवस्था करती हैं। विदेशी टेलीविजन और वीडियो नेटवर्क भी प्रभाग की फिल्मों को रायल्टी के आधार पर दिखाते हैं। प्रभाग की 119 फिल्मों क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित करने के लिए भेजी गईं।

अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्म समारोह

फिल्म प्रभाग को वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्मों के मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह द्विवार्षिक समारोह है। वर्ष 1990 में इस समारोह की शुरुआत हुई थी, और 3 से 9 फरवरी 2004 तक आयोजित समारोह इस कड़ी का आठवां आयोजन था। वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्मों का नौवां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह मुंबई के पी.एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी में 3 से 9 फरवरी 2006 तक सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित हो रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां

इस वर्ष के दौरान फिल्म प्रभाग ने विभिन्न विषयों पर कई फिल्मों

का निर्माण किया। जीवनी पर आधारित फिल्मों में, के.आर. नारायणन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, रानी शशमोनी, कुमार गंधर्व, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार गणपति सतपथी, पं. राम नारायण, शंकर देव प्रमुख हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भारत की ज्ञानवर्द्धक अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर, ग्रामीण भारत के लिए नये विचार, शीर्षक से फिल्में बनीं। स्वास्थ्य पर चीर-फाड़ से नशाबंदी नहीं, जनसंख्या स्थिरीकरण पर अधिकार प्राप्त कार्य समूह, रक्षा क्षेत्र पर हवाई रक्षा नियंत्रण और सामरिक युद्ध क्षेत्र की कहानी तथा ए आर वी के बी-वाहनों के प्रयोग से समुत्थान तकनीक पर फिल्में बनाई गई।

फिल्म प्रभाग की फिल्मों का डिजीटलीकरण और वेबकास्टिंग

लम्बे समय से रखी फिल्म प्रभाग की काफी फिल्में सड़-गलकर खराब हो गईं। इन फिल्मों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भावी पीढ़ी के लिए इनके पुनरुद्धार और परिरक्षण की जरूरत है। ये फिल्में फिल्म प्रभाग अभिलेखागार पुनरुद्धार और परिरक्षण योजना के अन्तर्गत संरक्षित की जाती हैं। फिल्म-प्रभाग की फिल्मों का

वर्ष 2005-2006 में फिल्म प्रभाग की प्रमुख गतिविधियों की झलक

- 1 अप्रैल 2005 से 30 नवंबर 2005 तक फिल्म प्रभाग की ओर से 21 वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्में (17 फिल्में विभाग की ओर से बनाई गईं और 3 फिल्मों का निर्माण निजी निर्माताओं ने किया) तथा 9 न्यूज मैगजीन बनाई गईं।
- 1 अप्रैल 2005 से 31 दिसंबर 2005 तक 29 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया गया जिनमें 81 फिल्में दिखाई गईं। इसके अलावा 24 राष्ट्रीय फिल्म समारोह व राज्य स्तरीय फिल्म समारोहों में 120 फिल्में प्रदर्शित की गईं।
- 1 अप्रैल 2005 से 23 दिसंबर 2005 तक सिनेमाघरों के लिए 40 फिल्मों के 10,900 प्रिंट जारी किए गए।
- उपरोक्त अवधि के दौरान सिनेमा प्रदर्शकों से किराए के रूप में 4,24,04,449 रुपये अर्जित किए गए।
- 1 अप्रैल 2005 से 31 दिसंबर 2005 तक प्रिंटो/कैसेटों/वीसीडी/बीटा 1 स्टाक शॉट और रायल्टी आदि से 10,59,550 रुपये की राशि अर्जित की गई।
- उपरोक्त अवधि के दौरान कुल 1341 सूचनाप्रद और शिक्षाप्रद फिल्मों का डिजीटलीकरण किया गया।
- 1 अप्रैल 2005 से 30 नवंबर 2005 तक किराए, प्रिंटों, स्टाक शॉट, वीडियो कैसेटों की बिक्री तथा अन्य प्राप्तियों से कुल 528 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि अर्जित की गई।

डिजीटलीकरण और वेबकास्टिंग इसी परियोजना का आधुनिक स्वरूप है। इंटरनेट के व्यापक विस्तार के साथ-साथ दूरदर्शन सूचना प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसलिए फिल्म प्रभाग भी अपनी सूचनाप्रद और शिक्षाप्रद फिल्मों के वितरण के लिए ऐसे ही आधुनिक मार्गों को अपनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा की फिल्मों का डिजीटलीकरण और परिरक्षण करना जरूरी है ताकि इनका प्रसारण और हस्तांतरण सुलभ हो

सके। इस दिशा में कदम उठाते हुए फिल्म प्रभाग द्वारा जल्दी ही अपनी सेल्युलाइड फिल्मों को ऊंची बिड दर (करीब 9 एम वी पी एस) पर 4:2:0 की हाई डेफिनेशन टेप्स में बदलने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ-साथ हाई डेफिनेशन टेप्स पर अतिरिक्त डिजीटल ऑडियो ट्रांसफर की व्यवस्था है। इस वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2005 से 31 दिसंबर 2005 तक फिल्म प्रभाग ने 1341 फिल्मों का डिजीटलीकरण किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों का

वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वेबसाइट पर 220 घण्टे की अवधि के लिए फिल्में जारी करने का विचार किया गया है। इससे पहले ही फिल्म प्रभाग 330 घंटों की फिल्मों को कूटबद्ध करके अपने सरकारी वेबसाइट www.filmdivision.org में अप लोड कर चुका है। कूटबद्ध फिल्मों को नेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है ताकि उनके विभिन्न अंशों को सुगमता से देखा जा सके।

वेबसाइट और फिल्मों के वेबकास्टिंग को पूरे विश्व के वृत्तचित्र प्रेमियों द्वारा पसंद किया जा रहा है। वीडिओ और साफ्टवेयर की बढ़ती मांग के मद्देनजर फिल्म प्रभाग की फिल्मों को डी वी डी में बदलने का कार्य शुरू करने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

डिजिटल 2 डी/3 डी एनीमेशन स्टूडियो : फिल्म प्रभाग की चर्चित कार्टून फिल्म इकाई में परंपरागत एनीमेशन के स्थान पर कंप्यूटर एनीमेशन शामिल कर लिया गया है। हार्डवेयर और साफ्टवेयर की आधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ कार्टून फिल्म

इकाई ओपेरु, कंसर्ट हाई एड और माया जैसे साफ्टवेयर से यू.एस. - एनीमेशन, 2-डी और 3-डी एनीमेशन भी तैयार करती है।

प्रेस के लिए प्रदर्शन और सामान्य प्रदर्शन

गोर्की सदन, कोलकाता में फिल्म ‘ड्रीम्स ऑफ रविन्द्रनाथ’ का प्रेस शो आयोजित किया गया।

फिल्म प्रभाग ने इंडिया टाइम्स के सहयोग से प्रचुर सामग्री वेबसाइट www.filmdivision.org पर जारी किया।

लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322वीं और बंगाली फिल्म लवर्स सोसायटी ने के.जी. दास की फिल्मों का सिंहावलोकन आयोजित किया। फिल्म प्रभाग के सिनेमाघर में तीन सामान्य शो प्रस्तुत किए गए।

उधार पर फिल्म : मुंबई में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 8 संस्थानों

राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाने के लिए फिल्म प्रभाग की चुनिंदा फिल्में भारतीय पेनोरमा 2005 : फिल्म प्रावधि (आलार्मेल घाटी के नृत्य) विशेष प्रदर्शनों के लिए चुनी/प्रदर्शित फिल्में

क्रम संख्या	समारोह का नाम	प्रदर्शित फिल्म
1	बालीवुड एण्ड बियांड फिल्म समारोह बर्लिन	19 वृत्तचित्र
2	आशय फिल्म क्लब	10 वृत्तचित्र
3	हैदराबाद फिल्म क्लब - हैदराबाद	वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्म
4	कोलकाता नगर निगम	भारत के महान संतों पर वृत्तचित्र
5	फाइन आर्ट सोसायटी मुंबई	फारयेवर ए लेजेण्ड
6	प्रभात चित्रा मंडल मुंबई	सिद्धेश्वरी
7	चौराहा एन सी पी - ए मुंबई	सादेकला का छऊ और प्रवाही नृत्य
8	सुभाष लेन, गणेश सेवा मंडल, मुंबई	अंबेल सजग यात्रा और मेल का रास्ता
9	थर्ड आई फिल्म समारोह, मुंबई	कला मंडलम
10	अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह हैदराबाद	प्रतिबिम्ब, और हमारी पृथ्वी

और अन्य संगठनों को 15 फिल्मों उधार दी गईं।

फिल्म प्रभाग में आगंतुक : सात कालेजों और संस्थानों के 125 से अधिक विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने फिल्म प्रभाग का दौरा किया।

आयोजित समारोह : फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्रों के आयोजित समारोह इस प्रकार हैं।

- i) वायस ऑफ वडाला, मुंबई
- ii) वडाला सी जी एस कालोनी मुंबई
- iii) अंटोप हिल सी.जी.एस. कालोनी मुंबई।

फोटोग्राफों द्वारा कवर की गई घटनाएं :

- गणतंत्र दिवस
- शाखा प्रबंधक सम्मेलन
- अंटोप हिल फिल्म समारोह
- फिल्म प्रभाग की वेबसाइट जारी करना।
- वर्ग निर्धारण के लिए बैठक
- हिन्दी कार्यशाला
- डॉ. बी आर अम्बेडकर जयंती
- स्वतंत्रता दिवस
- हिन्दी सप्ताह
- सतर्कता जागरण सप्ताह

राष्ट्रीय अभियान में सहयोग

फिल्म प्रभाग ने सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकीकरण, अस्पृश्यता के बारे में शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय अभियानों को अपने वृत्तचित्रों, मैगजीनों और वीडियो फिल्मों के माध्यम से सतत प्रचार और संचार में सहयोग प्रदान किया।

फिल्मों का वितरण : 1 अप्रैल 2005 से 23 दिसंबर 2005 तक की अवधि में फिल्म प्रभाग ने सिनेमाघरों के लिए महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर आधारित 28 वृत्तचित्रों और 12 न्यूज मैगजीनों के 19900 प्रिंट जारी किए।

फिल्म लाइब्रेरी : फिल्म प्रभाग की फिल्म लाइब्रेरी भारत के समसामयिक इतिहास, समृद्ध धरोहर और कलात्मक परंपराओं संबंधित अमूल्य अभिलेखन सामग्री का खजाना है। दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं में इसकी बहुत अधिक मांग है। फिल्मों के निर्माण के लिए यह महत्वपूर्ण फुटेज प्रदान करने के साथ-साथ स्टॉक फुटेज की बिक्री से आय भी अर्जित करती है। फिल्म लाइब्रेरी में लगभग 1.9 लाख वस्तुएं हैं जिनमें मूल-पिक्चर निगेटिव, ड्यूप/इंटर निगेटिव, साउंड-निगेटिव, मास्टर/ इंटर पाजिटिव, सेचुरेटेड प्रिंट, इंटरनेशनल ट्रेक्स, प्रीडब साउंड-निगेटिव 16 मि.मी. प्रिंट, लाइब्रेरी प्रिंट, इंटरनेशनल ट्रेक्स, प्रीडब साउंड-निगेटिव 16 मि.मी प्रिंट, लाइब्रेरी प्रिंट तथा आनसर प्रिंट्स शामिल हैं। अभिलेखन महत्व की सभी फिल्मों डी वी डी फार्मेट में बदली जा चुकी हैं। अब तक डी वी डी फार्मेट में 2089 वृत्तचित्र, 1837 न्यूज रील तथा 255 न्यूज मैगजीन बदली जा चुकी हैं। लाइब्रेरी में यूजर-फ्रेंडली कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली मौजूद है। बदलती प्रौद्योगिकी के साथ-साथ, फिल्म लाइब्रेरी के बारे में विस्तृत सूचना और चुनींदा फिल्मों को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। जिससे पूरे विश्व में प्रभाग की फिल्मों को देखा जा सके।

फिल्म प्रभाग योजनागत कार्यक्रमों का निष्पादन :

वर्ष 2005-2006 के लिए फिल्म प्रभाग का योजना परिव्यय 12 47 लाख रुपए है जिसमें निम्नलिखित योजनागत कार्यक्रम शामिल हैं।

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र लघु और एनीमेशन फिल्म समारोह

स्वीकृत परिव्यय

98.00 लाख रुपये

नवंबर 2005 तक हुआ खर्च

3.52 लाख रुपये

फिल्म प्रभाग को वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्मों के मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 1990 में इस समारोह की शुरुआत हुई। 3 से 9 फरवरी 2006 तक आयोजित किया जाने वाला समारोह इस कड़ी का नौवां समारोह है।

इसमें दो खंड होते हैं - अंतर्राष्ट्रीय फिल्म/वीडियो प्रतियोगिता और राष्ट्रीय फिल्म/वीडियो प्रतियोगिता। प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में सर्वोत्तम फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा चुना जाता है और 26 लाख रुपये के नकद पुरस्कारों के साथ स्वर्ण और रजत शंख दिए जाते हैं। 1996 में स्थापित डा. व्ही शांताराम पुरस्कार भारत के वरिष्ठ वृत्तचित्र निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। एम.आई.एफ.एफ.-2006 में पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख कर दी गई है। इस समारोह का आयोजन, विश्व भर के फिल्म निर्माताओं के मिलने-जुलने, विचार-विमर्श करने, सह निर्माण की संभावना तलाशने और फिल्मों के विपणन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। एम.आई.एफ.एफ 2006 के बारे में प्रविष्टि फार्म, नियम और अधिनियम सहित सभी जानकारी वेबसाइट www.filmdivision.org पर उपलब्ध कराई गई है। यहां से भी प्रतिभागी फिल्म निर्माता प्रविष्टि फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने अपनी अलग से वेबसाइट www.miffindia.org और www.filmsdivision.org शुरू की है। यहां से भी प्रतिभागी फिल्म निर्माता प्रविष्टि फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। एमआईएफएफ-2006 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में भारत समेत 30 देशों से 186 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं और राष्ट्रीय वर्ग में 388 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं हैं।

नौवें एम आई एफ एफ-2006 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के फिल्म निर्माताओं के लिए एक विशेष पैकेज की शुरुआत की गई है जिसके तहत 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एम आई एफ एफ-06 में पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीन फिल्म-समारोह आयोजित करने के लिए 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर संघटक पर खर्च के लिए कुल 40 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ब) फिल्म प्रभाग का आधुनिकीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना

स्वीकृत व्यय

एक करोड़ पांच लाख रुपये

नवंबर 2005 तक हुआ व्यय

000.00 लाख रुपये

फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र, न्यूज मैगजीन और लघु फिल्मों का निर्माण करता है। समय बीतने के साथ-साथ इस प्रभाग के विभिन्न उपकरण घिस जाने या टूट-फूट और प्रौद्योगिकी में बदलाव के चलते बेकार हो चुके हैं। विश्व भर में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी और इसके समतुल्य फिल्म प्रभाग की कार्यकुशलता बनाए रखने के परिपेक्ष्य में इन उपकरणों का संवर्धन और आधुनिकीकरण जरूरी है ताकि प्रभाग गुणवत्ता की दृष्टि से पीछे न रह जाए। सेल्युलाइड फार्मेट में फिल्म प्रभाग की ओर से वृत्तचित्रों के निर्माण के अलावा वीडियो फार्मेट में कार्यक्रम तैयार करने की विभिन्न मंत्रालयों की ओर से मांग निरन्तर बढ़ती रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो फार्मेट में कार्यक्रम बनाने के लिए फिल्म प्रभाग को जरूरी उपकरणों से सज्जित और विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस समय कार्टून फिल्म इकाई एनीमेशन फिल्में बनाती है और वृत्तचित्रों के लिए एनीमेशन दृश्य भी परंपरागत तरीके से ही तैयार करती है।

इसलिए अब सेल एनीमेशन के स्थान पर कंप्यूटर सहायता प्राप्त एनीमेशन प्रणाली प्रयुक्त किये जाने की जरूरत है ताकि और अधिक कार्टून फिल्में बन सकें। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से फिल्म प्रभाग ने “आधुनिकीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना” योजना जारी रखी है। एस.एफ.सी. के अनुमोदन का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया और मंत्रालय से मिली मंजूरी के तहत उपकरण की प्राप्ति के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। मंत्रालय का सुझाव है कि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के योजना कार्यक्रम के अंतर्गत खरीदे जाने वाले उपकरणों के मूल्यांकन के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ रखा जाए और अनुमोदन के लिए एक नया तर्कसंगत एस एफ सी ज्ञापन भेजा जाए। बाहरी विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है।

(स) प्रभाग की फिल्मों का डिजिटलीकरण और वेबकास्टिंग:

स्वीकृत खर्च

दो करोड़ रुपये

नवंबर 2005 तक का खर्च

043.94 लाख रुपये

फिल्म प्रभाग की फिल्मों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वेबसाइट पर 220 घंटे की अवधि के लिए फिल्में जारी करने का विचार किया गया और वीडियो फिल्म तथा साफ्टवेयर की बढ़ती मांग को देखते हुए फिल्म प्रभाग की फिल्मों को डी वी डी में बदलने का प्रस्ताव योजना कार्यक्रम के तहत किया गया। फिल्मों को डीवीडी में बदलने के लिए कार्यवाही शुरू

हो चुकी है। वेबसाइट पर दृश्य-श्रव्य सामग्री नियमित अन्तराल पर बदली जा रही है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर 2005 तक योजना कार्यक्रम के तहत प्रभाग की 1341 फिल्मों डीवीडी पर हस्तान्तरित की गईं और अंतरराष्ट्रीय ट्रेक पर 606 फिल्मों डीवीडी पर हस्तान्तरित की गईं। इस पर कुल 49 लाख 76 हजार रुपये खर्च हुए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित संघटक के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्षेत्र से संबंधित विषयों पर आधारित फिल्मों के डिजीटलीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है।

(द) चलचित्रों के लिए संग्रहालय की स्थापना :

**स्वीकृत व्यय
खर्च**

**7 करोड़ 44 लाख रुपये
000.00 लाख**

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ फिल्म प्रभाग ने अपने मुंबई स्थित परिसर में चलचित्रों का एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार किया है।

- (1) भारतीय सिनेमा के विकास क्रम को दर्शाना तथा भावी पीढ़ी को फिल्म-निर्माण के क्षेत्र में हुए चरणबद्ध बदलाव से अवगत कराना।
- (2) नवोदित फिल्म निर्माताओं के लिए कार्यशाला और संगोष्ठियों को आयोजन करना।
- (3) वृत्तचित्र फिल्म आन्दोलन के क्षेत्र के प्रति भावी पीढ़ी में रुचि पैदा करना।
- (4) फिल्म उत्साहियों के लिए एक प्रदर्शनी दीर्घा शुरू करना।
- (5) जानी मानी संस्थाओं और निर्देशकों के वृत्तचित्रों के लिए एक स्थाई संग्रहालय स्थापित करना।

इस संदर्भ में मंत्रालय के निर्देशानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में बी इ सी आई एल को 10 लाख रुपये की धनराशि हस्तान्तरित कर दी गई है। इस बारे में आगे की वित्तीय और कार्य सम्बन्धी प्रगति बी इ सी आई एल के द्वारा किए गये प्रयासों के समानुपाती होगी। इस परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय की ओर से मापदण्ड निर्धारित किया जा रहा है।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना 1973 में सूचना एवं प्रसारण

मंत्रालय के अन्तर्गत एक कार्यालय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करना है। जिसके लिए निदेशालय निम्न गतिविधियों का आयोजन करता है।

1. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन।
2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहेब फालके पुरस्कार संबंधी आयोजन।
3. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और भारतीय फिल्मों का विदेशों में भारतीय मिशन के माध्यम से प्रदर्शन।
4. भारतीय पेनोरमा का चयन।
5. विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी
6. भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन।
7. प्रिंट संग्रहण और प्रलेखन।

निदेशालय अपनी निम्न गतिविधियों के माध्यम से सिनेमा के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच अनुभवों, विचारों तथा संस्कृति के आदान-प्रदान के लिए बेजोड़ मंच प्रदान करता है। यह भारतीय सिनेमा को सशक्त मंच प्रदान करने का माध्यम है जो भारतीय फिल्मों के लिए वाणिज्यिक अवसर भी पैदा करता है। यह विश्व सिनेमा की नवीनतम प्रवृत्तियों से देश के फिल्म उद्योग, छात्रों और आम लोगों को अवगत कराता है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आई.एफ.एफ.आई-2005

परिचय

36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2005 का आयोजन 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2005 तक गोवा में, वहां की सरकार के सहयोग से किया गया।

समारोह कार्यक्रम

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2005 में 43 देशों ने भाग लिया। 'विश्व सिनेमा' खंड और विदेशी फिल्मों के अन्य वर्गों के तहत कुल 97 फिल्मों दिखाई गईं। समारोह के प्रमुख खंड 'विश्व सिनेमा' की लगभग सभी फिल्मों पहले ही अन्य समारोहों में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थीं। प्रतियोगी खंड में 14 फिल्मों दिखाई गईं। असाधारण और मुख्य धारा के भारतीय सिनेमा, भारतीय पेनोरमा, श्रद्धांजलि, प्रशस्ति, सिंहावलोकन जैसे विविध वर्गों में 71

भारतीय फिल्मों में दिखाई गई। समारोह में प्रदर्शित सभी 182 फिल्मों का प्रेस और प्रतिनिधियों के लिए प्रदर्शन पांच थिएटरों में किया गया। समारोह के दौरान प्रेस/प्रतिनिधियों, आम लोगों तथा जूरी के लिए कुल 311 शो किए गए। लोगों को एक सप्ताह तक दो थियेटरों में फिल्मों दिखाई गईं।

उद्घाटन समारोह

36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह - आई एफ एफ आई 2005 का उद्घाटन 24 नवंबर, 2005 को सांय साढ़े पांच बजे इनोक्स मल्टीप्लैक्स के मैदान में किया गया। इसमें देव आनंद मुख्य अतिथि थे। केन्द्रीय शहरी विकास और संस्कृति मंत्री जयपाल रेड्डी तथा गोवा के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने दर्शकों को संबोधित किया। तेलुगु फिल्मों के युवा सक्रिय अभिनेता चिरंजीवी

ने सम्मान्य अतिथि के रूप में दर्शकों को संबोधित किया। बिपाशा बसु और तारा ने दीप प्रज्वलित करने में अतिथियों की सहायता की और जयपाल रेड्डी ने समारोह के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। इसके बाद प्रतियोगी खंड की जूरी के सदस्यों का दर्शकों से परिचय कराया गया।

उद्घाटन फिल्म के प्रदर्शन से पहले भारतीय सिनेमा के इतिहास तथा आर्विभाव का प्रदर्शन किया गया और प्रमुख फिल्मी अभिनेताओं/अभिनेत्रियों ने संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्राजील की जेमी मोन्जार्दिन द्वारा निर्देशित उद्घाटन फिल्म *ओल्गा* का प्रदर्शन इनोक्स मल्टीप्लैक्स की सभी चारों स्क्रीन पर लूपिंग प्रणाली से किया गया। उद्घाटन समारोह में फिल्मों से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां, प्रतिष्ठित व्यक्ति और अधिकारी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में



केन्द्रीय संस्कृति और शहरी विकास मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी, पणजी (गोवा) में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन करते हुए, 24 नवम्बर, 2005

केवल आमंत्रित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। उद्घाटन समारोह पहले से निर्धारित मिनट दर मिनट कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न किया गया। फिल्म समारोह के निम्न खंड थे :

1 प्रतियोगी खंड

एशियाई, अफ्रीकी तथा लेटिन अमरीकी निर्देशकों की फीचर फिल्में। प्रतियोगी खण्ड में 13 देशों ने भाग लिया और इसमें 14 फीचर फिल्में दिखाई गईं। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में एशिया के अलावा दो और महाद्वीप अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका भी शामिल हुए।

प्रतियोगी खंड जूरी में शामिल थे - चिली के मिग्यूएल लिट्टिन (अध्यक्ष), ईरान के जाने-माने अभिनेता फार्माज़ गारिबियन (सदस्य),

भारत के जाने माने फिल्म निर्माता सईद अख्तर मिर्ज़ा (सदस्य), फ्रांस के पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता एलेन कोर्नीयू (सदस्य) और ऑस्ट्रिया की विख्यात फिल्म निर्देशक सुश्री सबाइन डेरफ्लिंगर (सदस्य)।

पुरस्कार

- (क) सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर और दस लाख रुपए नकद का पुरस्कार, ईरानी फिल्म - ईरान आईलैण्ड के निर्देशक मोहम्मद रासोलोफ को दिया गया।
- (ख) सर्वाधिक उदीयमान निर्देशक के लिए रजत मयूर और पांच लाख रुपये नकद का पुरस्कार, अर्जेन्टीना की फिल्म कैप्ट एण्ड ड्रीमलैस (लस मैन्टैनीडास सिन सुएनोस) की निर्देशक सुश्री वीरा इयूजिना फोगविल और श्री मार्टिन देसाल्वो को



नई दिल्ली में आयोजित 52वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री अदूर गोपालकृष्णन को वर्ष 2004 के लिए दादा साहेब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में श्री अदूर गोपालकृष्णन के शानदार योगदान के लिए दिया गया है, 21 अक्टूबर, 2005

दिया गया।

(ग) विशेष जूरी पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की फिल्म रेड डस्ट के निर्देशक टॉम हूपर को दिया गया। इसके तहत रजत मयूर और पांच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।

2. विश्व सिनेमा खंड

यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रमुख औपचारिक पुरस्कार है। 36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2005 में इस खंड के अन्तर्गत, पिछले लगभग दो वर्षों में बनी 39 देशों की 61 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों दिखाई गईं। ये वे फिल्मों थीं जिन्हें अपने देश तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार मिल चुके थे या फिर इन्हें काफी सराहा गया था। अधिकतर देशों की फिल्मों इसलिए शामिल की गईं थीं ताकि विभिन्न देशों के सिनेमा में आ रही नवीनतम प्रवृत्तियों की झलक मिल सके। इस खंड की लगभग सभी फिल्मों को काफी सराहना मिली।

3. विदेश सिंहावलोकन, देश संकेंद्रण, श्रद्धांजलि

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह - 2005 के विदेश सिंहावलोकन खंड में इटली के फिल्म निर्देशक लाइन वर्टमुल्लर की फिल्म, फ्रांस की अभिनेत्री इसाबैले हर्पर्ट की फिल्म, बादेन वर्टर्मबर्ग से फिल्मों, जाने माने फिल्म निर्माता इस्माईल मर्चेंट की श्रद्धांजलि और ईरान से फिल्मों शामिल थीं। इस खंड में कुल 29 फिल्मों दिखाई गईं।

4. जर्मन छात्र (लघु) फिल्मों

जर्मनी से सात पुरस्कार विजेता छात्र फिल्मों में प्रदर्शित विविधता और मनोरंजन से विशेषकर फिल्म संस्थान के छात्र बहुत प्रभावित हुए।

5. भारतीय खंड

इस खंड में निम्न उपखंड थे :

1. भारतीय पेनोरमा
2. भारतीय मुख्यधारा
3. श्री ऋषिकेश मुखर्जी का सिंहावलोकन
4. संगीत का विशेष खंड

5. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण

6. श्रद्धांजलि

7. प्रीमियर

भारतीय पेनोरमा : इस खंड का शुभारंभ 25 नवंबर 2005 को जयराज द्वारा *दैवनामथिल* (मलयालम फीचर) और गौतम सैक्या द्वारा जॉस ऑफ डैथ से किया गया। कुल 21 फीचर और 16 गैर फीचर फिल्मों प्रदर्शित की गईं।

भारतीय मुख्यधारा : इस खंड का उद्घाटन भारतीय फिल्म परिसंघ के अध्यक्ष श्री आदि सेषागिरि राव ने किया। इस खंड का शुभारंभ संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म *ब्लैक* से किया गया। इसमें भारतीय फिल्म परिसंघ द्वारा सुझाई गई 12 फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया।

ऋषिकेश मुखर्जी का सिंहावलोकन : इस खंड का आयोजन ऋषिकेश मुखर्जी की प्रशस्ति के लिए किया गया। इसका उद्घाटन राजेश खन्ना ने 27 नवंबर 2005 को अपनी फिल्म आनंद से किया। इसमें संपादक-निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की छह फिल्मों का प्रदर्शन करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया।

विशेष संगीत खंड : इस खंड का उद्घाटन प्रख्यात तेलुगु निर्देशक के. विश्वनाथ ने किया और इस खंड को रोचक बना दिया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण : इस नए खंड के अंतर्गत 50 वर्ष पहले राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली दो फिल्मों - *श्यामची आई* (मराठी-1953) और *मिर्जा गालिब* (हिन्दी-1954) प्रदर्शित की गईं। 90 वर्षीय अभिनेत्री वनमाला देवी ने भी ये फिल्मों देखीं। उन्होंने समारोह को संबोधित किया और दर्शकों के मन में पुरानी यादें ताजा कर दीं।

श्रद्धांजलि : समारोह में जैमिनी गणेशन की फिल्म *पार्थीबन कनावू* (तमिल) और सुनील दत्त की फिल्म *मुझे जीने दो* दिखाकर इन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन प्रदर्शनों में जैमिनी गणेशन की पुत्रियों डा. कमला सेल्वाराज और जानी मानी अभिनेत्री रेखा ने भाग लिया। इस समारोह में सुनील दत्त के दामाद कुमार गौरव भी उपस्थित हुए।

प्रीमियर : समारोह में निम्नलिखित फिल्मों के प्रीमियर भी आयोजित किए गए जिनमें इन फिल्मों के सितारों ने भाग लिया।

1. विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 'दिवाने हुए पागल' (हिन्दी)
2. राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित 'परजनिया' (अंग्रेजी)
3. विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित 'ब्लू अम्ब्रेला' (अंग्रेजी)
4. डा. मृणालिनी पाटिल दयाल द्वारा निर्देशित 'मंथन - एक अमरुल प्याला' (मराठी)
5. प्रकाश झा द्वारा निर्देशित 'अपहरण' (हिन्दी) - मिड फेस्ट गाला में वर्ल्ड प्रीमियर
6. आदित्य भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 'दुबई रिटर्न' (हिन्दी)

विशेष खंड

मास्टर क्लासेस नामक एक विशेष खंड का संचालन फिल्म निर्माता विजय सिंह ने किया। समारोह के दौरान श्याम बेनेगल, डॉलोरेस चैपलिन, एलेन कॉर्नीयू, मधुर भंडारकर, सिमॉन रेलफ, सुधीर मिश्रा जैसे जाने माने फिल्म निर्माताओं ने कक्षाओं का संचालन किया।

समापन समारोह

36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का समापन समारोह 4 दिसंबर 2005 को कला अकादमी में हुआ। प्रतियोगिता को जूरी के अध्यक्ष मिग्यूएल लिट्टिन ने दर्शकों को संबोधित किया और पुरस्कारों की घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव और बंगाल से जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी समारोह को संबोधित किया और पुरस्कार प्रदान किए।

समारोह का समापन फ्रांस के जीन पॅरे दार्देन और ल्यूस दार्देन द्वारा निर्देशित फिल्म *द चाइल्ड (एल एन्फैंट)* से किया गया। इसे पहले कला अकादमी में और बाद में इनोक्स की चारों स्क्रीन पर दिखाया गया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

52वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत तीन जूरी का गठन किया गया जिसमें फिल्म उद्योग के विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल किया गया। फीचर फिल्मों की 16 सदस्यों की जूरी के प्रमुख सुधीर मिश्रा थे तथा 6 सदस्यों की गैर फीचर फिल्मों की जूरी के प्रमुख ए.के. बीर थे जबकि सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए तीन सदस्यों की जूरी के अध्यक्ष रॉफ अहमद थे।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 21 अक्टूबर 2005 को किया गया। माननीय राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों का प्रदर्शन 4 से 13 अक्टूबर, 2005 तक सिरीफोर्ट काम्प्लेक्स के दो ऑडिटोरियम में किया गया।

मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म पेज 3 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण कमल और पचास हजार रुपये नकद दिए गए। गैर फीचर फिल्म वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार उमेश कुलकर्णी द्वारा निर्देशित फिल्म *गिरनी* हिंदी को दिया गया। सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार रूपा स्वामीनाथन और वर्ष 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार नम्रता जोशी को दिया गया।

भारतीय पेनोरमा 2005

भारतीय पेनोरमा के लिए फिल्मों का चयन पांच सदस्यों की दो जूरी ने किया। फीचर फिल्म जूरी के प्रमुख एम एस सैथ्यू थे और गैर फीचर फिल्म जूरी के प्रमुख अरिबम श्याम शर्मा थे। जूरी ने सितंबर अक्टूबर 2005 को फिल्मों को देखने के बाद 21 फीचर और 16 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया। भारतीय पेनोरमा पैकेज का प्रदर्शन गोवा में आयोजित 36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किया गया। इन फिल्मों के निर्माता और निर्देशक भी इनके प्रदर्शन के समय उपस्थित थे।

उन्होंने गोवा के पणजी में कला अकादमी के मीडिया सेंटर में अपनी फिल्मों के बारे में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। निदेशालय ने इन फिल्मों का विस्तृत ब्यौरा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। इस पुस्तिका को समारोह के दौरान भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों को वितरित किया गया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम/भागीदारी तथा विशेष पैकेज समाहांत फिल्म समारोह

देव आनंद की फिल्मों, पाथेर पांचाली के 50 वर्ष - सत्यजीत रे को एक श्रद्धांजलि, कादल मन्नान - जैमिनी गणेशन (किंग ऑफ रोमांस) और सुनील दत्त को श्रद्धांजलि के सिलसिले में फिल्मों का प्रदर्शन, नई दिल्ली के सिरीफोर्ट आडिटोरियम-II में किया गया।

यंग तुर्क्स (तुर्की - जर्मन सिनेमा) फिल्म समारोह का आयोजन नई दिल्ली के सिरीफोर्ट आडिटोरियम-II में किया गया।

भारतीय फिल्मों ने भी भारत तथा विदेश में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। यह समारोह हैं - तिरुअनंतपुरम फिल्म समारोह, सिनेफैन फिल्म समारोह, एशियाई फिल्म समारोह, मध्य प्रदेश में भारतीय फिल्म समारोह, कोलकाता फिल्म समारोह, पांडिचेरी में भारतीय फिल्म समारोह, मद्रास फिल्म समारोह, ऑरोफिल्म समारोह तमिलनाडु और त्रिचुर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। भारतीय फिल्म समारोहों का आयोजन सी ई पी के तहत मैक्सिको, दोहा और मलेशिया में किया गया।

भारतीय फिल्मों ने दिसंबर 2005 तक 22 देशों में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में हिस्सा लिया। ये देश हैं- सिंगापुर, स्पेन, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इटली, नीदरलैंड, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जिम्बाब्वे, ईरान, ब्रसेल्स, कजाकिस्तान, बेलग्रेड, फिलिपीन्स, थाइलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, इण्डोनेशिया और मिस्र।

कुल स्वीकृत 48 पदों में से, एक पद संयुक्त निदेशक का, एक पद उपनिदेशक का, एक पद सहायक का, एक पद आशुलिपिक 'डी', तीन पद यू डी सी, एक पद सफाई वाले का, एक पद सुरक्षा गार्ड का एक पद स्टॉफ कार ड्राइवर का और एक पद मजदूर का रिक्त पड़ा है। बारह पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हैं।

कार्य अध्ययन

ई.आर.सी. सिफारिशों पर अंतिम फैसला आने तक आंतरिक कार्य अध्ययन एकक की सिफारिशें लागू करना लंबित रखा गया है।

फिल्म समारोह निदेशालय में सतर्कता तथा शिकायत संगठन

1. सतर्कता

फिल्म समारोह निदेशालय की गतिविधियां

क्रम संख्या	गतिविधियां	2003-2004		2004-2005		2005-2006			
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां		
1.	भारतीय पेनोरमा	1	1	1	1	1	1		
2.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत फिल्म समारोह तथा अन्य प्रदर्शन	1. भारत में		6	4	6	5		
		2. विदेशों में		6	8	6	3		
3.	विदेशी फिल्म समारोह में भागीदारी (फिल्मों को पहुंचाना और लाना सहित)	45	55	45	23	45	34		
4.	राष्ट्रीय फिल्म समारोह	1	1	1	1	1	1		
5.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	1	1	1	1	1	1		
6.	भारतीय पेनोरमा की फिल्मों के सबटाइटल के प्रिन्ट की तैयारी								
		(क) फीचर फिल्में		21	18	21	21	21	21
		(ख) गैर फीचर फिल्में		21	13	21	20	21	16

वरिष्ठ उपनिदेशक शंकर मोहन को फिल्म समारोह निदेशालय में सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है।

2. शिकायतें

उप निदेशक (प्रशासन) निदेशालय के शिकायत अधिकारी हैं। निदेशालय को इस वर्ष के दौरान कोई शिकायत/फरियाद नहीं मिली

और ऐसा कोई मामला समाधान के लिए लंबित भी नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में रिपोर्ट

इस निदेशालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई पद रिक्त नहीं है।

इस वर्ष की मुख्य घटनायें

फिल्म समारोह निदेशालय

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI 2005)

- भारत का 36वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2005 तक गोआ में राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। देव आनंद इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।
- इस वर्ष यह प्रतिस्पर्धा एशिया के अतिरिक्त अफ्रीका और लेटिन अमरीका के दो और महाद्वीपों में विस्तारित किया गया।

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह 21 अक्टूबर, 2005 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया जिसमें वर्ष 2004 के दौरान निर्मित फिल्मों के पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार श्री अदूर गोपालकृष्णन को दिया गया।

अन्य झलकियां

- देव आनन्द की फिल्मों का समारोह, 'पाथेर पांचाली' के 50 वर्ष - सत्यजीत राय को श्रद्धांजलि, क्राधल मन्नान - जेमिनी गणेशन (रोमांस के बादशाह) तथा 'सुनील दत्त को श्रद्धांजलि' नई दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम-II में आयोजित किए गये।
- 'यंग तुर्कस' (तुर्की-जर्मन सिनेमा) फिल्म समारोह सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम-II, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- भारतीय फिल्मों ने भारत तथा विदेश में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, जैसे त्रिवेन्द्रम फिल्म समारोह, सिनेफैन फिल्म समारोह, एशियन फिल्म समारोह, मध्य प्रदेश में भारतीय फिल्म समारोह, कोलकाता फिल्म समारोह, पांडेचिरी में भारतीय फिल्म समारोह, मद्रास फिल्म समारोह, ऑरोफिल्म समारोह, तमिलनाडु तथा त्रिशुर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, में भाग लिया।
- भारतीय फिल्म समारोह मैक्सिको, दोहा तथा मलेशिया में सीईपी के तहत आयोजित किए गये।
- भारतीय फिल्मों ने वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2005 तक 22 देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी भाग लिया। ये देश थे : सिंगापुर, स्पेन, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इटली, नीदरलैंड, अमरीका, आस्ट्रिया, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, जिम्बाब्वे-इरान, ब्रूसल्स, कजाकिस्तान, बेलग्रेड, फिलीपीन्स, थाइलैंड, डेनमार्क, इन्डोनेशिया और मिस्र।

उपनिदेशक (प्रशासन) को निदेशालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।

वर्ष 2005-2006 के लिए हिन्दी भाषा में कामकाज के बारे में रिपोर्ट

- (1) हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म समारोह निदेशालय के कर्मचारी, काफी कामकाज मूल रूप से हिंदी भाषा में ही कर रहे हैं।
- (2) दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों या विचार के समानार्थकों को कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है।
- (3) इस वर्ष हिन्दी निबन्ध/टिप्पणी/पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

वर्ष 2005-2006 के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जन्म शताब्दी और पुण्यतिथि के सिलसिले में आयोजन किए गए।

अधिकारियों तथा अन्य कर्मियों ने 'आतंकवाद विरोधी दिवस' पर शपथ ग्रहण की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की याद में 30 जनवरी को मौन रखा गया।

कम्प्यूटीकरण

- (1) निदेशालय की अपनी वेबसाइट है-dffiffi@hub.nic.in.
- (2) कार्यालय में लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है।
- (3) सभी अधिकारी तथा कर्मचारी कम्प्यूटर पर काम करते हैं और अधिकतर पत्राचार ई मेल के ज़रिए किया जाता है।

लेखा

फिल्म समारोह निदेशालय, सिरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रखरखाव करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, इस परिसर में फेरबदल तथा संयोजन पर पंद्रह करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंत्रालय ने वर्ष 2002-03 और वर्ष 2003-04 के लिए 3 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपए की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी। इसमें से वर्ष 2002-03 के दौरान डेढ़ करोड़ रुपए और वर्ष 2003-04 के दौरान एक करोड़ अठारह लाख रुपए दिए गए। चालू वित्त वर्ष 2005-

2006 के लिए मंत्रालय ने एक करोड़ 96 लाख रुपए की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी है।

निदेशालय, सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम को कार्यक्रम आयोजनों के लिए किराए पर भी देता है। किराया राशि और सेवा कर को सरकारी खाते में जमा किया जाता है। इसे चलान के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी (एम एस), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के खाते में जमा किया जाता है।

नई पहल

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2005 के प्रतिस्पर्धा खंड में प्रविष्टियां एशिया के अतिरिक्त दो अन्य महाद्वीपों, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में विस्तारित की गईं।

एक अन्य नया खंड "एन एफ ए गोल्ड" इफ्फी 2005 में जोड़ा गया। इस खण्ड में दो फिल्में यानि श्यामची आई (मराठी-1953) तथा मिर्जा गालिब (हिन्दी-1954), जिन्होंने 50 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जीता था, भी दिखाई गईं।

उपर्युक्त के अलावा 'मास्टर्स क्लास' नामक एक विशेष खंड भी इफ्फी 2005 में जोड़ा गया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के महान फिल्मकारों ने भाग लिया तथा समारोह के दौरान फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर कक्षाएं आयोजित की।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व

विश्व भर में फिल्म को कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सहेजने की महत्ता पहचानी गई है। सिनेमा को उसकी विविध अभिव्यक्तियों और रूपों में संरक्षित करने का कार्य एक ऐसे राष्ट्रीय संगठन को दिया गया जिसके पास पर्याप्त संसाधन, स्थायी ढांचा और स्थानीय फिल्म उद्योग का विश्वास है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व की स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई :

1. राष्ट्रीय सिनेमा को भावी पीढ़ी के लिए धरोहर के तौर पर प्राप्त करके संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का प्रतिनिधि संग्रह तैयार करना।
2. फिल्म से संबंधित डाटा का वर्गीकरण करके उसे सहेजना, सिनेमा पर शोध कार्य करना तथा उसे बढ़ावा देना और इन अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन और वितरण करना।

3. देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के केन्द्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा का प्रचार करना।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने अपने 42 वर्ष के काल के दौरान इन उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पहली अप्रैल 2005 तक एन एफ ए आई ने 70 नई फिल्मों का संग्रह किया। इनमें 14 डुप्लीकेट प्रिंट, और 151 फिल्मों मुफ्त संग्रह के तौर पर 23 वीडियो कैसेट, 179 किताबें, 2,138 पटकथाएं 11 स्लाइड 2,112 चित्र 14,380 प्रेस कतरने, 42 गीत पुस्तिकाएँ, 254 पोस्टर, 3 फिल्म फोल्डर और 13 डीवीडी., शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय से 80 वृत्तचित्र भी प्राप्त किए गए। रिपोर्ट में दर्शायी गई अवधि के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई से 35 चित्र और ध्वनि नेगेटिव भी पुरातत्व में संरक्षण के लिए प्राप्त किए गए। संग्रह के लिए फिल्म केन्द्र, मुंबई से लगभग 22 सौ रील भी प्राप्त की गई। 163 फिल्मों की रील केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से पुरातत्व के उद्देश्य से प्राप्त की गई। अनुलग्नक 'अ' में विस्तृत ब्यौरा दिया है।

फिल्म संस्कृति का प्रसार

भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार से संबंधित गतिविधियों में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। देश भर में उसकी वितरण लाइब्रेरी के लगभग 40 सक्रिय सदस्य हैं। पुरातत्व अपने साथ प्रमुख केन्द्रों पर साप्ताहिक पाक्षिक और मासिक आधार पर फिल्म शो का आयोजन भी करता है। इसके अलावा फिल्मों के प्रशिक्षण योजना के तहत पुरातत्व अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। इन पाठ्यक्रमों के लिए यह भारतीय फिल्म और टेलिविजन संस्थान तथा अन्य शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों से सहयोग लेता है।

पुणे में इस वर्ष आयोजित फिल्म पाठ्यक्रम में 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 4 सप्ताह के इस पाठ्यक्रम में विभिन्न निकायों और पेशेवरों ने हिस्सा लिया।

- तीसरा पुणे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 14 से 20 जनवरी 2005 में आयोजित किया गया। इसके लिए राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरातत्व ने ऑडिटोरियम और पुरातत्व फिल्मों देकर सहयोग किया।
- पुरातत्व ने रूपकला केन्द्र, कोलकाता को नन्दन में 15 से 21

फरवरी 2005 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक संचार सिनेमा सम्मेलन के लिए 7 फिल्मों की आपूर्ति की।

- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने युवा विकास और गतिविधि केन्द्र द्वारा आयोजित लघु फिल्म कोर्स के लिए फिल्मों की आपूर्ति प्रिव्यू थियेटर प्रदान किया। इस कोर्स में 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसी प्रकार का एक अन्य पाठ्यक्रम महिन्द्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज, पुणे ने आयोजित किया था जिसमें 16 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था।
- आशय फिल्म क्लब की पहल पर पुणे में तीसरा एशियाई फिल्म समारोह आयोजित किया गया जिसके लिए राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरातत्व ने कार्यक्रम सहयोग दिया।

पुरातत्व ने कई अन्य उत्सव भी आयोजित किए जिसमें फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों की फिल्मों प्रदर्शित की गईं। इसके लिए पुरातत्व ने एलाइंस फ्रेनसाइज, मैक्समुलर भवन और रूसी सांस्कृतिक केन्द्र, मुम्बई का सहयोग लिया।

वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने जिन अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष पैकेज की आपूर्ति की उनमें महत्वपूर्ण हैं:-

- मुम्बई में आयात-निर्यात फिल्म प्रदर्शन के लिए मजलिस को 'लाइट ऑफ एशिया' फिल्म उपलब्ध कराई गई।
- पुणे में मार्च 2005 में राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरातत्व के सहयोग से "लाइट, कैमरा, एक्शन" फिल्म समारोह के लिए डी वाई पाटिल इंजीनियरिंग कालेज के रोट्रेक्ट क्लब को पांच फिल्मों की आपूर्ति की गई।
- सिनेमा में संगीत पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए युवा विकास और गतिविधि केन्द्र, पुणे को फिल्म सप्लाय की गई।
- महिलाओं द्वारा निर्मित फिल्म समारोह के लिए आई सी ए फोरम चेन्नई को फिल्म की आपूर्ति की गई। 30 अप्रैल से 1 मई 2005 तक पुणे में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह के लिए कार्यक्रम सहयोग दिया गया। तिरुअनंतपुरम में आयोजित फिल्म समारोह में एफआई एलसीए को 15 फिल्मों की आपूर्ति की गई।
- नई दिल्ली में सिरीफोट ऑडिटोरियम में आयोजित स्वर्गीय

वर्ष के दौरान प्राप्त की गई महत्वपूर्ण फिल्मों निम्नलिखित हैं:

सीताराम कल्याणम	एन.टी. रामाराव/तेलुगु/1961
हरियाली और रास्ता	विजय भट्ट/1962
आयात सीनेमेक अर्धशतक	श्रीनिवास जोशी/मराठी/1967
हर हर गंगे	बाबूभाई मिस्त्री/हिंदी/1978
दादर कीर्ति	तरूण मजूमदार/बंगाली/1980
पथिक	जब्बार पटेल/अंग्रेजी/1988
मैंने प्यार किया	ताराचंद बड़जात्या/हिंदी/1989
हम आपके हैं कौन	सूरज आर बड़जात्या/हिंदी/1994
लाल दर्जा	बी देशगुप्ता/बंगाली/1996
अनल	परमानंद राजवंशी/असमी/1999
माझा/दी रैन	लेनिन राजेन्द्रम/मलयालम/2000
एक और एक ग्यारह	डेविड धवन/हिंदी/2002
हमराज	अब्बास मस्तान/हिंदी/2002
हम किसी से कम नहीं	डेविड धवन/हिंदी/2002
मैंने दिल तुझको दिया	शोहेल खान/हिंदी/2002
परदेशी रे	केवल कृष्ण/हिंदी/2002
तीजन बाई	बी पकरीस्वामी/हिंदी/2002
आकाशीतोद्धार कथा रे	संगीता तमोली/असमी/2003
अव आकरे आ	सुभाष दास/उड़िया/2003
भालो देखो	गौतम हलदर/बंगाली/2003
भूत	रामगोपाल वर्मा/हिंदी/2003
छायाम	बीजु सी कानन/मलयालम/2003
चोखेर बाली	रितुपर्णोघोष/बंगाली/हिंदी डब/2003

चौदा	वेणुगोपाल/मलयालम/2003
डांस लाइक ए मैन	पॉमेली रॉक्स/अंग्रेजी/2003
इयारकी	एस पी शनातन/तमिल/2003
फंटूश	इम्तियाज पंजाबी/हिंदी/2003
गंगाजल	प्रकाश झा/हिंदी/2003
गैंग्स आफ न्यूयॉर्क	मार्टिन स्कोर्स/हिंदी डब/2003
हवा	गुड्डू धानोआ/हिंदी/2003
हजारों ख्वाइशें ऐसी	सुधीर मिश्रा/हिंदी/अंग्रेजी/तेलुगु/2003
जोड़ी क्या बनी वाह-वाह रामजी	विवेक सुचांती/हिंदी/2003
कल हो न हो	निखिल आडवाणी/हिंदी/2003
खाकी	राजकुमार संतोषी/हिंदी/2003
कोई मिल गया	राकेश रोशन/हिंदी/2003
कुछ तो है	अनिल वी कुमार/हिंदी/2003
क्यों	कल्पना लाजमी/हिंदी/2003
माहुल बानिर सेरिंग	शेखर दास/बंगाली/2003
मानसरोवर	अनुप कुरियन/मराठी/2003
मकबूल	विशाल भारद्वाज/हिंदी/2003
मारगम	राजीव विजय राघवन/मलयालम/2003
मीनाक्षी 'ए टेल ऑफ श्री सिटीज'	एम.एफ. हुसैन/हिंदी/2003
नई पड़ोसन	बी एच तरूण कुमार हिंदी/2003
नॉट ओनली मिसेज राउत	अदिति देशपांडे/मराठी/2003
पिंजर	डा० चन्द्रप्रकाश द्विवेदी/हिंदी/03
पिथामागन	वी ए दुरई/तमिल/2003
परवाना	पी आर रामदास नायडू/कनाडा/2003
प्रीति प्रेम प्रणया	कविता लंकेश/कनाडा/2003

रूद्राक्ष	मणिशंकर/हिंदी/2003
समय	रूबि ग्रेवाल/हिंदी/2003
टैगोर	वी विनायक/तेलुगु/2003
अकेली	श्यामा प्रसाद/मलयालम/2004
अलीशा	राजेन्द्र तललाक/कोंकणी मोनो/2004
अंजी	कोडी रामकृष्णा/तेलुगु/2004
ऑटोग्राफ	चेरन/तमिल/2004
चले चलो	सत्यजीत/भटकल/हिंदी/2004
छोटा सिपाही/लिटिल सोल्जर	जयश्री केनाल के एस कामत/हिंदी/2004
छुटकन की महाभारत	संकल्प मेशराम/हिंदी/2004
देव	गोविंद निहलानी/हिंदी/2004
ग्रहानाम	मोहन कृष्ण इंदिरा गांधी/तेलुगु/2004
हम तुम	कुणाल कोहली/हिंदी/2004
आई कुड नाट बी योर सन मॉम	सोहनी दासगुप्ता/अंग्रेजी/2004
आई टी आई श्रीलंका	अंजन दास/बंगाली/2004
क्यों हो गया ना	समीर कार्निक/हिंदी/2004
रेनकोट	रितुपर्णो घोष/हिंदी/2004
शादी का लड्डू	राज कौशल/हिंदी/2004
स्वदेश	आशुतोष गवारीकर/हिंदी/2004
स्वापनेर डिन	बुद्धदेव दास गुप्ता/बंगाली/2004
स्वाराभिषेकम	के विश्वनाथ/तेलुगु/2004
उत्तरायन	बिपिन नादकर्णी/मराठी/2004
इकबाल	नागेश कुकुनूर/हिंदी 2005

जैमिनी गणेशन के फिल्म पुनरावलोकन के लिए 7 फिल्में फिल्म समारोह निदेशालय को दी गईं। वरिष्ठ अभिनेता सुनील दत्त का भी पुनरावलोकन आयोजित किया गया। जून 2005 में फिल्मोत्सव 2005 आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश सूचना केन्द्र, भोपाल को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने 4 फिल्मों की आपूर्ति की।

- महान निर्देशक सत्यजीत रे की 'पाथेर पंचाली' की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए विभिन्न फिल्म समितियों को इस फिल्म के प्रिंट भेजे गये। यह फिल्म नई दिल्ली में आयोजित 7वें एशियाई सिनेमा फिल्म उत्सव में भी प्रदर्शित की गई।
- फिल्म और विकलांगता पर एबिलिटी फाउंडेशन, चेन्नई द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला के लिए 8 फिल्में सप्लाई की गईं। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर 6 मूक फिल्मों भी प्रदर्शित की गईं।
- 26 अगस्त से 1 सितम्बर 2005 को त्रिचूर में आयोजित द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 41 फिल्मों का एक पैकेज दिया गया।
- 22 अगस्त से 28 अगस्त 2005 तक सांस्कृतिक केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित फिल्म समारोह के लिए 7 फिल्में सप्लाई की गईं।
- मुम्बई में ग्रेजुएट ऑफ फिल्म एण्ड टी वी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुनरावलोकन "इन फोकस" के लिए 8 फिल्मों की आपूर्ति की गई।
- पुरातत्व ने आरईएसीएच-ग्रामीण कला और सांस्कृतिक विरासत उद्यमता, देहरादून द्वारा विरासत उत्सव आयोजित करने के लिए कार्यक्रम-सहयोग दिया और 8 फिल्मों की आपूर्ति की।
- अक्टूबर 2005 में मुम्बई में "थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल" आयोजित करने के लिए प्रभात चित्र मंडल, मुम्बई को पुरातत्व ने 4 फिल्में उपलब्ध कराईं।
- 26 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2005 तक आयोजित द्वितीय कोच्चि अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन के लिए कोच्चि फिल्म समिति को 8 फिल्में उपलब्ध कराई गईं।
- 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2005 तक चेंगनचेरी, कोट्टायम

में संत जोसेफ कॉलेज ऑफ कम्प्यूनीकेशन और राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरातत्व द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव आयोजित किया गया। इसके लिए 27 फिल्में उपलब्ध कराई गईं।

- 10 नवम्बर से 17 नवम्बर, 2005 तक ग्यारहवें कोलकाता अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 10 फिल्में नन्दन को सप्लाई की गईं।
- नई दिल्ली में इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कालजयी फिल्मों के समारोह के लिए 6 फिल्में उपलब्ध कराई गईं।
- 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक हैदराबाद में आयोजित 12वें एशियाई बाल फिल्म समारोह के लिए 3 फिल्में सप्लाई की गईं।
- पणजी गोवा में आयोजित 36वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए फिल्म समारोह निदेशालय को 7 फिल्मों की आपूर्ति की गई।
- 21 से 25 नवम्बर 2005 में पुणे में रूसी सांस्कृतिक केन्द्र मुम्बई और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व द्वारा संयुक्त रूप से रूसी फिल्म समारोह आयोजित किया गया।
- 1 से 7 दिसम्बर 2005 के बीच पुणे में तीसरा यूरोपीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया। इसका आयोजन संयुक्त रूप से एलायंस फ्रांसाइज, ब्रिटिश लाइब्रेरी, मैक्समुलर भवन और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने किया।
- मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और कोचिन में एफ एफ एस आई द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के लिए अनेक फिल्में उपलब्ध कराई गईं।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और अन्य विशेष कार्यक्रमों के लिए भेजी गईं फिल्में-

- मार्च 2005 के दौरान रॉयल ट्रापिकल इंस्टीट्यूट, एम्सर्टडम नीदरलैंड को मलयालम फिल्म समारोह के लिए 'नीलाक्कूल' और 'अम्मा अरियन' फिल्में भेजी गईं।
- मई 2005 के दौरान रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत म्यूजियम आफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयार्क को 'संत तुकाराम', 'कालिया मर्दन' और 'राजा हरिश्चन्द्र' फिल्में प्रदर्शन के लिए भेजी गईं।

- जुलाई 2005 में कोलम्बो में श्रीलंका के राष्ट्रीय फिल्म कारपोरेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला के लिए 11 फिल्मों भेजी गई।
- अगस्त 2005 के दौरान दक्षिण कोरिया में आयोजित पुसान अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 'भुवन शोम' फिल्म भेजी गई।

थियेटर सुविधाएं

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के पास दो थियेटर हैं जिसमें क्रमशः 330 और 30 सीटों की क्षमता है। पुरातत्व द्वारा अपने कार्यक्रम तथा फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अलावा इन सुविधाओं का लाभ अन्य संस्थानों द्वारा उनके कार्यक्रम, भाषण और सेमिनार आयोजित करने के लिए किया जाता है।

पुणे में मैक्समुलर भवन और एलायंस फ्रांसाइज अपने सदस्यों के लाभ के लिए और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व फिल्म सर्किल के सदस्यों के लाभ के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम प्रदर्शित करते रहते हैं। आलोच्य अवधि के दौरान मुख्य ऑडिटोरियम और प्रिव्यू थियेटर को 560 कार्यक्रमों के लिए किराये पर दिया गया।

अनुसंधान गतिविधियां

आलोच्य अवधि के दौरान जैसा कि दूसरे हमें देखते हैं भारत पर विदेशियों द्वारा बनाई गई फिल्मों पर एक अनुसंधान परियोजना तथा 2 मौखिक इतिहास परियोजना जो कि वयोवृद्ध राजनेता चन्द्रकांत गोखले और ए नागेश्वर राय पर आधारित थे, पूरे किए गये।

संरक्षण कार्य

भारत की चल छवि विरासत की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उसके संरक्षण के लिए सतत और विशेष प्रयास किये जायें। इस कार्य में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण पर्दानशी नामक फिल्म है जिसको पुरातत्व ने बंगलौर के एक निजी गोदाम से प्राप्त किया। यह फिल्म 1940 के पूर्वार्ध में बनी थी।

निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को सुविधाएं

कॉपीराइट मालिकों को डिपॉजिट समझौते के तहत राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरातत्व निर्माताओं और कॉपीराइट मालिकों को अपनी सेवाएं

देने के प्रति वचनबद्ध है। इन सेवाओं के तहत एक मौलिक निगेटिव की मरम्मत के लिए कच्ची फिल्म की सप्लाई, डुप्लीकेट प्रिंट तैयार करने और प्रसारण उद्देश्य के लिए वीडियो तैयार करने में मदद करता है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व को इस बात का गर्व है कि उसने हाल के वर्ष में अपनी पहल पर कई फिल्मों का पुनरुद्धार किया है। कई सेट्टेलाइट चैनलों और राष्ट्रीय उपग्रह टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली फिल्मों को उसने अपने संग्रह से प्रसारण के लिए दिया है। इन गतिविधियों से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक 'स' में उपलब्ध हैं।

योजना और गैर योजना

योजना परिव्यय

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व का वर्ष 2005-07 के दौरान दो योजनाओं के लिए 472 लाख रुपये के बजट का प्रावधान था। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के बीच पुरातत्व के लिए 1,360 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।

अप्रैल से दिसम्बर 2005 की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने 179 किताबें, 11 स्लाइड, 3 फिल्म फोल्डर, 2,138 फिल्मों की पटकथाएं, 2,112 चित्र, 42 गीत-पुस्तिकाएं, 14,380 प्रेस कतरने और 254 दीवार पोस्टर प्राप्त किए। पुरातत्व ने इस दौरान 235 फिल्मों, 23 वीडियो कैसेट और 13 डी वी डी प्राप्त किए। इनमें से 6 भारतीय फिल्म के सब टाइटल अंग्रेजी में थे।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के लिए भवन निर्माण के दूसरे चरण का काम प्रगति पर है।

वर्ष 2005-06 के दौरान योजना प्रदर्शन एनेक्स्वर ब में दर्शाया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के लिए बजट प्रावधान भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के कार्य की प्रकृति को देखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के लिए बजट प्रावधान की संभावनाओं पर विचार नहीं किया गया।

पहली जनवरी 2006 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि के दौरान अनुमानित कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-

अवधि के दौरान करीब 50 फिल्मों, 50 वीडियो कैसेट और डी वी डी प्राप्त किए जायेंगे। पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के भवन निर्माण के दूसरे चरण का 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

योजना और गैर योजनागत बजट के लिए निम्नलिखित वक्तव्य हैं:

प्रशासन

संगठनात्मक ढांचा

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व का मुख्यालय पुणे में है। इसके तीन कार्यालय हैं जो बंगलौर, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में कार्य कर रहे हैं। इन तीन क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कार्य फिल्म समितियों, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रों में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय कार्यालय का कार्य निदेशक देखते हैं, जिसमें उनका सहयोग उपनिदेशक करते हैं। उपनिदेशक मुख्यालय में तकनीकी और प्रशासनिक शाखा के प्रमुख होते हैं। वर्तमान में उपनिदेशक के पास निदेशक का कार्यभार

योजना और गैर योजना के लिए		बजट अनुमान 2005-06 (लाख रुपये में)		
2005-2006		योजना	गैर योजना	कुल
मुख्य शीर्ष 2220-सूचना और प्रचार				
राजस्व खंड		72.00	109.00	181.00
मुख्य शीर्ष पंजीगत परिव्यय (सूचना एवं प्रचार)				
● भवन		400.00	--	400.00
कुल		472.00	109.00	581.00
संशोधित अनुमान 2005-2006				
मुख्य शीर्ष 2220 (सूचना और प्रचार)				
राजस्व खंड		73.00	133.08	206.08
मुख्य शीर्ष 4220 पूंजीगत परिव्यय (सूचना एवं प्रचार)				
● भवन		400.00	--	400.00
कुल		473.00	133.08	606.08
बजट अनुमान 2006-07				
मुख्य शीर्ष 2220 (सूचना और प्रचार)				
राजस्व खंड		73.00	143.00	216.30
मुख्य शीर्ष 4220 पूंजीगत परिव्यय (सूचना एवं प्रचार)				
● भवन		500.00	--	500.00
कुल		573.00	143.08	716.30

भी है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के मुख्यालय और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में 51 लोग कार्यरत हैं। इनमें से 25 प्राशासनिक शाखा में और 26 तकनीकी शाखा में कार्य कर रहे हैं।

जनजातीय उपयोजना/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजना के सम्बन्ध में बजट प्रावधान

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के कार्यों की प्रकृति को देखते हुए जनजातीय उपयोजना/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजना के सम्बन्ध में बजट प्रावधान पर विचार नहीं किया गया।

समितियां/आयोग

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व की एक सलाहकार समिति है और इन पुनर्गठित समिति में पांच सरकारी और पांच गैर सरकारी सदस्य हैं। संयुक्त सचिव फिल्म इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति की वर्ष के दौरान 27 अगस्त, 2005 को बैठक हुई।

फिल्म पुरातत्व का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ—एफ आई ए एफ

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व मई 1969 से फिल्म पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ का सदस्य है। इसका सदस्य होने के कारण पुरातत्व को फिल्मों के संरक्षण के बारे में विशेषज्ञों की राय, अन्य जानकारी और सामग्री प्राप्त होती रहती है। इसके जरिये दस्तावेज और ग्रंथ सूचियां तैयार करने में भी मदद मिलती है। परिसंघ के माध्यम से पुरातत्व आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत अन्य देशों के पुरातत्व विभागों से दुर्लभ फिल्मों की आदान-प्रदान की सुविधा भी प्राप्त होती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को नियमानुसार भरा गया है।

सरकारी भाषा में हिंदी का प्रयोग

14 से 30 सितम्बर, 2005 को हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में नकद इनाम प्रदान किए गए।

विभागीय लेखा

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने 1976 में विभागीय लेखा प्रणाली शुरू की थी। इस व्यवस्था के तहत पुरातत्व का वेतन और लेखा

विभाग का नियंत्रण फिल्म प्रभाग, मुंबई के वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुरातत्व के निदेशक विभाग के प्रमुख होने के नाते आहरण एवं वितरण अधिकारी मनोनीत किए गए हैं जिन्होंने ये अधिकार पुरातत्व के प्राशासनिक अधिकारी को दे रखे हैं।

लेखा परीक्षण में लंबित आपत्तियां

पुस्तकालय से कीताबें गुम होने, कच्चे माल की जांच और फिल्मों के भंडार के व्यक्तिगत निरीक्षण के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण की आपत्तियां अभी लंबित हैं। इनको शीघ्र पूरा किए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कार्य योजना का क्रियान्वय

पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के भवन के दूसरे चरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रतिनियुक्ति/शिष्टमंडल

पुरातत्व के निदेशक ने नौवें दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत श्रव्य दृष्य पुरातत्व संगठन के वार्षिक सम्मेलन और दो मई से 6 मई, 2005 के दौरान बुनई में आयोजित आम सभा में हिस्सा लिया

24 से 26 जुलाई, 2005 के दौरान कोलम्बो में राष्ट्रीय फिल्म निगम श्रीलंका द्वारा फिल्मों पर आधारित कार्यशाला आयोजित करवाने के लिए पुरातत्व के निदेशक स्वयं कोलम्बो गए।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में किए गए कार्य के बारे में नीतिगत वक्तव्य

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण पर जारी नीतिगत वक्तव्य के दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुए इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक उपाय किए और मंत्रालय द्वारा जारी मानदंडों का पालन किया।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व मुख्यतः आवासीय क्षेत्र में स्थित है और आम तौर पर इस इलाके को नागरिक इकाइयों द्वारा स्वच्छ रखा जाता है और इस कार्य में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व भी पूरा सहयोग करता है।

पुरातत्व ने अपने परिसर को हरा-भरा रखने के लिए विशेष ध्यान दिया है। फिल्मों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायनों में हानिकारक पदार्थों की मात्रा नगण्य है और यह फिल्म पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है। अपने आसपास के क्षेत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व की गतिविधियों से नुकसान पहुंचने की कोई संभावना नहीं है।

सतर्कता गतिविधियां

आलोच्य वर्ष के दौरान सतर्कता गतिविधियों के बारे में सूचनाएं निम्नलिखित हैं :

1. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता ढांचे का ब्यौरा

कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है इसलिए कार्यालय प्रमुख होने के नाते निदेशक को ही मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पदभार सौंपा गया है।

2. अवधि के दौरान सतर्कता गतिविधियां

अ. वर्ष के दौरान नियमित निरीक्षणों की संख्या : 12

ब. अवधि के दौरान औचक निरीक्षणों की संख्या : 4

3. अवधि के दौरान निगरानी और खुफिया गतिविधियां

अ. निगरानी के लिए चुनी गई फिल्मों की सुरक्षा और उनका प्रतिरूप तैयार करना

ब. निगरानी के तहत रखे गए व्यक्तियों की संख्या-शून्य

4. दंडात्मक गतिविधियां

1. अवधि के दौरान शिकायतें/संदर्भ की संख्या : 0

2. उन मामलों की संख्या जिसमें प्राथमिक जांच की गई : 01
3. प्राथमिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या : 0
4. बड़े दंड के लिए आरोप पत्र जारी होने वाले मामलों की संख्या : 0
5. छोटे दंड के लिए आरोप पत्र जारी होने वाले मामलों की संख्या : 0
6. ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको बड़ा दंड दिया गया : 0
7. ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको छोटा दंड दिया गया : 0
8. निलंबित किए गए व्यक्तियों की संख्या : 0
9. चेतावनी या प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या : 0
10. नियमों के प्रावधान के अनुसार समय से पहले सेवा निवृत्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या : 0

अनुलग्नक 'अ'

31 दिसम्बर, 2005 को समाप्त हुए वर्ष में पुरातत्व के लिए प्राप्ति का वक्तव्य

सामग्री	31-12-2004	जनवरी-दिसम्बर 2005	31.12.2005
फिल्में	15,591	542	16,133
वीडियो कैसेट्स	2,220	44	2,264
किताबें	25,228	272	25,500
पटकथाएं	29,953	3,227	33,180
प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स	1,098	—	1,098
स्टिल्स	1,21,420	3,352	1,24,772
दीवार पोस्टर	12,269	402	13,671
संगीत पुस्तिकाएं	10,313	142	10,455
ऑडियो टेप	170	2	172
प्रेस कतरनें	1,43,493	16,216	1,59,709
पेंपलेट्स/फोल्डर्स	7,955	47	8,002
स्लाइड्स	8,361	122	8,483
माइक्रोफिस्च	42	—	42
माइक्रोफिल्म्स	1,957	—	1,957
डिश रिकॉर्ड्स	2,973	—	2,973
ऑडियो कम्पैक्ट डिक्स	98	57	155
डी वी डी	266	21	287

योजना निष्पादन 2005-2006

अनुलग्नक 'ब'

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम/योजना	अनुमोदित योजना परिव्यय 2005-06	पूर्वानुमानित व्यय 2005-06 के दौरान	नवम्बर 2005 तक का खर्च
पुरातत्व फिल्म का अधिग्रहण और प्रदर्शन	72.00	73.00	38.33
नई योजना पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व के लिए भवन निर्माण का फेज-II	400.00	400.00	300.00
कुल	472.00	473.00	338.33

एन एफ ए आई की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आंकड़े

	रीलों की संख्या		
	16 एम.एम.	35 एम.एम.	
1. फिल्मों की विस्तृत जांच	-	180	
2. फिल्मों की दैनिक जांच	554	23,182	
फिल्म संस्कृति को प्रोत्साहन			
1. वितरण, पुस्तकालय सदस्य	10 (नया)	30 (पुर्ननवीनीकरण)	40 (कुल)
2. पुस्तकालय सदस्यों में फिल्मों के वितरण की संख्या	71		
3. विशेष अवसरों के लिये फिल्मों का वितरण	271		
4. संयुक्त प्रदर्शन	40		
5. फिल्म प्रोत्साहन पाठ्यक्रम के लिये फिल्मों का वितरण	192		
6. प्रोड्यूसर/कापीराइट मालिकों/वीडियो बनाने के लिये फिल्मों का वितरण	46		
7. शोधार्थियों के लिए फिल्म देखने की सुविधाओं में विस्तार	30		
8. एफ.टी.आई.आई. को शैक्षिक प्रदर्शनों के लिए फिल्मों का वितरण	189		
9. कुल दिखाई गई फिल्मों की संख्या	133		
10. पुस्तकालय सेवा प्राप्त करने वाले पाठकों की संख्या	1675		
11. प्रलेखन खंड की सेवाएं प्राप्त करने वाले शोधार्थियों की संख्या	1365		

केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत गठित केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) भारत में प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करता है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 25 गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय - बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में हैं। सलाहकार पैनल फिल्मों की जांच में क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करते हैं। इन पैनलों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। 13 अक्टूबर 2004 से मशहूर फिल्मी हस्ती शर्मिला टैगोर बोर्ड की अध्यक्ष हैं।

वर्ष 2004 में 5472 के मुकाबले जनवरी से दिसंबर 2005 के दौरान बोर्ड ने 7488 प्रमाण-पत्र जारी किए। इनमें 3231 प्रमाण-पत्र बड़े पर्दे की फिल्मों के लिए तथा 4257 वीडियो फिल्मों के लिए जारी किए। इस अवधि के दौरान 1041 भारतीय फीचर फिल्मों और 270 विदेशी फीचर फिल्मों प्रमाणित की गईं। वर्ष में प्रमाणित फिल्मों का प्रमाणपत्रवार और वर्गवार विवरण परिशिष्ट-II और III में दिया गया है।

जनवरी से दिसंबर 2005 के दौरान प्रमाणित 1499 भारतीय फीचर फिल्मों में 992 को 'यू' प्रमाण-पत्र, 257 को 'यूए' प्रमाणपत्र तथा 250 को 'ए' प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसी प्रकार वर्ष के दौरान प्रमाणित 671 विदेशी फिल्मों में से 206 को 'यू' प्रमाण-पत्र, 157 को 'यू ए' प्रमाण-पत्र तथा 308 को 'ए' प्रमाण-पत्र दिए गए हैं।

बोर्ड ने जनवरी से दिसंबर 2005 के दौरान कुल 4569 भारतीय लघु फिल्मों को प्रमाणित किया जिनमें से 4279 को 'यू' प्रमाण-पत्र 194 को 'यू ए' प्रमाण-पत्र और 193 को 'ए' प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसी वर्ष 636 विदेशी लघु फिल्मों में से 491 को 'यू' प्रमाण-पत्र, 76 को 'यू ए' प्रमाण-पत्र और 69 को 'ए' प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। जनवरी 2005 से दिसंबर 2005 के दौरान कुल 4257 वीडियो फिल्मों को प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इनमें 458 भारतीय फीचर फिल्मों, 401 विदेशी फीचर फिल्मों, 3079 भारतीय लघु फिल्मों, 310 विदेशी लघु फिल्मों तथा 9 फिल्मों अन्य वर्गों (फीचर फिल्मों की बजाय लंबी फिल्मों) भी थीं।

जनवरी से दिसंबर 2005 के दौरान 9 भारतीय फीचर फिल्मों तथा 4 विदेशी फीचर फिल्मों को सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के खंड 5बी(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के एक या दो से अधिक उल्लंघन के कारण प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए। इनमें से कुछ को संशोधन के बाद प्रमाणित किया गया।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों की 107वीं बैठक 6 मई 2005 को मुंबई में आयोजित हुई।

फिल्मों के प्रमाणन के लिए सलाहकार पैनलों के सदस्यों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पिछले वर्ष की तरह ही सलाहकार पैनलों के सदस्यों और परीक्षण अधिकारियों के लाभ हेतु विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में फिल्मों के परीक्षण के दौरान आने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ तथा फिल्म प्रमाणन के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश तय करने के लिए कुछ चुनिंदा फिल्मों के कट किए गए दृश्यों को दिखाया गया। आचरण और अनुशासन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत न तो बोर्ड और ना ही केंद्र सरकार को फिल्मों के प्रदर्शन के समय बोर्ड के निर्णय को बदलने का अधिकार है। सारा मामला राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासन पर ही निर्भर रहता है। बोर्ड ने फिल्मों में बाद में दृश्यों को जोड़ने का पता लगाने के लिए कुछ व्यवस्था की है।

वर्ष के दौरान सभी 9 क्षेत्रों में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को रोकने के लिए निजी जासूसी एजेंसियों को नियुक्त किया गया। स्थायी आधार पर सभी नौ क्षेत्रों में निजी जासूसी एजेंसियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनवरी से दिसंबर 2005 के दौरान विभिन्न स्थानों पर छेड़छाड़ के दृश्य जोड़ने के 83 मामले पकड़े गए और सत्यापित रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भेजा गया।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
 प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण
 1-1-2005 से 31-12-2005 तक

सेल्युलाइड

	'यू'	'यू-ए'	'ए'	'एस'	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	601	224	216	-	1041
विदेशी फीचर फिल्में	73	64	133	-	270
भारतीय लघु फिल्में	1460	70	60	-	1590
विदेशी लघु फिल्में	244	45	37	-	326
फीचर के इतर लंबी अवधि की भारतीय फिल्में	4	-	-	-	4
फीचर के इतर लंबी अवधि की विदेशी फिल्में	-	-	-	-	-
कुल	2382	403	446	-	3231
	वीडियो				
भारतीय फीचर फिल्में	391	33	34	-	458
विदेशी फीचर फिल्में	133	93	175	-	401
भारतीय लघु फिल्में	2819	124	133	3	3079
विदेशी लघु फिल्में	247	31	32	-	310
फीचर के अलावा लंबी अवधि की भारतीय फिल्में	5	1	-	-	6
फीचर के अलावा लंबी अवधि की विदेशी फिल्में	1	2	-	-	3
कुल	3596	284	374	3	4257
कुल (फिल्मों और वीडियो)	5978	687	820	3	7488

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
1-1-2005 से 31-12-2005 के दौरान प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों
क्षेत्रवार, भाषावार (सेल्युलाइड फिल्मों)

अनुलग्नक-2

क्रम सं.	भाषा	मुंबई	कोल.	चेन्नई	बंगलौर	तिरुअ.	हैद.	दिल्ली	कटक	गुवा.	कुल
1)	हिंदी	215	1	7	7	8	5	2	-	-	245
2)	तमिल	-	-	118	5	2	11	-	-	-	136
3)	तेलुगु	1	-	29	4	7	227	-	-	-	268
4)	मलयालम	-	-	-	-	66	1	-	-	-	67
5)	कन्नड़	-	-	-	81	-	-	-	-	-	81
6)	बांग्ला	2	37	-	-	-	-	1	-	-	40
7)	गुजराती	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
8)	मराठी	57	-	-	-	-	-	-	-	-	57
9)	अंग्रेजी	14	1	4	-	-	1	—	-	-	20
10)	अंग्रेजी (डब)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11)	उड़िया	-	1	-	-	-	-	-	17	-	18
12)	असमिया	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
13)	अवधी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14)	राजस्थानी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15)	भोजपुरी	37	2	-	-	-	-	-	-	-	39
16)	पंजाबी व उर्दू	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
17)	भोजपुरी (डब)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
18)	कन्नड़ (डब)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
19)	मलयालम (डब)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20)	नागपुरी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
21)	बांग्ला (डब)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22)	गुजराती (डब)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23)	तमिल (डब)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
24)	कोंकणी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
25)	तेलुगु (डब)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
26)	मैथिली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27)	पंजाबी	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
28)	हिंग्लिश	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
29)	गढ़वाली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30)	हिंदी (डब)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
31)	संस्कृत	1	-	-	-	-	-	-	—	-	1
32)	तिब्बती अंग्रेजी सब टाइटल्स के साथ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
33)	मणिपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
34)	मोंपा-अरुणांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	कुल	381	45	158	98	83	245	4	17	10	1041

मु. - मुंबई, कोल. - कोलकाता, चे. - चेन्नई, बं. - बंगलौर, ति० - तिरुवनंतपुरम,
है. - हैदराबाद, दि. - दिल्ली, कट. - कटक, गु. - गुवाहाटी

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का विषयानुसार वर्गीकरण
1-1-2005 से 31-12-2005 तक
(सेल्युलाइड)

क्रम. सं.	भाषा	मुंबई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरुवनंत-पुरम	हैदराबाद	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1)	सामाजिक	298	43	155	72	66	198	2	17	10	861
2)	अपराध	12	-	-	19	8	15	-	-	—	54
3)	डरावनी	9	2	1	-	1	9	-	-	-	22
4)	भक्ति	2	-	-	1	-	1	-	-	-	4
5)	एक्शन	7	-	1	-	2	1	-	-	-	11
6)	बाल फिल्में	10	-	-	-	5	6	1	-	-	22
7)	फंतासी	1	-	1	1	-	-	1	-	-	4
8)	पौराणिक	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
9)	हास्य	10	-	-	1	-	1	-	-	-	12
10)	शैक्षिक	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
11)	एक्शन/रोमांच	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12)	रहस्य	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13)	रोमांच	15	-	-	-	-	1	-	-	-	16
14)	ऐतिहासिक	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
15)	आत्मकथात्मक	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
16)	फिक्शन	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
17)	रहस्य/रोमांच	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18)	अन्य	-	-	-	1	-	7	-	-	-	8
19)	व्यंग्य	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
20)	अपराध/रोमांच	-	-	-	1	-	-	-	—	-	1
21)	रहस्य	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22)	वृत्तचित्र	3	1	-	-	1	-	-	-	-	5
23)	रोमांस हास्य	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	381	46	158	98	83	245	4	17	10	1041

भारतीय बाल फिल्म समिति

1. परिचय/अवलोकन

भारतीय बाल फिल्म समिति की स्थापना भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में मई, 1955 में की गई थी। इसकी स्थापना बच्चों में अत्यधिक दिलचस्पी रखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर फिल्म जांच समिति (1949) की सिफारिशों पर की गई थी। भारतीय बाल फिल्म समिति, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत

है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को फिल्मों के माध्यम से मूल्य आधारित मनोरंजन उपलब्ध कराना है।

समिति का अध्यक्ष, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बनाया जाता है। वह कार्यकारिणी परिषद तथा साधारण सभा का प्रमुख होता है जिनके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। सभी विभागों के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन होते हैं।

यह प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा विभाग के रोज़मर्रा के काम भी देखता है। भारतीय बाल फिल्म समिति का मुख्यालय मुंबई में है और इसके शाखा कार्यालय नई दिल्ली तथा चेन्नई में हैं।

II. वर्ष 2005-06 के दौरान गतिविधियां

(क) निर्माण

वर्ष 2005-06 (दिसंबर 05 तक) पूरी की गई फिल्मों

फिल्म	निर्देशक
1. श्रीमान पिकू (वीडियो फिल्म)	संजीत घोष
2. गिली गिली अट्टा (हिंदी फीचर)	पंकज पराशर
वर्ष 2005-06 के दौरान पूरी होने वाली संभावित फिल्मों	
1. कमांड फॉर चोटी (हिंदी लघु)	रमेश अशेर द्वारा
2. द स्टोरी ऑफ नोक्योकलीबा (नगा लघु एनिमेशन)	मेरेन इम्चेन द्वारा
3. बंदू बॉक्सर (हिंदी फीचर)	राजीव मोहन द्वारा
4. गाजा उकिलर हत्या रहस्य (बंगला फीचर)	जगन्नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा
5. परफेक्ट मैच (लघु एनिमेशन)	ध्वनि देसाई द्वारा
वर्ष 2005-06 के दौरान जिन फिल्मों की डबिंग पूरी की गई	
1. पिकी एंड द मिलियन पग	जर्मन से हिंदी
2. टोरा	असमिया से हिंदी
3. ये है छक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो	हिंदी से कन्नड़
4. बाजा	हिंदी से कन्नड़
5. एक अजूबा	हिंदी से कन्नड़
6. माल्ली	हिंदी से कन्नड़

ख. विपणन

अप्रैल 2005 से दिसंबर 2005 तक विपणन गतिविधियां

प्रदर्शन के तरीके को व्यापक रूप से निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

1. थियेट्रों और स्कूलों में व्यक्तिगत शो।
2. जिला प्रशासन के सहयोग से जिला समारोह।
3. आदिवासी इलाकों में नगर निगम स्कूलों के सुविधा विहीन बच्चों के लिए निशुल्क शो।
4. वितरकों के जरिए, 35 एम एम और 16 एम एम प्रोजेक्टरों के माध्यम से शो का आयोजन।
5. समूचे राज्य में सभी जिलों/थियेट्रों में राज्यस्तरीय फिल्म समारोह।

भारतीय बाल फिल्म समिति का विपणन प्रभाग, मुंबई में अपने मुख्यालय और दिल्ली तथा चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस वर्ष के दौरान समिति ने 5,689 शो आयोजित करके अब तक सबसे अधिक 24,37,594 बच्चों को फिल्में दिखाईं।

1. **व्यक्तिगत शो** : कई स्कूलों और व्यक्तियों ने थियेट्रों और स्कूलों में 35 एम एम/16 एम एम प्रोजेक्टरों के माध्यम से, गैर-वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए निर्धारित किराए का भुगतान करके फिल्में प्राप्त कीं।
2. **जिला स्तरीय समारोह** : यह आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाता है। विभिन्न राज्यों में लगभग 60-70 जिलों का चयन किया गया है और इनमें प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें नाममात्र का शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है। स्कूलों के बच्चों, विशेषकर सरकारी/नगर निगम स्कूलों के छात्रों को ये फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से टिकटों के विक्रय से इन कार्यक्रमों के प्रति विश्वसनीयता बनती है। इस प्रकार ये फिल्म समारोह, भारतीय बाल विकास समिति के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। इन समारोहों के जरिए 1,860 शो किए गए और इन्हें 10,01,044 दर्शकों ने देखा।
3. **निशुल्क शो** : वे बच्चे जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, सुविधाविहीन

हैं और जिनके पास मनोरंजन का कोई बड़ा साधन नहीं है उनके लिए भारतीय बाल फिल्म समिति ने एक अनूठी योजना शुरू की है। इसके तहत नगर निगम स्कूलों और आदिवासी इलाकों के बच्चों के लिए निशुल्क शो आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन जैसे गैर सरकारी संगठनों की सेवाएं ली जाती हैं। निशुल्क शो आयोजित करने का खर्च, भारतीय बाल फिल्म समिति, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सहायता अनुदान राशि से वहन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अनाथालयों, सुधारगृह इत्यादि में रह रहे बच्चों के मनोरंजन के लिए भी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है।

इस वर्ष के दौरान देश के 11 राज्यों में 773 निशुल्क शो आयोजित किए गए जिन्हें 2,20,250 बच्चों ने देखा।

4. वितरकों के माध्यम से शो का आयोजन: भारतीय बाल फिल्म समिति वितरकों/आयोजकों के जरिए थियेट्रों और स्कूलों में शो का आयोजन करता है। वे निर्धारित मासिक किराए पर फिल्में लेते हैं और आवंटित क्षेत्र में फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं। इस वर्ष के दौरान 1,317 शो आयोजित किए गए जिन्हें 5,10,100 दर्शकों ने देखा।

5. राज्यस्तरीय समारोह : मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय बाल फिल्म समिति के सहयोग से समूचे राज्य में बड़े पैमाने पर फिल्मों के आयोजन किए। समिति ने 60-70 फिल्मों का पैकेज उपलब्ध कराया और इन्हें राज्य भर के थियेट्रों में दिखाया गया। मध्य प्रदेश में 1622 शो आयोजित किए गए जिन्हें 46 जिलों के 6,48,800 बच्चों ने देखा।

6. वी एच एस कैसेट और वी सी डी का विक्रय : वैयक्तिक और सामुदायिक प्रदर्शनों के लिए कुल 458 वी एच एस और वी सी डी का प्रदर्शन किया गया।

7. एनीमेशन और फिल्म निर्माण कार्यशाला : फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहन जानकारी देने के लिए भारतीय बाल फिल्म समिति ने फिल्म निर्माण पर कार्यशालाओं का आयोजन किया।

8. (क) अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों में भागीदारी

भारतीय बाल फिल्म समिति की फिल्में 23 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई गईं। ये फिल्में थीं -

(ख) भारतीय बाल फिल्म समिति के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल

क्रम सं.	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	देश	फिल्म
1.	फिल्म समारोह, जैड एल आई एन	चेक रिपब्लिक	छोटा सिपाही
2.	गोयांग अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	कोरिया	द फ्रेंड
3.	सिओल में ग्रीन फिल्म समारोह	दक्षिण कोरिया	माल्ली
4.	तेल अवीव अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	इस्राइल	छोटा सिपाही
5.	22वां शिकागो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	शिकागो, अमरीका	टोराज लव
6.	सान डिएगो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	वीस्ता, अमरीका	हेडा होडा
7.	14वां गोल्डन एलिफेंट अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह	भारत (हैदराबाद)	छुटकन की महाभारत रंग मॉरिशस, छोटा सिपाही, मिट्टी और चांद, लिटिल वारजू एंड द फ्रेंडली फ्लूट, जीयो और जीने दो।

फिल्म समारोह का आयोजन :

भारतीय बाल फिल्म समिति ने 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हैदराबाद में 14 से 20 नवंबर 2005 तक किया। इसमें डेढ़ सौ से अधिक प्रतिनिधि (देश और विदेश) शामिल हुए। समारोह में भारत के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से लगभग साढ़े चार सौ बाल प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यशालाओं, खुले मंचों जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी समारोह के दौरान आयोजन किया गया। भारतीय बाल फिल्म समारोह के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उदघाटन समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया गया। समारोह में 35 देशों की 170 फिल्मों 10 थियेट्रों में दिखाई गईं।

जनवरी-मार्च, 2006 के दौरान नियोजित गतिविधियां

फिल्म निर्माण तथा संवर्धन कार्यशालाएं निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित की गई हैं।

1. गुजरात : वड़ोदरा नादियाड़
2. महाराष्ट्र : ठाणे
3. राजस्थान : जयपुर
4. दिल्ली : दिल्ली (2 कार्यशाला)
5. कर्नाटक : मैसूर, मेडिकेरी
6. गोवा : पणजी

जिला फिल्म-समारोह/नगर निगम के स्कूलों में फिल्म प्रदर्शन - जिला स्तरीय बाल फिल्म समारोह आयोजित करने की योजना निम्न जिलों के ग्रामीण बच्चों/नगर निगम के स्कूलों के बच्चों के लिए बनाई गई।

1. गुजरात	:	वडोदरा, खेड़ा-नादियाड़, पंचमहल-गोधरा, पाटन, मेहसाणा, साबरकंटा - हिम्मतनगर
2. महाराष्ट्र	:	अहमदनगर, औरंगाबाद, परभनी
3. उत्तर प्रदेश	:	बनारस, मऊ
4. पंजाब	:	संगरूर
5. हरियाणा	:	यमुना नगर
6. कर्नाटक	:	मैसूर, हासन, चिकमगलूर
7. आंध्र प्रदेश	:	चित्तौड़, प्रकाशम, विशाखापटनम
8. गोवा	:	पणजी

बजट प्रावधान

(क) योजना : भारतीय बाल फिल्म समिति के संबंध में अनुमोदित वार्षिक योजना 2005-2006 निम्न प्रकार है।

योजना का नाम जारी योजनाएं	स्वीकृत (लाख रुपये में)
योजना - 1 निर्माण, खरीद तथा डबिंग/सबटाइटलिंग	352.00
योजना II फिल्म समारोह	110.00
योजना - III आधुनिकीकरण तथा संवर्धन (क) वीडियो (ख) सूचना प्रौद्योगिकी	2.80
योजना IV एनिमेशन तथा पांडुलिपि लेखन कार्यशाला	4.60
योजना V दर्शक अनुसंधान एवं विपणन सर्वेक्षण और भारतीय बाल फिल्म समिति की फिल्मों का विपणन	0.00
नई योजनाएं	
योजना - VI भारतीय बाल फिल्म समिति की फिल्मों का डिजिटलीकरण और वेबकास्टिंग	0.00
योजना - VII नगर निगम स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी	50.00
	519.40

(ख) गैर योजना : वर्ष 2005-2006 के दौरान गैर योजना गतिविधियों के लिए 15 लाख रुपये की निर्धारित अनुदान राशि आवंटित की गई।

अन्य कार्यक्रमों संबंधी गतिविधियां :

(क) आधुनिकीकरण

भारतीय बाल फिल्म समिति का मुंबई स्थित समूचा मुख्यालय और इसके शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत हैं। चूँकि फिल्म निर्माण समिति की मुख्य गतिविधि है इसलिए समय-समय पर निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा संवर्धन किया जाता है ताकि निर्माण उपकरणों आदि के आधुनिकीकरण का अध्ययन तकनीकों को साथ लेकर चला जा सके।

(ख) जन्मशती/पुण्यतिथि के सिलसिले में आयोजन

इस कार्यालय ने राष्ट्रीय नेताओं की जन्मशती/पुण्यतिथि के मौके पर निम्न आयोजन किए-

- (1) 'कौमी एकता सप्ताह' 19 से 25 नवंबर 2005 तक
- (2) 'सद्भावना दिवस' 20 अगस्त से 5 सितंबर 2005 तक
- (3) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 7-11-2005 से 13.11.2005 तक

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती सरकारी निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों पर की जा रही है।

छोटा संगठन होने के कारण समूचे कार्यालय के लिए कल्याण गतिविधियां चलाई जाती हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी भी शामिल होते हैं।

(घ) पूर्वोत्तर संघटक

भारतीय बाल फिल्म समिति क्षेत्रीय भाषाओं की बाल फिल्मों का

निर्माण और प्रदर्शन करके इन्हें बढ़ावा देती है। नगा भाषा की लघु एनिमेशन फिल्म 'द स्टोरी ऑफ नोक्योक्लीबा' फिल्म का निर्माण प्रगति पर है। इस फिल्म का निर्देशन एक उदयमान निर्देशक को सौंपा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल फिल्म समारोहों का आयोजन (राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर) वर्ष 2005 के अप्रैल और मई महीने के दौरान किया गया। ये समारोह मेघालय, असम और त्रिपुरा में आयोजित किए गए। इनमें 206 से अधिक शो आयोजित किए गए जिन्हें लगभग 97,000 बच्चों ने देखा।

(च) बाल दिवस समारोह : 14 नवम्बर 2005 को बाल दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर निम्नलिखित आयोजन किए गए :

(क) 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह 14 नवंबर 2005 से 20 नवंबर 2005 तक आयोजित किया गया। भागीदारी और फिल्मों की गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से समारोह बहुत सफल रहा।

(ख) भारतीय बाल फिल्म समिति की पुरस्कृत फिल्म टोरा (असमिया) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2005 को दिखाई गई।

नई पहल

ऐसे सुविधाविहीन ग्रामीण बच्चों व आदिवासी बच्चों के लिए, जो मनोरंजन के स्रोतों से वंचित हैं सी एफ एस आई ने निशुल्क प्रदर्शन की एक अनोखी योजना प्रारंभ की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसी गैर सरकारी संस्थाओं की सेवा इस कार्य के लिये ली गई। सी एफ एस आई इन निशुल्क प्रदर्शनों को दिखाने का खर्चा सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से वहन करती है। इस योजना के अंतर्गत मनोरंजन से विहीन रिमांड होम/अनाथालयों के बच्चों को भी फिल्म दिखाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश के 11 राज्यों के 2,20,250 बच्चों के लिए अब तक 733 फिल्म प्रदर्शन हुये हैं।

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां भारतीय बाल फिल्म समिति (CFSI)

- सी एफ एस आई ने 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह हैदराबाद में 14-20 नवंबर 2005 को आंध्र प्रदेश की सरकार के सहयोग से आयोजित किया।
- दस सिनेमाघरों में 35 देशों की 170 फिल्में दिखलाई गईं।
- उद्घाटन समारोह के दौरान सी एफ एस आई ने हीरक जयंती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया।
- सी एफ एस आई का मुंबई स्थित मुख्यालय और नई दिल्ली, चेन्नई में स्थित शाखा कार्यालयों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया गया।
- थियेट्रों या स्कूलों में दिखाये जाने वाले गैर व्यावसायिक 117 फिल्म प्रदर्शनों के जरिये 57,400 बच्चे लाभान्वित हुए।
- जिला स्तर पर 1,860 प्रदर्शनों के जरिये 10,01,044 लोगों ने फिल्में देखीं।
- देश के 11 राज्यों में 2,20,250 बच्चों के लिये 773 निशुल्क प्रदर्शन किये गये।
- सी एफ एस आई के सहयोग से मध्य प्रदेश की सरकार ने 46 जिलों में 1622 फिल्म प्रदर्शनों के जरिये 6,48,800 बच्चों को फिल्में दिखाई।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रदर्शनों के लिये कुल 458 वी एच एस और वी सी डी का विक्रय हुआ।
- 23वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सी एफ एस आई की फिल्में शामिल की गईं।
- अप्रैल और मई 2005 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में (राज्य और जिलास्तर पर) बाल फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। मेघालय, आसाम और त्रिपुरा में कुल 206 फिल्म प्रदर्शनों के जरिये 97,000 बच्चे लाभान्वित हुये।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

प्रस्तावना

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन की कला और तकनीक में नवीनतम शिक्षा और प्रौद्योगिकी के अनुभव प्रदान करता है। दूरदर्शन और अन्य संस्थानों के सभी वर्ग के अधिकारियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। यह नॉन लीनीयर, बीटा कैम और ए/बी रोल एडिटिंग सेटअप जैसे आधुनिक डिजिटल और ब्राडकास्ट ग्रेड प्रोडक्शन सेट अप, सोनी बी वी पी 500 पी जैसे डिजिटल कैमरों, सॉफ्टक्रोमा कीयर, डिजिटल स्पेशल एफेक्ट जनरेटर, एलियास साफ्टवेयर के साथ सिलिकॉनग्राफिक्स 02 वर्कस्टेशन, मॉडर्न मूवी कैमरों, रि-रिकार्डिंग उपकरणों से लैस

है जिससे फिल्म और टेलीविजन के शिक्षकों और छात्रों को बेहतरीन जानकारी मिलती है।

वर्ष 2005 के लिये 1585 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1554 आवेदकों को 8 मई 2005 को 14 सेंट्रों 1. इलाहाबाद, 2. अहमदाबाद, 3. अमृतसर, 4. भोपाल, 5. भुवनेश्वर, 6. कोलकाता, 7. चेन्नई, 8. गुवाहाटी, 9. हैदराबाद, 10. मुंबई, 11. नयी दिल्ली, 12. पटना, 13. पुणे, 14. तिरुवनंतपुरम में प्रवेश परीक्षा के लिये बुलाया गया।

416 उम्मीदवारों का ओरिएन्टेशन प्रोग्राम/इंटरव्यू/ऑडिशन टेस्ट/वर्कशॉप के लिये चयन किया गया। भारतीय छात्रों के अलावा आई सी सी आर, नयी दिल्ली के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिये आरक्षित



सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थाई समिति के सदस्यों ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कामकाज की मॉके पर जाकर समीक्षा की, 6 अक्टूबर, 2005

चार सीटों के लिये एफ्रो-एशियाई देशों से 16 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से उपयुक्त पात्र माने गये 11 उम्मीदवारों को सम्बद्ध दूतावासों और उच्चायोग में लिखित परीक्षा के लिये बुलाया गया था। अंततः तीन उम्मीदवारों का दाखिले के लिये चयन किया गया।

इसी प्रकार एन आर आई/विदेशी सीट के लिये एफ्रो-एशियाई देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से 16 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवारों का दाखिले के लिये चयन किया गया।

अंततः विदेशी उम्मीदवारों सहित 132 उम्मीदवारों का वर्ष 2005 के लिये विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये चयन किया गया। चयन किये गए छात्रों का पाठ्यक्रम के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) फिल्म और टेलीविजन का तीन वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

फिल्म और टेलीविजन के तीन वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के पहले वर्ष में दाखिले के लिये 46 उम्मीदवारों का चयन किया गया जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	निर्देशन (फिल्म और टेलीविजन)	12
2.	सिनेमेटोग्राफी (फिल्म और टेलीविजन)	12
3.	एडिटिंग (फिल्म और टेलीविजन)	12
4.	ऑडियोग्राफी (फिल्म और टेलीविजन)	10

पाठ्यक्रम 10 अक्टूबर 2005 से शुरू हुआ

(ख) फिल्म और टेलीविजन अभिनय में दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

फिल्म और टेलीविजन अभिनय में दो वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के लिये 20 छात्रों का दाखिले के लिये चयन किया गया। यह पाठ्यक्रम 10 अक्टूबर 2005 से शुरू हुआ।

(ग) टेलीविजन में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

टेलीविजन में एक वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिये 30 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इन छात्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1.	निर्देशन	07
2.	इलेक्ट्रानिक सिनेमेटोग्राफी	08
3.	वीडियो एडिटिंग	08
4.	ऑडियोग्राफी और टीवी इंजीनियरिंग	07

ये पाठ्यक्रम 28 जुलाई 2005 से शुरू हुआ।

(घ) फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले लेखन में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले लेखन के एक वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिये 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया। ये पाठ्यक्रम 18 जुलाई 2005 से शुरू हुआ।

(ङ) कला निर्देशन में दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

कला निर्देशन में दो वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिये 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया। ये पाठ्यक्रम 19 सितम्बर 2005 से शुरू हुआ।

(च) एनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ साल का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

एनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ साल के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिये 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया। ये पाठ्यक्रम 18 जुलाई 2005 से शुरू हुआ।

प्रशिक्षु के रूप में विदेशी छात्र

अमेरिका के फुलब्राइट स्कॉलर श्री ब्रीस वरसेस्टर को सितम्बर 2005 से 9 महीने के लिये पर्यवेक्षक के रूप में एफ टी आई आई का दौरा करने की इजाजत दी गई।

31-12-2005 को छात्रों की संख्या इस प्रकार थी :

अगले शिक्षा सत्र 2006-2007 के लिये दाखिले का नोटिस फरवरी 2006 में प्रकाशित होगा।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, इंटरनेशनल लायजन् सेंटर ऑफ सिनेमा एंड टी वी स्कूल्स (सिलेक्ट) का एक सदस्य है जिससे विश्व भर के सभी प्रमुख टेलीविजन और फिल्म स्कूल

फिल्म और टेलीविजन में तीन वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

वर्ष	दाखिले का वर्ष	पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों की संख्या				छात्रों की कुल संख्या	विदेशी	
		निर्देशन	सिनेमा	एडिटिंग	ऑडियो		पाठ्यक्रम	देश
I वर्ष	2005	11	11	11	10	43	निर्देशन-1 सिनेमा-1 एडिटिंग-2	जर्मनी कनाडा आस्ट्रेलिया नेपाल
वर्ष	दाखिले का वर्ष	पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों की संख्या				छात्रों की कुल संख्या	विदेशी	
		निर्देशन	सिनेमा	एडिटिंग	ऑडियो		पाठ्यक्रम	देश
II वर्ष	2004	12	11	11	06	40	निर्देशन-3 सिनेमा-2 एडिटिंग-1	फ्रांस फिलीपीन्स स्वीडन फ्रांस नेपाल अमेरिका
III वर्ष	2003	09	11	09	08	37	निर्देशन-1 सिनेमा-2 ऑडियो-1	नेपाल नेपाल अमेरिका नेपाल
		32	33	31	24	120		

संबद्ध हैं। संस्थान का एक अध्यापक और एक छात्र आम तौर पर सिलेक्ट की बैठकों में भाग लेते हैं। इससे संस्थान को फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन और फिल्म और टेलीविजन से जुड़ी पढ़ाई के बारे में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय जानकारी मिलती रहती हैं।

अध्याय-II एक नजर

प्रशासन

भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में

भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना की। 1974 में इसमें टेलीविजन शाखा को जोड़ देने के बाद संस्थान को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान नाम दिया गया। रजिस्ट्रेशन और सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अंतर्गत अक्टूबर 1974 में संस्थान एक सोसाइटी बन गया। सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी प्रमुख हस्तियां, संस्थान के पुराने छात्र और सरकार के पदेन सदस्य शामिल हैं। संस्थान को संचालन परिषद चलाती है, जिसका एक अध्यक्ष होता है। जाने-माने लेखक डा. यू.आर. अनंतमूर्ति इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। संस्थान की पाठ्यक्रम नीतियों और योजनाओं

अभिनय में दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

वर्ष	पाठ्यक्रम	छात्रों की कुल संख्या	विदेशी
2005 (प्रथम वर्ष)	अभिनय	20	1-दुबई
2004 (द्वितीय वर्ष)	अभिनय	18	—

कला निर्देशन में दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

वर्ष	पाठ्यक्रम	छात्रों की कुल संख्या	विदेशी
2005	कला निर्देशन	12	—

एनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ साल का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

वर्ष	पाठ्यक्रम	छात्रों की कुल संख्या	विदेशी
2005	एनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स	12	—

टेलीविजन में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

दाखिले का वर्ष	पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों की संख्या				छात्रों की कुल संख्या	विदेशी
	निर्देशन	सिनेमा	एडिटिंग	ऑडिया		
2005	07	08	08	07	30	—

फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले लेखन में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

वर्ष	पाठ्यक्रम	छात्रों की कुल संख्या	विदेशी
2005	स्क्रीन प्ले लेखन	11	—

पाठ्यक्रम के अनुसार 1 दिसम्बर 2005 को छात्रों की कुल संख्या

तीन वर्ष का डिप्लोमा	अभिनय	कला निर्देशन	एनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स	टेलीविजन में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	एस पी डब्ल्यू में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	कुल
120	38	12	12	30	11	223

को शिक्षा परिषद तैयार करती है। वित्त से जुड़े मसले स्थायी वित्त समिति नियंत्रित करती है।

संस्थान की दो शाखाएं हैं : फिल्म और टेलीविजन शाखा जो फिल्म और टेलीविजन के पाठ्यक्रम की पढ़ाई का अवसर प्रदान करते हैं। फिल्म पाठ्यक्रम में निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग

और ऑडियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया जाता है। टेलीविजन शाखा निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और ऑडियोग्राफी और टीवी इंजीनियरिंग में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाती है। टेलीविजन शाखा दूरदर्शन के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी

के दौरान प्रशिक्षण देने की पेशकश करती है। इसमें टीवी प्रोडक्शन, टेक्नीकल ऑपरेशन, एडिटिंग, साउंड रिकार्डिंग, कैमरा, ग्राफिक्स और सेट डिजाइन का प्रशिक्षण शामिल है। अन्य संगठनों को भी लघु अवधि के कोर्स कराए जाते हैं। नये पाठ्यक्रम में संस्थान के छात्र तकनीकी क्षमता हासिल करेंगे जो दोनों पेशों के लिये जरूरी है। दोनों शाखाओं के विभाग द्वारा तैयार पाठ्यक्रम में फिल्म और टेलीविजन को बराबर महत्व दिया गया है और मीडिया में कम्प्यूटर की जानकारी का महत्व बताया गया है।

फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के संयुक्त तत्वावधान में 16 मई 2005 से 11 जून 2005 तक 30वां फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में 59 पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अध्यापक और मीडिया से जुड़े लोग शामिल हुए।

फिल्म समारोहों में भागीदारी

भारत और विदेशों में छात्रों की प्रतिभा को उभारने के लिये डिप्लोमा के छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शामिल की जाती हैं। इस साल संस्थान ने निम्न समारोहों/घटनाओं में भाग लिया :

- 15वां सर्जी-पोंटोयस अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह, 15 से 17 अप्रैल 2005 के बीच फ्रांस में आयोजित किया गया।
- बूसान एशियन लघु फिल्म समारोह, 2005। 4 से 8 मई 2005 के बीच कोरिया में आयोजित किया गया।
- 51वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह, 5 से 10 मई 2005 के बीच ओबेरहॉसन, जर्मनी में आयोजित किया गया।
- कान फिल्म समारोह, फ्रांस 2005, 11 से 22 मई 2005 तक आयोजित किया गया।
- जॉन अब्राहम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये साइंस 2005-वृत्तचित्र और वीडियो में लघु फीचर समारोह 25 से 30 मई 2005 के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया।
- 52वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म समारोह निदेशालय, नयी दिल्ली (प्रवेश तिथि : 30 मई 2005)
- “फेसिनेशन ऑफ फ्लाइट” पर प्रतिस्पर्धा ए आई आर ए आर टी 2005, ई ए डी एस, जर्मनी द्वारा आयोजित (पुरस्कार समारोह 02-06-2005 को)
- प्रोबलोफ xi कला अकादमी, बर्लिन 03-06-2005 को आयोजित
- 52वां सिडनी फिल्म समारोह, 2005, 10 से 15 जून 2005 तक आयोजित
- कनाडा फिल्म सेंटर का विश्वव्यापी लघु फिल्म समारोह, टोरंटो, 14 से 19 जून 2005 तक आयोजित
- वारसा ग्रीष्म फिल्म समारोह, पोलैंड, 27 जून से 2 जुलाई 2005 तक आयोजित
- जुलाई 2005 में स्टॉकहोम, स्वीडन में आई आई एस विश्व सम्मेलन में एफ टी आई आई के छात्रों की फिल्मों दिखाई गईं।
- प्रोमेक्स और बी डी ए इंडिया, मुंबई ने सेट स्टूडेंट प्रोमो चैलेंज जुलाई 2005 में आयोजित किया।
- भारतीय फिल्म समारोह, बॉलीवुड एंड बियोण्ड, स्टुटगार्ट, जर्मनी में 13 से 17 जुलाई 2005 तक।
- आसियन सिनेफैन एशियन फिल्म समारोह द्वारा आयोजित टेलेंट कैम्पस इंडिया कार्यशाला 17 से 21 जुलाई 2005 तक आयोजित
- मैक्सिको में एक्प्रेसन एन-कोर्टो फिल्म समारोह, 23 से 30 जुलाई 2005 के बीच आयोजित
- अंतर्राष्ट्रीय नवीन फिल्म समारोह, कार्लोवी वेरी में 24 से 28 अगस्त 2005 के बीच आयोजित।
- नोवा समारोह, ब्रुसेल्स, बेल्जियम और तस्वीर समारोह, सिएटल अमेरिका में सितम्बर 2005 में आयोजित
- नेक्स्ट रील अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, न्यूयार्क में अक्टूबर 2005 में आयोजित
- तीसरा एशियाई फिल्म समारोह, पुणे में 19 से 25 अक्टूबर 2005 तक आयोजित।
- थर्ड आई - चौथा एशियाई फिल्म समारोह, मुंबई 2005, 20 से 27 अक्टूबर 2005 तक आयोजित
- एस जे सी सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2005 - कैम्पस फिल्म प्रतिस्पर्धा, चंगनाचैरी, 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2005 तक आयोजित।

23. 14वां गोल्डन एलीफेंट बाल फिल्म समारोह, हैदराबाद में 14 से 20 नवम्बर 2005 तक
24. पी ई के फिल्म समारोह, हालैंड में नवम्बर 2005 तक
25. केस्टलीनारिया - 18वां अंतर्राष्ट्रीय युवा फिल्म समारोह - बेलिनजोना/स्विटजरलैंड में 19 से 26 नवम्बर 2005 तक आयोजित।
26. 36वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा में 24 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2005 तक आयोजित।
27. सिनेमेटोग्राफी कला पर 13वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कैमरीमेज, लोड्ज, पोलैंड में 27 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2005 तक आयोजित
28. शार्ट कट्स कोलोन लघु फिल्म समारोह, जर्मनी 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2005 तक आयोजित
29. रियो द जनेरियो अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह-कर्टा सिनेमा 2005, ब्राजील में 1 से 11 दिसम्बर 2005 तक आयोजित।
30. शार्ट कट्स फिल्म सोसाइटी, हैदराबाद (मासिक मिनी-समारोह) संस्थान इस वर्ष के दौरान निम्न फिल्म समारोहों में भी भाग लेगा।
 - (क) नयी दिल्ली में 20 से 22 जनवरी 2006 तक होने वाला जीविका फिल्म समारोह
 - (ख) 3 से 9 फरवरी 2006 तक वृत्त चित्र लघु और एनीमेशन फिल्म का 9वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह।
 - (घ) 14 से 19 मार्च 2006 तक माल्मो, स्वीडन में आयोजित बफ फिल्म समारोह।
2. अनिल जनकार ने 4.4.2005 से 5.4.2005 तक “पटकथा का ढांचा और तेजी से काम करने” पर लेक्चर दिया।
3. सुभाष साहू ने 6 से 7 अप्रैल 2005 तक “लोकेशन रिकार्डिंग” पर कार्यशाला की।
4. उमेश गुप्ता ने “नॉन लीनीयर एडिटिंग” पर 8 से 9 अप्रैल 2005 तक कार्यशाला की।
5. विकास देसाई ने “गीतों के फिल्मांकन” पर 11 से 14 अप्रैल 2005 तक एक कार्यशाला की।
6. दिलीप खत्री ने “गीतों के फिल्मांकन” पर 12 से 13 अप्रैल 2005 तक एक कार्यशाला की।
7. प्रहलाद कक्कड़ ने 15 से 16 अप्रैल 2005 तक “विज्ञापन” पर कार्यशाला की।
8. शरद राज ने “वर्किंग आन कन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव हैड” पर 17 अप्रैल 2005 को कार्यशाला की।
9. भास्कर चंदावरकर ने “बैकग्राउंड म्यूजिक” पर 18 अप्रैल 2005 को लेक्चर दिया।
10. जीतू मंडल ने “एडिटिंग एस्थेटिक्स : फिक्शन एंड नॉन फिक्शन” पर 18 से 20 अप्रैल 2005 तक एक कार्यशाला की।
11. बी पी सिंह ने “लाइटनिंग फॉर सिंगल कैमरा” पर 19 से 20 अप्रैल 2005 तक एक कार्यशाला की।
12. योगेश माथुर ने 20 अप्रैल 2005 को एडिटिंग नरेटिव्स पर एक लेक्चर दिया।
13. प्रदीप राउतराय ने 22 अप्रैल 2005 को म्यूजिक रिकार्डिंग पर एक कार्यशाला की।
14. समर नखाटे ने 23 अप्रैल 2005 को “स्क्रीन स्टडीज” पर एक लेक्चर दिया।
15. उदय चित्रे ने 25 अप्रैल 2005 को “डिजिटल रिकार्डिंग एंड टेपलैस डिजिटल रिकार्डर” पर लेक्चर दिया।
16. आर एन चौधरी ने “लाइटिंग” पर 25 और 26 अप्रैल 2005 को एक कार्यशाला की।
17. अंजुम राजाबाली ने “बायो-पिक/इंडस्ट्रीयल आसपेक्ट्स” पर 30 अप्रैल 2005 को लेक्चर दिया।

कार्यशाला/संगोष्ठियां

छात्रों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये भारत और विदेशों के जाने-माने फिल्म निर्माताओं की कार्यशालाएं/संगोष्ठियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इस दौरान जानी-मानी फिल्मी हस्तियों की निम्न कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गईं -

1. उदय शंकर पाणी ने 31 मार्च 2005 से 1 अप्रैल 2005 तक प्रोडक्शन, योजना, बजटिंग और प्रबंधन पर एक कार्यशाला की।

18. उदय शंकर पाणी ने 9 मई 2005 को “प्रोडक्शन मैनेजमेंट” पर लेक्चर दिया।
19. समर मुखर्जी ने 9 मई 2005 से 11 मई 2005 तक “अभिनय” पर लेक्चर दिया।
20. अंजुम राजाबाली ने 20 मई 2005 को “स्क्रीन प्ले लेखन” पर एक लेक्चर दिया।
21. रामगोपाल बजाज ने “अभिनय” पर 15 मई 2005 से 19 जुलाई 2005 तक एक कार्यशाला की।
22. विनय शुक्ला ने “स्क्रीनप्ले लेखन” पर 20 मई 2005 को लेक्चर दिया।
23. बी सीताराम ने “डिजिटल वीडियो टेक्नालॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन्स” पर 25 जून 2005 को एक लेक्चर दिया।
24. एस एन जवालकर ने 24 जून 2005 को “सेटलाइट कम्युनिकेशन” पर एक लेक्चर दिया।
25. अंजुम राजाबाली ने “फाउंडेशन फॉर स्क्रीन प्ले राइटिंग” पर 18 जुलाई 2005 से 19 जुलाई 2005 तक लेक्चर दिया।
26. चन्द्र खन्ना ने “अभिनय” पर 19 जुलाई 2005 से 20 जुलाई 2005 तक कार्यशाला की।
27. समर जयसिंह ने “अभिनय” पर 19 जुलाई 2005 से 20 जुलाई 2005 तक कार्यशाला की।
29. अरविंद पांडे ने “अभिनय तकनीक और अभिनय के तरीके लागू करने” पर 2 अगस्त 2005 से 4 अगस्त 2005 तक लेक्चर दिया।
30. रूपेश थपलियाल ने “एक्टिंग सेन्स मेमोरी एंड इमेजिनेशन” पर 1 अगस्त 2005 से 5 अगस्त 2005 तक लेक्चर दिया।
31. अंजुम राजाबाली ने “स्टोरी फॉर स्क्रीन प्ले राइटिंग” पर 5 और 6 अगस्त 2005 को लेक्चर दिया।
32. समर जयसिंह ने “सबजेक्टिव स्टडी एंड टेक्नीकल आसपेक्ट ऑफ ट्रुथ एंड बीलीफ” पर 9 और 10 अगस्त 2005 को लेक्चर दिया।
33. अरविंद पांडे ने “टेक्नीक ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप एंड प्लान” पर 11 अगस्त 2005 को एक लेक्चर दिया।
34. रूपेश थपलियाल ने “ग्रामर ऑफ स्पीच एंड वॉयस मोड्यूलेशन” पर 12 और 13 अगस्त 2005 को लेक्चर दिया।
35. विनय शुक्ला ने “स्टोरी फॉर स्क्रीन प्ले राइटिंग” पर 17 अगस्त 2005 को लेक्चर दिया।
36. अरविंद पांडे ने “अभिनय” पर 16 और 17 अगस्त 2005 को लेक्चर दिया।
37. टॉम आल्टर ने 18 और 19 अगस्त 2005 को “अभिनय” पर लेक्चर दिया।
38. समर जयसिंह ने 22 और 23 अगस्त 2005 को “अभिनय” पर लेक्चर दिया।
39. गोपाल कृष्ण ने “कलर्स” पर 25 अगस्त 2005 को एक लेक्चर दिया।
40. रूपेश थपलियाल ने “अभिनय” पर 25 और 26 अगस्त 2005 को लेक्चर दिया।
41. रवि राय ने “लेखन और निर्देशन” पर 26 अगस्त 2005 को एक लेक्चर दिया।
42. राकेश सारंग ने “प्रोडक्शन ऑफ टी वी सीरियल्स” पर 27 अगस्त 2005 को एक लेक्चर दिया।
43. आदिल अमान ने “एक्शन प्रॉब्लम/इंप्रोवाइजेशन सेंस मेमोरी” पर 29 अगस्त से एक सितम्बर 2005 तक लेक्चर दिया।
44. अरविंद पांडे ने “एक्टिंग स्टडी” पर 5 और 6 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिया।
45. कमलनाथ ने “प्लेबैक” (डांस) पर 2, 8, 9, 10 सितम्बर और 15 तथा 16 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिया।
46. अंजुम राजाबाली ने “केरेक्टराइजेशन” पर 9 और 10 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिया।
47. आदिल अमान ने “सेंस मेमोरी एंड अंप्रोवाइजेशन्स” पर 12 सितम्बर 2005 को एक लेक्चर दिया।
48. जयनेश शेट्टी ने “फाइट मास्टर फॉर एक्टिंग” पर 13 और 14 सितम्बर 2005 और “फाइट फॉर एक्टिंग” पर 26 और 27 अक्टूबर 2005 को लेक्चर दिया।

49. अनुराग कश्यप ने 13 और 14 सितम्बर 2005 को “स्क्रीनप्ले राइटिंग” पर लेक्चर दिया।
50. अरविंद पांडे ने “आब्जर्वेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन” पर 17 सितम्बर 2005 को एक लेक्चर दिया।
51. आदिल अमान ने “एक्टिंग इम्प्रोवाइजेशन” पर 19 और 20 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिया।
52. महेश दिगराजकर ने “प्रोसेस आफ फिल्म मेकिंग इन इंडस्ट्री” पर 20 सितम्बर 2005 को एक लेक्चर दिया।
53. मंदार दिगराजकर ने “कम्प्यूटर एप्लीकेशन इन आर्ट” पर 21 सितम्बर 2005 को एक लेक्चर दिया।
54. ए जी अली ने “टाइप्स ऑफ वुड एंड कारपेन्ट्री प्रोसेस/स्ट्रक्चर एंड मीनिंग आफ टिम्बर” पर 21 सितम्बर और 24 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिये।
55. टॉम आल्टर ने “अभिनय” पर 21 सितम्बर और 3 और 4 नवम्बर 2005 को कार्यशाला की।
56. नरिन्दर भसीन ने “फिल्म इमेज - एस्थेटिक रिसपान्सबिलिटी/स्प्रिचुअल फिलॉस्फी आफ आर्ट” पर 22 सितम्बर और 29 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिये।
57. नितिन हदप ने “हिस्ट्री आफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर - फॉर आर्ट डायरेक्शन” पर 23 सितम्बर से 30 सितम्बर 2005 तक लेक्चर दिया।
58. आदिल अमान ने “एक्शन एंड टेक्नीक” पर 23 और 24 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिये।
59. अजीत पांडे ने “इंट्रोडक्शन आफ कम्प्यूटर हार्डवेयर” पर 24 और 27 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिये।
60. संजय ददारकर ने “मीडियमस एंड मोल्टिंग टेक्नीक्स” पर 23 और 26 से 27 सितम्बर 2005 तक लेक्चर दिया।
61. अरविंद पांडे ने “एक्टिंग सिचुएशन एंड प्रोसेसिंग इवेंट विद थॉट्स एंड आइडियाज” पर 26 और 27 सितम्बर 2005 को लेक्चर दिये।
62. श्री ए.जी. माली ने 3 से 7 अक्टूबर 2005 तक “कारपेन्ट्री प्रेक्टिकल” कराए।
63. मेघन मांजरेकर ने “पेंटिंग टेक्नॉलाजी” पर 3 अक्टूबर 2005 को एक लेक्चर दिया।
64. सुरिन्दर पाल ने “अभिनय” पर 5 और 6 अक्टूबर 2005 को कार्यशाला की।
65. आदिल अमान ने “एक्टिंग इम्प्रोवाइजेशन एंड एमेजीनेशन” पर 28 और 29 सितम्बर और 3 से 4 अक्टूबर 2005 तक लेक्चर दिये।
66. सुधीर बरसे ने “आर्ट डायरेक्शन” पर 30 सितम्बर और 3 से 7 अक्टूबर 2005 तक लेक्चर दिये।
67. नरिन्दर भसीन ने “स्प्रिचुअल फिलॉस्फी आफ आर्ट” पर 5 अक्टूबर 2005 को एक लेक्चर दिया।
68. नीतिन हदप ने “आर्किटेक्चर स्क्ल्पचर” पर 7 अक्टूबर 2005 को एक लेक्चर दिया।
69. किशोर कुमार ने “अभिनय” पर 7 अक्टूबर 2005 को एक लेक्चर दिया।
70. अदिल अमान ने “अभिनय” पर 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2005 तक लेक्चर दिये।
71. अंजुम राजाबाली ने “स्क्रीनप्ले राइटिंग स्ट्रक्चर” पर 10 और 11 अक्टूबर 2005 को लेक्चर दिये।
72. रजा मुराद ने “अभिनय” पर 13 और 14 अक्टूबर 2005 को लेक्चर दिये।
73. कमलनाथ ने “प्लेबैक डांस” पर 17 और 18 अक्टूबर 2005 को लेक्चर दिये।
74. सुश्री सौदामिनी ने “वीडियो डाक्यूमेंट्री” पर 17 से 29 अक्टूबर 2005 तक कार्यशाला की।
75. प्रणंजय गुहा ठाकुरता ने “मीडिया एथिक्स एंड रेग्यूलेशन” पर 19 अक्टूबर 2005 को एक कार्यशाला की।
76. जावेद खान ने “अभिनय” पर 19 और 20 अक्टूबर 2005 को कार्यशाला की।
77. अरविंद पांडे ने “अभिनय” पर 21 और 22 अक्टूबर 2005 को लेक्चर दिया।

78. अर्जुन गौरीसारिया ने “एडिटिंग” पर 22 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2005 को कार्यशाला की।
79. आदिल अमान ने “अभिनय” पर 24 अक्टूबर और 5 नवम्बर 2005 को लेक्चर दिये।
80. रजा मुराद ने “वायस स्पीच” पर 28 और 29 अक्टूबर 2005 को लेक्चर दिये।
81. ब्रिज एम. बक्शी ने “स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग” पर 28 अक्टूबर 2005 को एक कार्यशाला की।
82. जहांगीर चौधरी ने “न्यू कलर एमल्शन टेस्टिंग” पर 3 अक्टूबर 2005 को एक कार्यशाला की।
83. सुरेश नायक ने “इंट्रोडक्शन टु स्पेशल इफेक्ट्स इन कैमरा” पर नवम्बर 2005 में एक लेक्चर दिया।
84. रमेश मीरचंदानी ने “डिजिटल इफेक्ट्स” पर नवम्बर 2005 में एक लेक्चर दिया।
85. अनूप जोतवानी ने “लाइटिंग फॉर टेबल टॉप” पर नवम्बर 2005 में एक लेक्चर दिया।
86. मणि कौल ने तृतीय वर्ष के फिल्म निर्देशन डिप्लोमा छात्रों के लिये “फिल्म निर्देशन में मास्टर क्लास कार्यशाला” 14 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2005 तक आयोजित की।
87. किशोर कुमार ने “अभिनय” पर 7 और 8 नवम्बर 2005 को कार्यशाला की।
88. विश्वदीप चटर्जी ने “संगीत” पर 7 नवम्बर से 9 नवम्बर 2005 तक लेक्चर दिये।
89. श्रीकर प्रसाद ने “एडिटिंग” पर 7 नवंबर से 12 नवम्बर 2005 तक कार्यशाला की।
90. डा चन्द्र प्रकाश ने “अभिनय” पर 9 से 10 नवम्बर 2005 तक कार्यशाला की।
91. उदयन वाजपेयी ने “फिल्म एंड आर्ट” पर 9 नवम्बर 2005 को एक लेक्चर दिया।
92. कुंदन शाह ने “स्क्रीन प्ले राइटिंग” पर 11 और 12 नवंबर 2005 को लेक्चर दिया।
93. सुरेश नाइक ने “स्पेशल इफेक्ट्स इन सिनेमेटोग्राफी” पर 16 से 18 नवम्बर 2005 तक कार्यशाला की।
94. रमेश मीरचंदानी ने “स्पेशल इफेक्ट्स” पर 16 से 18 नवंबर 2005 तक एक कार्यशाला की।
95. आदिल अमान ने “अभिनय” पर 11, 16 और 19 नवम्बर को लेक्चर दिया।
96. श्री अनूप सिंह ने “फिल्म थ्योरी” पर 7 से 19 नवम्बर 2005 तक एक कार्यशाला की।
97. अनूप जोतवानी ने “लाइटिंग” पर 20 और 21 नवम्बर 2005 को लेक्चर दिये।
98. अवीक मुखोपाध्याय ने “लाइटिंग” पर दिसम्बर 2005 में एक कार्यशाला की।
99. के. मोहनन ने “सिनेमास्कोप लाइटिंग” पर दिसम्बर 2005 में एक कार्यशाला की।
100. च्यांग कोहंग ने “लोकेशन” पर दिसम्बर 2005 में एक कार्यशाला की।
101. के. रामचन्द्र बाबू ने “एडवांस्ड लाइटिंग” पर दिसम्बर 2005 में एक कार्यशाला की।
102. संजय अग्रवाल ने “हाई डेफिनेशन वीडियो” पर दिसम्बर 2005 में एक कार्यशाला की।
103. अवीक मुखोपाध्याय ने “सिनेमेटोग्राफी” पर 8 दिसम्बर से 11 दिसम्बर 2005 तक कार्यशाला की।
104. अनूप सिंह ने “एडिटिंग” पर 5 से 8 दिसम्बर 2005 तक कार्यशाला की।
- इन कार्यशालाओं और लेक्चर के अलावा अनेक नामी लेक्चरर्स एफ टी आई आई आए और उन्होंने छात्रों और विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण पा रहे लोगों से बातचीत की।

स्टडी टूर

- i. “ब्राडकास्ट इंडिया प्रदर्शनी” देखने के लिये 21.10.2005 को एक स्टडी टूर मुंबई गया।

अन्य लघु पाठ्यक्रम

संस्थान ने निम्न लघु पाठ्यक्रम चलाए :

- i. टी वी प्रोडक्शन और टेक्नीकल आपरेशन में 51वां पाठ्यक्रम 11 जुलाई से 1 अक्टूबर 2005 तक चलाया गया।

- ii. 12वां बेसिक वीडियोग्राफी पाठ्यक्रम 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2005 तक चला।
- iii. टी वी प्रोडक्शन के लिये ओरिएन्टेशन कोर्स इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन 3 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2005 तक चलाया गया।
- iv. वृत्तचित्र निर्माण पाठ्यक्रम 7 नवम्बर से 17 दिसम्बर 2005 तक चलाया गया।
- v. ऑडियो डिजाइनिंग पाठ्यक्रम 7 से 19 नवम्बर तक चलाया गया।
- vi. मेकअप पाठ्यक्रम 21 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2005 तक चला।
- vii. मल्टी कैमरा टीवी स्टूडियो प्रोडक्शन एंड एडवांस वीडियोग्राफी पर कार्यशाला 21 से 26 नवम्बर 2005 तक आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान संस्थान निम्न पाठ्यक्रम भी चलाएगा -

- i. टीवी प्रोडक्शन के लिये ओरिएन्टेशन कोर्स इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन-2 जनवरी से 28 जनवरी 2006 तक।
- ii. ऑडियो डिजाइनिंग कोर्स - 13 फरवरी से 25 फरवरी 2006 तक।
- iii. टीवी टेक्नॉलाजी कोर्स - 13 फरवरी से 25 फरवरी 2006 तक।

उपकरण

वर्ष के दौरान डिजिटल विजन मिक्सर, ऑडियो कंसोल और डीवीसी ए एम कैसेट रिकार्डर, डी वी सी ए एम कैमकार्डर्स, आडियो वर्कस्टेशन और कई किस्म के डायनमिक और वायरलैस माक्रोफोन खरीदे गये।

किताबों की लायब्रेरी

लायब्रेरी में फिल्म और टेलीविजन के विभिन्न पहलुओं पर 26,131 से ज्यादा दुर्लभ किताबें हैं।

फिल्म लायब्रेरी

संस्थान की फिल्म लायब्रेरी में 3000 से ज्यादा भारतीय और

विदेशी फीचर और लघु फिल्मों, अध्ययन सार और एफ टी आई आई फिल्मों का संग्रह है। फिल्म लायब्रेरी में आडियो विजुअल सामग्री जैसे डिस्क रिकार्ड्स, वीडियो कैसेट और डीवीडी वीसीडी का भी संग्रह है।

वीडियो टेप लायब्रेरी

वीडियो लायब्रेरी में वी एच एस और यू-मेटिक, भारतीय और विदेशी तथा लघु फिल्मों के बीटाकैम कैसेट, वृत्तचित्र और छात्रों द्वारा बनाई फिल्मों, टीवी कार्यक्रम, छात्रों और टीवी प्रशिक्षकों द्वारा बनाए गये वीडियो वृत्तचित्रों का संग्रह है।

इन टेपों की मदद से छात्रों को विकास और प्रोडक्शन तकनीक का गहराई से अध्ययन करने में मदद मिलती है और वो एडिटिंग टेबल पर ही फिल्म देख सकते हैं।

नियुक्तियां

इस वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि “विशेष भर्ती अभियान” के तहत ग्रुप ए और बी पद के लिये इंटरव्यू लिये गए और छह चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिये गए। ग्रुप सी और डी पदों के लिये इंटरव्यू जनवरी, 2006 में होंगे।

संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- i. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में 3 सितम्बर 2005 को लेनसाइट डिप्लोमा फिल्म समारोह आयोजित किया।
- ii. संस्थान ने 14 सितम्बर से 21 सितम्बर 2005 तक हिन्दी सप्ताह मनाया। संस्थान ने आतंकवाद विरोधी दिवस, सद्भावना दिवस और कौमी एकता दिवस भी मनाया। इन दिवसों पर सभी कर्मचारियों, छात्रों और प्रशिक्षुओं ने शपथ ली।

प्रमुख आगंतुक

- i. एफ टी आई आई के छात्रों को जानकारी देने के लिये एरिफ्लेक्स कंपनी के इंजीनियरों श्री क्लॉज रिक्टर और सुश्री स्टेफनी ने 9 अप्रैल 2005 को फिल्म और टेलीविजन संस्थान का दौरा किया।
- ii. सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने “मौके पर

मुआयना करने” के लिये 6 अक्टूबर 2005 को संस्थान का दौरा किया।

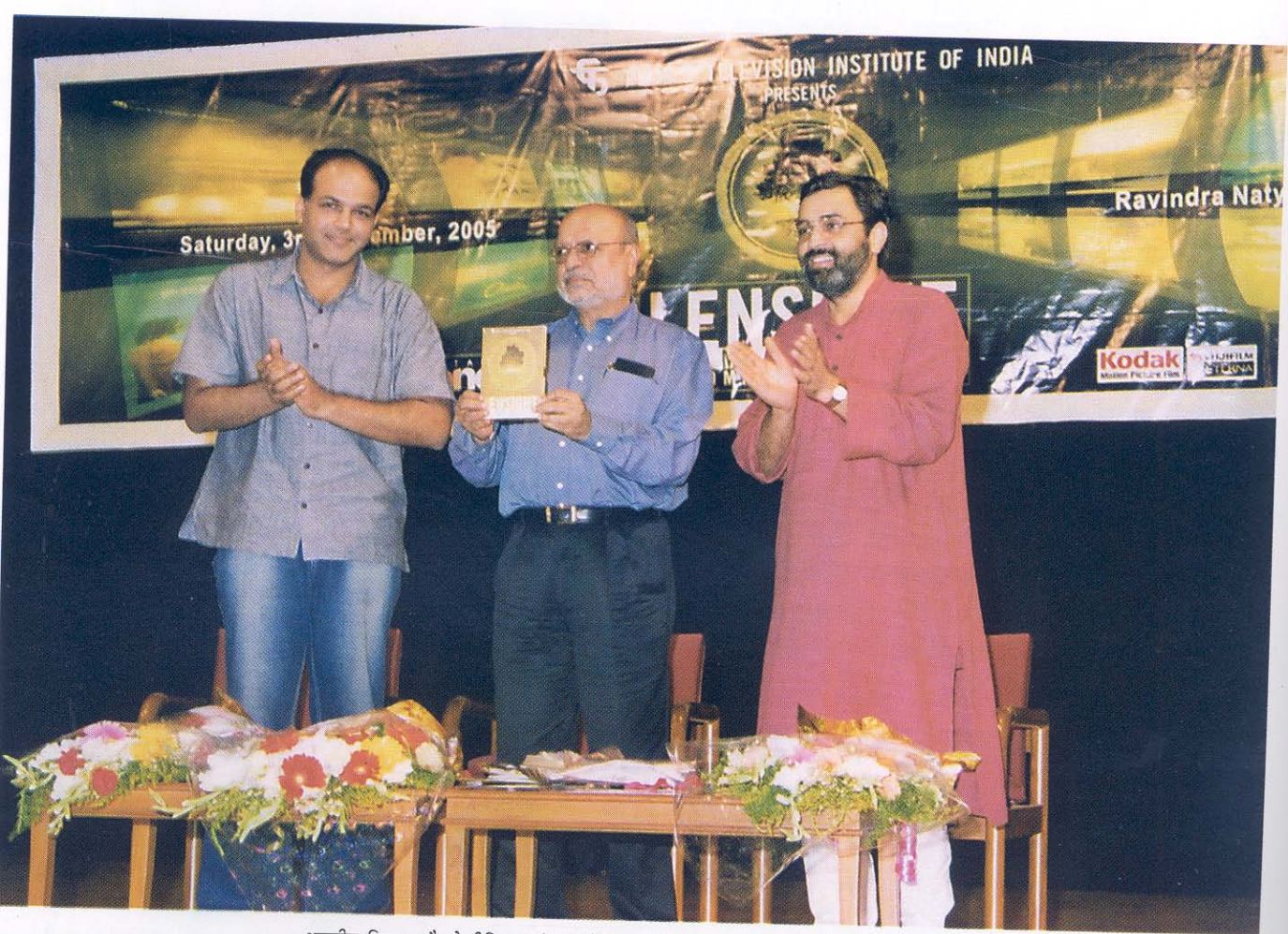
- iii. भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिये आयोजित 39वें प्रोफेशनल कोर्स में 21 देशों के 24 विदेशी राजनयिकों ने भाग लिया और विदेश मंत्रालय के 3 अधिकारी 10 दिसम्बर 2005 को संस्थान में आए।

शिष्टमंडल

- i) टी वी टेक्नीकल आपरेशन्स के प्राध्यापक जी.बी. सिंह को “शैक्षिक एवं सामाजिक संचार में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास

के प्रभाव” विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसका आयोजन शैक्षिक संचार संघ, एन एस सी कैम्पस, नई दिल्ली ने 17 से 18 मई 2005 को किया।

- ii) एफ टी आई आई के निदेशक त्रिपुरारी शरण को 2 से 5 जून 2005 तक जर्मनी के बर्लिन में प्रोबलोफ XI में शामिल होने के लिए भेजा गया।
- iii) एफ टी आई आई के निदेशक त्रिपुरारी शरण को 15 से 20 अक्टूबर 2005 तक किंगदाओ, चीन में सिलेक्ट के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया।



भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने मुम्बई के रविन्द्रन नाट्य मंदिर में लेंसाईट डिप्लोमा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया, 3 सितम्बर, 2005

iv) एफ टी आई आई के निदेशक त्रिपुरारी शरण और पाठ्यक्रम समन्वयक [डीन (फिल्म्स)] श्री सतीश कुमार ने 2 से 4 जनवरी 2006 तक स्टेमफोर्ड यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश का दौरा किया।

एफ टी आई आई में सतर्कता और निगरानी कार्य

एफ टी आई आई में 01-04-2005 से लेकर 31-12-2005 तक सतर्कता से जुड़ा कोई मामला नहीं होने के कारण सतर्कता और निगरानी कार्य नगण्य रहे।

अध्याय-III

वित्त

वर्ष 2004-2005 वित्त वर्ष के लिए संस्थान का वास्तविक खर्च इस प्रकार रहा :-

लाख रुपये में

	संशोधित अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक खर्च
गैर योजना	639.00 (शुद्ध)	624.00 (शुद्ध)	751.76*
योजना	276	306.31	294.03**
कुल	915.00	930.31	1045.59

* 127.76 लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च को वर्ष 2004-2005 के दौरान जुटाई गई 150.57 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति से पूरा किया गया। 22.81 लाख रुपये की शेष बची हुई राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मार्च 2005 के महीने के वेतन के आंशिक भुगतान के लिए किया गया।

** योजना के तहत 306.31 लाख रुपये के अंतिम अनुदान में से 294.03 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया और शेष बची हुई राशि 12.28 लाख रुपये वर्ष 2004-2005 के अंत तक इस्तेमाल नहीं हुई। भारत सरकार से विदेशी शिष्टमंडलों के लिए स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम और छात्रवृत्ति जैसे मानव संसाधन विकास के पहलुओं के कुछ कमी रह गई।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के स्वीकृत बजट अनुदान और योजना और गैर योजना के तहत 31.10.2005 तक का वास्तविक खर्च इस प्रकार है।

लाख रुपये में

	स्वीकृत बजट अनुदान	वास्तविक खर्च
गैर योजना	617.00 (शुद्ध)	404.67*
योजना	220.60	118.94
कुल	837.60	523.61

योजना और गैर योजना कार्य

वार्षिक योजना 2005-2006

वर्ष 2005-2006 के लिए 220.60 लाख रुपये की अनुदान सहायता वार्षिक योजना के लिये स्वीकृत की गई। वर्ष 2005-2006 की संशोधित वार्षिक योजना के लिए 612.93 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें एफ टी आई आई, पुणे के 'उन्नतीकरण और आधुनिकीकरण' के तहत वर्तमान योजना का दायरा बढ़ाने के लिये अतिरिक्त योजना शामिल है। इसे स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेजा गया है।

2) गैर योजना

जहां तक गैर योजना कार्यों का प्रश्न है, संस्थान को सरलता से चलाने के लिए खर्च वेतन, किराया दरों और करों आदि के मद में किया गया।

1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2006 तक किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष 2005-2006 के लिए प्रस्तावित संशोधित अनुमान 761.36 लाख रुपये (शुद्ध) और 2006-2007 का प्रस्तावित बजट अनुमान 800.26 लाख रुपये (शुद्ध) है।

अवधि	तीन वर्ष से ज्यादा का बकाया	तीन वर्ष और उससे कम का बकाया	लेखा द्वारा उठाई गई अनियमितताओं की श्रेणी
1996-97	कुछ नहीं	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. लगातार अनियमितताएं। 2. स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले लोगों से 21,20,076 रुपये के जल शुल्क की वसूली नहीं। 3. केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (गैर लाभार्थी संगठनों और ऐसे ही संस्थानों) के लिए समान लेखा प्रणाली। 4. राजस्व प्राप्तियां और उसकी वैधता। 5. कामकाज की समीक्षा 6. निर्धारित परिसम्पत्तियां। 7. सी सी डब्ल्यू (सिविल और इलेक्ट्रिकल) ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान 8. फंड को रोकना। 9. भंडारण के मद में अनावश्यक खर्च। 10. ठेके में शर्तों का पालन नहीं होने के कारण ई पी ए बी एक्स प्रणाली की क्षति/नुकसान

(4) लेखा टिप्पणियां

31.3.1997 तक उठाई गई लेखा आपत्तियां और 31.12.2005 तक लंबित लेखा आपत्तियां इस प्रकार हैं :

(क) 1997-2004 के लिए लेखा निदेशक, मुंबई की निरीक्षण रिपोर्ट एवं टिप्पणियां और 31.12.2005 तक लंबित रिपोर्ट :

मुख्य लेखा निदेशक, मुंबई को उपरोक्त टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के बारे में ब्यौरा दिया जा रहा है।

(ख) 01-04-2004 से 31-03-2005 की अवधि के लिए संस्थान के खातों का लेखा जोखा मुख्य लेखा निदेशक मुंबई द्वारा किया जाना बाकी है।

वर्ष 2004-2005 के लिए संस्थान के खातों का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नामित मैसर्स पाटनकर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा-जोखा किया गया है। लेखा रिपोर्ट के

साथ वार्षिक खातों को 25-10-2005 को एस एफ सी की बैठक में मंजूरी के लिए रखा गया है।

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

(1) परिचय

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान के रूप में की गई। संस्थान के पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। फिल्म जगत की मशहूर हस्ती सत्यजीत राय की स्मृति में कोलकाता में स्थापित यह संस्थान सरकार का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। संस्थान निर्देशन 'पटकथा लेखन' चलचित्र फोटोग्राफी, फिल्म-संपादन और साउंड रिकार्डिंग में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। बुनियादी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान फिल्म और टेलीविजन से सम्बन्धित संबंधी विषयों में अल्पावधि और मध्यम अवधि के पाठ्यक्रम भी संचालित

करता है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र, संस्कृति और फिल्म प्रौद्योगिकी तथा टेलीविजन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और शोधपूर्ण अध्ययन इस संस्थान के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

(2) प्रबंध और संगठनात्मक ढांचा

सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अर्न्तगत वित्त स्वायत्तशासी संस्थान है जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति करती है। इस समिति का अध्यक्ष एक शासी-परिषद् के माध्यम से इसका संचालन करता है। इसमें समिति के चुर्नीदा सदस्य होते हैं। शासी-परिषद् संस्थान की सभी कार्यकारी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह आवश्यकतानुसार विभिन्न समितियों/संस्थाओं का गठन करती है जिनमें शैक्षिक परिषद् और स्थाई वित्त समिति शामिल हैं।

इस समिति में सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। शासी-परिषद् और स्थाई वित्त समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारी पदेन सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। संस्थान की नई समिति का गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया गया है जिसमें जाने-माने फिल्म-निर्माता श्री बासु चटर्जी को अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद के साथ-साथ वे शासी परिषद् और अन्य समितियों के भी अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक की अवधि में समिति की एक और शासी-परिषद् की दो बैठकें आयोजित हुईं।

(3) बुनियादी ढांचा और उपकरणीय सुविधाएं

(3-1) प्रमुख बुनियादी ढांचा और उपकरण :

सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता में पूर्वी महानगर बाह्य-मार्ग पर 39.36 एकड़, के विशालकाय क्षेत्र में निर्मित है। बुनियादी ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित भवन और सुविधाएं हैं :

निर्देशन विभाग : एस ब्लाक में मुख्य रूप से निर्देशन और क्रय विभाग के कार्यालय हैं। इसमें दो वातानुकूलित क्लासरूम, एक कंप्यूटर लैब है। यह विभाग वी.एच.एस./वी.सी.डी./एल डी जैसी अवलोकन सुविधा और एक डी.वी.डी. सहित एडिटिंग रूम से सुसज्जित है। मुख्य कला रूप गृह थिएटर सुविधासे लैस है। निर्देशन-कौशल और कार्यनीतियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में कार्यशालाओं के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित व्यवसायियों को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

ध्वन्यांकन विभाग : इस विभाग में ध्वन्यांकन, ध्वनि संपादन और निर्माण परवर्ती चरण के लिए ट्रैक लेइंग के वास्ते तीन बड़े स्टूडियो और एक अलग डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है। इसके अतिरिक्त दो समर्पित डिजिटल वर्क स्टेशन, तीन डी ए डब्ल्यूज़ और सॅराउन्ड मिक्सिंग सुविधा के साथ एक डिजिटल वर्क स्टेशन, तीन डी ए डब्ल्यूज़ और सॅराउन्ड मिक्सिंग सुविधा के साथ एक डिजिटल वर्क स्टेशन भी है। कलाकार की सुविधा और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए परंपरागत ऑडियो निर्माणोत्तर पद्धति, एनाॅलाग रिकार्डिंग की रमणीयता का मिश्रण अत्याधुनिक डिजिटल रिकार्डिंग प्रौद्योगिकियों के साथ किया जाता है। ध्वनि विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अनुषंगी प्रौद्योगिकियों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, ताकि सही अर्थों में पूर्ण साउंड रिकार्डिस्ट तैयार किए जा सकें।

संपादन विभाग : इस विभाग में एक फिल्म और एक वीडियो अनुभाग है। फिल्म अनुभाग में अलग-अलग चैम्बरों में 10 एडीटिंग टेबल, सिंक्रोनाइजर्स, स्प्लीसर्स आदि रखे गए हैं। एसवीएचएस, यू-मैटिक और बीटा फोर्मेट्स में संपादन कार्य के लिए वीडियो अनुभाग में छह एनाॅलाग वीडियो एडीटिंग सूट्स, एक अविड मीडिया कंपोजर, छह पिक-सिंक्स और एक मूवीवाला की व्यवस्था है। डिजिटल नॉन-लिनियर संपादन कक्ष दो अविड मीडिया कम्पोजर्स और एक फाइनल कटप्रो से सुसज्जित है, जिसमें फिल्म संपादन के लिए सिनेमा टूल, पांच अविड डीवी एक्सप्रेस, 4 एफसीपी, एक डीपीएस वेलोसिटी, एक एडिट-5 और एडोब प्रीमियर सैटअप है, जो नॉनलिनियर संपादन के प्रति समर्पित है। विभाग में 5 लिनियर वीडियो एडीटिंग सूट्स और एक ग्राफिक्स अनुभाग भी है, जिसमें तीन समर्पित वर्कस स्टेशन्स हैं, विभाग के पास नियमित स्क्रॉनिंग, विचार विमर्श और विश्लेषण के लिए अवलोकन और डिजिटल संपादन डिमोस्ट्रेशन सुविधाओं सहित एक विशेष क्लासरूम, एगिट-प्रोप भी है।

चलचित्र छायांकन विभाग : इस विभाग में व्यापक रेंज के कैमरे लगे हैं, जैसे दो ए.आर.आर.आई.टू.सी. 35 एम.एम. कैमरे, एक एस आर III और एक एस आर II कैमरा (दोनों 16 एम एम), एक नई पीढ़ी का अत्याधुनिक नॉन-ब्लिम्प 35 एमएम कैमरा, एआरआरआई 435, जिसमें वीडियो सहायता प्रणाली भी लगी है, दो डीवाईसी 637 वीडियो कैमरे (जिनमें से एक में अतिरिक्त एसवीएचएस अटैच है), दो बीटा कैम रिकार्डर्स, एक हाईबैंड रिकार्डर, चार डिजिटल कैमरे, एचएम आई लाइट्स और सभी प्रकार की कैमरा एक्सेसरीज, जिनमें लाइट मीटर और अन्य उपकरण शामिल हैं।

विभाग को कुछ और सुविधाओं से सुसज्जित किया गया, जिनमें टेलीविजन स्टूडियो में 'तीन कैमरा सैटअप' और एक स्टिल फोटोग्राफी अनुभाग शामिल हैं, जहां 16 कैमरे और श्वेत श्याम तथा रंगीन फिल्मों की प्रोसेसिंग, डिवेलपिंग और प्रिंटिंग सुविधाएँ मुहैया कराई गयी हैं। विभाग ने हाल ही में अरी सनसीरीज एचएमआई लाइटें खरीदी हैं, इससे लाइटों के विभागीय संग्रह में अत्याधुनिकता आई है। विभाग अग्रिम पंक्ति की प्रयोगशालाओं से सक्रिय संपर्क कायम करता है, ताकि विद्यार्थी नियमित रूप से इन प्रयोगशालाओं में जा सकें।

(3.2) सहायक सुविधाएं :

फिल्म स्टूडियो एवं टेलीविजन स्टूडियो : संस्थान में दो-मंजिला वाला शानदार स्टूडियो है। इसका फिल्म स्टूडियो पूर्वी क्षेत्र का सर्वोत्तम स्टूडियो है। स्टूडियो तल का आकार (80'x50') बड़े बजट के भव्य सेट के लिए भी उपयुक्त है इसमें पूर्ण रूप से वातानुकूलित मेकअप रूम, विशिष्ट कैमरों के लिए भूमिगत विट, प्रकाश व्यवस्था के लिए 3 टीयर प्लेटफार्म, कला सामग्री रखने हेतु एक बड़ा स्टोर रूम और एक सुसज्जित काष्ठकारी एवं रंगरोगन कक्ष है।

50'x50' परिमाण का पूरी तरह वातानुकूलित कलरयुक्त टेलीविजन स्टूडियो में तीन कैमरों के साथ एक नियंत्रण कक्ष है। इसमें पैनल मोटोराइज्ड टेलिस्कोपिंग लाइटिंग ग्रिड तथा साइक्लोसमा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस स्टूडियो का इस्तेमाल टी.वी. कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण और मुख्य कैमरा स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट के लिए होता है। कैमरों और लाइटिंग उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए दोनों स्टूडियो में अलग-अलग कमरे हैं।

सभागार और फिल्म प्रदर्शन की सुविधा : संस्थान में सेल्युलाइड और वीडियो फार्मेट, दोनों में ही प्रीव्यू और फिल्मों के प्रदर्शन की बहुआयामी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसमें 370 सीटों वाले मुख्य थियेटर और प्रीव्यू थियेटर (72 सीटों वाला) में 35 एम एम और वीडियो प्रोजेक्शन की बहु प्रयोजन सुविधाएँ उपलब्ध हैं और साथ ही एक मुक्त आकाश थियेटर है, जिसमें 500 से अधिक दर्शकों के लिए सेल्युलाइड प्रोजेक्शन सुविधा उपलब्ध है।

पुस्तकालय : तेजी से बढ़ रहे दो मंजिले पुस्तकालय में एक बड़ा अध्ययन कक्ष, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वीडियो दृश्यांकन कक्ष और साथ ही अनेक दृश्यांकन बूथ और संगीत सुनने तथा अध्ययन करने के कई बूथों सहित संगीत कक्ष है। पुस्तकालय में

विभिन्न विषयों की पुस्तकों, पत्रिकाओं, वीएचएस कैसेटों, एल डी जी/वी डीज वीसीडी का शानदार संग्रह है।

फिल्म लाइब्रेरी : संस्थान के फिल्म पुस्तकालय में 1451 फिल्मों (फीचर : 501 और वृत्तचित्र : 950) का संग्रह है। इन फिल्मों का इस्तेमाल मुख्य रूप से शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

छात्रावास : 2001 में निर्मित नये छात्रावास की क्षमता 160 सीटों की है। इसके अतिरिक्त इसमें दो भोजन हाल, एक रसोई घर, आमोदालय, तथा जिम्नेजियम सहित चिकित्सा कक्ष है, इनमें इंटरकोम की सुविधा उपलब्ध है।

आवासीय परिसर : संस्थान के कर्मचारियों के लिए कुल 41 क्वार्टर हैं।

अतिथि-गृह : संस्थान के अतिथि गृह में दो विशिष्ट कक्ष हैं और डबलबेड के 16 कमरे उपलब्ध हैं। इसमें भोजन हाल, रसोई घर के अलावा खूबसूरत लांज, स्वागत कक्ष, स्टोर रूम और आंगन भी उपलब्ध है।

अन्य सुविधाएं : (1) संस्थान परिसर में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा संचालित एक डाक घर भी है।

(2) एक कैंटीन जिसका संचालन निजी ठेकेदार द्वारा होता है।

(4) **शैक्षिक मामले :** छठवें बैच के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया अप्रैल 2004 में आरंभ हुई। 5 सितंबर 2004 को अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित की गई और चयन प्रक्रिया दिसंबर 2004 में पूरी हो गई।

4.11. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

पाठ्यक्रम का नाम	सिनेमा में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पाठ्यक्रम की अवधि	3 (तीन) वर्ष
न्यूनतम योग्यता	स्नातक या समकक्ष (साउंड रिकार्डिंग के लिए : 10+2 या समकक्ष परीक्षा में भौतिक शास्त्र एक विषय रहा हो)

सीटों की मौजूदा संख्या :

क्र. सं.	संचालित पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	सीटों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या				
			तृतीय बैच	चतुर्थ बैच	पंचम बैच	छठा बैच	कुल
1.	फिल्म निर्देशन एवं पटकथा लेखन	10	10	10	10	10	30
2	चलचित्र छायांकन	10	09	10	10	09	29
3	संपादन	10	09	10	10	09	29
4	ध्वन्यांकन	10	07	07	07	09	23
कुल		40	35	37	37	37	109
अभ्युक्तियां :		<ol style="list-style-type: none"> ध्वन्यांकन में चौथे और पांचवें बैच में समुचित दाखिले उपयुक्त उम्मीदवार न मिल पाने की वजह से नहीं हो पाये। पाठ्यक्रम बीच में अधूरे छोड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, चतुर्थ बैच : 03 पांचवां बैच : 03 छठा बैच : 03 					
विशेष नोट :		<ol style="list-style-type: none"> प्रत्येक पाठ्यक्रम में दो सीटें विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। आरक्षण सरकारी मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा। 					

4.12 संस्थान द्वारा संचालित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश-विधि :

प्रवेश प्रतियोगात्मक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। यह परीक्षा सामान्यतः हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है। प्रवेश परीक्षा के तहत पहले लिखित परीक्षा होती है। उसके बाद चुने गये योग्य उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा और पारस्परिक विचार-विनिमय का सत्र होता है। नये प्रवेश जुलाई में होते हैं जिसके लिए आमतौर पर प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष जनवरी/फरवरी में शुरू हो जाती है। प्रवेश संबंधी विज्ञापन देश के प्रमुख समाचार पत्रों और रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जाता है। लिखित परीक्षा विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित होती है जबकि मौखिक परीक्षा और पारस्परिक विचार विनिमय सत्र संस्थान परिसर कोलकाता में ही आयोजित होता है। लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान और बौद्धिक-योग्यता पर आधारित होता है जबकि दूसरा प्रश्नपत्र चुने गये विषय की विशिष्ट योग्यता क्षेत्र पर आधारित होता है।

4.2 अध्ययन/शैक्षिक भ्रमण : अक्टूबर 2005 के दौरान एम.पी.पी. विद्यार्थियों का चौथा बैच सितम्बर-अक्टूबर 2005 में चेन्नई के टेलीसिन के लिए मुंबई के अध्ययन दौरे पर गया। संस्थान विद्यार्थियों के तीसरे बैच ने चेन्नई प्रयोगशाला का दौरा किया।

4.3 संस्थान के नियमित संकाय :

संस्थान के संकाय में 9 शिक्षक हैं, जिनमें 4 सहायक प्रोफेसर और 5 प्रवक्ता हैं मौजूदा संकाय के सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ये या तो फिल्म स्कूल के पूर्व स्नातक हैं या फिर हम पेशे की जानी मानी हस्ती हैं।

(4.4) संस्थान के अतिथि शिक्षक : संस्थान फिल्म उद्योग के पेशेवर व्यक्तियों को कक्षाओं में पढ़ाने और विशेष विषयों में प्रेक्टिकल कराने के लिए अतिथि शिक्षकों के रूप में आमंत्रित करता है। नियमित शिक्षकों की सीमित संख्या को देखते हुए संस्थान की नियमित कक्षाओं के पाठ्यक्रम के लिए भी अतिथि शिक्षकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा संस्थान फिल्म और टेलीविजन

प्रेस की प्रमुख हस्तियों को कार्यशालायें आयोजित करने के लिए भी आमंत्रित करता है।

(4.5) प्रदर्शन कार्यक्रम और समारोह तथा सिंहावलोकन :

2005-2006 (इस रिपोर्ट के तैयार होने तक) के दौरान शैक्षिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में 223 फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। नियमित प्रदर्शनों के अतिरिक्त संस्थान के विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम के तहत नवंबर 2005 में कोलकाता में आयोजित फिल्म समारोह में हिस्सा लिया।

(4.6) डिप्लोमा फिल्म परियोजना : संस्थान में तीसरे बैच के सभी विद्यार्थियों ने अपनी डिप्लोमा परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। चौथे बैच के विद्यार्थियों की यही परियोजना इन दिनों जारी है। इसके तहत कुछ बहुत अच्छी फिल्मों के जारी होने की आशा है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर सकेगी।

(4.7) समारोह जिनमें, शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए :

1. 10वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, कोलकाता - नवंबर, 2005
2. इंटरनेशनल फोरम फार न्यू सिनेमा, कोलकाता - नवंबर 2004
3. भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा, 2005
4. केरल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह - 2005

(4.8) एस आर एफ टी आई की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान/संगोष्ठी और कार्यशाला

1. सत्यजीत राय स्मृति व्याख्यान-2005 श्री बुद्धदेव दास गुप्ता ने व्याख्यान दिया)
2. डोसेज-2005 (पान्डूलिपि विकास, संयुक्त निर्माण और तारत्व पर कार्यशाला)

(4.9) विशेष प्रदर्शन : गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड विजन इन्डिया के लिए बाल फिल्मों के विशेष प्रदर्शन और विचार-विमर्श आयोजित

किए गए। यह आयोजन स्ट्रीट चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट प्रतिभागियों के लिए था।

(4.91) विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम : संस्थान ने एच एफ एफ फिल्म स्कूल पोत्सदम जर्मनी के साथ संयुक्त रूप से विद्यार्थियों का आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अंतर्गत इस संस्थान के 9 विद्यार्थियों अक्टूबर 2005 में जर्मनी की यात्रा की।

(5) एस आर एफ टी आई की ओर से संस्थान में आयोजित फिल्म समारोह :

1. फास बिंडर सिंहावलोकन, अप्रैल 2005
2. फ्रेंच फिल्म समारोह, नवंबर 2005
3. वीरा चिस्तोलोवा सिंहावलोकन, नवंबर 2004

(5.1) प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संस्थान में आगमन :

अप्रैल 2005 से फरवरी 2006 की अवधि के दौरान अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति और शिष्टमंडल संस्थान में पधारें।

1. श्री एस.के. अरोड़ा, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
2. लीना पासानेन, निर्देशक, यूरोपियन डाक्यूमेंटरी नेटवर्क, डेनमार्क
3. श्री मृणाल सेन, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता
4. श्रीमती तस्लीमा नसरिन, सुविख्यात लेखिका
5. श्री आइम्रे लेजर, प्रथम सचिव हंगरी दूतावास
6. श्री यू. राधाकृष्णन, एफ.एफ.एस.,आई नई दिल्ली
7. श्री जेय रोसन ब्लाट फिल्म निर्माता, अमरीका
8. श्री स्टीफेनो टिल्डी, निर्माता-निर्देशक इटली
9. सुश्री क्रिस्टीना पर्विल, निर्माता, मिलेनियम फिलज, फिनलैंड
10. सुश्री केथरीन मसूद, निर्माता और श्री तारिक मसूद, निदेशक, बांग्लादेश
11. विकास देसाई, जाने-माने चल चित्रकार

(5.2) संस्थान द्वारा निर्मित नई सराहनीय फिल्में :

निर्मित फिल्म का नाम	निर्देशक	समारोह का नाम
चुर्नीदा कथा साहित्य	जे.कृष्णन	मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2006 फिल्म एवं वीडियो प्रतियोगिता खंड में चयन (राष्ट्रीय खण्ड)
चेंग पाओ. चाइनीज		
चिली सॉस	सायरस खंबाटा	वैसा ही
प्लाइट ऑफ डिस्ट्रेस	सोम देव चटर्जी	वैसा ही
हियर इन माई नॉक्टर्न	अनीरबन दत्ता	वैसा ही

6. डिप्लोमा फिल्म प्रोजेक्ट

2001-04 बैच के विद्यार्थियों ने हाल ही में अपना डिप्लोमा फिल्म प्रोजेक्ट पूरा किया है। इन फिल्मों के निर्माण पश्चात के कार्य संस्थान में जारी हैं।

7. सतर्कता रिपोर्ट :

1. सतर्कता अधिकारी/गतिविधियां

- 1.1 संस्थान का रजिस्ट्रार ही इसका सतर्कता अधिकारी होता है।
- 1.2 इस संस्थान की फिलहाल कोई शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।
- 1.3 संस्थान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, जैसे सतर्कता आधारित कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है और इस बारे में समय-समय पर मंत्रालय को सूचित किया जाता है।

2. रोधात्मक सतर्कता गतिविधियां

1. इस अवधि के दौरान नियमित निरीक्षण किए गए - 03
2. ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जिन पर नजर रखना जरूरी था - 02

3. निगरानी और गुप्तचर गतिविधियां

1. निगरानी के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण - सभी
2. निगरानी में रखे जाने वाले चिन्हित व्यक्ति - कोई नहीं

4. दंडात्मक गतिविधियां (4 (i) से (10) तक के सन्दर्भ में संख्या दर्शानी है जहां राष्ट्रपति के बजाय कोई और नियुक्तिकर्ता है)

1. प्राप्त शिकायतों एवं संदर्भों की संख्या - कोई नहीं
2. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई - कोई नहीं
3. जिन मामलों में प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई - कोई नहीं
4. ऐसे मामले जिनमें हल्के दंड के लिए आरोपपत्र जारी किए गए - कोई नहीं
5. हल्के दण्ड के लिए जारी की गई चार्ज शीट - कोई नहीं
6. वे व्यक्ति जिन पर भारी दंड लगाया गया - कोई नहीं
7. उन लोगों की संख्या जिन पर हल्के दंड लगाए गए - कोई नहीं
8. निलंबित लोगों की संख्या - कोई नहीं
9. ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध चेतावनी जारी करने जैसी प्रशासनिक कार्यवाई की गई - कोई नहीं
10. नियमों के तहत स्थाई रूप से सेवा निवृत्त किए गए लोगों की संख्या - कोई नहीं

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

देश में अच्छे सिने आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एन एफ डी सी) की स्थापना की गई थी। एन एफ डी सी को भारतीय फिल्म उद्योग के समन्वित तथा सक्षम विकास के लिए योजना बनाने, तथा इस उद्योग को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। इसलिए निगम का लक्ष्य फिल्म उद्योग की सेवा करना तथा उत्कृष्ट सिनेमा को बढ़ावा देना है। एन एफ डी सी के कार्य निम्नलिखित।

1. सामाजिक उपयोगिता तथा सुरुचिपूर्ण फिल्मों का निर्माण तथा इनके लिए चित्र व्यवस्था।

2. विभिन्न चैनलों के माध्यम से फिल्मों का आयात और वितरण।
3. विदेशों में भारतीय फिल्मों का प्रचार और निर्यात।
4. भारतीय फिल्म उद्योग को निर्माण-पूर्व व निर्माण पश्चात तकनीकी परियोजना सेवाएं प्रदान करना।
5. भारत में फिल्मों की शूटिंग और इनसे जुड़े कार्यों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना
6. सिने माध्यम के जरिए देश तथा विदेश में संस्कृति तथा समझबूझ को बढ़ावा देना। इसके लिए फिल्म संस्थानों,



भारत-ब्रिटेन फिल्म सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी, नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2005

राष्ट्रीय फिल्म सर्किल तथा अन्य संगठनों के सहयोग से फिल्म समारोहों का आयोजन करना

7. भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष (सीएडब्ल्यूएफआई) के जरिए पुराने जरूरतमंद सिने कलाकारों के लिए कल्याणकारी उपाय करना। सीएडब्ल्यूएफआई निगम द्वारा स्थापित एक परोपकारी न्यास (चैरिटेबल ट्रस्ट) है।
8. विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी एजेंसियों के लिए कार्यकारी, निर्माता के रूप में फिल्मों का निर्माण करना।
9. विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों की तरफ से सामाजिक जागृति संदेश अभियान चलाना।
10. फिक्की तथा भारतीय उद्योग परिसंघ जैसे औद्योगिक निकायों के सहयोग से भारत तथा विदेशों के अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्म बाजारों का आयोजन।

1. फिल्मों का वित्तपोषण और निर्माण

एनएफडीसी बेहतरीन विषय वस्तु लेकिन कम बजट वाली फिल्मों की अवधारणा को बढ़ावा देता है। निगम प्रतिभाशाली युवा फिल्म निर्माताओं को अपने कौशल विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है। निगम द्वारा वित्त पोषित/निर्मित फिल्मों तथा इनके कलाकारों और निर्माण से जुड़े कर्मियों को विगत में कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और ये पुरस्कार अच्छे सिनेमा तथा नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रति निगम की कटिबद्धता के प्रमाण हैं। ए एफ डी सी (पहले के एफ एफ सी सहित) अभी तक विभिन्न स्कीमों के तहत ऐसी लगभग 315 फिल्मों का निर्माण/वित्तपोषण कर चुका है।

एन एफ डी सी की फिल्म परिणामम् को (मलयालम) इस वर्ष (2005-06) इजरायल के अशदोन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेणु द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नेदुमुदि वेणु, कुंजुकुट्टन आदि कलाकारों ने अभिनय किया है। निगम द्वारा सहनिर्मित फिल्म आनन्द (तेलुगु) को हैदराबाद में राज्य के नन्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के सभी कलाकार नए थे। फिल्म को इन कलाकारों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

निगम ने इस वर्ष कोई नई फीचर फिल्म शुरू नहीं की। लेकिन, निगम ने महेन्द्रन द्वारा निर्देशित फिल्म ससनम (तमिल) और नब्येन्दु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म संस्कार (बंगाली) को

पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। जयदीप घोष की फिल्म तेनरा का निर्माण भी जल्द ही शुरू होने की आशा है।

2. फिल्मों का आयात और वितरण

निगम फिल्मों का आयात और वितरण फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है और इसके लिए विदेशी निर्यातकों से बात चल रही है। साथ ही रंगमंचीय, टी.वी. उपगृह, वीडियो, प्रसारण अधिकार आदि प्राप्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

3. टी.वी. विपणन

निगम इस समय दूरदर्शन को उसके विभिन्न चैनलों जैसे, डीडी-इंडिया, डी-डी-5 पोडुगाई चैनल, डीडी-4 मलयालम चैनल आदि के लिए साफ्टवेयर उपलब्ध करा रहा है। निगम ने दूरदर्शन को सभी चार महानगरों में उपलब्ध तकनीकी तथा स्टूडियो सुविधाओं के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है।

4. फिल्मों का निर्यात

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान दिसंबर 2005 तक 10 फिल्मों का निर्यात की और इससे 24.73 लाख रुपये की आय हुई। इस वर्ष निगम 50 फिल्मों का निर्यात करने की योजना बना रहा है।

निगम फिल्मों तथा शिष्टमण्डलों के जरिए नियमित रूप से फिल्म समारोहों/बाजारों में भाग लेता रहता है। निगम प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों जैसे कान्स हांगकांग और अमरीकी फिल्म बाजार में शामिल होने के लिए विभिन्न भारतीय कंपनियों के वास्ते मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। कान्स बाजार-2005 में एक बड़े औद्योगिक शिल्पमण्डल ने भाग लिया और निगम ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से भाग लेने वाली कंपनियों को भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से सहायता पहुंचाई। निगम के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हांगकांग में आयोजित फिल्म मार्ट-2005 में भाग लिया। निगम ने नवम्बर 2005 में आयोजित अमरीकी फिल्म बाजार में एक कार्यालय स्थापित किया और इस प्रकार भारतीय फिल्मों के खरीददार और क्रेताओं के लिए कारोबारी सौदेबाजी तथा बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराया।

(ख) समारोहों में शिरकत के जरिए भारतीय फिल्मों को विदेशों में प्रोत्साहन

निगम ने वर्ष 2005-06 में दुनिया के 14 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म

समारोहों में भाग लिया और विभिन्न भारतीय भाषाओं की 9 फिल्मों का प्रदर्शन किया। निगम ने वर्ष 2005-06 (दिसंबर, 2005) तक। आठ अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया और 19 भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन किया। अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के जगत में निगम ने अच्छी साख बना ली है और इन समारोहों में एन एफ डी सी एक जाना-माना नाम बन गया है।

(ग) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति

एन एफ डी सी की फिल्म परिणामम (मलयालम) को वर्ष 2005-06 के दौरान इजरायल के अशदोद फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेणु द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नेदुमुदि वेणु, कुंजुकुट्टन आदि ने अभिनय किया है।

(घ) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (इप्फी) गोवा

निगम ने भारत के 36वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान गोवा में भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) के सहयोग से फिल्म बाजार का आयोजन किया। निगम द्वारा सह-निर्मित फिल्म आनन्द को इप्फी-गोवा के भारतीय पैनोरमा खण्ड में प्रदर्शन के लिए चुना गया।

5. विशेष तकनीकी परियोजनाएं

उपशीर्षन केन्द्र-लेज़र फिल्म सबटाइटलिंग, मुम्बई निगम के पास लेज़र के जरिए फिल्मों के उपशीर्षन के लिए अत्याधुनिक सुविधा मौजूद है। तेजी से प्रसंस्करण तथा बेहतर क्वालिटी के लिए इन सुविधाओं को हाल ही में उन्नत बनाया गया है। केन्द्र में उपलब्ध सुविधा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है और विदेशों में उपलब्ध ऐसी सुविधाओं से किसी भी मायने में कम नहीं है।

सबटाइटलिंग की सुविधा भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, अरबी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, पूर्वी (चीनी) भाषाओं और जापानी भाषाओं में उपलब्ध है। हाल ही में रूसी भाषा में सबटाइटलिंग का कार्य भी शुरू किया गया है। हिन्दी, बंगाली और सिंहली भाषाओं में लेज़र सबटाइटलिंग शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

यूनिट दो अत्याधुनिक तथा स्वचालित मिलेनिया की सॉलिटड स्टेट लेज़र मशीनों से लैस है।

इंटरपॉजिटिव लेज़र सबटाइटलिंग जैसी नई सुविधाएं मौजूद

सुविधाओं में शामिल कर ली गई हैं। नेगेटिव से सबटाइटल युक्त प्रिंट तैयार करने की जरूरत को देखते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके द्वारा विदेशों तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ प्रिंट जारी करने के लिए जरूरत के अनुसार प्रतियां तैयार की जा सकती हैं।

यूनिट में वीडियो सबटाइटलिंग तथा सम्पादन की भी सुविधाएं हैं। हाई बैण्ड वीटाकैम और डिजिवीटाकैम फार्मेट में सबटाइटलिंग की सुविधा सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध हैं।

यूनिट में वीडियो में 16 मि.मी./35 मि.मी. की स्लाइड ट्रांसफर सुविधा मौजूद है। इसमें रेखीय तथा गैर-रेखीय फार्मेट में रंगों में बदलाव सुधार तथा अफैक्ट्स की सुविधा भी है।

सबटाइटलिंग की यह सुविधा फिल्म उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के अलावा विदेश मंत्रालय, फिल्म समारोह निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और दूरदर्शन आदि की जरूरतें भी पूरी करती है।

डी वी डी/वी सी डी आथरिंग/मास्टरिंग एण्ड डुप्लीकेशन फैसिलिटीज - मुंबई

निगम ने यह सुविधा अभी हाल ही में 2004 से शुरू की है तथा इसके जरिए निजी कम्पनियों की जरूरतें पूरी करने के अलावा इंडियन पैनोरमा 2004 तथा 2005 के कई आर्डर भी सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।

16 मि.मी./35 मि.मी. कैमरा सुविधाएं, मुंबई

निगम की कैमरा यूनिट सभी सहायक उपकरणों से युक्त सुपर 16 मि.मी. एस आर फिल्म कैमरा और वीडियो एसिस्त्र यूनिट तथा सभी सहायक उपकरणों से युक्त ए आर आर आई बी एल फिल्म कैमरा से सुसज्जित है।

वीडियो तथा टी वी बुनियादी सुविधा, मुंबई

एन एफ डी सी के अपने वीडियो सम्पादन कक्ष हैं, जहां गुणवत्ता जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये सम्पादन कक्ष कैप्सूलों के अलावा प्रमोशनल सामग्री के निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं।

यूनिट को अत्याधुनिक कम्पोनेंट रिकार्डिंग स्टूडियो उपलब्ध करा कर उन्नत बनाया गया है। स्टूडियो में डिजिटल बीटालैस और डिजिटल सोशल एफैक्ट मशीनें भी हैं। दूरदर्शन को प्रदान

की जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निकट भविष्य में चरणबद्ध तरीके से यूनिट को डीवी कैम और एच डी सिस्टम से सज्जित करने की योजना है।

स्टूडियो में डबिंग और वीडियो फिल्म आदि की सुविधा है। गैर-रेखीय सम्पादन सुविधा शामिल करने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके लिए डी वी फॉर्मेट वाली सुविधाओं को वरीयता दी जाएगी।

नई दिल्ली स्टूडियो

एनएफडीसी के अपने वीडियो सम्पादन कक्ष हैं जो गुणवत्ता जांच की सुविधाओं से युक्त हैं ये कक्ष प्रोमो कैप्सूल तथा प्रमोशनल सामग्री के निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं।

यूनिट में गैर-रेखीय सम्पादन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें सम्पादन के लिए नवीनतम ए वी आई डी मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है।

केन्द्र ने इग्नू में स्थापित वीडियो सर्वर को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की है। केन्द्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के एकलव्य चैनल को भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

पीवीआर यूनिट, चेन्नई

चेन्नई स्थित यह वीसीआर यूनिट सारे दक्षिण क्षेत्र के फिल्म उद्योग की जरूरतें पूरी करता है। केन्द्र के पास गुणवत्ता जांच के साथ-साथ प्रमोशनल सामग्री के निर्माण के लिए हाई बैण्ड, बीटा कैम सम्पादन सुविधाएं मौजूद हैं।

यूनिट एफडीएल 60 टेलीसिने मशीनों के जरिए हाइबैण्ड, बीटाकैम और डिजि बीटा कैम फॉर्मेट में फिल्मों को वीडियो में रूपान्तरित करने के उपकरण से युक्त है।

यूनिट में एविड एक्सप्रेस प्रणाली का इस्तेमाल करने वाली और रेखीय सम्पादन सुविधा को शामिल कर और आधुनिक बनाया गया है।

पूरे दक्षिण क्षेत्र को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत इस केन्द्र को आधुनिकतम वीडियो सबटाइटलिंग सुविधाओं से लैस किया गया है। केन्द्र कार्यक्रम सामग्री की भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, अंग्रेजी भाषा और अरबी भाषा में सबटाइटलिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। सबटाइटलिंग

की सुविधा हाई बैण्ड, बीटाकैम और डिजि बीटाकैम फॉर्मेट में उपलब्ध है।

केन्द्र डीवीडी/वीसीडी मास्टरिंग/ऑथरिंग तथा डुप्लीकेशन सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।

उपरोक्त के अलावा केन्द्र विभिन्न सरकारी विभागों के लिए वृत्तचित्रों के निर्माण का भी कार्य करता है।

16 मि.मी. फिल्म केन्द्र, कोलकाता

केन्द्र पूर्वी क्षेत्र के फिल्म उद्योग को निर्यात के दौरान तथा निर्यात के बाद की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। केन्द्र एक 16 मि.मी. एस आर फिल्म कैमरा और सिंक्रोनाइज्ड शूटिंग के लिए नाग्रा 4.21 ध्वन्यांकन सुविधा तथा सिनेमास्कोप और सामान्य लेंसों के साथ एआरआरआई 35 मि.मी कैमरा से लैस है।

रिकार्डिंग तथा री-रिकार्डिंग स्टूडियो 16 मि.मी. और 35 मि.मी. फॉर्मेटों के लिए मैग्नाटेक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो सिस्टम से युक्त है।

केन्द्र के पास फिल्मों के सम्पादन के लिए स्टीन बेक एडिटिंग टेबल और ऐक्मे पिकसिंक मशीनें उपलब्ध हैं।

कोलकाता के बेहाला स्थित इस केन्द्र के पास वीडियो फॉर्मेट के लिए सर्व सुविधायुक्त हाई बैण्ड सम्पादन प्रणाली है और यहां दूरदर्शन तथा पूर्वी क्षेत्र के अन्य उद्योगों के लिए सम्पादन का काफी कार्य किया जाता है।

यूनिट एफडीएल 60 टेलीसिने मशीनों के जरिए हाईबैण्ड, बीटाकैम पर फिल्मों के वीडियो में रूपान्तर की सुविधा भी मौजूद है।

बेहतर सेवा तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य सेकैमाक स्ट्रीट स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अत्याधुनिक बीटाकैम और डिजि बीटाकैम स्टूडियो, ध्वनि स्थपित किया गया है। यह यूनिट फिल्म तथा वीडियो के गैर-रेखीय सम्पादन तथा कम्प्यूटर ग्राफिक्स और एनीमेशन की समन्वित सुविधा उपलब्ध कराती है। इस केन्द्र में वीसीडी मास्टरिंग के लिए इस वर्ष एक और यूनिट स्थापित की जा रही है।

6. भारतीय पैनोरमा और राष्ट्रीय फिल्म सर्किल

निगम देश के विभिन्न केन्द्रों में फिल्म सप्ताहों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों तथा फिल्म संख्याओं को हर संभव

सहायता उपलब्ध कराता है। इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि कई सामाजिक गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन तथा महिला संगठन फिल्म समारोहों के आयोजन में रुचि दिखा रहे हैं। देश में इस बात की काफी मांग है कि भारतीय पैनोरमा के लिए चुनी गई ऐसी अच्छे फिल्मों में फिल्म समारोहों और फिल्म समारोहों के लिए उपलब्ध कराई जाए।

निगम ने वर्ष 2005-2006 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान देश के 28 केंद्रों में पैनोरमा फिल्मों का प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के तत्वावधान में राष्ट्रीय फिल्म सर्किल, भारतीय फिल्म अभिलेखागार और सीएफसीआई नेहरू सेन्टर और एनसीपीए में अच्छी फिल्मों का प्रदर्शन कर रहा है। राष्ट्रीय फिल्म सर्किल ने वित्तीय वर्ष 2005-2006 (अक्टूबर, 2005 तक) 58 फिल्मों का प्रदर्शन किया।

एन एफ डी सी ने सात बड़े क्षेत्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन किया।

7. भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष

निगम द्वारा फिल्म उद्योग के अब तक के सबसे बड़े कोष भारतीय सिने कलाकार कल्याण कोष की स्थापना 1992 में की गई थी। इस कोष से बीते जमाने के जरूरतमंद सिने कलाकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। न्यास की राशि अब बढ़ कर 4.48 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक 969 सिने कलाकार इस न्यास से पेंशन और अन्य फायदे ले चुके हैं। इस समय 537 सिने कलाकारों को 31.70 लाख रुपये की राशि पेंशन के रूप में भुगतान की जा चुकी है। अगले वर्ष सिने कलाकारों को पेंशन और अन्य लाभों के रूप में 47.00 लाख रुपये की राशि के भुगतान किए जाने की आशा है।

8. स्तर्कता संबंधी उपाय

वर्ष के दौरान निर्णय लेने की तथा खरीद आदि की विभिन्न प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू की गईं।

9. राजभाषा नीतियों का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम, राजभाषा विभाग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय व सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में जारी आदेशों को वर्ष के दौरान निगम के कार्यालयों में लागू किया गया।

निगम के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2005-2006 के वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए यथोचित कदम उठाए गए। इस वर्ष निगम को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुम्बई के सार्वजनिक उद्यमों में द्वितीय पुरस्कार यानि “आशीर्वाद पुरस्कार” से सम्मानित किया गया।

8. योजना स्कीम तथा कार्य निष्पादन

निगम पिछले नौ सालों से अपनी विकासात्मक योजना गतिविधियों को पूरी तरह से अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा कर रहा है। इसके लिए सरकार से उसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है। पिछले सालों में निगम को हुए वित्तीय घाटे की वजह से निगम के आंतरिक स्रोत सूख चले हैं और इसलिए पिछले दो सालों के दौरान निगम योजना स्कीमों पर कोई बड़ा खर्च नहीं कर सका है। आगे योजना स्कीम के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतया सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर करेगा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान निगम के वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश परिशिष्ट “क” पर दिए गए हैं।

परिशिष्ट “क”

पिछले पांच वर्षों के दौरान निगम के वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश

(रुपये लाख में)

पूंजीगत ढांचा	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
प्राधिकृत पूंजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
प्रदत्त पूंजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
वित्तीय उपलब्धियां					
कारोबार	6,875.36	8,545.52	7,779.54	3,690.65	2,209.28
व्यय	6,538.61	7,980.82	8,442.77	4,616.14	2,596.02
लाभ/(हानि) कर पूर्व	336.75	564.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)
लाभ/हानि कर पश्चात	319.66	409.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)
विदेशी मुद्रा में आम	274.26	119.81	93.36	69.00	100.03
संचालनात्मक उपलब्धियां					
फिल्म निर्माण तथा फिल्म उपकरणों की खरीद के लिए ऋण वितरण	-	7.39	15.75	11.86	-
स्व निर्माण/सह-निर्माण में निवेश	127.89	250.52	277.75	186.73	13.87
थिएटर निर्माण के लिए ऋण वितरण	-	-	-	-	-
आय					
टीवी के माध्यम से फिल्मों का वितरण	5,701.97	7,355.78	6,388.96	2578.19	1,408.56
फिल्म साफ्टवेयर का निर्यात	250.10	252.17	172.34	141.51	133.21
विदेशी फिल्मों का वितरण	126.54	249.66	469.87	61.50	28.67
विशेष परियोजनाएं	607.32	442.50	406.26	518.02	297.49

6

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को

भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्थाओं में से एक है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, समाज-विज्ञान, संस्कृति और संचार माध्यमों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। 1981 में यूनेस्को की महासभा के 21वें अधिवेशन में सदस्य देशों के बीच परस्पर संवाद व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की संवाद क्षमताओं को उन्नत करना था। इसकी स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत अन्तरशासकीय परिषद के सदस्य के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संचार क्षमता विकास कार्यक्रम का सदस्य भी है।

यूनेस्को की आम सभा की बैठक सामान्यतः हर दो वर्ष के अंतराल पर होती है। यूनेस्को की 33वीं बैठक पेरिस में 3 से 21 अक्टूबर 2005 तक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2006-07 की अवधि के दौरान मसौदा कार्यक्रम तय करने और बजट-व्यवस्था के बारे में विचार-विमर्श किया गया। 11 से 13 अक्टूबर 2005 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया। इसका नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने किया। मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करने का फैसला किया।

भारतीय समाचार पूल डेस्क और गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल

गुटनिरपेक्ष समाचार पूल का औपचारिक रूप से गठन वर्ष 1976 में हुआ। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर सूचना के असंतुलन को दूर करना है। यह गुटनिरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के बीच समाचारों और सूचना के आदान-प्रदान का प्रबंध करता है। इसका खर्च सदस्य देश उठाते हैं। इसकी कार्य प्रणाली का संचालन समय-समय पर चुनी गई समन्वय समिति करती है। भारत भी समन्वय-समिति का सदस्य है। वर्ष की समीक्षा के तहत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पी टी आई) ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल में भारतीय समाचार पूल डेस्क का संचालन किया। अफगानिस्तान की बख्तर समाचार एजेंसी के साथ समाचारों के आदान-प्रदान का समझौता इस वर्ष की प्रमुखता रही। अब बख्तर समाचार एजेंसी ई-मेल के जरिए पी टी आई की समाचार-सेवा प्राप्त कर रही है। पी.टी.आई. ने बख्तर समाचार एजेंसी के पत्रकारों

और इंजीनियरों को दिल्ली के पी टी आई में प्रशिक्षित करने की पेशकश की है।

पी टी आई क्यूबा की प्रेंसना लातिना (Prensa Latina) समाचार एजेंसी पहले से भी समाचारों का आदान-प्रदान कर रही है। व दोनों के बीच इस समझौते का नवीनीकरण किया गया है। घाना की समाचार एजेंसी और सर्बिया मॉन्टेनेग्रो (Serbia Montenegro) की तानजुंग समाचार एजेंसी के साथ समाचारों के आदान-प्रदान का फैसला विचाराधीन है। पी टी आई और तानजुंग समाचार एजेंसी 1976 में गुट-निरपेक्ष समाचार सेवा पूल के गठन से लेकर 25 वर्षों तक सक्रिय सहयोगी रह चुके हैं।

19 से 22 नवम्बर 2005 तक मलेशिया के कुआलालम्पुर में गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों का छठा सम्मेलन हुआ। **गतिशील गुटनिरपेक्ष की दिशा में सूचना और संचार सहयोग तकनीक का आधुनिकीकरण** विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने किया। इस दौरान अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष (प्रगति) के मूल्यांकन, सूचना व संचार विकास, नवीन विश्वस्तरीय सूचना तंत्र व संचार आदेश, गुटनिरपेक्ष देशों के प्रसारण सगठन, गुटनिरपेक्ष एजेंसी पूल और गुटनिरपेक्ष देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सूचना केंद्रों का महत्व (स्थिति) पर विचार-विमर्श हुआ।

भारत और सार्क

भारत, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सक्रिय सदस्य है। सार्क के सदस्य देशों के सूचना मंत्री प्रति वर्ष बैठक के दौरान मिलते हैं। सार्क के सदस्य देशों के सूचना मंत्रियों की पांचवीं बैठक नेपाल की राजधानी काठमांडू में 29-30 अगस्त 2005 को हुई थी। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व माननीय सूचना प्रसारण व संस्कृति मंत्री ने किया। बैठक में पिछले निर्णयों को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त सूचना व मीडिया 2004 की संशोधित कार्य योजना तथा सार्क देशों के प्रिंट मीडिया और टी.वी. व रेडियो के राष्ट्रीय संगठन प्रमुखों की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की गई। क्षेत्र में ट्रांस नेशनल सेटलाइट ब्राडकास्टिंग पर आदर्श दिशा-निर्देश और सूचना जगत से जुड़े अन्य पक्षों के बारे में विश्व-सम्मेलन में सार्क की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सार्क देशों के सूचना मंत्रियों की अगली बैठक भारत में 2006 में आयोजित की जाएगी।

7

योजना एवं गैर-योजना कार्यक्रम

योजना आबंटन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक योजना 2005-06 के लिए 1120 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें प्रत्यक्ष बजट सहयोग 528 करोड़ रुपये का है और बाकि के 592

करोड़ रुपये आंतरिक तथा बजट के बाहर के संसाधनों से जुटाए जाएंगे। वार्षिक योजना 2005-06 का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	प्रत्यक्ष बजट सहयोग	आंतरिक तथा बजट के बाहर	कुल
1.	सूचना क्षेत्र	38.00	—	32.00
2.	फिल्म क्षेत्र	35.00	—	35.00
3.	प्रसारण क्षेत्र	455.00	592.00	1047.00
	कुल	528.00	592.00	1120.00

2. वार्षिक योजना 2005-06 के लिए मीडिया इकाईयों/योजना कार्यक्रमों का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है। 528 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष बजट सहयोग में से विभिन्न मीडिया इकाईयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 111.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जो प्रत्यक्ष बजट सहयोग का 21.07% है।

3. प्रसार भारती को वार्षिक योजना 2005-06 के कुल परिव्यय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेडियो और टी वी कवरेज के लिए 107.77 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 111.15 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज शामिल है। ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

	आकाशवाणी			दूरदर्शन			कुल प्रसार भारती
	पूँजी	राजस्व	कुल	पूँजी	राजस्व	कुल	
पूर्वोत्तर पैकेज	18.00	2.90	20.90	40.00	46.87	86.87	107.77
जम्मू कश्मीर विशेष पैकेज	1.20	4.00	5.20	5.95	100.00	105.95	111.15

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
स्वीकृत वार्षिक योजना 2005-06

(लाख रुपये में)

क्रम. सं.	मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए
(1)	(2)	(3)	
I	सूचना क्षेत्र		
1.	पत्र सूचना कार्यालय	1933.50	27.00
2.	प्रकाशन विभाग	46.00	
3.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	309.00	31.00
4.	भारतीय जन संचार संस्थान	240.80	15.00
5.	फोटो प्रभाग	110.00	
6.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	226.00	60.00
7.	गीत एवं नाटक प्रभाग	850.00	100.00
8.	गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	15.00	
9.	भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	19.70	
10.	सूचना भवन	0.00	
11.	मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण	50.00	
	कुल (I) : प्रत्यक्ष बजट सहयोग	3800.00	233.00
II	फिल्म क्षेत्र		
1.	फिल्म प्रभाग	1247.00	100.00
2.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संस्थान	472.00	
3.	भारतीय फिल्म प्रशिक्षण संस्थान, पुणे	220.60	
4.	सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	37.00	
5.	फिल्म समारोह निदेशालय	548.00	
6.	भारतीय बाल फिल्म समिति	519.40	10.00
7.	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	336.00	5.00
8.	भारतीय फिल्म परिसंघ समिति/गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	20.00	
9.	भारत तथा विदेशों में फिल्म बाजार में भागीदारी	100.00	
	कुल (II) : प्रत्यक्ष बजट सहयोग	3500.00	115.00

(लाख रुपये में)

क्रम. सं.	मीडिया इकाई	स्वीकृत परिव्यय	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए
(1)	(2)	(3)	
III	प्रसारण क्षेत्र		
1.	आकाशवाणी प्रत्यक्ष बजट सहयोग आई.ई.बी.आर.	23365.00 10165.00 13200.00	2090.00
2.	दूरदर्शन प्रत्यक्ष बजट सहयोग आई.ई.बी.आर.	80335.00 34335.00 46000.00	8687.00
	कुल प्रसार भारती (1+2)	103700.00	10777.00
3.	प्रत्यक्ष बजट सहयोग आई.ई.बी.आर. केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा (सी एम एस)	44500.00 59200.00 1000.00	
	कुल प्रसारण क्षेत्र (1+2+3)	104700.00	10777.00
	प्रत्यक्ष बजट सहयोग आई.ई.बी.आर.	45500.00 59200.00	
	कुल सू. एवं प्रसा. मंत्रालय (I+II+III)	112000.00	11125.00
	प्रत्यक्ष बजट सहयोग आई.ई.बी.आर.	52800.00 59200.00	

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वार्षिक योजना 2005-06 कार्यक्रमानुसार स्वीकृत व्यय (14.02.2005 तक)

		(लाख रुपये में)
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2004-2005 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
(क)	सूचना क्षेत्र	
I	पत्र सूचना कार्यालय सतत कार्यक्रम	
1	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	1819.00
2	प.सू.का. के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण की गतिविधियां i) डिजिटल स्टोरेज एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन ii) सूचना केंद्र की स्थापना और सम्पर्क सूत्र प्रदान करना	56.35 42.65
3	पूर्वोत्तर तथा उन स्थानों में प.सू. कार्यालय खोलना जहां सरकार ने भूमि आबंटित कर दी है	15.00
	कुल	1933.50
II	प्रकाशन विभाग सतत कार्यक्रम	
1	विभाग के प्रकाशन कार्यक्रम	46.00
	कुल	46.00
III	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सतत कार्यक्रम	
1	विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा और संप्रेषण	309.00
	कुल	309.00
IV	भारतीय जनसंचार संस्थान (सहायता अनुदान) सतत कार्यक्रम	
1	भवन और आवास परियोजना	115.30
2	अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	38.50
3	इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट/रेडियो और टीवी पत्रकारिता की सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार	27.00
4	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ सहयोग	60.00
	कुल	240.80

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई/योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2006 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
V	फोटो प्रभाग सतत कार्यक्रम	
1	फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण	110.00
	कुल	110.00
VI	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सतत कार्यक्रम	
1	फिल्म/कैसेटों की खरीद	30.00
2	पूँजीगत स्टॉक का आधुनिकीकरण और परिष्करण	196.00
	कुल	226.00
VII	गीत एवं नाटक प्रभाग सतत कार्यक्रम	
1	पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी गतिविधियां	850.00
	कुल	850.00
VIII	गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	
1	भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण	15.00
	कुल	15.00
IX	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक	
1	विभाग के मुख्यालय का आधुनिकीकरण	19.70
	कुल	19.70
XI	मुख्य सचिवालय की योजनाएं सतत कार्यक्रम सूचना भवन का निर्माण (चरण-IV)	0.00

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2006 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
XII	नए कार्यक्रम मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	50.00
	कुल	50.00
	सूचना क्षेत्र के लिए कुल	3800.00
I	फिल्म क्षेत्र फिल्म प्रभाग सतत कार्यक्रम	
1	अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्म समारोह	98.00
2	प्रभाग के पुराने उपकरणों का आधुनिकीकरण और उनकी जगह नए उपकरण खरीदना	105.00
3	चलचित्रों के संग्रहालय की स्थापना	744.00
	कुल	947.00
II	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय सतत कार्यक्रम	
1	पुरानी फिल्मों को प्राप्त करना और उनका प्रदर्शन	72.00
	कुल	72.00
III	फिल्म समारोह निदेशालय	
1	फिल्म समारोह परिसर-संशोधन एवं संवर्द्धन-प्रमुख कार्य	200.00
	कुल	200.00
IV	भारतीय बाल फिल्म समिति (सहायता अनुदान)	
1	फिल्म निर्माण	
	(क) फिल्म निर्माण	352.00
	(ख) फिल्म समारोह	110.00
	(ग) आधुनिकीकरण एवं संवर्द्धन	2.80
	(घ) एनिमेशन और पटकथा लेखन कार्यशालाएं	4.60
2	समिति द्वारा निर्मित फिल्मों का नगरपालिका विद्यालयों में प्रदर्शन	50.00
	कुल	519.40

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2006 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
VII	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सतत कार्यक्रम	
1	बोर्ड में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध प्रणाली की स्थापना और मूल ढांचे का उन्नतिकरण	140.00
2	हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना	21.00
	कुल	161.00
III	प्रशिक्षण	
	(क) कैप्टिव टी वी चैनल योजनाएं (भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे)	10.00
	(ख) सामुदायिक रेडियो की स्थापना (भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे)	10.00
	(ग) कैप्टिव टी वी चैनल योजनाएं (सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता)	12.00
	(घ) सामुदायिक रेडियो की स्थापना (सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता)	5.00
	(ङ) प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी और आधुनिकीकरण (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) (पूर्ववर्ती-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अध्ययन संस्थान)	175.00
	कुल	212.00
IV	छात्रवृत्ति कार्यक्रम	
	(क) मानव संसाधन विकास के पहलू जिनमें छात्रवृत्ति और आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं (भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे)	10.00
	(ख) मानव संसाधन विकास के पहलू जिनमें छात्रवृत्ति आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं (सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता)	20.00
	कुल	30.00
V	कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था	
	(क) भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे को उन्नत और आधुनिक बनाना	190.60
	(ख) भारतीय बाल फिल्म समिति का डिजिटलाइजेशन और वेबकास्टिंग योजनाएं	0.00
	(ग) भारतीय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के दूसरे चरण का निर्माण	400.00
	(घ) फिल्म प्रभाग की फिल्मों का डिजिटलाइजेशन और वेबकास्टिंग	300.00
	कुल	890.60

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2006 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
VI	फिल्मों का निर्यात और विपणन (क) भारत में फिल्म समारोहों के जरिये निर्यात प्रोत्साहन (फिल्म समारोह निदेशालय) (ख) भारत और विदेशों में फिल्म बाजार में भाग लेना (मुख्य सचिवालय)	348.00 100.00
	कुल	448.00
VIII	भारतीय फिल्म फेडरेशन सोसायटी और गैर-कानूनी रूप से फिल्मों की नकल तैयार करने के काम को रोकने में लगे गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (मुख्य सचिवालय)	20.00
	फिल्म क्षेत्र के लिए कुल	3500.00
(ग)	प्रसारण क्षेत्र (प्रसार भारती) (सहायता अनुदान/ऋण)	
I	आकाशवाणी	
1	सतत कार्यक्रम (क) मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार (ख) एफ एम सेवाओं का विस्तार (ग) कर्मचारी आवास और कार्यालय भवन (घ) शार्टवेव सेवाओं का विस्तार (ङ) अभिलेखागार (च) विविध प्रभार (छ) विभिन्न परियोजनाएं (जिनमें एंफ्लिफायरों, सी डी प्लेयर्स माइक्रोफोनों और अप्रत्याशित रूप से अन्य सामानों को बदलना शामिल है) (ज) जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज (पूंजी) (राजस्व विविध) (राजस्व साफ्टवेयर)	1590.60 186.00 150.00 52.00 0.00 10.50 00.00 372.10 520.00 120.00 400.00 00.00
2	सुधार/विस्तार कार्यक्रम (क) मीडियमवेव सेवाओं का विस्तार (ख) एफ एम सेवाओं का विस्तार	300.00 6634.40 127.75 6506.65

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2006 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
3	आधुनिकीकरण कार्यक्रम (क) निर्माण स्त्राओं का डिजिटलाइजेशन (ख) स्टुडियो सेवाओं को स्वचालित बनाना (ग) प्रसारण सुविधाओं को स्वचालित बनाना	2260.95 991.35 1264.60 5.00
4	स्थानापन्न कार्यक्रम (क) वर्तमान उपकरणों को बदलना (ख) विविध प्रभार (ग) विविध योजनाएं (जिनमें एंप्लिफायरों, सी डी प्लेयर्स, माइक्रोफोनों और अप्रत्याशित रूप से अन्य सामानों को बदलना शामिल हैं)	1075.95 909.60 166.35
5	नई परियोजनाएं (क) पूर्वोत्तर पैकेज पूंजी राजस्व-सॉफ्टवेयर राजस्व-विविध (ख) नई प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट रेडियो प्रसारण, डिजिटल प्रसारण इत्यादि (ग) कर्मचारियों के लिए आवास (घ) स्थापना प्रभार (ङ) प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नत और मजबूत बनाना च) सुरक्षा उपाय आदि (छ) सुविधाओं आदि में सुधार (ज) सॉफ्टवेयर	8538.10 2090.00 1800.00 190.00 100.00 785.50 566.00 2350.00 00.00 300.00 236.60 2210.00
6.	राजस्व (विविध)	3265.00
	कुल (पूंजी)	17200.0
	कुल (राजस्व विविध)	3765.00
	कुल (राजस्व-सॉफ्टवेयर)	2400.00
	कुल (आकाशवाणी)	23365.00
	प्रत्यक्ष बजट सहयोग	10165.00
	आंतरिक तथा बजट बाहर के संसाधन	13200.00

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2005 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
I	दूरदर्शन	
1	सतत कार्यक्रम	19620.00
	(क) टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर	506.00
	(ख) निर्माण सुविधाएं (स्टूडियो/ओ बी)	100.00
	(ग) उपग्रह प्रसारण उपकरण	106.00
	(घ) स्थापना प्रभार	
	(ड) जम्मू और कश्मीर विशेष योजना	10595.00
	पूंजी	595.00
	राजस्व विविध	0.00
	राजस्व सॉफ्टवेयर	10000.00
	(च) राजस्व विविध	8313.00
2	सुधार/विस्तार कार्यक्रम	4275.00
	(क) डी.डी.-1 के संदर्भ में मौजूदा ट्रांसमीटरों में सुधार और नए ट्रांसमीटरों की स्थापना के द्वारा टैरेस्ट्रियल कवरेज का विस्तार	2048.00
	(ख) डी.डी.-2 के संदर्भ में मौजूदा ट्रांसमीटरों में सुधार और नए ट्रांसमीटरों की स्थापना के द्वारा टैरेस्ट्रियल कवरेज का विस्तार	135.00
	(ग) के यू बैंड में बहु चैनल डिजिटल उपग्रह वितरण के जरिए उन क्षेत्रों में प्रसारण जहां फिलहाल यह उपलब्ध नहीं है	2090.00
3	आधुनिकीकरण योजना	13746.00
	(क) निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो/ओ बी) का डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण	7289.00
	(ख) उपग्रह प्रसारण उपकरणों का डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण	2583.00
	(ग) मौजूदा स्टूडियो सुविधाओं का विस्तार	1870.00
	(घ) ट्रांसमीटरों का स्वचालन (कम शक्ति और बहुत कम शक्ति के ट्रांसमीटर)	2004.00
4	स्थानापन्न योजनाएं	3937.00
	(क) खराब/पुराने/अप्रचलित होने के कारण मौजूदा ट्रांसमीटरों को बदलना	1129.00
	(ख) खराब/पुराने/अप्रचलित होने के कारण मौजूदा निर्माण उपकरणों (स्टूडियो/ओ बी) को बदलना	1503.00

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2006 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
5	(ग) खराब/पुराने/अप्रचलित होने के कारण उपग्रह प्रसारण उपकरणों को बदलना नई योजनाएं (क) पूर्वोत्तर विशेष पैकेज पूँजी राजस्व-सॉफ्टवेयर राजस्व-विविध (ख) नई निर्माण सुविधाएं (ग) नए उपग्रह प्रसारण उपकरण (घ) डी टी टी (ङ.) डायरेक्ट टू होम (च) एच डी टी वी (छ) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम मल्टीमीडिया (ज) अनुसंधान और विकास/विपणन (झ) कर्मचारियों के लिए आवास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में बढ़ोतरी (ण) प्रशिक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी (ट) डिजिटल उपकरणों के लिए मरम्मत केंद्रों/कार्यशालाओं की स्थापना (ठ) स्थापना (सिविल निर्माण कार्य शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय) और मध्यस्थता (ड) सॉफ्टवेयर प्राप्त / तैयार करना (सामान्य और विविध) कुल (पूँजी) कुल (राजस्व) कुल (राजस्व-सॉफ्टवेयर) कुल (राजस्व-विविध)	1305.00 38757.00 8687.00 4000.00 4500.00 187.00 1057.00 615.00 2.00 300.00 300.00 490.00 130.00 4000.00 21.00 290.00 2530.00 20335.00 37000.00 43335.00 34835.00 8500.00
	कुल (दूरदर्शन)	80335.00
	प्रत्यक्ष बजट सहयोग	34335.00
	आई.ई.बी.आर.	46000.00
	कुल (प्रसार भारती)	103700.00

(लाख रुपये में)		
क्रम संख्या	मीडिया इकाई योजना कार्यक्रम का विवरण	2005-2006 स्वीकृत परिव्यय
[1]	[2]	[3]
	प्रत्यक्ष बजट सहयोग	44500.00
	आई.ई.बी.आर.	59200.00
(घ)	अन्य केंद्रीय अनुश्रवण सेवा : प्रत्यक्ष बजट सहयोग	1000.00
	कुल प्रसारण क्षेत्र (I + II + III)	104700.00
	प्रत्यक्ष बजट सहयोग	45500.00
	आंतरिक तथा बजट बाहर के संसाधन	59200.00
	कुल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (क + ख + ग + घ)	112000.00
	प्रत्यक्ष बजट सहयोग	52800.00
	आई.ई.बी.आर.	59200.00

टिप्पणी : (i) साफ्टवेयर के विकास तथा रखरखाव और हार्डवेयर की प्राप्ति तथा प्रशिक्षण सहित सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सभी मीडिया इकाइयों को अपने बजट से अधिक खर्च का कम से कम 2 से 3 प्रतिशत स्वयं वहन करना

होगा।

(ii) प्रसार भारती को क्लासिकल के विषयों की रचना के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करनी चाहिए।

8

नई पहल

डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) सेवा

डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवा से आशय केयू बैंड में सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग कर बिना किसी बिचौलिया संस्था जैसे कि केबल आपरेटर के सीधे उपभोक्ता के घर तक टी वी सिग्नल पहुंचाना है। केबल नेटवर्क संचालकों के लिए डी टी एच प्लेटफार्म का वितरण अनिवार्य है। मार्च 2001 में जारी डी टी एच दिशा-निर्देशों में अधिकतम 20 प्रतिशत को एफ डी आई के साथ किसी डी टी एच कंपनी को 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट है जिसमें एफ डी आई/एन आर आई/ओ सी बी/एफ आई आई शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक डी टी एच कंपनी के लिए यह हमेशा जरूरी है कि बोर्ड में बहुमत के साथ प्रबंधन भारतीय हो साथ ही कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय नागरिक हो। डी टी एच दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेब साइट (<http://www.mib.nic.in>) पर उपलब्ध है।

2. मंत्रालय को डी टी एच लाइसेंस प्रदान करने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक प्राइवेट सेवा प्रदाता एम/एस ए एस सी इंटरप्राइजेज लि. अक्टूबर 2003 में अपनी सेवा पहले ही शुरू कर चुका है। दो अन्य कंपनियों ए एस /स्पेस टीवी प्राइवेट लिमिटेड और (ii) एम/एस सन डाइरेक्ट टीवी लिमिटेड को डी टी एच सेवा शुरू करने के लिए **लैटर ऑफ इंटेंट** जारी किए जा चुके हैं। तीन अन्य कंपनियों के आवेदन स्वीकृति के लिए विभिन्न स्थितियों में मंत्रालय के पास हैं। जबकि दूरदर्शन अपनी फ्री टु एयर डी टी एच सेवा टैरेस्ट्रीयल प्रसारण से छूटे और कम पहुंच वाले क्षेत्रों को टी वी कवरेज के नजरिये से पहले ही शुरू कर चुका है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर यह सेवा संपूर्ण भारत में उपलब्ध है। अब एक छोटे आकार की रिसीवर प्रणाली की सहायता से 33 टी वी चैनल तथा 12 रेडियो चैनलों को देखना संभव हो गया है।

प्राइवेट एम एम रेडियो फेज-II

30 जून 2005 को प्राइवेट एजेंसियों (फेज-II) के जरिये एम एम

रेडियो ब्राडकास्टिंग सेवा के विस्तार की नीति स्वीकृत की गई और 13 जुलाई 2005 को इसे अधिसूचित किया गया। इस नीति की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- पहले के तय वार्षिक लाइसेंस शुल्क के मुकाबले, एकमुश्त एंटीशुल्क (ओटीईएफ) तथा वार्षिक शुल्क के आधार पर अनुमति;
- विदेशी निवेश के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति;
- सी और डी वर्ग के शहरों में एक क्षेत्र में नेटवर्क चैनलों को अनुमति;
- जिन चैनलों के पास फेज-I के लाइसेंस हैं उन्हें तयशुदा नीति के तहत लागू दिशा-निर्देशों के आधार पर दूसरे फेज-II में जाने की अनुमति।

सरकार ने 91 शहरों में 337 एफ एम रेडियो चैनलों के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं जिनमें से 280 चैनलों के लिए निविदाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हुईं। सरकार को इससे 1157.35 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जिसमें एकमुश्त प्रवेश शुल्क के अलावा मौजूदा एफ एम चैनलों से दूसरे फेज-II में जाने की माइग्रेशन भी शामिल है।

डाउनलिंग दिशा-निर्देश

भारत सरकार ने 11.11.2005 को टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंग के लिए नीति निर्धारक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बिना पंजीकृत हुए कोई व्यक्ति/फर्म चैनल की डाउनलिंग नहीं कर सकता। इसमें आगे प्रावधान है कि दिशानिर्देशों के तहत डाउनलिंग के इच्छुक व्यक्ति/फर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पहले अनुमति लेनी होगी। इन दिशा निर्देशों के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय सेवा प्रदाता अर्थात केबल आपरेटर और डी टी एच सेवा प्रदाता केबल टीवी नेटवर्क

रूल्स, 1994, केबल टी वी नेटवर्क (रेग्युलेशन) एक्ट, 1995 तथा डी टी एच दिशा निर्देशों के अनुसार प्रसारण/पुनर्प्रसारण करने वाले टी वी चैनल कार्यक्रम और विज्ञापन कोड मानने को बाध्य होंगे। अब डाउनलिंग दिशा-निर्देशों के द्वारा विदेशों से अपलिंग और भारत में डाउनलिंग करने वाले चैनलों की कोड का पालन करना अनिवार्य हो गया है। डाउनलिंग की शर्तों का उल्लंघन आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त कारण होगा।

विषय सामग्री नियमन

केबल नेटवर्क सेवा के जरिये प्रसारित/पुनः प्रसारित सैटेलाइट टीवी चैनलों के कार्यक्रमों को केबल टीवी नेटवर्क (रेग्युलेशन) एक्ट, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड का अनुसरण करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने कार्यक्रम कोड तथा विज्ञापन कोड के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक्ट के खंड 20 के अंतर्गत एक **अंतरमंत्रालय** समिति गठित की है। समिति में गृह मंत्रालय, विदेश मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और एक प्रतिनिधि एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड कार्सिल (ए एस सी आई) तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सदस्य होते हैं। समिति स्वयं संज्ञान अथवा शिकायत प्राप्ति पर कोड के उल्लंघन के मामलों को देखती है।

सरकार ने विषय सामग्री नियमन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं जो निम्न प्रकार हैं :

- (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टी वी चैनल तथा स्थानीय केबल टी वी द्वारा कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड के उल्लंघनों का पता लगाने और कोड संबंधी उल्लंघन को जनता से प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए जांच समिति गठित करने को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं।
- (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो केबल टीवी नेटवर्क (रेग्युलेशन) एक्ट, 1995 के तहत तथा इसके अंतर्गत सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत फिल्म प्रमाणन के लिए बने दिशा-निर्देशों/कोड को समकालीन सामुदायिक स्तर को सुधारने के लिए समीक्षा करेगी।

आदिवासी बच्चों के लिए निशुल्क प्रदर्शन

ग्रामीण और सुविधाहीन तथा किसी बड़े मनोरंजन से वंचित बच्चों

को मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से सी एफ एस आई ने आदिवासी बच्चों के लिए निशुल्क शो आयोजित करने की एक उत्तम स्कीम शुरू की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने इस गतिविधि का लाभ उठाया। इस निशुल्क शो में खर्च होने वाली राशि का वहन सी एफ एस आई करती है।

इस स्कीम के तहत रिमांडघरों, अनाथालयों आदि में रह रहे ऐसे बच्चों, जोकि किसी तरह का मनोरंजन प्राप्त नहीं कर पाते, को भी बाल फिल्मों देखने का लाभ दिया जाता है।

देश के 11 राज्यों में 2,20,250 बच्चों के लिए 773 निशुल्क शो आयोजित किए गये।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आइ एफ एफ आई)-2005

आई एफ एफ आई 2005 के प्रतियोगिता खंड में एशिया के अतिरिक्त दो अन्य यूरोपीय देशों अफ्रीका और लातिन अमरीका को भी शामिल किया गया।

आई एफ एफ आई-2005 में 'एन एफ ए गोल्ड' शीर्षक से एक नया खंड शुरू किया गया। इस खंड में 50 वर्ष पहले राष्ट्रपति को स्वर्ण पदक प्राप्त दो फिल्मों श्यामची आई (मराठी-1953) और मिर्जा गालिब (हिंदी-1954) का प्रदर्शन किया गया।

इसके अतिरिक्त आई एफ एफ आई-2005 में 'मास्टर्स क्लास' नाम का एक विशेष खंड भी शुरू किया गया जिसमें समारोह के दौरान विश्व प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया तथा फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न कक्षाएं आयोजित कीं।

भारत सरकार और इटली के बीच दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण समझौता

सूचना प्रसारण व संस्कृति मंत्री एस. जयपाल रेड्डी मई 2005 में रोम गए और भारत सरकार की ओर से भारत सरकार तथा इटली के बीच एक दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कई दौर की बातचीत के बाद ही हो पाया और इससे ऐसे कई समझौतों के लिए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। जिनके लिए कई देशों ने भारत सरकार से संपर्क साधा था।

2. अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण समझौते एक प्रकार से **व्यापक** समझौते हैं जिनके अंतर्गत प्राइवेट; अर्ध-सरकारी अथवा सरकारी एजेंसियां आपस में मिलकर फिल्म निर्माण के अनुबंध कर सकती हैं। ऐसी फिल्मों दोनों देशों में राष्ट्रीय फिल्मों के रूप में मान्य होंगी।

भारत सरकार और ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड सरकारों के बीच फिल्म सह-निर्माण समझौता

भारत सरकार तथा ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच फिल्म सह-निर्माण समझौते पर सूचना और प्रसारण मंत्री पी.आर. दासमुंशी तथा ब्रिटेन के संस्कृति, मीडिया और खेल के राज्य सचिव आर.टी.आन. टेसा जॉवेल, एम.पी. ने 5 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। युनाइटेड किंगडम के साथ कई दौर की बातचीत के बाद हुए इस समझौते से भारत तथा यूके के निर्माताओं के बीच फलदायक सहयोग के कई द्वार खुलने की आशा है।

प्रिंट मीडिया नीति

सरकार ने प्रिंट मीडिया नीति की समीक्षा कर एफ आई आई, एन आर आई और पी आई ओ के लिए नए सेक्टर खोले हैं। पहले इस क्षेत्र में केवल 26 प्रतिशत तक ही एफ डी आई की अनुमति थी। गैर-समाचार क्षेत्र में पहले की 74 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

नीति की समीक्षा के बाद निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं :

I (क) विदेशी स्वामित्व वाली वैज्ञानिक, तकनीकी और विशेषज्ञ पत्रिकाओं/ नियतकालीन/पत्रों के भारतीय संस्करण के प्रकाशन की अनुमति (जो समाचार तथा सामयिक मामलों को प्रकाशित नहीं करते, जैसा कि समझा जाता है।) यह अनुमति केस दर केस आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विशेष सिफारिशों पर तथा मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऐसी स्थितियों पर निर्भर करेगी।

(ख) भारतीय फर्मों जो वैज्ञानिक/तकनीकी तथा विषय विशेष की पत्रिकाओं/नियतकालिक/जर्नल प्रकाशित करती हैं में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश (जिसमें एफ डी आई शामिल है) की अनुमति।

II (क) समाचार तथा सामयिक मामलों के क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफ डी आई की शर्त को जारी रखना। यद्यपि मान्यता प्राप्त एफ आई आई द्वारा किया गया निवेश एन आर आई/पी आई ओ और पोर्टफोलियो निवेश समाचार तथा सामयिक मामलों के वर्ग में एफ डी आई दायरे में शामिल किया जा सकता है।

III कुल प्रकाशित क्षेत्र की सिंडिकेशन सीमा 'ऑटोमेटिकरूट' के तहत 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

डी.सी.ए.	प्रिंसीपल एकाउंट आफिस एवं पी एण्ड ओ सी.जी.ए. के नियंत्रण में
(डब्ल्यू एम)	आई डब्ल्यू एस यू (बी एंड ए)
यू एस एंड पी.सी.)	पी सी सेल
एफ एंड,)	फाई-II
एस (बीए-ई)	फाई-I एंड III
एस [बीए-पी]	बी ए (ई)
	बी ए (पी)
	ए ई (सी आर एस)
(एफ एम-II)	ए ई (एफ एम)
(एफ एम-I)	बी पी एंड एल
सडी (बी)	बी (एफ)
एस (बी डी)	बी (डी)
डी (इनसेट)	बी सी - IV
	बी सी - III
एस (बी सी)	बी सी - II
	बी सी - I
	एफ (आई) डेस्क
	एफ (सी) डेस्क
	एफ (ए) डेस्क
	एफ (टी आई) डेस्क
	एफ (एफ) डेस्क
। डी (आई पी)	पी पी सेल
	आई पी एंड एम सी
एस (विज)	विजिलेंस
	हिंदी यूनिट
स एडमिन । एंड कैश रियामेंट सेल	पार्लियामेंट सेल
	एडमिन-III
	एडमिन-I
	कैश
ई आई एस	आई आई एस (II)
	आई आई एस (I)
न ।। एंड । V)	एडमिन-II
	एडमिन-IV
एस (एम सी)	एम यू सी
	एफ (एस) डेस्क
एस (I)	प्रेस

मंत्रालय में पदनाम

ए एस एंड एफ ए	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
जे एस (पी एंड ए)	संयुक्त सचिव (नीति, मीडिया और प्रशासन) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
जे एस (फिल्मस)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
जे एस (बी)	संयुक्त सचिव (प्रसारण)
सी सी ए	मुख्य लेखा नियंत्रक
डायरेक्टर (एडमिन एंड आई.आई.एस.)	निदेशक (प्रशासन एवं आई.आई.एस.)
डायरेक्टर (ओ एल)	निदेशक (राजभाषा)
डायरेक्टर (पी.पी)	निदेशक (नीति और नियोजन)
डायरेक्टर (फिल्मस)	निदेशक (फिल्म)
डायरेक्टर (बी सी)	निदेशक (बी.सी.)
डायरेक्टर (एफ एंड पी सी)	निदेशक (वित्त एवं नियोजन समन्वय)
डी एस (बी पी एंड एल)	निदेशक (प्रसारण नीति एवं विज्ञापन)
डी एस (आई पी)	उपसचिव (सूचना नीति)
डी एस (जनरल एडमिन एंड कोआर्ड)	उप सचिव (सामान्य प्रशासन एंड समन्वय)
डी एस (बी ए)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन)
डी एस (बी एंड ए)	उप सचिव (बजट और लेखा)
सी.ए.	लेखा नियंत्रक
यू एस (आई)	अवर सचिव (सूचना)
यू एस (एम सी)	अवर सचिव (मीडिया समन्वय)
यू एस (एडमिन II एंड IV)	अवर सचिव (प्रशासन-I और IV)
यू एस (आई आई एस)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
यू एस (एडमिन I, III कैश एंड पार्लियामेंट सेल)	अवर सचिव (प्रशासन-I, III रोकड़ और संसद सेल)
यू एस (विजिलेंस)	अवर सचिव (सतर्कता)
ओ एस डी (आई पी)	विशेष कार्यधिकारी (सूचना नीति)
यू एस (बी सी)	अवर सचिव (प्रसारण विषय वस्तु)
डी डी (इनसेट)	उपनिदेशक (इनसेट)
यू एस (बी डी)	अवर सचिव (प्रसारण विकास)
ओ एस डी (बी)	विशेष कार्यधिकारी (प्रसारण)
यू.एस. (एफ एम-I)	अवर सचिव (फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन-I)
यू.एस. (एफ एम-II)	अवर सचिव (फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन-II)
यू एस (बी ए-पी)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन-कार्यक्रम)
यू-एस (बी ए-इ)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरी)
यू एस (एफ-I एंड III)	अवर सचिव (वित्त-I और वित्त III)
यू एस (एफ-II एंड पी सी)	अवर सचिव (वित्त-II और योजना समन्वय)
यू एस (डब्ल्यू एम)	अवर सचिव (कार्य मूल्यांकन)
डी सी ए	उप लेखा नियंत्रक
एडमिन. I	प्रशासन I
एडमिन. II	प्रशासन II
एडमिन. III	प्रशासन III
एडमिन. IV	प्रशासन IV
कैश	रोकड़
पार्लियामेंट सेल	संसदीय सेल
आई पी एंड एम सी	सूचना नीति और माध्यम समन्वय
पी पी सेल	नीति नियोजन एकक
प्रेस	प्रेस
एफ (एस) डेस्क	फिल्म सोसायटीज डेस्क
आई आई एस-II	भारतीय सूचना सेवा-II
आई आई एस-I	भारतीय सूचना सेवा-I
एम यू सी	मीडिया यूनिट एकक
एफ (एस)	फिल्म सोसायटीज डेस्क
हिंदी यूनिट	हिंदी एकक
एफ (एफ) डेस्क	फिल्मोत्सव डेस्क
एफ (ए) डेस्क	फिल्म प्रशासन डेस्क
एफ सी डेस्क	फिल्म प्रमाणन डेस्क
एफ (टी आई) डेस्क	फिल्म और टेलीविजन संस्थान डेस्क
एफ (आई) डेस्क	फिल्म उद्योग डेस्क
सतर्कता	सतर्कता
बी सी-I	प्रसारण विषयवस्तु-I
बी सी-II	प्रसारण विषयवस्तु-II
बी सी-III	प्रसारण विषयवस्तु-III
बी सी-IV	प्रसारण विषयवस्तु-IV
बी (डी)	प्रसारण (विकास)
बी (फाईनेंस)	प्रसारण (वित्त)
बी पी एंड एल	प्रसारण नीति और विधायन
बी ए (पी)	प्रसारण प्रशासन (कार्यक्रम)
ए ई (एफ एम)	सहायक इंजीनियर (फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन)
ए ई (सी आर एस)	सहायक इंजीनियर (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
बी ए (ई)	प्रसारण प्रशासन (इंजीनियरी)
फाइनेंस I एंड III	वित्त I और III
फाइनेंस II	वित्त II
पी सी सेल	योजना समन्वय एकक
बी एंड ए	बजट एवं लेखा
आई डब्ल्यू एस यू	आंतरिक कार्य अध्ययन एकक
पी एंड ए ओ एस	वेतन और लेखा अधिकारी
सी.सी.ए.	महालेखा नियंत्रक

मीडिया अनुसार बजट

परिशिष्ट - II

मांग संख्या 58 — सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(हजार रुपये में)

क्र.सं.	मीडिया इकाई/ गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
राजस्व अनुभाग				
मुख्य शीर्ष '2251' सचिवालय सामाजिक सेवाएं				
1.	मुख्य सचिवालय (वेतन और लेखा कार्यालय सहित) मुख्य शीर्ष '2205' — कला और संस्कृति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमा फिल्मों का प्रमाणन	17,000	1,73,600	1,90,600
2.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	17,500	23,000	40,500
3.	फिल्म प्रमाणन अपील न्यायाधिकरण	0	1,100	1,100
मुख्य शीर्ष '2205' का योग		17,500	24,100	41,600
मुख्य शीर्ष - '2220' सूचना फिल्म और प्रचार				
4.	फिल्म प्रभाग	29,800	2,39,700	2,69,500
5.	फिल्म समारोह निदेशालय	34,800	48,800	83,600
6.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	7,200	10,900	18,100
7.	सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	3,700	38,900	42,600
8.	भारत की बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	50,940	1,500	52,440
9.	भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान	3,000	61,700	64,700
10.	फिल्म समितियों को अनुदान सहायता	0	0	0
11.	केन्द्रीय अनुश्रवण एकांश	1,00,000	51,000	1,51,000
12.	गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	1,500	8,600	10,100
13.	भारतीय जनसंचार संस्थान को अनुदान सहायता	5,200	36,100	41,300
14.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	27,800	5,88,900	6,16,700
15.	पत्र सूचना कार्यालय	6,910	2,01,200	2,08,110
16.	भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	19,000	19,000
17.	पी.टी.आई. को कर्ज पर देय ब्याज के बदले सहायता	0	0	0
18.	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100
19.	पत्रकार कल्याण निधि में हस्तांतरण	0	0	0
20.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	2,000	2,31,200	2,33,200
21.	गीत और नाटक प्रभाग	74,600	1,39,200	2,13,800
22.	प्रकाशन विभाग	4,600	1,22,200	1,26,800
23.	रोजगार समाचार	0	2,30,600	2,30,600
24.	भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक	1,970	23,900	25,870
25.	फोटो प्रभाग	5,000	23,800	28,800
26.	संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	100	100
27.	एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्राडकास्ट डेवेलपमेंट को अंशदान	0	2,000	2,000
कुल : मुख्य शीर्ष '2220' का योग		3,59,020	20,79,400	24,38,420
कुल : मुख्य शीर्ष 2251, 2205 और 2220		3,93,520	22,77,100	26,70,620

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2005-2006			बजट अनुमान 2006-2007		
योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
6	7	8	9	10	11
17,000	1,77,330	1,94,330	17,000	1,74,300	1,91,300
17,500	26,000	43,500	18,600	27,600	46,200
0	1,100	1,100	0	1,200	1,200
17,500	27,100	44,600	18,600	28,800	47,400
31,500	2,38,400	2,69,900	21,000	2,56,400	2,77,400
34,800	47,000	81,800	35,300	47,400	82,700
7,200	13,600	20,800	7,300	14,000	21,300
3,700	65,100	68,800	27,900	48,500	76,400
45,400	1,500	46,900	52,130	1,500	53,630
3,000	69,800	72,800	3,000	68,200	71,200
0	0	0	0	0	0
73,000	2,500	75,500	58,500	30,000	88,500
1,500	8,570	10,070	2,500	8,900	11,400
1,930	37,200	39,130	3,980	40,000	43,980
27,800	5,98,150	6,25,950	23,300	592,500	6,15,800
6,960	2,03,969	2,10,929	7,196	2,16,947	2,24,143
0	21,731	21,731	0	23,153	23,153
0	0	0	0	0	0
0	100	100	0	100	100
0	0	0	0	0	0
700	2,39,400	2,40,100	900	2,70,100	2,71,000
74,600	1,33,300	2,07,900	72,500	1,23,600	1,96,100
4,000	1,35,050	1,39,050	0	1,30,700	1,30,700
0	2,79,200	2,79,200	0	2,91,700	2,91,700
1,970	24,000	25,970	0	24,800	24,800
5,000	25,000	30,000	7,500	27,100	34,600
0	1,400	1,400	0	1,400	1,400
0	2,000	2,000	0	2,000	2,000
3,23,060	21,46,970	24,70,030	3,23,006	22,19,000	25,42,006
3,57,560	23,51,400	27,08,960	3,58,606	24,22,100	27,80,706

क्र.सं.	मीडिया इकाई/ गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
प्रसारण (मुख्य शीर्ष-2221)				
ध्वनि प्रसारण (उपमुख्य शीर्ष)				
निर्देशन व प्रशासन (लघु शीर्ष)				
वेतन				
		100	100	200
टेलीविजन (उप मुख्य शीर्ष)				
वेतन				
		100	100	200
सामान्य (उप मुख्य शीर्ष)				
प्रसार भारती (माइनर शीर्ष)				
अनुदान सहायता				
		16,22,400	84,73,300	10,09,5,700
कुल - प्रसारण		16,22,600	84,73,500	10,09,6,100
पूर्वोत्तर क्षेत्र : पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लाभ के लिए अन्य खर्च योजनाएं				
एकमुश्त प्रावधान (मुख्य शीर्ष-2552)				
		5,24,200	0	5,24,200
कुल - राजस्व खंड		25,40,320	1,07,50,600	1,32,90,920

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2005-2006			बजट अनुमान 2006-2007		
योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
6	7	8	9	10	11
100	100	200	100	100	200
100	100	200	100	100	200
16,22,400	94,29,100	1,10,51,500	29,81,900	93,58,400	1,23,40,30
16,22,600	94,29,300	1,10,51,900	29,82,100	93,58,600	1,23,40,700
5,23,700	0	5,23,700	4,64,600	0	4,64,600
25,03,860	1,17,80,700	1,42,84,560	38,05,306	1,17,80,700	1,55,86,006

क्र.सं.	मीडिया इकाई/का नाम	बजट अनुमान 2005-2006		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
पूँजीगत खंड				
प्रमुख शीर्ष '4220' — सूचना और प्रचार के लिए पूँजी परिव्यय				
अ) मशीनें और उपकरण				
1.	फिल्म प्रभाग के लिए उपकरण की प्राप्ति	10,500	0	10,500
2.	पत्र सूचना कार्यालय के लिए उपकरण की प्राप्ति	1,790	0	1,790
3.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिये उपकरण की प्राप्ति	14,600	0	14,600
4.	गीत एवं नाटक प्रभाग के लिए उपकरण की प्राप्ति	400	0	400
5.	फोटो प्रभाग के लिए उपकरणों की प्राप्ति	6,000	0	6,000
6.	मुख्य सचिवालय के लिए उपकरणों की प्राप्ति	0	0	0
7.	भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए उपकरण की प्राप्ति	0	0	0
8.	सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के लिए उपकरण की प्राप्ति	0	0	0
9.	फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पुणे के लिए उपकरण की प्राप्ति	19,060	0	19,060
10.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के लिए उपकरण की प्राप्ति	15,600	0	15,600
ब) भवन				
11.	फिल्म प्रभाग के लिए बहुमंजिला भवन-प्रमुख कार्य	0	0	0
12.	चलचित्र संग्रहालय (फि.प्र.) का निर्माण मुख्य कार्य	74,400	0	74,400
13.	एन.एफ.ए.आई. के लिये नाइट्रेट वाल्ट/कर्मचारी आवास निर्माण	0	0	0
14.	एन.एफ.ए.आई. कॉम्प्लेक्स के लिये द्वितीय फेज का निर्माण	40,000	0	40,000
15.	फिल्म समारोह भवन-संयोजन एवं परिवर्तन-प्रमुख कार्य	20,000	0	20,000
16.	कोलकाता में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना-भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण	0	0	0
17.	सूचना भवन निर्माण-प्रमुख कार्य	0	0	0
18.	क्षेत्रीय प्रचार के लिये कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण-प्रमुख कार्य	0	0	0
19.	पी.आई.बी. के लिए राष्ट्रीय प्रेस केंद्र एवं मिनी मीडिया सेंटर की स्थापना	1,81,950	0	1,81,950
20.	भारतीय प्रेस परिषद के भवन का निर्माण	0	0	0
21.	भारतीय जनसंचार संस्थान की भवन तथा आवास परियोजना	11,530	0	11,530
22.	निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों के लिए टॉवर और भवन	0	0	0

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2005-2006			बजट अनुमान 2006-2007		
योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
6	7	8	9	10	11
0	0	0	10,000	0	10,000
1,540	0	1,540	4,500	0	4,500
3,000	0	3,000	8,300	0	8,300
400	0	400	2,500	0	2,500
6,000	0	6,000	5,000	0	5,000
0	0	0	0	0	0
6,420	0	6,420	9,370	0	9,370
0	0	0	0	0	0
19,090	0	19,090	20,511	0	20,511
10,000	0	10,000	6,913	0	6,913
0	0	0	0	0	0
0	0	0	70,000	0	70,000
0	0	0	0	0	0
40,000	0	40,000	40,000	0	40,000
20,000	0	20,000	31,800	0	31,800
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
66,190	0	66,190	1,00,000	0	1,00,000
0	0	0	0	0	0
1,500	0	1,500	2,500	0	2,500
80,000	0	80,000	1,00,000	0	1,00,000

क्र.सं.	मीडिया इकाई/ गतिविधि का नाम	बजट अनुमान 2005-2006		
		योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5
	निवेश			
	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0
	कुल : पूंजी अनुभाग प्रमुख शीर्ष '4220'	4,01,680	0	4,01,680
	सूचना और प्रचार के लिए ऋण (मुख्य शीर्ष 6220)			
	फिल्में : (उप मुख्य शीर्ष)			
	सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों के लिए ऋण			
	मुख्य शीर्ष			
	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम			
	ऋण और अग्रिम	0	0	0
	प्रसारण के लिए ऋण (मुख्य शीर्ष)			
	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण			
	प्रसार भारती : ऋण तथा अग्रिम	17,49,700	0	17,49,700
	उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय व अन्य कार्य उत्तर- पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/योजना (मुख्य शीर्ष 4552)			
	एकमुश्त प्रावधान	5,88,300	0	5,88,300
	कुल पूंजीगत खंड	27,39,680	0	27,39,680
	कुल मांग संख्या 58	52,80,000	1,07,50,600	1,60,30,600

(हजार रुपये में)

संशोधित अनुमान 2005-2006			बजट अनुमान 2006-2007		
योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0
2,54,140	0	2,54,140	4,62,894	0	4,62,894
0	47,700	47,700	0	0	0
17,49,700	0	17,49,700	4,57,100	0	4,57,100
34,600	0	34,600	6,54,700	0	6,54,700
20,38,440	47,700	20,86,140	15,74,694	0	15,74,694
45,42,300	1,18,28,400	1,63,70,700	53,80,000	1,17,80,700	1,71,60,700